राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 199

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 27 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

दशक के पांच सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटरों में विराट भी शामिल

>> 14

सरोकार

बीस साल की 'कैद' से निकल अब जिंदगी बुन रहा अरविंद

अमृतसर : यह कहानी मानसिक चुनौती का सामना करने वाले एक बहादुर बच्चे की है। जिसे निराश स्वजनों ने बीते बीस साल से कमरे में कैद कर रखा था। उसके चाचा ने साहस किया और बंधन खोला तो अरविंद ने चुनौती को धता बता जिंदगी जीत ली। (पेज-6)

जागरण विशेष

जैतून ने कर ली राजस्थान से यारी, अब दूसरों की बारी

जयपुर : जी हां, कम तापमान पर पैदा होने वाले जैतून ने तपते राजस्थान से यारी कर ली है। 2006 में इजरायल के तकनीकी परामर्श से शुरू हुआ यह प्रयोग आम किसान के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है। पौध अन्य राज्यों में भी जाना शुरू हो गई है। (पेज-7)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

कैडर विलय से प्रभावित नहीं होगी अफसरों की वरिष्ठता

नई दिल्ली : रेल मंत्री पीयूष गोयल व रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने आशंकित अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि रेलवे सेवाओं के कैडर विलय से उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। रेल मंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'रेलवे बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए अफसरों को योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर समान अवसर मिलेंगे।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

आतंकियों को ढूंढ़-ढूंढ़ कर मारो : दिलबाग सिंह

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वादी में सक्रिय आतंकियों के सफाए के लिए आतंकरोधी अभियानों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों को ढूंढ़-ढूंढ़ कर मारो।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

फ्रॉड रोकने के बैंकों के दावों की कलई खुली

नई दिल्ली : सरकारी क्षेत्र के बैंक चाहे जितनी भी सुरक्षित बैंकिंग व्यवस्था का बखान करें, हकीकत यह है कि वे बैंकिंग फ्रॉड यानी धोखाधड़ी को रोकने में एकदम विफल रहे हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में देश के बैंकिंग सेक्टर में कुल 71,543 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले सामने आए हैं।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

इजरायल में आज तय होगा पीएम नेतन्याहू का भविष्य

यरुशलम : भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी ही पार्टी के भीतर चुनौती मिली है। सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी का नया नेता चुनने के लिए गुरुवार को प्राइमरी चुनाव कराया गया। नेतन्याहू का सियासी भविष्य तय करने वाले इस चुनाव का नतीजा शुक्रवार को आने की उम्मीद है।

लोगों को हिंसा के लिए भड़काने वाले नेता नहीं : जनरल रावत

- नागरिकता कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर सेना प्रमुख ने की टिप्पणी
- कहा, नेता वही जो लोगों को सही राह दिखाए, विवि, कॉलेजों के छात्रों के आंदोलनों का दिया हवाला

> नेता वह है, जो आपको सही दिशा में ले जाए, सही सुझाव दे और यह सुनिश्चित करे कि जिनका नेतृत्व वह कर रहा है, उनकी उसे परवाह है। नेता अपना व्यक्तिगत उदाहरण देकर समझाता है। यही वह चीज है, जिस पर हम सेना के लोग गर्व करते हैं।
>
> **-जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख**

नई दिल्ली में गुरुवार को एक कार्यक्रम में थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत। प्रेट्र

नई दिल्ली, एजेंसियां : नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि लोगों को हिंसा के लिए भड़काने वाले नेता नहीं हैं। गुरुवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को नेता नहीं कहा जा सकता, जो लोगों को गलत दिशा में ले जाते हैं। लोगों का सही दिशा में नेतृत्व करने वाले को ही नेता कहा जाएगा। जनरल रावत की इस टिप्पणी से सियासी घमासान तेज हो गया और विपक्षी दलों ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की।

सेना प्रमुख ने कहा कि नेतृत्व एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, हर कोई आपके पीछे चलने लगता है। यह उतना आसान नहीं है। यह आसान दिखता है, लेकिन असल में जटिल प्रक्रिया है। हालांकि भीड़ से भी नेता उभरता है। लेकिन, नेता वह है, जो लोगों को सही दिशा में ले जाए। इन दिनों विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का उदाहरण देते हुए जनरल रावत ने कहा कि जिस तरह शहरों में लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है, वह नेतृत्व नहीं है।

नागरिकता कानून पर हुए हिंसक प्रदर्शन : इसी माह संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पारित किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कई लोग घायल हुए और कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई। आंदोलनकारियों से निपटने में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

पूर्व नौसेना प्रमुख ने बयान को गलत बताया : पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास ने जनरल रावत के सार्वजनिक बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि नियम बहुत साफ है कि हम देश की सेवा करते हैं और राजनीतिक बल नहीं हैं। राजनीतिक बयान देना, जैसा कि हमने आज सुना है, किसी भी सेवारत सैनिक के लिए पूरी तरह गलत है। चाहे वह शीर्ष पर बैठा हो या निचले स्तर पर हो।

सेना ने दिया स्पष्टीकरण : जनरल रावत की टिप्पणी पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के बाद सेना ने एक बयान जारी कर सफाई दी कि सेना प्रमुख ने नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र नहीं किया है। बयान में कहा गया है कि उन्होंने किसी राजनीतिक घटना या व्यक्तित्व का हवाला नहीं दिया है। वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे। छात्रों को सही राह दिखाना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे देश के भविष्य हैं। कश्मीर घाटी में युवाओं को पहले उन लोगों द्वारा गुमराह किया गया, जिन पर उन्होंने विश्वास किया कि ये हमारे नेता हैं।

बयान पर बिफरा विपक्ष

सेना प्रमुख ने नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों पर कहा कि नेता वह नहीं है, जो लोगों को हिंसा के लिए भड़काए। मैं आपसे सहमत हूं जनरल साहब। लेकिन, नेता वह भी नहीं है, जो अपने समर्थकों को सांप्रदायिक आधार पर नरसंहार में शामिल होने की इजाजत दे। क्या आप मुझसे सहमत हैं जनरल साहब?

-दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता

हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी दावा करते हैं कि उन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। यदि कहीं हिंसा होती है, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस है। नागरिक मामलों में सेना क्यों दखल दे रही है।

-असदुद्दीन ओवैसी, एआइएमआइएम प्रमुख

सेना प्रमुख के बयान से स्पष्ट है कि मोदी सरकार के समय में हालात किस कदर बिगड़े हैं कि सेना के शीर्ष पर बैठा आदमी इस तरह से अपनी संवैधानिक भूमिका का उल्लंघन कर रहा है। इससे स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या सेना का राजनीतीकरण कर हम पाकिस्तान के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं?

-पोलित ब्यूरो, माकपा

डिटेंशन सेंटर पर खुद फंसी कांग्रेस

प्रहार ▶ भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताया 'झूठों का सरदार'

राहुल गांधी का विवादित ट्वीट-आरएसएस के प्रधानमंत्री ने भारत माता से झूठ बोला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के ट्वीट पर तल्खी, भाजपा ने कांग्रेस राज में डिटेंशन सेंटर के दिए सुबूत

संबित पात्रा। फाइल

डिटेंशन सेंटर पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस अब खुद ही फंस गई है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध करते-करते पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी दलीलें कांग्रेस पर तब भारी पड़ गईं जब पलटवार में भाजपा ने सुबूतों के साथ यह साफ कर दिया कि डिटेंशन सेंटर कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू हुए थे। राहुल के प्रधानमंत्री को झूठा व आरएसएस का पीएम कहने पर भाजपा ने राहुल को 'झूठों का सरदार' करार दिया। साथ ही संप्रग सरकार के आधिकारिक बयान और असम की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से जारी श्वेत पत्र का हवाला देकर बताया कि असम में डिटेंशन सेंटर कांग्रेस शासनकाल में ही बने थे।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी को झूठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कामदार बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल के मुद्दे पर माफी मांगने वाले राहुल अब डिटेंशन सेंटरों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल को किसी भी चीज का जानकारी नहीं है, लेकिन हर मुद्दे पर बोलते जरूर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, 'प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इतना कहा था कि ऐसे कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनाए गए हैं, जहां एनआरसी के बाद मुसलमानों को रखा जाएगा।' उन्होंने पीएम मोदी के रविवार के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि एनआरसी का डिटेंशन सेंटर से कोई लेना-देना नहीं है और एनआरसी के लिए कोई डिटेंशन सेंटर नहीं खोला गया है।

भाजपा प्रवक्ता पात्रा ने बताया कि असम में तीन डिटेंशन सेंटर उस समय बनाए गए थे, जब केंद्र और असम दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी। असम की तरुण गोगोई सरकार की ओर से 2012 में जारी श्वेत पत्र को दिखाते हुए पात्रा ने कहा कि इसके पेज नंबर 38 पर साफ लिखा है कि केंद्र सरकार ने असम सरकार को डिटेंशन सेंटर खोलने का निर्देश दिया था। श्वेत पत्र में यह भी लिखा था कि असम के गोलपाड़ा, कोकराझाड़ और सिलचर में तीन डिटेंशन सेंटर हैं, जिनमें क्रमशः 66, 32 और 20 विदेशियों को रखा गया है। इसी तरह पात्रा ने 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार की ओर जारी आधिकारिक बयान की प्रति भी दिखाई। इसमें असम में डिटेंशन सेंटर खोलने की बात कही गई थी।

जेल नहीं होते हैं डिटेंशन सेंटर पेज>>5
एनपीआर के वेश में एनआरसी लाना चाह रही सरकार : कांग्रेस पेज>>5
गिरिराज बोले-राहुल गांधी झूठे और ओवैसी देश के दुश्मन पेज>>6

कांग्रेस नेता ने ट्वीट समेत वीडियो किया जारी

राहुल गांधी। फाइल

इससे पहले, गुरुवार की सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह असम में डिटेंशन सेंटर नहीं होने की बात पर देश से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हैशटैग झूठ झूठ झूठ के साथ विवादित ट्वीट किया, 'आरएसएस के प्रधानमंत्री ने भारत माता से झूठ बोला।' राहुल ने अपने आरोपों के समर्थन में ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप भी पोस्ट की जिसमें मोदी को कहते हुए दिखाया गया है कि कांग्रेस, उसके सहयोगी दल और 'अर्बन नक्सल' यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। इस वीडियो क्लिप में असम में कथित डिटेंशन सेंटर का निर्माण होते भी दिखाया गया है।

उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, कई जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम
- डीजीपी ने बैठक कर चप्पे-चप्पे पर नजर रखने का दिया निर्देश

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए 27 दिसंबर को एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को नमाज के बाद सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा का कड़ा घेरा रहेगा। डीजीपी ओपी सिंह ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चप्पे-चप्पे पर नजर रखे जाने के निर्देश दिए हैं। पीस कमेटी की बैठकें कर आपसी समन्वय से शांति-व्यवस्था कायम रखने को कहा गया है। थानों में आउट रीच प्रोग्राम के तहत पीस कमेटी की बैठकें कर सीएए के बारे में जानकारी भी दी गई। कई संवेदनशील जिलों में ऐतिहातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

फीरोजाबाद, आगरा, मथुरा में जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद करा दी है। गश्त बढ़ाने के अलावा पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। गोरखपुर में प्रशासन ने शुक्रवार को शहर, खासकर कोतवाली इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दोपहर की नमाज से पहले उपद्रव प्रभावित इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स और भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। मुरादाबाद मंडल को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

मेरठ के डीआइजी दफ्तर में सोशल मीडिया लैब बनी है। यही लैब डिजिटल वालंटियर्स के जरिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पर नजर रख रही है। पुलिस ने सभी मस्जिदों की सूची बनाकर सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।

रामपुर में पीएसी और आरएएफ तैनात रहेगी। गाजियाबाद जिले में गुरुवार देर रात से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बिजनौर में शुक्रवार रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा आरएएफ, पीएसी को सौंपी गई है। यहां इंटरनेट सेवा पर पाबंदी बरकरार है। सहारनपुर में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। शामली में इंटरनेट सेवा शाम छह बजे से बंद कर दी गई। बदायूं में बिना अनुमति सत्याग्रह करने निकले लोकमोर्चा के 10 पदाधिकारियों को जेल भेज दिया गया। अलीगढ़ में रात शुक्रवार शाम पांच बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जरूरत पड़े तो गठित करें एसआइटी पेज>>6

श्रीनगर पर चढ़ा फुटबॉल का खुमार...

श्रीनगर में गुरुवार को रीयल कश्मीर और चेन्नई सिटी के बीच आइ-लीग का फुटबॉल मुकाबला हुआ। पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह पहला फुटबॉल मैच था। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंचीं। (खबर पेज-14 पर) कामरान रशीद बट

टुकड़े-टुकड़े गैंग को सबक सिखाएं : शाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- गृह मंत्री ने कहा, सीएए पर भ्रमित कर देश को दंगे की आग में झोंका
- दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी बोला हमला

गुरुवार को नई दिल्ली के कड़कड़डूमा में पूर्वी दिल्ली हब के शिलान्यास के अवसर पर लोगों को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और टुकड़े-टुकड़े गैंग ने देश व दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया और शांति खत्म कर दी है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने संसद में इस कानून को लेकर कुछ नहीं बोला और बाहर निकलकर देश को भ्रमित करने का काम किया। अब वक्त आ गया है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग और कांग्रेस को दंड दिया जाए।

अमित शाह गुरुवार को कड़कड़डूमा में ईस्ट दिल्ली हब की नींव रखने के दौरान आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व टुकड़े गैंग के भ्रमित करने की वजह से जगह-जगह विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भ्रांति फैलाकर देश की शांति भंग कर दी। शाह ने आप सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार तो कांग्रेस की गलत कार्य संस्कृति से भी आगे निकल गई। कांग्रेस की एक सरकार योजना बनाती थी, दूसरी बजट आवंटित करती थी, तीसरी भूमि पूजन करती थी और चौथी इसे भूल जाती थी, लेकिन केजरीवाल जी न सोचते हैं, न बजट बनाते हैं और न भूमि पूजन करते हैं, सीधे विज्ञापन देकर उस पर अपना ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन, मोदी सरकार शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन भी करती है। हर काम का समय तय है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हर घर में साफ पानी, जहां झुग्गी वहीं मकान और 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का काम किया, लेकिन विज्ञापन देने वाली यह सरकार उसका श्रेय लेने में जुटी है। गरीबों को हक से वंचित करने के लिए आयुष्मान और प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं किया। लेकिन, मोदी सरकार 10 लाख झुग्गीवासियों को मकान देने जा रही है।

दिल्ली ही नहीं, यह देश की पहली योजना पेज>>6

पीएम का अंदाज

सूर्यग्रहण देखने की कोशिश करते पीएम की तस्वीर पर यूजर ने किया था ट्वीट, मोदी के जवाब ने यूजर्स का दिल जीता, जमकर हुआ लाइक और रीट्वीट

ट्विटर यूजर ने कहा-मजाक बनेगा आपका, मोदी बोले-मजे करो

जेएनएन, नई दिल्ली

नई दिल्ली में गुरुवार को सूर्यग्रहण का नजारा देखने के लिए विशेष चश्मा पहनकर आसमान की ओर निहारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

लाइव स्ट्रीमिंग से देखा सूर्यग्रहण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये सूर्यग्रहण का नजारा देखा। उन्होंने ट्वीट कर बताया, 'कोझिकोड एवं देश के अन्य हिस्सों में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये सूर्यग्रहण की झलक देखी। इस दौरान विशेषज्ञों से चर्चा कर इस संदर्भ में अपनी जानकारी बढ़ाई।' मोदी ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये सूर्यग्रहण देखते हुए और विशेषज्ञों से चर्चा करते हुए तस्वीरें भी शेयर कीं।

अपने नरम अंदाज से माहौल को हल्का बना देने की कला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत मानी जाती है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर उनकी यह खूबी फिर देखने को मिली। मोदी ने अपनी तस्वीर पर मीम बनाए जाने के ट्वीट पर बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब देकर सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया। कुछ ही घंटों में पीएम के ट्वीट को करीब सवा लाख लाइक मिल गया। 23 हजार लोगों ने इसे रीट्वीट किया और साढ़े छह हजार से ज्यादा लोगों का कमेंट आया। देर रात तक लाइक और रीट्वीट का यह सिलसिला जारी रहा।

गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। इसमें वह हाथ में चश्मा थामे आसमान की ओर ताकते दिख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा था, 'दुर्भाग्य से आसमान में बादल होने के कारण मैं सूर्यग्रहण का नजारा नहीं देख पाया।' इस तस्वीर के शेयर होने के कुछ देर बाद गप्पिस्तान रेडियो नाम के यूजर ने मोदी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, 'इस पर मीम बनने जा रहा है।' इस ट्वीट ने लोगों का ध्यान तब खींचा जब मोदी ने खुद इस पर जवाब दिया। मोदी ने मीम बनने के ट्वीट पर जवाब दिया, 'बहुत-बहुत स्वागत है... मजे करो।' ट्वीट पर पीएम का जवाब आते ही लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया।

बनने लगे हैं मीम : पीएम मोदी की तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मीम बनाना भी शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने आसमान की ओर निहारते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई अन्य नेताओं की तस्वीरें साझा कीं। कुछ यूजर्स तस्वीर के साथ तरह-तरह की मजाकिया टिप्पणी भी करते दिखे। सोशल मीडिया पर मोदी के हाथ में पकड़े चश्मे की कीमत और कंपनी पर भी कयास लगाया जाने लगा। एक यूजर ने तस्वीर के साथ लिखा कि मोदी चांदनी चौक की एक दुकान में चश्मे का सही-सही रेट लगाने को कह रहे हैं।

मीम पर पहले भी बोले हैं पीएम : लोकसभा चुनाव से पहले बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। उस दौरान उन्होंने पूछा था कि अपने ऊपर बने मीम देखकर मोदी को कैसा लगता है। इस पर मोदी ने कहा, 'मैं इन्हें देखकर एंजॉय करता हूं। यह सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात है। इससे कॉमन मैन की क्रिएटिविटी समझने का मौका मिलता है। कितनी जल्दी सोच लेते हैं लोग। मैं इनमें मोदी नहीं लोगों की क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूं। क्रिएटिविटी के साथ मेरा घोर विरोध हो, तब भी मजा आता है।'

क्या होता है मीम? : सोशल मीडिया पर किसी तस्वीर को अलग-अलग तरह से पेश कर मजाक बनाने या संदर्भ से इतर बातें लिखने को मीम कहा जाता है। किसी तस्वीर से मिलती-जुलती अन्य संदर्भ वाली तस्वीरों को जोड़ते हुए मजाक बनाना भी इसी का हिस्सा है।

शोएब अख्तर ने कहा-हिंदू होने के कारण कनेरिया ने सही मुसीबत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

रहस्योद्घाटन

- कहा, साथी खिलाड़ी साथ में खाना नहीं खाने देते थे
- लतीफ ने कहा, यूसुफ के साथ भी किया गया बुरा बर्ताव

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने देश के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया पर हैरान करने वाला रहस्योद्घाटन किया है। पाकिस्तान के एक टीवी शो में शोएब ने कहा कि दानिश हिंदू थे इसलिए उनके साथ नाइंसाफी हुई। हमारे कुछ खिलाड़ियों को तो इस बात पर भी ऐतराज था कि वह हमारे साथ खाना क्यों खाते थे? 'गेम ऑन है' नामक चैट शो में शोएब के साथ पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ और पूर्व बल्लेबाज आसिम कमाल भी थे।

कनेरिया पर शोएब का रहस्योद्घाटन : शोएब ने कहा कि मुहम्मद यूसुफ (यूसुफ योहाना) के 12000 रन होने थे, लेकिन हमने उन्हें कभी सेफगार्ड नहीं किया। मेरी दो-तीन खिलाड़ियों से लड़ाई हुई। मैंने कहा कि अगर कोई हिंदू है तो भी वह खेलेगा और उसी हिंदू ने हमें टेस्ट सीरीज जिताई। टीवी शो के होस्ट डॉक्टर नुमान रियाज ने फौरन कहा कि दानिश कनेरिया ने जिताई। शोएब ने आगे कहा कि बात खुल जाएगी लेकिन, बता दूं कि कुछ खिलाड़ियों ने मुझसे कहा कि यह (दानिश) यहां से खाना क्यों ले रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें यहां से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। कप्तान होगे, तुम अपने घर के। वह तुम्हारे लिए छह-छह विकेट ले रहा है। इंग्लैंड में दानिश और शमी ने ही हमें सीरीज जिताई थी।

ड्रेसिंग रूम खराब कर देते हैं खिलाड़ी पेज>>6

349 दर्ज किया गया गुरुवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स। फरीदाबाद में यह 360, गाजियाबाद में 359, ग्रेटर नोएडा में 370, गुरुग्राम में 290 और नोएडा में यह 370 रहा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 27 दिसंबर 2019

राजघाट से दौड़ीं 100 नई अल्ट्रा मॉडर्न बसें

सुरक्षित सफर ▸ बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट, पैनिक बटन समेत सभी आधुनिकतम सुविधाएं हैं उपलब्ध

राजघाट क्लस्टर डिपो से सीएम ने दिखाई हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राजघाट क्लस्टर डिपो से 100 नई अल्ट्रा मॉडर्न बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें दिल्ली के 12 रूटों पर संचालित की जाएंगी। इन बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे एवं जीपीएस समेत सभी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। केजरीवाल ने कहा कि पिछले चार माह में बेड़े में अब 529 नई बसें शामिल हो गई हैं। इससे दिल्ली की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 100 और बसों को डीटीसी के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली के निवासियों को सरकार की तरफ से हर सप्ताह खुशखबरी मिल रही है। अगले तीन-चार महीने में और बसें आने वाली हैं। अब लोगों को बस की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारा मकसद दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बहुत ही आधुनिक बनाना है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आज हमें 100 नई अल्ट्रा मॉडर्न बसें मिली हैं। नई बसों में तीन सीसीटीवी कैमरे हैं। हर वैकल्पिक सीट पर एक पैनिक बटन है और अगर एक पैनिक बटन दबाया जाता है तो एक बड़ा हूटर कमांड सेंटर को सक्रिय करेगा। दिल्ली की हर बस में मार्शल हैं। दिल्ली को नियमित रूप से नई बसें मिलती रहेंगी।

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की ओर से 300 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। ये 1,000 क्लस्टर ई-बसों के अतिरिक्त होंगी, जिन्हें पहले से ही मौजूदा बेड़े में जोड़ा जाना तय है। टेंडर प्रक्रिया जारी है। 1,000 लो-फ्लोर, वातानुकूलित, सीएनजी-रन क्लस्टर बसों के लिए वित्तीय बोली भी खोली गई है। 2019-20 के लिए दिल्ली सरकार के बजट के अनुसार इस वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता सहित विभिन्न कारणों से ई-बस खरीद परियोजना में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई। इससे पहले दिल्ली सरकार ने इस साल 2 मार्च को 385 पूर्ण-इलेक्ट्रिक बसों के पहले बेड़े के लिए निविदाओं को मंजूरी दी थी। निविदाएं 10 मार्च को मंगाई गई थीं, लेकिन मतदान के कारण प्रक्रिया बाधित हो गई थी। अब प्रक्रिया चल रही है।

राजघाट कलस्टर बस डिपो से नई बसों के शुभारंभ से पूर्व पैनिक बटन की जांच करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (दाएं)। जागरण

महिपालपुर में किया भूमिगत जलाशय का उद्घाटन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ मुख्यमंत्री बोले, एक लाख से अधिक परिवारों को होगा लाभ

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिपालपुर में 60 लाख लीटर क्षमता के नवनिर्मित भूमिगत जलाशय (यूजीआर) का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके चालू हो जाने से आसपास के इलाकों में रह रहे एक लाख से अधिक परिवारों को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड ने हैदरपुर प्लांट से 12 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर यहां तक पानी पहुंचाया है। 15 करोड़ रुपये की लागत से बने इस भूमिगत जलाशय से महिपालपुर एक्सटेंशन, रंगपुरी गांव, रंगपुरी एक्सटेंशन व वसंत कुंज एंक्लेव समेत कई अन्य इलाके के लोग लाभांवित होंगे।

मुख्यमंत्री ने महिपालपुर में भूमिगत जलाशय का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इलाके के निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस इलाके में पानी की बहुत ज्यादा समस्या रहा करती थी। अब यहां पानी की समस्या का निवारण हो जाएगा। यहां तक पानी पहुंचाने में बहुत सारी अड़चनें आईं। हम सभी अड़चनों को दूर करने के बाद इसे चालू कर रहे हैं। अभी इसकी नई-नई पाइपलाइन है। इसलिए अभी 10 से 15 दिनों तक कुछ परेशानी होगी। इसके बाद ठीक से पानी आने लगेगा। वसंत कुंज एंक्लेव की भी कुछ समस्या थी। उसको भी ठीक कर दिया। अब इसके जरिये वसंत कुंज एंक्लेव में भी पानी पहुंच जाएगा। पांच साल से हमारी सरकार की यही कोशिश रही है कि दिल्ली के कोने-कोने में पानी की लाइन बिछा दी जाए। अगले एक से डेढ़ साल में पूरी दिल्ली में हर घर के अंदर टोंटी से पानी आ जाएगा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव का कभी भी हो सकता है एलान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ समीक्षा बैठक में ज्यादातर तैयारियों को लेकर संतुष्ट दिखा आयोग

▸ कम मतदान वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश

चुनाव आयोग ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा बैठक की। आयोग ज्यादातर तैयारियों से संतुष्ट दिखा। हालांकि इस बीच कम मतदान वाले क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। वहीं, ऐसे क्षेत्रों की खासतौर से पहचान करने और उपयुक्त उपाय करने को कहा गया जहां मतदाता निष्पक्ष मतदान न होने को लेकर आशंकित हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों का एलान अब कभी भी हो सकता है। दिल्ली की मौजूदा सरकार का कार्यकाल फरवरी 2020 में खत्म हो रहा है और चुनाव इससे पहले होने हैं।

चुनाव आयोग ने इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के पुलिस आयुक्त के साथ एक अलग से भी बैठक की। दिल्ली के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन ने कानून-व्यवस्था को लेकर प्रजेंटेशन दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ इस दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र भी मौजूद रहे। बैठक में आयोग ने चुनाव से जुड़े सभी बिंदुओं पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से एक-एक कर जानकारी ली। साथ ही बैठक में मौजूद अधिकारियों से भी सवाल-जबाव किए। आयोग ने इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट के प्रशिक्षण से जुड़े अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक लाने और छोड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए सभी जरूरी जनसुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। आयोग ने इस दौरान शिकायतों के लिए तैयार किए गए एप (एप्लीकेशन) की जानकारी भी ली। साथ ही निर्देश दिया कि एप पर आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

इस अहम बैठक में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, दिल्ली छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि मौजूद थे।

न्यूज गैलरी

प्रत्येक जिले में एसआइटी की नहीं है जरूरत

नई दिल्ली : एक याचिका के जवाब में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में विशेष जांच दल (एसआइटी) की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों पर वरिष्ठ अधिकारी जांच पूरी होने तक नजर रखते हैं। एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि यौन शोषण के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए हर जिले में एसआइटी बनाई जाए। दिल्ली पुलिस ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा है कि यौन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए कुशल और समयबद्ध तरीके से जांच की जाती है। विशेष पुलिस आयुक्त के अधीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है। इसके बाद निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों की एफआइआर दर्ज करने के समय से ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी नजर रखेंगे। (जासं)

विस चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित की स्क्रीनिंग कमेटी

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) ने गुरुवार शाम स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी। यही कमेटी दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से गठित की गई इस कमेटी का अध्यक्ष वरिष्ठ नेता राजीव सातव को बनाया गया है। वीरेंद्र सिंह राठौर एवं चल्ला वेम्शी चंद रेड्डी को सदस्य रखा गया है। कमेटी में दिल्ली से पार्टी प्रभारी पीसी चाको, सह प्रभारी कुलजीत सिंह नागरा और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को शामिल किया गया है। (जासं)

साफ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, अपनी दिल्ली अभियान शुरू

नई दिल्ली : दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन और समाज कल्याण मंत्री ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में साफ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, अपनी दिल्ली अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही एक थीम गीत भी लांच किया गया। इस अवसर पर शहरी विकास विभाग की प्रधान सचिव मनीषा सक्सेना सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत दिल्ली को संवारने और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। (जासं)

दागदार कुंडली वाले इंस्पेक्टर नहीं बन सकेंगे एसीपी

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

▸ पुलिस मुख्यालय ने जिले और यूनिटों के डीसीपी से मांगी जानकारी

दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टरों को पदोन्नति देकर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 93 इंस्पेक्टरों की सर्विस कुंडली खंगाली जा रही है। इनमें से जिनके खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत पर प्रारंभिक जांच, विभागीय जांच, आपराधिक मामले व विजिलेंस जांच आदि हुई है तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। मुख्यालय ने गत 24 दिसंबर को सभी 15 जिले व यूनिटों के डीसीपी को पत्र भेजकर इस संबंध में 30 दिसंबर तक जानकारी देने को कहा है। निर्धारित तिथि तक किसी इंस्पेक्टर के बारे में मुख्यालय को जवाब नहीं मिलेगा तो इसके लिए इंस्पेक्टर खुद भी जिम्मेदार होंगे।

दिल्ली पुलिस के विभिन्न जिले व यूनिटों में तैनात 12 दानिप्स एसीपी को गत दिनों उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पदोन्नत कर एडिशनल डीसीपी बना दिया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस में एसीपी के 12 पद पद खाली हो गए हैं। वहीं विभिन्न थानों व यूनिटों में तैनात 93 इंस्पेक्टरों की पदोन्नति विचाराधीन है। उन्हें वेतन तो एसीपी ग्रेड का मिल रहा है, लेकिन उन्हें एसीपी का रैंक नहीं मिल पाया है। इनमें कुछ इंस्पेक्टर तो ऐसे हैं, जो लगातार सात बार थानाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जिन्हें एक या दो बार ही थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक के सफर में बहुत अधिकारी होते हैं, जिन पर कोई दाग न लगा हो। इसलिए मुख्यालय ने जिले व यूनिटों में तैनात इंस्पेक्टरों के बारे में डीसीपी से वर्तमान स्टेटस के बारे में जानकारी मांगी है। यह जानकारी भविष्य में पदोन्नति को लेकर होने वाली बैठक में रखी जा सकेगी। सूत्रों के मुताबिक इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सब डिवीजन, स्पेशल सेल व क्राइम जैसी यूनिटों में इंस्पेक्टरों को भेजा जाएगा। इसे लेकर इंस्पेक्टरों में खलबली है। सभी अपने-अपने अधिकारियों से मिलकर रिपोर्ट दुरुस्त करने में जुटे गए हैं। सूत्र बताते हैं कि 93 इंस्पेक्टरों की सूची लंबी है, इनमें उन्हीं इंस्पेक्टरों को पदोन्नत किया जाएगा, जिनपर कभी दाग नहीं लगा है।

निर्भया के दोषी मुकेश ने जेल प्रशासन को नोटिस का नहीं दिया जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों को जेल प्रशासन की ओर से जारी नोटिस का उत्तर देने की समय सीमा गुरुवार को समाप्त हो गई। सात दिनों में जेल प्रशासन को सिर्फ दोषी अक्षय, विनय और पवन की ओर से ही जवाब मिला, जबकि मुकेश ने जवाब नहीं दिया है। जेल के अतिरिक्त महानिरीक्षक राजकुमार ने बताया कि इस मामले में जेल प्रशासन की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट को वस्तुस्थिति की जानकारी दी जाएगी। कोर्ट का जो निर्देश आएगा, उसका पालन किया जाएगा।

जेल प्रशासन की ओर से चारों दोषियों को जारी किए गए नोटिस में सात दिन का वक्त दिया गया था। इस नोटिस के जवाब में अक्षय, विनय व पवन की ओर से जेल प्रशासन को बताया गया कि अभी उनके पास दया याचिका से पूर्व क्यूरेटिव याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है। क्यूरेटिव याचिका दायर करने के बाद जो नतीजे आएंगे, उसके आधार पर आगे क्या करना है, यह तय करेंगे। जेल प्रशासन के अनुसार, सात जनवरी को इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है।

'समय निकाल कर शाह आएं, मैं उन्हें सरकारी स्कूल दिखाता हूं'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ अमित शाह के बयान पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया पलटवार

▸ बोले, आपको दिल्ली में कुछ ऐसे लोगों से मिला देते हैं, जिनकी बिजली फ्री हुई है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरी गृहमंत्री से विनती है कि वह दो-चार दिन का समय निकालें तो मैं उन्हें दिल्ली सरकार के स्कूल और एमसीडी के स्कूल दिखा देता हूं।

शाह ने एक कार्यक्रम में आरोप लगाया कि केजरीवाल सिर्फ प्रचार करते हैं और दूसरों के कराए काम पर ठप्पा लगाते हैं। इस पर सिसोदिया ने कहा कि मेरी गृहमंत्री से विनती है कि वह दो-चार दिन का समय निकालें। अगर चुनाव से फ्री हो गए हों तो दिल्ली चुनाव से पहले आएं तो मैं उन्हें दिल्ली सरकार के स्कूल दिखा देता हूं, एमसीडी के स्कूल दिखा देता हूं, कुछ मोहल्ला क्लीनिक दिखा देता हूं, कुछ सरकारी अस्पताल दिखा देता हूं। साथ तो चलिए हम आपको दिल्ली में कुछ ऐसे लोगों से मिला देते हैं, जिनकी बिजली फ्री हुई है। मेरी विनती है दिल्ली की ओर चलिए तो सही। दिल्ली की तरफ ध्यान तो दीजिए। प्रवेश वर्मा पर तंज करते हुए कहा कि पहले वे बता तो दें कि सीएम पद का उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को बना रहे हैं या मनोज तिवारी को।

केजरीवाल का काम मोदी के नाम पर गिनाने में जुटे शाह : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि रामलीला मैदान से पड़ी डांट के कारण मोदी को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल का काम मोदी के नाम पर गिनाने पर जुट गए हैं। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि चार दिन पहले मोदी जी ने रामलीला मैदान से अमित शाह को डांट लगाई तो वे मोदी जी को खुश करने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल का काम मोदी के नाम पर गिनाने में जुट गए हैं। वहीं एक अन्य ट्वीट में संजय सिंह ने कहा कि 2019 का सबसे बड़ा मजाक। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के कामों में अड़ंगा लगा रहे हैं।

डीएसजीपीसी सरकारी योजनाओं की जानकारी अल्पसंख्यकों को देगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) ने कई नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणजीत कौर ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने का निर्देश दिया।

कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन जसविंदर सिंह जौली ने कहा कि अल्पसंख्यक बच्चों के लिए भी कई सरकारी योजनाएं हैं, जिसके तहत स्कूल फीस माफी के साथ छात्रवृत्ति और पाठ्य सामग्री भी दी जाती है। इसका लाभ सिख बच्चों को मिले, इसके लिए नोडल अधिकारी लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें आवेदन करने में भी मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि पहली से 12वीं कक्षा तक 50 फीसद से ज्यादा अंक हासिल करने और कक्षा में 70 फीसद उपस्थिति वाले अल्पसंख्यक छात्रों को फीस माफी का लाभ मिलता है।

चुघ होंगे भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है। पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी तरुण चुघ इस समिति के संयोजक होंगे। वहीं, चांदनी चौक के सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के नेतृत्व में अनुभवी नेता घोषणा पत्र तैयार करेंगे। चुनाव की तैयारी व प्रचार अभियान को ध्यान में रखकर कुल 35 विभाग बनाए गए हैं। प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख होगा।

रचनात्मक तरीके से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए राज्यसभा सदस्य विजय गोयल की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। यह टीम सोशल मीडिया के लिए वीडियो व ऑडियो सहित होर्डिंग तैयार करेगी। टीम में तेजिंदर बग्गा, आतिफ रशीद, राजकुमार भाटिया, प्रत्यूष कंठ, वरुण छाबड़ा, सुनील यादव आदि शामिल हैं। सांसद हंसराज हंस और गौतम गंभीर की देखरेख में समाज के अलग-अलग वर्गों में संपर्क अभियान चलेगा। इस टीम में सूरज प्रकाश खत्री, भोलानाथ विज, रजनीश गोयनका, केएस दुग्गल व सुधीर गुप्ता को शामिल किया गया है। हर्ष मल्होत्रा को बूथ स्तर पर चुनावी कार्य का प्रभारी और धर्मवीर सिंह को प्रमुख बनाया गया है।

वैशाली से मोहननगर तक कॉरिडोर बनने पर दौड़ेगी स्वचालित मेट्रो

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

वैशाली से मोहननगर तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर पर स्वचालित ट्रेन दौड़ेगी। कंट्रोल रूम से संचालन किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को इस कॉरिडोर की संशोधित डीपीआर की मुख्य विशेषताओं की कॉपी जीडीए को सौंपी। उसमें बताया कि वर्ष 2020 में निर्माण शुरू होने पर वर्ष 2025 तक कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा सकता है। यह कॉरिडोर मेट्रो की यमुना बैंक से वैशाली तक ब्लू लाइन का विस्तार होगा।

संशोधित डीपीआर के मुताबिक वैशाली से मोहननगर तक 5.04 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके निर्माण में 1808.22 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस कॉरिडोर पर प्रहलादगढ़ी, वसुंधरा सेक्टर-14, साहिबाबाद और मोहननगर पर स्टेशन बनेंगे। साहिबाबाद स्टेशन पर इसे दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इससे यात्री दोनों रेल सेवाओं का लाभ ले सकें। पहले इस कॉरिडोर को साहिबाबाद तक बनाया जा रहा था। तब इसकी लंबाई 4.16 किलोमीटर थी। लागत 1438 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

फैक्ट फाइल

- कॉरिडोर पर आठ कोच की मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी
- एक ट्रेन में 2352 यात्रियों को सवार करने की क्षमता होगी
- ट्रेन की न्यूनतम गति 33 और अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी
- केंद्र सरकार लागत में 20 प्रतिशत का अंशदान देगी
- वैशाली से मोहननगर तक 79134.5 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा कॉरिडोर

डीएमआरसी ने वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो कॉरिडोर की संशोधित डीपीआर की मुख्य विशेषताओं की कॉपी सौंपी है। इस कॉरिडोर के निर्माण में पांच साल का वक्त लगेगा। पूरी तरह ऑटोमैटिक मेट्रो ट्रेन ट्रैक पर उतारी जाएगी। उसमें ड्राइवर नहीं होगा।
–विवेकानंद सिंह, मुख्य अभियंता, जीडीए।

ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम लगेगा : वैशाली से मोहननगर तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर में ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम लगेगा। संशोधित डीपीआर में जिक्र है कि स्मार्ट कार्ड, मोबाइल एप से ही टिकटिंग सुविधा दी जाएगी। 2025 में टोकन व्यवस्था लगभग खत्म कर हो जाएगी।

घर के बाहर ही नहीं अंदर भी असुरक्षित है आधी आबादी

लोकेश चौहान, नई दिल्ली : महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावों के बीच दिल्ली की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राजधानी में घर के अंदर ही आबादी के उत्पीड़न में इस साल वृद्धि हुई है। थाने पहुंचे मामलों को ही देखा जाए तो अब इसमें 17 फीसद की वृद्धि दर्ज हुई है। इसमें महिलाओं के साथ मारपीट व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।

राजधानी के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए ससुराल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामलों में सबसे अधिक मामले पति द्वारा मारपीट किए जाने के थे। इसके बाद पति और ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले में भी सामने आए। 15 नवंबर 2019 तक थानों में दर्ज मामलों की संख्या 3187 थी, जबकि 15 नवंबर 2018 तक विभिन्न थानों में 2716 मामले दर्ज किए गए थे। पूरे वर्ष की बात की जाए, तो 2018 में 3416 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में नवंबर और दिसंबर के डेढ़ माह में ही राजधानी में ससुराल में महिलाओं के साथ हिंसा के 700 मामले दर्ज किए गए थे। ये वे मामले हैं, जो पुलिस थाने में दर्ज किए गए हैं, जबकि कितने ही ऐसे मामले हैं, जो दर्ज ही नहीं किए गए।

केजरीवाल बोले, पांच साल में गंदे पानी की समस्या लगभग खत्म

मावलंकर सभागार में आप के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में अगली पंक्ति में बैठे (बाएं से) विधायक सोमनाथ भारती, कमांडो सुरेंद्र सिंह, मंत्री गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मावलंकर सभागार में नई दिल्ली लोकसभा के तहत आने वाली 10 विधानसभा सीटों के लोगों के साथ टाउनहॉल मीटिंग की। इस दौरान लक्की ड्रा के माध्यम से आठ लोगों के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। साथ ही जिन लोगों के सवाल लक्की ड्रा में नहीं निकल पाए, उनका जवाब एसएमएस से दिया जाएगा। जो लोग मीटिंग में आए थे, उनका पंजीकरण कराने के बाद ही हॉल में प्रवेश दिया गया था।

आइएनए से आए शिवेंद्र मिश्रा के गंदे पानी की आपूर्ति के सवाल का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब हम आए थे तो दिल्ली में केवल 58 फीसद पानी की आपूर्ति पाइपलाइन से होती थी, लेकिन अब यह 93 फीसद हो गई है। बाकी जगह भी पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। हमारे सरकार में आने के दौरान 2300 स्थानों पर गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत मिली थी जो कि अब यह महज 125 रह गई है। हमारे विरोधी भी यह मुद्दा उठा चुके हैं और कहते हैं कि दिल्ली में 10 लाख लोगों के घर में वाटर प्यूरीफायर लगा है। दिल्ली में 50 लाख लोगों में 10 लाख लोगों के घर में वॉटर प्यूरीफायर लगा है तो 40 लाख लोग तो नल का ही पानी पी रहे हैं। मैं मानता हूं कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उन्हें तेजी से दूर किया जा रहा है।

पांच साल में दिल्ली को चमका देंगे : सीएम ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड रखते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि हमारी सरकार ने इन दो मुद्दों पर बहुत ही गंभीरता से कार्य किया है। इससे अब सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम निजी स्कूलों से बेहतर हो रहे हैं।

जो रजिस्ट्री दे, उसी पर करना विश्वास : आरके पुरम की झुग्गी बस्तियों से आए संजय रॉबिंसन ने सवाल किया कि उनके मकानों को पक्का करने की बात हो रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या पक्का हुआ है। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने नवंबर 2015 में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया था। लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। दिल्ली में बिजली-पानी पर होते काम को देखते हुए अब केंद्र सरकार इन कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की बात कह रही है। हमने आठ हजार करोड़ की राशि से कच्ची कॉलोनियों में गली से लेकर नाली बनवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मकान जब ही पक्का माना पाएगा जब उसकी रजिस्ट्री हो। इसलिए उसी पर विश्वास करना जो आपके मकानों की पक्की रजिस्ट्री दे दे। वहीं मोती नगर की मेघना साहू ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान राशि को कम करने का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इससे लोग यातायात नियमों को मानने लगे हैं, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इस पर वह जरूर विचार करेंगे।

विधायकों के समर्थन के नारे पर सीएम ने जताई नाराजगी : मीटिंग में संवाद के दौरान कुछ लोगों ने दिल्ली कैंट से विधायक सुरेंद्र कमांडो और आरके पुरम से प्रोमिला टोकस के समर्थन में नारे लगाए तो अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे लगाना ठीक नहीं है। हम यहां देश बदलने के लिए आएं हैं, किसी को टिकट दिलाने के लिए नहीं।

आयोजन

जोधपुर का दही चिकन, उड़ीसा के छेन्नापोडो, मुंबई की पुरनपोली और दिल्ली के लजीज स्ट्रीट फूड का लें स्वाद

जेएलएन में 26 राज्यों के स्ट्रीट फूड का उठाएं लुत्फ

रितु राणा, नई दिल्ली

जोधपुर का दही चिकन, उड़ीसा के छेन्नापोडो, मुंबई की पुरनपोली और दिल्ली के लजीज स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना है तो पहुंच जाइए जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम। जेएलएन स्टेडियम में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) की ओर से पांच दिवसीय 11वें राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी में पड़ रही कड़ाके की ठंड में दिल्ली के साथ-साथ यहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिमी भारत समेत 26 राज्यों के स्ट्रीट फूड का लुफ्त मिलेगा। नासवी की ओर से आयोजित इस फेस्टिवल का उद्देश्य देश के हर कोने के स्ट्रीट वेंडर्स को एक स्थान पर लाकर सम्मान दिलाना है।

जेएलएन में आयोजित यह फूड फेस्टिवल 29 दिसंबर तक चलेगा। इसकी एंट्री फीस 100 रुपये है। यहां आपको उचित दामों में देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यजंनों का स्वाद मिल जाएगा। दिल्ली के मयूर विहार इलाके की प्रसिद्ध राज कचोड़ी, चांदनी चौक की दौलत की चाट, लक्ष्मी नगर की स्पेशल अमृतसरी नान खाकर आपको मजा जा जाएगा। वहीं, नॉन वेज में जामिया नगर बाटला हॉउस का चिकन तंदूरी, चिकन मलाई टिक्का, चिकन सीख कबाब का स्वाद लाजवाब है। लक्ष्मी नगर के कौशल अलवी के चिकन शामी कबाब, चिकन बिरयानी, मटन शामी कबाब व कोरमा का भी कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा यहां लोग लक्ष्मी नगर के अमृत स्पायरल पटैटो खूब पसंद कर रहे हैं। यहां एक स्टिक में फ्राइड पटैटो चिप्स को स्पायरल करके परोसा जा रहा है, जिसका स्वाद लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

द्वारका के पिज्जा ऑमलेट स्टॉल पर पहुंचते ही लोगों की नजरें वहीं थम जाती हैं। यहां आपको स्वादिष्ट पिज्जा ऑमलेट मिलेगा, जिसे पैन में फ्राइ करके उससे आग निकालकर पकाया जाता है। इस तरह से पिज्जा ऑमलेट बनाने के तरीके को देखकर लोग खूब आकर्षित हो रहे हैं। वहीं, इंडिया गेट के इस्माइल के फायर वाले पान का भी लोग खूब लुत्फ ले रहे हैं। करोल बाग के अफगानी मोमो, अचारी मोमो व चॉकलेट मोमो का स्वाद भी लाजवाब है।

विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का लें स्वाद

बिहार के पनीर लिट्टी व चिकन लिट्टी, उत्तराखंड के प्रसिद्ध मनडुव की रोटी व मनडुव का हलवा, लखनऊ की प्रसिद्ध कुल्फी, अयोध्या की कुल्हड़ जलेबी व खुरचन पेड़ा। पंजाब की खास गुड़ की चाय, मुंबई का मिस्कल पाव, जुनाका भाकर, पुरनपोली व कड़ी समोसा, मध्य प्रदेश का इंदौरी पोहा भी हैं खास। वहीं, नॉन वेज में उड़ीसा का माछ भात व माछ तरकारी भात, मोतीहारी का मीट भात, कर्नाटक का चिकन 65, पुडुचेरी का चिकन पेरी का स्वाद भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

खाने के साथ गीत-संगीत का भी लें आनंद

स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में बच्चों के मनोरंजन के लिए किड्स एक्टिविटी जोन बनाया गया है। यहां नृत्य, संगीत के साथ-साथ कई गतिविधियों से बच्चों का मनोरंजन किया जा रहा है। यहां बच्चे चाहें तो नृत्य व गायन भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक लोग यहां व्यंजन के साथ गीत-संगीत का आनंद ले रहे हैं। स्टेज से घोषणा करके बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है।

1.8 लाख हाउसिंग यूनिट की बिक्री नहीं हुई है शहरी भारत में। जिसकी कुल लागत 1.4 लाख करोड़ रुपये है। इसमें सबसे अधिक यूनिट (49027) एनसीआर की है। इसका मूल्य 33990 करोड़ रुपये है।

न्यूज गैलरी

डाटा रिकवरी के लिए पुलिस लेगी एफबीआइ की मदद

पुणे : पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार नक्सल समर्थक वरवर राव के घर से बरामद क्षतिग्रस्त हार्ड डिस्क से डाटा हासिल करने में अमेरिकी खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसी एफबीआइ से मदद लेने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अगस्त 2018 में छापे के दौरान बरामद हार्ड डिस्क को फोरेंसिक लैब भेजा गया था, लेकिन वहां डाटा रिकवर करने में कोई सफलता नहीं मिली। जांच से संबंधित एक अधिकारी ने कहा कि इसे सबसे पहले पुणे की एक लैब में भेजा गया था जहां विशेषज्ञ डाटा हासिल नहीं कर सके। बाद में हार्ड डिस्क को मुंबई स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला महानिदेशालय भेजा गया, लेकिन वहां विशेषज्ञ भी इसे खोल नहीं पाए। अधिकारी ने कहा, 'एफबीआइ की प्रयोगशालाएं काफी उन्नत हैं। हार्ड डिस्क को वहां भेजने का फैसला किया जा चुका है और गृह मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है।' (प्रेट्र)

'कलासा-बांडुरी नहर पर जावडेकर का पत्र निराधार'

पणजी : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर की ओर से कर्नाटक सरकार को हाल ही में भेजे गए पत्र का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कलासा-बांडुरी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी की दरकार नहीं है। गोवा के जल संसाधन मंत्री फिलिप नेरी रोड्रिग्स ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक महादेइ नदी बेसिन से पानी को मोड़ना शुरू कर चुका है। राज्य ने महादेइ अंतर-राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल की अधिसूचना का इंतजार भी नहीं किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में संबंधित मुद्दे के लंबित रहने के कारण इस पत्र का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है। रोड्रिग्स ने कहा कि कई और पत्र, कई और पत्राचार हो सकते हैं। वे और मांग रख सकते हैं। उनके पत्राचार से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। कलासा-बांडुरी नहर का काम शुरू हो जाने को देखते हुए इस पत्र का कोई औचित्य नहीं रह गया है। गोवा सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर कर कर्नाटक पर आरोप लगाया है कि इसने नदी के पानी को दूसरी दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया है। (आइएएनएस)

कैंट इलाकों में गरीबों को नहीं लगना चाहिए डर : राजनाथ

नई दिल्ली : कैंट एरिया में रहने वाले ज्यादातर लोग बहुत गरीब होते हैं और कैंट बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों अधिकारियों से डर न लगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने कैंट बोर्डों के लिए 2019 के एक्सीलेंस एवार्ड वितरित किए। कैंट एरिया में स्वास्थ्य, सफाई, प्राथमिक शिक्षा जैसी जनसेवाएं कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, इन इलाकों में रहने वाले लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि अगर वे किसी अफसर के पास जाएंगे तो उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव है कि एक गरीब व्यक्ति की आह सबसे बुरी होती है। ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। आपको गरीब लोगों पर शासन नहीं करना है, बल्कि उनकी सेवा करना है। कैंट बोर्ड महानिदेशक, डिफेंस इस्टेट (डीजीडीई) के अधीन आते है। (प्रेट्र)

नवजात की हत्या की दोषी महिला सुप्रीम कोर्ट से बरी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नवजात बच्ची की गला घोंटकर हत्या करने की दोषी और उम्रकैद की सजा पाई एक महिला को बरी कर दिया है। अस्पताल में ही मार दी गई नवजात की मां को बरी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि एक महिला के लिए खुद ही अपने ही बच्चे की हत्या करना 'पूरी तरह से अस्वाभाविक' है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के मार्च 2010 के महिला के खिलाफ फैसले को पलटते हुए उस पर लगाए दोष और सजा को खारिज कर दी। जस्टिस एमएम शांतनागौदर और आर. सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने कहा कि यह सच है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर के मुताबिक नवजात बच्ची की मौत दम घुटने से हुई थी और उसके गले पर गला दबाए जाने के निशान भी थे। (प्रेट्र)

कैडर विलय से प्रभावित नहीं होगी अफसरों की वरिष्ठता

चिंता दूर ▶ रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने किया आश्वस्त

कहा-अफसरों को योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर समान अवसर मिलेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने आशंकित अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि रेलवे सेवाओं के कैडर विलय से उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

रेल मंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'रेलवे बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए अधिकारियों को योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर समान अवसर मिलेंगे। पदों का निर्धारण अधिकारियों के कैडर के आधार पर नहीं होगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे कि सभी 8,400 अधिकारियों की प्रोन्नति और वरिष्ठता सुरक्षित रहे।' वहीं, वीके यादव ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रेलवे सुनिश्चित करेगी कि एक भी अधिकारी को उसके करियर की प्रगति में नुकसान न हो।

पीयूष गोयल फाइल

विलय के बाद यूपीएससी के जरिये भर्तियां : वीके यादव ने बताया कि रेलवे की आठों सेवाओं के विलय के बाद बनने वाली इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस (आइआरएमएस) में भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के जरिये की जाएंगी। अभ्यर्थियों को पहले प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना होगा। उसके बाद उन्हें आइआरएमएस के लिए अपनी प्राथमिकता दर्शानी होगी। इसमें पांच विशेषज्ञता क्षेत्र होंगे, इनमें चार तकनीकी और एक गैर-तकनीकी क्षेत्र होगा। तकनीकी क्षेत्र में सिविल, मैकेनिकल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग से जुड़े पद होंगे। जबकि गैर-तकनीकी पदों पर अकाउंट्स, कार्मिक और यातायात विभागों के लिए भर्ती की जाएगी। इसकी सटीक रूपरेखा पर काम चल रहा है, लेकिन यह काफी कुछ ऐसी ही होगी।

तर्कसंगत बनेंगे यात्री किराये व मालभाड़े : वके यादव ने बताया कि अपने घटते राजस्व को बढ़ाने के लिए रेलवे ने पहले ही कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, 'हम अपने यात्री किराये और मालभाड़े को तर्कसंगत बनाने जा रहे हैं। इस बारे में कुछ सोचा जा रहा है। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, यह संवेदनशील विषय है। मालभाड़ा पहले से ही ज्यादा है, लिहाजा हमारा लक्ष्य इस संबंध में यातायात को सड़क से रेलवे की ओर लाने का है।'

लद्दाख की सीमा के पास चीनी सेना ने बनाई सुरंगें

- पीएलए टेंट लगाकर पैंगोंग झील के पास और भी भूमिगत सुरंगें खोद रही
- चीनी सेना ने इलाके में अपनी सेना की तैनाती और गश्त भी बढ़ाई

नई दिल्ली, आइएएनएस : चीन ने एक बार फिर लद्दाख सीमा के पास भारत की सुरक्षा के खिलाफ एक कदम उठाया है। लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में चीन अपनी सेना के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील के पास सैन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर काम करना शुरू कर दिया है।

एक सूत्र ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने इस इलाके में टेंट लगाए हैं और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इसी इलाके में भूमिगत सुरंगों का निर्माण किया है। इतना ही नहीं चीनी सेना पैंगोंग त्सो क्षेत्र के पास विवादित फिंगर 8 माउंटेन स्पर में और अधिक सुरंगों का निर्माण कर रही है। सूत्र के मुताबिक, 'ये भी देखा गया है कि चीनी सेना ने इस इलाके में अपनी सेना की तैनाती और गश्त भी बढ़ाई है। इतना ही नहीं, अब वे आसपास के इलाकों में भारतीय सेना की आवाजाही पर एतराज जता रहे हैं।'

बता दें अब तक इस विवादित क्षेत्र में किसी तरह का सैन्य ढांचा नहीं बनाया गया है, जहां चीनी सेना गश्त के लिए आ जाया करती थी। लेकिन टेंट की स्थापना करने के साथ ही चीनी सेना ने जिस तरह खुद को इस सीमावर्ती इलाके में तैनात कर लिया है, यह भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है।

पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर करीब 134 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच कई दफा झड़प हो चुकी है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर फिंगर-8 (पर्वतीय स्पर्स) क्षेत्र में विवादित फिंगर-5, भारत और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक झड़प का गवाह बना था। 15 अगस्त, 2017 को एक-दूसरे को घायल करने के लिए दोनों सेनाओं ने पत्थरों और लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया था। पैंगोंग झील के उत्तरी तट इलाके का दो-तिहाई हिस्सा चीन के कब्जे में है जो तिब्बत से लेकर लद्दाख तक फैला हुआ है। भारत और चीन के बीच मानी गई वास्तविक सीमा रेखा (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल-एलएसी) को लेकर दोनों देशों के विरोधाभासी नजरिए के चलते यह विवाद होते रहे हैं। ऐसे किसी भी विवाद के बाद दोनों देशों की सेनाओं के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडलों की बातचीत होती है।

आरएएन का लाभ नहीं मिलने पर स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गरीब रोगियों के बारे में एक शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। शिकायत है कि जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे गरीब रोगी यदि आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं तो वह राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के तहत इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं।

एनएचआरसी के मुताबिक, उसे शिकायत मिली है कि बीपीएल कार्ड धारक रोगी यदि एबी-पीएमजेएवाई के लाभार्थी हैं तो उन्हें आरएएन का लाभ नहीं मिल रहा है। यहां तक कि रोगी को जानलेवा बीमारी होने और जिसपर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो सकता है तो भी आरएएन का लाभ नहीं मिल रहा है। आयोग ने मंत्रालय से उपयुक्त कदम उठाने और छह सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। आयोग ने स्वास्थ्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा है, 'शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस तरह की विसंगति के कारण समाज के अत्यंत गरीब तबके के लोगों को अपना घर, जमीन बेचनी पड़ रही है और इलाज का खर्च वहन करने के लिए ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि सरकार को आवश्यक कदम उठाने को कहा जाए ताकि गरीबों को आरएएन का लाभ मिले।'

उच्च शिक्षण संस्थानों में बदलेगा मूल्यांकन का पैटर्न

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं के मूल्यांकन पर उठ रहे सवालों के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसमें बदलाव का बड़ा फैसला लिया है। संभव है कि बदलाव का यह प्रयोग ठीक वैसा ही होगा जैसा कुछ साल पहले स्कूली शिक्षा में अपनाया गया था। जिसमें छात्रों के बौद्धिक विकास और ज्ञान आदि पर जोर दिया गया था। बावजूद इसके स्कूलों में बदलाव की यह मंशा साकार होते नहीं दिख रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल्यांकन सुधार को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालयों में मानवीय मूल्यों को मजबूत बनाने वाले कार्यक्रम 'मूल्य प्रवाह', शिक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम 'गुरु दक्षता', शैक्षिक शोध की गुणवत्ता को मजबूत बनाने वाले कार्यक्रम 'केयर' को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में अंकों की जगह ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाने पर जोर किया गया है।

फिलहाल इस सारी कवायद के पीछे यूजीसी का सिर्फ एक ही मकसद है, उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को मजबूत बनाना। यही वजह है कि मूल्यांकन सुधार को भी गुणवत्ता की इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। यूजीसी के मुताबिक यह इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि मौजूदा समय में स्नातक करने के बाद यदि स्नातकोत्तर में दाखिला लेना होता था, उसके लिए भी उसे प्रवेश देना होता था। इसी तरह नेट या पीएचडी करने के बाद भी नौकरी के लिए अलग से परीक्षा देना जरूरी होता है। ऐसे में हमारे ही मूल्यांकन पर सवाल उठ रहे थे। खासकर उस समय जब हम अपने संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। हालांकि यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह के मुताबिक इन कदमों से बदलाव के असर आने वाले तीन से चार साल में दिखेंगे।

अब ज्ञान, कौशल, विश्लेषण क्षमता की होगी परख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनाई रूपरेखा

यूजीसी दफ्तर। फाइल

विवि को शोधों की उपयोगिता का देना होगा ब्योरा : निशंक

मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शोध में गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों को ही जरूरी बताया। विश्वविद्यालयों को शोधों के दोहराव (नकल) से बचने की नसीहत भी दी। साथ ही कहा कि अब तक उनके संस्थानों में जितने भी शोध हुए हैं, वे उसका ब्योरा भी दें और बताएं वे कितने उपयोगी रहे। इस दौरान विवि के प्रमुखों से कहा कि किसी की राय या विरोध से वे अपने कदम पीछे न हटाएं, बल्कि अपने काम को आगे बढ़ाने में जुटे रहें।

रमेश पोखरियाल निशंक। फाइल

इन चार पहलुओं पर होगा मूल्यांकन : यूजीसी के मूल्यांकन सुधार को लेकर जारी गाइडलाइन के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल्यांकन के प्रमुख चार आधार होंगे। पहला-शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा- नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य, तीसरा- सामाजिक संवेदनशीलता और चौथा- गुणवत्ता होगा। सवाल के साथ दिए जाने वाले जवाबों का भी इसी आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

महाराष्ट्र में डीआइजी पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

- आइपीएस अधिकारी पर दोस्त की बेटी के जन्मदिन के मौके पर उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप

मिड डे, मुंबई : उप महानिरीक्षक (डीआइजी) निशिकांत मोरे के खिलाफ अंततः पॉक्सो अधिनियम के कठोर प्रावधानों व आइपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इस पुलिस अधिकारी पर अपने दोस्त की बेटी का उसके जन्मदिन की पार्टी पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

नवी मुंबई पुलिस को दिए गए बयान में पीड़िता ने अपनी त्रासदी की जानकारी दी। उसने कहा कि पूर्व में भी महाराष्ट्र मोटर परिवहन विभाग में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मोरे ने अनुचित तरीके से स्पर्श किया था और विरोध के बावजूद उसे कई बार चूमा था। मिड डे ने इस मामले को उठाया और एक नाबालिग लड़की की संवेदनशील कहानी की शृंखला चलाई। नवी मुंबई पुलिस ने आखिरकार डीआइजी मोरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गुरुवार शाम मामला दर्ज होने के बाद से अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया है।

नवी मुंबई के तालोजा थाने में मामला दर्ज किया गया है। नवी मुंबई पुलिस ने बुधवार शाम को ही एफआइआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। टाइपिस्ट के साथ महिला पुलिस अधिकारियों की टीम ने पीड़िता के घर का दौरा किया और हिंदी भाषा में उसका बयान दर्ज किया। पीड़िता को हिंदी में लिखे 12 सवालों की सूची दी गई और लड़की ने अधिकारियों और अपने परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। बुधवार देर रात और गुरुवार तक पूरा बयान दर्ज किया गया। पीड़िता ने दर्ज कराए गए बयान में पांच जून को अपने जन्मदिन के मौके पर उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी जानकारी दी है। आरोपित पुलिस अधिकारी उस दिन शराब के नशे में थे। इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं होने पर परिवार ने डीजीपी से शिकायत की थी।

सरकारी एजेंसियों को उधार टिकट नहीं देगी एयर इंडिया

- 10 लाख रुपये से ज्यादा बकाए वाली एजेंसियों पर सख्ती
- सीबीआइ, ईडी और वीएसएफ जैसी एजेंसियां शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्ज के बोझ तले दबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अब उधार पर काम चलाने वाले सरकारी एजेंसियों पर रुख सख्त किया है। विमानन कंपनी ने ऐसी सरकारी एजेंसियों को उधार टिकट देने मना कर दिया है, जिन पर 10 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है। इनमें सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियां शामिल हैं।

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा, 'सीबीआइ, ईडी, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, बीएसएफ और इंडियन ऑडिट बोर्ड समेत विभिन्न सरकारी एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है कि उनके अधिकारियों को उधार पर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इन सभी एजेंसियों पर एयर इंडिया का 10 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है।' अब इन सरकारी एजेंसियों के अधिकारी अन्य सामान्य यात्रियों की तरह ही एयर इंडिया का टिकट खरीद सकेंगे। विभिन्न सरकारी एजेंसियों पर एयर इंडिया का कुल बकाया 268 करोड़ रुपये है। एयरलाइन ने इन एजेंसियों से करीब 50 करोड़ रुपये वसूले हैं।

एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 8,556 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का कुल कर्ज अभी 60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। पांच दिसंबर को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को बताया था कि एयर इंडिया में विनिवेश के लिए अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने के लिए पीआइएम तैयार किया जा रहा है।

जनवरी के अंत में मंगाई जा सकती है बोली : एयर इंडिया में विनिवेश के लिए विनिवेश विभाग सर्दियों की छुट्टी के बाद अभिरुचि पत्र जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, 10 जनवरी के बाद कभी भी इस संबंध में कदम बढ़ाया जा सकता है। इसमें विदेशी खरीदारों को लुभाने का प्रयास किया जाएगा। निवेशकों को लुभाने के लिए हाल ही में सिंगापुर और लंदन में रोडशो किया गया था। सरकार इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है।

हड़ताल की तैयारी में कर्मचारी : अपने भविष्य को लेकर चिंतित एयर इंडिया कर्मचारी अब हड़ताल का रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुंबई में एयर इंडिया यूनियनों और अन्य कर्मचारी संगठनों की बैठक में दो विकल्पों पर विचार हुआ है। इसमें एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाने या हड़ताल पर जाने के विकल्पों पर बात हुई। अंतिम फैसले के लिए अभी और चर्चा होगी। अगर हड़ताल का रास्ता चुना गया तो इसकी शुरुआत आठ जनवरी से हो सकती है।

गुजरात के पूर्व आइएएस अफसर की 36 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले में गुजरात कैडर के पूर्व आइएएस अधिकारी संजय गुप्ता व उनके परिवार की 36 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 1985 बैच के अधिकारी रहे गुप्ता ने वर्ष 2002 में नौकरी छोड़कर आतिथ्य सेवा (हॉस्पिटैलिटी) का कारोबार शुरू किया था, जिसका नाम नीशा ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ईडी ने उनके खिलाफ मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदाबाद कंपनी लिमिटेड से संबंधित गबन तथा आपराधिक कदाचार के मामले में केस दर्ज किया है। गुप्ता अप्रैल 2011 से अगस्त 2013 के बीच कंपनी के चेयरमैन थे। ईडी के अनुसार, 'जांच में पाया गया कि गुप्ता ने चेयरमैन रहते हुए विभिन्न पदों पर अपने करीबियों की नियुक्ति की। गुप्ता ने वर्ष 2012-13 में कई मुखौटा कंपनियां बनाईं और इन कर्मचारियों को उनका निदेशक बना दिया।' ईडी ने गुप्ता, उनकी पत्नी नीलू गुप्ता, नीशा ग्रुप की कंपनियों- नीशा लेजर लिमिटेड, नीशा टेक्नोलॉजी, नीशा एग्रीटेक एंड फूड्स की संपत्तियों की जब्त करने के लिए आदेश जारी किया था। जब्त संपत्तियों में अहमदाबाद के धनंजय टॉवर में स्थित फ्लैट, इसी इलाके की कुछ अचल संपत्तियां, थलतेज स्थित कैंबेज होटल, विशालपुर, चांगोदर व दसकरोई स्थित प्लॉट्स एवं फैक्ट्रियां व जोधपुर का कैसेला टॉवर शामिल हैं।

आरएसएस प्रमुख का समावेशी बयान भी विपक्ष को नहीं भाया

- माकपा नेता वृंदा करात ने कहा, संविधान पढ़ें आरएसएस प्रमुख
- बसपा ने संविधान की भावना और प्रकृति के खिलाफ बताया
- ओवैसी ने इसे आरएसएस की सोच बताया

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत की 130 करोड़ आबादी को हिंदू बताने संबंधी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का समावेशी बयान भी विपक्ष को पसंद नहीं आया है। माकपा ने गुरुवार को कहा कि आरएसएस प्रमुख को देश का संविधान पढ़ना चाहिए। वहीं, बसपा ने उनके बयान को संविधान की भावना और प्रकृति के खिलाफ करार दिया।

माकपा नेता बृंदा करात ने कहा, 'मैं मोहन भागवत से अनुरोध करती हूं कि कृपया भारत का संविधान पढ़ें। बेशक, वह भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ऐसे बयान देने से पहले कम से कम उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। वह जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वह ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं जिसकी संविधान के तहत कोई अहमियत नहीं है।' उन्होंने कहा कि कौन भारतीय है यह देश के कानून से तय होता है, भागवत के कहने से नहीं। बृंदा ने कहा, 'मोहन भागवत यह कहने वाले कौन हैं कि कौन भारतीय है अथवा कौन नहीं है। भारत का संविधान क्या कहता है, हम सिर्फ उसकी परवाह करते हैं। संविधान परिभाषित करता है कि कौन भारतीय है। देश के कानून परिभाषित करते हैं कि कौन भारतीय है, न कि भागवत क्या कहते हैं।'

वहीं, बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने कहा, 'आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान हमारे संविधान और राष्ट्रीय एकता की भावना और प्रकृति के खिलाफ है क्योंकि भारत का संविधान ही 130 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है।' उन्होंने कहा कि यह बयान समाज में संघर्ष पैदा करने के लिए दिया गया है। आरएसएस प्रमुख को ऐसा करने से बचना चाहिए। ऐसा करके वह समाज और देश को विभाजित कर रहे हैं जो इस समय देश की एकता के लिए बेहद खतरनाक है।

जबकि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के बयान पर पर कहा कि संघ भारत में एक मजहब चाहता है। यह सिर्फ आरएसएस की सोच है। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि देश के संविधान में हर धर्म को सम्मान दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 40 महिलाओं और संस्थानों को राष्ट्रीय अवार्ड

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगले साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कम से कम 40 महिलाओं और संस्थानों को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड महिला अधिकारिता और समाज कल्याण की दिशा में उनकी अथक सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। यह सालाना पुरस्कार व्यक्तियों, समूहों, संस्थानों को विशेष रूप से नाजुक और वंचित महिलाओं के लिए महिला अधिकारिता की दिशा में किए गए उनके काम को मान्यता दिलाने के लिए दिया जाएगा। मंत्रालय के बयान में कहा गया है, 'पात्रता की शर्तें और दिशानिर्देश डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नारीशक्तिपुरस्कार डॉट डब्ल्यूसीडी डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन/नामांकन विचार के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।' राष्ट्रीय अवार्ड के लिए आवेदन सौंपने की अंतिम तारीख सात जनवरी 2020 निर्धारित की गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है। हर साल मंत्रालय प्रमुख संगठनों और संस्थाओं को उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए पुरस्कृत कर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है।

नाराजगी

सीएए समेत विभिन्न मसलों पर बंगाल के राज्यपाल के रुख से नाराज हैं एएफएसयू और एफईटीएसयू, गत दिनों राज्यपाल को जेयू के दीक्षा समारोह में आने से भी रोका गया था

धनखड़ को कुलाधिपति के पद से 'निष्कासित' करेंगे जेयू के छात्र संगठन

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल रखे जादवपुर यूनिवर्सिटी (जेयू) के छात्र संगठनों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्हें कुलाधिपति के पद से 'निष्कासित' करने का फैसला किया है। जेयू की आर्ट्स फैकल्टी स्टूडेंट्स यूनियन (एएफएसयू) और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूनियन (एफईटीएसयू) ने राज्यपाल को इस बाबत खुला पत्र लिखकर उन्हें कुलाधिपति के पद से 'निष्कासित' किए जाने की जानकारी दी है। साथ ही उन्हें 'मेरुदंड विहीन' भी कहा है। एएफएसयू की नेत्री उशाषी पाल ने कहा-'हम राज्यपाल को सांकेतिक तौर पर जेयू जैसे प्रमुख शिक्षा संस्थान के कुलाधिपति के पद से निष्कासित करेंगे। जेयू ने हमेशा उदारवादी सोच और समग्रता को प्रोत्साहित किया है।' एएफएसयू के इस कड़े रुख पर जेयू के कुलपति सुरंजन दास ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले जेयू में एक कार्यक्रम में

जगदीप धनखड़। फाइल

शामिल होने पहुंचे केंद्रीय वन व पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो का वहां के छात्र-छात्राओं ने घेराव किया था। उस वक्त राज्यपाल वहां पहुंचकर बाबुल को छात्र-छात्राओं से मुक्त कराकर अपने साथ ले गए थे। उसी वक्त से जेयू के छात्र-छात्राओं के साथ उनकी टकराहट शुरू हुई थी।

राज्यपाल पर उठाई ऊंगली : खुले पत्र में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल की मौजूदगी में बदमाशों ने गत 19 सितंबर को जेयू परिसर में बमबाजी और तोड़फोड़ की और महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। यह भी कहा गया कि राज्यपाल को 22 दिसंबर को जेयू में आमंत्रित नहीं किया गया था वह बिन बुलाए पहुंचे थे और छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शर्मनाक काम कर रहे हैं और इस तरह से अपना मूल्यवान समय नष्ट कर रहे हैं। पत्र में आगे कहा गया कि राज्यपाल से एनआरसी, सीएए और एनपीआर से संबंधित कई सवाल किए गए, जिन पर उनका जवाब असंतोषजनक रहा है। राज्यपाल का सामान्य ज्ञान भी संतोषजनक नहीं है। उनका इतिहास का ज्ञान शून्य है और समग्र चरित्र मेरुदंड विहीन है। गौरतलब है कि एएफएसयू राष्ट्रीय नागरिकता कानून (सीएए) समेत विभिन्न मसलों पर राज्यपाल के रुख से नाराज है।

बंगाल सरकार भी कम कर चुकी है अधिकार : बंगाल सरकार भी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल के अधिकारों में कटौती कर चुकी है। नए नियमों के मुताबिक अब कुलाधिपति विवि के दैनिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे और न ही विवि के पदाधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से परामर्श दे सकेंगे। कुलाधिपति और विवि प्रबंधन के बीच वार्ता अब राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से हो सकेगी।

राज्यपाल को ई मेल कर रोका था : एएफएसयू की ओर से 24 दिसंबर को राजभवन में ईमेल कर राज्यपाल को जेयू के दीक्षा समारोह में नहीं आने को कहा गया था। ईमेल में लिखा था-'आपका काम करने का तरीका निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख की तरह नहीं है। आपका व्यवहार भी छात्र-छात्राओं के अभिभावक की तरह नहीं है इसलिए जेयू परिसर में आपका स्वागत नहीं किया जाएगा।' राज्यपाल गत सोमवार (23 दिसंबर) को जब विवि की बैठक में भाग लेने गए थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। मंगलवार को उन्हें दीक्षा समारोह में शामिल होने से भी रोक दिया गया था। राज्यपाल ने इसे कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो जाना करार दिया था।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

11 सीटों पर किस्मत आजमाई थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम ने झारखंड में। इन सीटों पर पार्टी को नोटा के बराबर मत (1.36 फीसद) भी हासिल नहीं हो सके। संबंधित सीटों पर झारखंड की जनता ने उसे महज 1.16 फीसद वोट ही दिए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 27 दिसंबर 2019

न्यूज गैलरी

झारखंड के विवि में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति

रांची : झारखंड के चार विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की अनुशंसा पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत झारखंड रक्षा विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के एक पद (अनारक्षित), रांची विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के एक पद (अनारक्षित), विनोबा भावे विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक तथा वित्त पदाधिकारी के एक-एक पद (अनारक्षित) तथा नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के एक पद (अनारक्षित) पर नियुक्ति होगी। रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी तथा परीक्षा नियंत्रक पद के लिए 55 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। डिप्टी रजिस्ट्रार पद के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 20 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। (राब्यू)

जाति प्रमाण पत्र मामले में गुना के सांसद यादव को राहत

ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले गुना-शिवपुरी सीट के भाजपा सांसद डॉ. केपी यादव को बड़ी राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के एसडीएम के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में सांसद यादव के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करने का भी आदेश दिया है। यादव की याचिका पर सात जनवरी तक राज्य शासन से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सांसद यादव के वकील एमपीएस रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा माधुरी पाटिल मामले में दिए गए फैसले का दृष्टांत देते हुए कहा कि शीर्ष कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र के संबंध में फैसला लेने का अधिकार राज्य स्तरीय कमेटी को दिया है, लेकिन डॉ. केपी यादव का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश एसडीएम ने जारी किया है। (नईदुनिया)

जनवरी के पहले हफ्ते में उत्तराखंड कांग्रेस की नई कार्यकारिणी

देहरादून : प्रदेश कांग्रेस को नई कार्यकारिणी के लिए इंतजार कुछ दिन और बढ़ गया है। 28 दिसंबर को सीएए-एनआरसी पर पार्टी के देहरादून में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के बाद ही नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। अब माना जा रहा है कि नए वर्ष 2020 के पहले महीने जनवरी के पहले हफ्ते में कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। टीम प्रीतम की नई कार्यकारिणी की घोषणा में लंबे अरसे से देरी हो रही है। पहले सहकारिता, फिर नगर निकायों के चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी के गठन के कयास लगाए गए थे। इन चुनाव के बाद भी नई कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन टाल दिया गया। फिर लोकसभा और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों तक नई कार्यकारिणी की घोषणा लटक गई। (राब्यू)

उत्तराखंड विस का विशेष सत्र जनवरी के पहले सप्ताह में

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसे सभी राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराया जाना जरूरी है। इसलिए यह सत्र बुलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया है। इसे अब राष्ट्रपति ने अनुमोदन देना है। यह तभी होगा, जब सभी राज्यों की विधानसभा से इसे पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद ही राष्ट्रपति इस पर अनुमोदन देंगे। इसे देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को इसके लिए अपनी विधानसभाओं से 10 जनवरी से पहले इसे पारित करने को कहा है। इस कड़ी में एक पत्र उत्तराखंड सरकार को भी भेजा गया है। पत्र मिलने के बाद प्रदेश में भी विशेष सत्र को बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है। (राब्यू)

झारखंड में सत्ता परिवर्तन का असर, जेल में सजा लालू का दरबार

जागरण संवाददाता, रांची

- चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव पुराने अंदाज में आए नजर
- रिम्स में हेमंत सोरेन के अलावा 6-7 लोगों ने की मुलाकात
- राजद नेता ने बताया- मिली है अनुमति, जेल अधीक्षक का इन्कार

झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने की प्रक्रिया के बीच चारा घोटाले में सजायाफ्ता और रांची के रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) में इलाजरत राजद प्रमुख लालू प्रसाद जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर पेइंग वार्ड के बरामदे में जनता दरबार लगा रहे हैं। गुरुवार को आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने बारी-बारी से लालू प्रसाद से मुलाकात की।

हेमंत सोरेन के लालू से मुलाकात कर निकलने के बाद से यह सिलसिला चालू हुआ। लालू प्रसाद से मुलाकात करने के लिए रिम्स के पहले तल्ले में धड़ाधड़ लोग अंदर घुसते रहे, जबकि वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने एक बार भी इसकी सुध नहीं ली। लालू से मुलाकातियों के नाम के बारे में जब पुलिसकर्मियों से पूछा गया तो इंस्पेक्टर अशोक मंडल ने सिर्फ हेमंत सोरेन का नाम बताया। इस बीच सात लोगों ने लालू से मुलाकात की, लेकिन इसका रजिस्टर तक में कोई जिक्र नहीं है।

जेल प्रशासन से मिली है अनुमति : लालू प्रसाद से मुलाकात कर निकलते हुए राजद नेता जनार्दन प्रसाद से जब मीडिया ने लालू से मुलाकात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन से उन्हें अनुमति मिली है, जबकि जेल अधीक्षक के अनुसार उनका नाम मुलाकातियों की सूची में है ही नहीं। वहीं बिहार के पूर्व कृषि नरेंद्र सिंह ने भी जेल मैनुअल का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से लालू प्रसाद की तबीयत को लेकर चिंतित थे, इसलिए उनका हाल जानने आए थे।

> लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए गुरुवार को हेमंत सोरेन, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह को विशेष अनुमति दी गई थी। 7-8 लोगों के मिलने की जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद रिपोर्ट मिलने पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।
>
> -अशोक चौधरी, जेल अधीक्षक, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, रांची

रांची में गुरुवार को रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) के पेइंग वार्ड से सटे हुए कॉटेज के बाहर बैठे चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद (बाएं) और उनसे बात करते बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह। जागरण

शनिवार का दिन तय, गुरुवार को इतने लोगों को विशेष अनुमति कैसे?

जेल प्रशासन द्वारा लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए शनिवार का दिन तय है। इस दिन तीन लोगों को लालू से मुलाकात की अनुमति दी जाती है। वहीं परिवार के सदस्य के लिए सप्ताह में किसी भी दिन एक सदस्य को विशेष परिस्थिति में मिलने की अनुमति दी जाती है। करीब तीन महीने पहले जेल प्रशासन ने लालू के बेटे तेजस्वी को भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद उन्हें बगैर मुलाकात के लौटना पड़ा था।

कौन-कौन मिला ये नहीं पता : सुरक्षा प्रभारी

पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा प्रभारी अशोक मंडल ने बताया कि हेमंत सोरेन के अलावा लालू प्रसाद से कौन-कौन मिला ये नहीं पता। जब रजिस्टर में इंट्री देखी गई तो उसमें हेमंत सोरेन का भी नाम नहीं था। बाकियों ने भी बगैर किसी प्रक्रिया के लालू से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार चुनाव रिजल्ट आने के बाद से हर दिन 4-5 लोग लालू प्रसाद से पेइंग वार्ड में मुलाकात करते हैं।

रखी बात ▶ झारखंड में सरकार गठन की कवायद और शपथग्रहण की तैयारियों के बीच बोले हेमंत सोरेन

'दुर्भावना से काम नहीं करेगी सरकार'

प्रमुख नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी, प्रधानमंत्री से मांगा समय

कहा, सभी मिलकर करें राज्य का विकास

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में नई सरकार के गठन और मंत्रालयों के बंटवारे की कवायद की बीच झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सबको मिलजुलकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए काम करना चाहिए। विपक्ष की भूमिका को भी अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी के प्रति दुर्भावना से काम नहीं करेगी और सबको साथ लेकर चलेगी। इस बीच नई सरकार के गठन और शपथग्रहण समारोह को लेकर हेमंत के प्रमुख नेताओं से मुलाकात का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। हेमंत ने शपथग्रहण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का वक्त मांगा है। हेमंत सोरेन और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 29 दिसंबर को दो बजे शपथ लेंगे। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने गुरुवार को हेमंत सोरेन से मुलाकात कर शपथ ग्रहण के लिए विधिवत आमंत्रित किया।

गुरुवार को हेमंत ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लालू ने हेमंत को सरकार चलाने में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। हेमंत के शपथग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले बुधवार को सोरेन नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले थे। हेमंत ने उन्हें 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और चुनाव के दौरान मिले सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।

रघुवर के खिलाफ दर्ज केस वापस लेंगे : विधानसभा चुनाव के दौरान एक बयान को लेकर हेमंत सोरेन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति थाने में शिकायत की थी। बुधवार को उनकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई, लेकिन हेमंत सोरेन अब इस मामले को तूल नहीं देना चाहते। अब वह रघुवर दास के खिलाफ थाने में की गई शिकायत वापस लेंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार किसी के प्रति दुर्भावना से काम नहीं करेगी। लालू से मुलाकात के संदर्भ में कहा कि लालू प्रसाद उनके अभिभावक हैं और सरकार संचालन को लेकर उनके मार्गदर्शन व दिशानिर्देश की आवश्यकता है। कहा, राज्य को दिशा देने के लिए सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष की भी अहम भूमिका होगी। सकारात्मक सोच के साथ ही सारा काम संभव है। वे इसी सोच के साथ राज्य को दिशा देना चाहते हैं।

भाकपा माले का भी समर्थन : हेमंत सोरेन की सरकार को भाकपा माले का भी समर्थन मिलेगा। गुरुवार को इस बाबत निर्णय किया गया। बगोदर के नवनिर्वाचित विधायक विनोद कुमार सिंह इस बार विधानसभा में भाकपा माले के एकमात्र चेहरा हैं।

रांची में गुरुवार को रिम्स में उपचाराधीन चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने के बाद रिम्स ट्रामा सेंटर का निरीक्षण करने जाते झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हेमंत सोरेन (दाएं), साथ में रिम्स डायेक्टर डीके सिंह (बाएं)। जागरण

ईसाई धर्मगुरु बताएं वह किस कारण भाजपा के शासन में डरे हुए थे

जागरण संवाददाता, रांची

- रांची में आर्च बिशप के सत्ता परिवर्तन संबंधी बयान का विरोध तेज

झारखंड में सत्ता परिवर्तन को लेकर रांची धर्मप्रांत के आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो के बुधवार को दिए बयान का विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को श्री महावीर मंडल डोरंडा केंद्रीय समिति के अध्यक्ष संजय पोद्दार, मंत्री पप्पू वर्मा ने चर्च धर्मगुरु के उस बयान की निंदा की है कि भाजपा के शासन में हम सब डरे हुए थे। वर्तमान सरकार क्रिसमस गिफ्ट है।

मंडल के अध्यक्ष संजय पोद्दार ने कहा कि एक धर्मगुरु को इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण और तुष्टीकरण की राजनीति है। अगर हिंदू धर्म गुरु हिंदुओं के पक्ष में बयान दें तो हम सांप्रदायिक कहे जाते हैं। ईसाई धर्मगुरु को बताना चाहिए कि वह भाजपा के शासन में किस कारण से डरे हुए थे। क्या विवादित संस्था जहां बच्चों की खरीद फरोख्त होती थी, उसकी जांच, धर्म परिवर्तन पर रोक, विदेशी फंडिंग की जांच से डरे हुए थे। आर्च बिशप को इन बातों का भी जवाब देना चाहिए।

यह दिया था बयान : बुधवार को रांची धर्मप्रांत के आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने कहा था- 'पिछली सरकार में हमलोग तनाव में रहते थे। उम्मीद है कि नई सरकार में हमें ज्यादा समर्थन मिलेगा। आशा है कि नई सरकार के कामकाज से लोगों में सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और अविश्वास का वातावरण दूर होगा।' यह भी कहा कि मिशन द्वारा किए जा रहे शिक्षा के कामों में सरकार की ओर से ज्यादा बाधा आ रही थी। वह यहां भी नहीं रुके और कहा- पिछली सरकार में हमलोग प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। एक साल पहले एक प्रेयर बनाया गया था, जो हर गिरजाघर में हर समुदाय के लोगों द्वारा प्रतिदिन पढ़ी जाती थी।

पिछली सरकार ने चर्च के गलत कामों पर अंकुश लगाने का काम किया : मेघा उरांव

झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुर्वा रांची के अध्यक्ष मेघा उरांव ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि पिछली सरकार ने चर्च के गलत कामों पर अंकुश लगाने का काम किया है।

भाजपा सरकार बेरोकटोक आदिवासियों के धर्मांतरण में बाधा बन रही थी।

आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का अभियान रोकना पड़ा था। विदेशी फंडिंग की जांच से धर्मांतरण में जुटे मिशनरी परेशान थे। चर्च पोषित कई संस्थाएं बच्चा बेचने का काम कर रही थी। इस पर सरकार का चाबुक चला। वास्तव में इन्हीं सब कारणों के कारण ये लोग बौखलाए हुए हैं। मेघा उरांव ने कहा कि जब-जब आदिवासी हितों को प्रभावित करने का प्रयास होगा संगठन प्रखर रूप से अपनी आवाज बुलंद करेगा।

सावित्री बाई ने कांग्रेस भी छोड़ी बोलीं-प्रियंका ने आंदोलन से रोका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा, बनाएंगी नई पार्टी
- लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ी थी पूर्व सांसद ने भाजपा

लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाली पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले का यहां से भी मोहभंग हो गया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। तर्क दिया है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरक्षण और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर आंदोलन करने से रोका तो लगा कि भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है।

सावित्री बाई फुले फाइल

सावित्री बाई फुले 2014 में भाजपा के टिकट पर उप्र के बहराइच से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं। इसके बाद पार्टी से किसी मुद्दे पर विवाद के चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। दो मार्च 2019 को कांग्रेस की सदस्यता ली। गुरुवार को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया। पूर्व सांसद का कहना है कि भाजपा सरकार में आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। संविधान को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। आरक्षण के समर्थन में आंदोलन किया तो भाजपा में उन्हें हीन भावना से देखा गया। तब लगा कि भाजपा को सिर्फ कांग्रेस ही रोक सकती है, इसलिए कांग्रेस में आई। सावित्री बाई का कहना है कि करीब पंद्रह दिन पहले दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर प्रियंका वाड्रा से मुलाकात हुई। ईवीएम और आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन की बात कही तो प्रियंका ने यह कहकर मना कर दिया कि ईवीएम हमारी सरकार ही लाई थी। अब लगता है कि भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, इसलिए कांग्रेस भी छोड़ दी। बताया कि 19 जनवरी को उन्होंने लखनऊ के रविंद्रालय में नमो बुद्धाय जनसेवा समिति के बैनर तले अधिवेशन बुलाया है। उसमें ही नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर 14 अप्रैल से बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय आंदोलन शुरू किया जाएगा।

पंजाब सरकार अब अपने प्रोजेक्टों का सोशल ऑडिट करवाएगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने अब अपने प्रोजेक्टों का सोशल ऑडिट करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विजिलेंस ब्यूरो के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रोजेक्ट को अमल में लाने की प्रक्रिया में से भ्रष्टाचार खत्म करने में सहायक सिद्ध होगा।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रस्ताव के मुताबिक नागरिकों व करदाताओं की जानकारी के लिए सरकार के चल रहे या भविष्य में होने वाले कामों को दिखाते 'नागरिक सूचना बोर्ड' काम वाले स्थानों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा संबंधित विभाग द्वारा एहतियाती सतर्कता स्कीम के अंतर्गत यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी जरूरी होगी। इंजीनियरिंग कामों के अलावा गैर-इंजीनियरिंग कामों के कुछ अन्य बोर्डों को भी मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत विभिन्न विभाग शामिल किए जाएंगे। इनमें लोक निर्माण विभाग, मंडी बोर्ड, पुडा, शहरी स्थानीय संस्थाएं, पंचायती राज, पीएसआइईसी, सिंचाई (जल संसाधन विभाग), पंजाब पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन, पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड और पंजाब जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग शामिल हैं।

दीक्षा समारोह में मुस्लिम छात्रा को प्रवेश न देने की रिपोर्ट तलब

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने कुलपति से मांगा जवाब

पुडुचेरी, एएनआइ : पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के दीक्षा समारोह में एक मुस्लिम छात्रा को शामिल होने की कथित तौर पर इजाजत न दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने यूनिवर्सिटी के कुलपति से मामले की रिपोर्ट मांगी है।

आरोप है कि यूनिवर्सिटी के 27वें दीक्षा समारोह में सोमवार को रुबीहा अब्दुर्रहीम को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह के मुख्य अतिथि थे। माना जा रहा है कि उसने स्कार्फ को अलग तरीके से पहन रखा था। शायद इसीलिए उसे इजाजत नहीं दी गई होगी। बाद में रुबीहा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ अपना गोल्ड मेडल लेने से इन्कार कर दिया था।

नारायणसामी ने ट्वीट किया, 'पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के दीक्षा समारोह में रुबीहा को शामिल होने की इजाजत न दिए जाने की घटना निंदनीय है। हालांकि, मैं वहां मौजूद था, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं हुई। मतभेद लोकतंत्र का एक पहलू है। मैंने इस मामले में कुलपति से रिपोर्ट तलब की है।' सीएम ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्होंने इस मामले में पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है।

नारायणसामी ने की एलजी किरण बेदी को वापस बुलाने की मांग

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उपराज्यपाल (एलजी) किरण बेदी को वापस बुलाने की मांग की है। नारायणसामी ने बेदी पर 'निरंकुश तरीके' से काम करने और 'कैबिनेट के फैसलों को पलटने' का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मीडिया से कहा कि 23 दिसंबर को राष्ट्रपति जब पुडुचेरी दौरे पर आए थे, तब उन्होंने इससे संबंधित एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बेदी अपने अधिकारों से इतर सरकार के रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही हैं। नारायणसामी ने एलजी पर पुडुचेरी के विकास को बाधित करने का भी आरोप लगाया है।

उत्तर प्रदेश में सातवीं आर्थिक गणना शुरू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का असर आर्थिक गणना पर भी दिखाई देगा। उप्र की सातवीं आर्थिक गणना में पहली बार मोबाइल एप का इस्तेमाल किया जा रहा है। दो लाख प्रशिक्षित कर्मी साढ़े तीन माह में इस काम को पूरा करेंगे। आर्थिक गणना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि यह गणना सटीक हुई तो उप्र आर्थिक महाशक्ति बनेगा।

लोकभवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने आर्थिक गणना का शुभारंभ मोबाइल एप के माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक गणना का अपना महत्व है। इसमें वह उद्योग और संस्थाएं शामिल होती हैं, जिनका अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। सही आंकड़ों से सरकार तय कर सकती है कि कैसी आर्थिक कार्ययोजना बनाई जाए। उदाहरण दिया कि जिला प्रशासन ने सही तथ्य जुटाए तो हम प्रयागराज में ठेले-रेहड़ी वालों का पुनर्वास कर सड़कें अतिक्रमणमुक्त कर सके। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का मानक बना। उन्होंने कहा कि देश आजाद हुआ, तब उप्र में प्रति व्यक्ति आय देश के औसत के बराबर थी लेकिन, पारंपरिक उद्योगों पर ध्यान न देने से यह पिछड़ती गई और आधे पर पहुंच गई।

प्रयास

विधायक रामकुमार गौतम ने दिखाए हैं बाकी तेवर, जजपा संरक्षक को भरोसा मना लिया जाएगा नाराज विधायक को

बीच का रास्ता निकालने में जुटे दुष्यंत चौटाला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जजपा) संरक्षक दुष्यंत चौटाला अपनी ही पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम के बागी तेवरों के मद्देनजर डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। पार्टी विधायकों की शिकायत को दूर करने के लिए वह बीच का रास्ता निकालने की राह पर चल रहे हैं।

गुरुवार को चंडीगढ़ पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने पहले पार्टी नेताओं से इस मसले पर चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी विधायक रामकुमार गौतम का इस्तीफा नहीं मिला है। गौतम हमारे सबसे बुजुर्ग और सीनियर नेता हैं और वह संगठन में अपनी बात रख सकते हैं। उनकी बातों का हम बुरा नहीं मानते। दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह व अन्य वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात कर गिले-शिकवों को लेकर चर्चा करेंगे। उनकी जो भी शिकायतें हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। विधायक देवेंद्र बबली से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह की जांच की मांग कर सकते हैं। यह उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। अगर मेरे विभाग में भी भ्रष्टाचार हो रहा था तो उसे रोकना मेरी जिम्मेदारी है।

दुष्यंत चौटाला फाइल

गौतम ने रखा था भाजपा संग सरकार बनाने का प्रस्ताव : दुष्यंत

गौतम ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का एलान करते हुए भाजपा से समझौते पर सवाल उठाए थे। दुष्यंत ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रामकुमार गौतम ही लेकर आए थे। यह दावा गलत है कि उन्हें विश्वास में लिए बगैर गठबंधन हुआ है।

मंत्रिमंडल गठन के पहले ही दिन पड़ गई थी असंतोष की नींव : जजपा में असंतोष की नींव मंत्रिमंडल गठन के पहले ही दिन पड़ गई थी। शुरुआत में जजपा की ओर से सिर्फ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शपथ लेते हुए 10 विभाग अपने पास रखे थे जिसके बाद पार्टी विधायकों में अंदरूनी स्तर पर विरोध के सुर उठने लगे थे। विधायकों का दबाव बढ़ा तो दुष्यंत ने पार्टी कोटे से अनूप धानक को मंत्री बना दिया, लेकिन अभी तक पार्टी के हिस्से का एक मंत्री पद खाली है।

पांच विधानसभा चुनावों में दो जीते गौतम : पुराने भाजपाई रहे रामकुमार गौतम ने फरवरी 2000 और फरवरी 2005 में हुए नारनौंद से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2005 में वह विधायक बने। अक्टूबर 2009 में नारनौंद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अक्टूबर 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार जजपा के टिकट पर चुनाव जीत गए।

ओडिशा में कांग्रेस नेता का विवादित वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

- जिला कांग्रेस के नवरंगपुर जिला बंद के दौरान कार्यकर्ताओं को भड़काया
- कहा- पेट्रोल, डीजल रेडी रखो, इशारा मिलते ही आग लगा देना, जो होगा देखा जाएगा
- वीडियो पर बोले प्रदीप माझी गांधी नीति से न्याय नहीं मिलने से अपनानी पड़ रही है सुभाष चंद्र बोस नीति

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप माझी के विवादित बयान वाला वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इसमें माझी फोन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, 'पेट्रोल-डीजल रेडी रखो, समझ रहे हो कि नहीं, जैसे ही दिशानिर्देश मिलेगा, आग लगा देना, इसके बाद जो भी होगा, देखा जाएगा।'

इस संदर्भ में पूछे जाने पर माझी ने कहा कि हमें अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। 14 दिसंबर को नवरंगपुर जिला के कोषागुमुड़ा ब्लॉक अंतर्गत नाबालिग का दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को पूर्व सांसद माझी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस ने नवरंगपुर जिला बंद आहूत किया था। इसी दौरान पूर्व सांसद ने उक्त विवादित बयान अपने समर्थकों को दिया। बंद के दौरान नवरंगपुर के आंबेडकर चौक में कार को प्रदर्शनकारी शरारती तत्वों ने आग लगा दी थी। जिस समय कार में आग लगाई गई वह सड़क के किनारे खड़ी थी। इस घटना को कांग्रेस नेता के बयान और बंद के आह्वान से जोड़कर देखा जा रहा है।

> एक जिम्मेदार राजनेता द्वारा हिंसा करना ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए भड़काना अशोभनीय है। उनकी यह भाषा आतंकवादी की तरह लग रही है। पिछले चुनाव में मिली हार के कारण वह इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं।
>
> -रमेश माझी, सांसद, बीजू जनता दल

राज्य सरकार हमें मजबूर कर रही है

माझी से विवादित टिप्पणी के बावत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के बयान पर कोई पछतावा नहीं है। दुष्कर्म और हत्या को 13 दिन बीत गए। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही है। बीजद सरकार में मां, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। हम क्या चुप बैठ जाएं, क्या हम चूड़ी पहने हैं। माझी ने कहा कि पिछले 10 साल में 30 हजार दुष्कर्म की घटना हुई है। हमारी मां बहनें सस्ती नहीं हैं। हम अब चुप नहीं बैठेंगे। कानून हाथ में लेने के लिए राज्य सरकार हमें मजबूर कर रही है। गांधी नीति से जब न्याय नहीं मिला तब हमने सुभाष चंद्र बोस की नीति को अपनाया है।

महात्मा गांधी जी के मार्ग पर चलकर हम हताश हो गए हैं। न्याय न मिलने पर अब हम न्याय छीनकर लेंगे। शांति से न्याय नहीं मिलेगा तो अशांत होना पड़ेगा और इसके लिए जो कुछ भी घटित होगा उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे।

62.1 फीसद भारतीय सीएए के पक्ष में हैं। साथ ही 65.4 फीसद लोग चाहते हैं कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाए। आइएएनएस–सीवोटर के हालिया सर्वे में यह बात सामने आई है।

जेल नहीं होते हैं डिटेंशन सेंटर

देश में डिटेंशन सेंटर (हिरासत केंद्र) को लेकर घमासान मचा है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) नागरिकता जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर भ्रम की स्थिति के बीच अब डिटेंशन सेंटर को लेकर विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक, देश के अलग-अलग राज्यों में पहले से ही डिटेंशन सेंटर्स स्थापित हैं। यह पूरी तरह से कानूनी हैं और यह सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हैं। बेहतर स्थिति वाले ये स्थान जेल से अलग होते हैं।

ऐसे समझिए डिटेंशन सेंटर

इन हिरासत केंद्रों को होल्डिंग सेंटर या ठहराव केंद्र भी कहा जाता है। जिन विदेशी नागरिकों की नागरिकता की पहचान और पुष्टि लंबित होती है, उन्हें यहां रखा जाता है। इस दौरान संबंधित देशों से उनके प्रपत्रों का सत्यापन किया जाता है फिर उन्हें उनके देशों में भेजा जाता है। यहां उनके रहने के दौरान हर तरीके की मानवीय दशाओं और सहूलियतों का ध्यान रखा जाता है। इस आशय के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इन केंद्रों में ऐसे इंतजाम किए जाते हैं।

भारत से निष्कासन संभव

फॉरेनर्स एक्ट 1946 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक के किसी विशेष स्थान पर आने-जाने पर रोक लगा सकता है। और उस व्यक्ति को किसी एक जगह पर रोकने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) कानून 1920 किसी भी शख्स को सीधे भारत से निष्कासित कर सकता है, जो कि भारत में बिना वैध पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के साथ आया है।

राज्यों को हासिल ताकत

केंद्र सरकार की इन शक्तियों का राज्य सरकारें भी इस्तेमाल कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत राज्य सरकारें ऐसा करने में सक्षम हैं। वे भी अवैध प्रपत्रों के साथ रह रहे विदेशी पर कार्रवाई करने में सक्षम हैं। केंद्र शासित प्रशासन को अनुच्छेद 239 के अंतर्गत इन शक्तियों के इस्तेमाल का अधिकार है।

नागरिकता की पुष्टि कराने में अक्षम रहने वाले विदेशी लोगों के लिए बेंगलुरु में बनाया गया डिटेंशन केंद्र। ● फाइल फोटो

1998 से जारी हो रहे निर्देश

डिटेंशन सेंटर में रह कर निष्कासन का इंतजार कर रहे इन विदेशी नागरिकों के लिए गृह मंत्रालय ने जुलाई 1998 से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिससे विदेशी नागरिकों की व्यक्तिगत उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए और यात्रा दस्तावेजों के तैयार होते ही उन्हें उनके देश भेज दिया जाए। सूत्रों के अनुसार, इन निर्देशों को 23 नवंबर 2009, 7 मार्च 2012, 29 अप्रैल 2014, 10 सितंबर 2014 और 7 सितंबर 2018 को दोहराया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने किया निर्देशित

28 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 7 मार्च 2012 को सरकार ने इस आशय का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि जो विदेशी नागरिक अपनी सजा पूरी कर चुका थे उसे तुरंत जेल से रिहा कर और उचित स्थान पर रखा जाए। इसे डिटेंशन सेंटर या कुछ भी कहा जा सकता है। ऐसे लोगों के रखे जाने वाले स्थान पर मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी और सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2018 के अपने आदेश में 10 सितंबर 2014 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का संज्ञान लिया, जिसमें राज्य सरकारों को अवैध प्रवासियों या विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को रोकने के लिए डिटेंशन या होल्डिंग सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए थे। ये निर्देश उनके बारे में थे जो नागरिकता की पुष्टि न करा पाने के चलते जेल की सजा पूरी कर चुके थे।

किसी राज्य ने नहीं किया पालन

शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद भी किसी भी राज्य ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। कोर्ट ने असम के गोलपारा में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत डिटेंशन सेंटर की प्रगति रिपोर्ट जाननी चाही। सरकार से उम्मीद जताई कि जल्द ही वह इस केंद्र को तैयार करेगी। अगली दो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्माण स्थिति की समीक्षा की। सुप्रीम कोर्ट के 20 सितंबर 2018 के निर्देशों के तहत एक आदर्श डिटेंशन सेंटर मैन्युअल तैयार किया गया और गृह मंत्रालय द्वारा नौ जनवरी 2019 को सभी राज्यों को भेजा गया।

इसलिए अहम हैं डिटेंशन सेंटर

डिटेंशन सेंटर्स की आवश्यकता विदेशी नागरिकों की व्यक्तिगत उपलब्धता हर समय सुनिश्चित करने के लिए है। जिससे शीघ्रता से उसके निर्वासन के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार किए जा सकें। यहां जीवन काट रहे लोगों को जेल की तरह सख्त नियम-कानून के तहत नहीं रहना होता है। असम सरकार पिछले कुछ दशकों से जेल के एक हिस्से को डिटेंशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

देश में यहां हैं डिटेंशन सेंटर

सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में कई राज्यों में यह डिटेंशन सेंटर अस्तित्व में आए हैं। असम के गोलपारा, कोकराझार, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और सिलचर जिले की जेलों में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली के लामपुर में सेवा सदन और महिलाओं के लिए महिला सदन, शहजादाबाग में बांग्लादेशियों के लिए, पंजाब में अमृतसर की सेंट्रल जेल में, राजस्थान में अलवर की जेल में और पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु में भी डिटेंशन सेंटर अस्तित्व में हैं।

ये है प्रक्रिया

फॉरेनर्स नियम, 1992 और फॉरेनर्स आदेश 1948 के मुताबिक केंद्र जिले के एसपी को फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है और नागरिक प्राधिकरण का काम विदेशी नागरिकों से जुड़े ऐसे मामलों से निपटना होता है। इसके अतिरिक्त देश के 12 शहरों में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। यह नागरिक प्राधिकरण के तरह काम करते हैं। फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के नियमों के मुताबिक नागरिक प्राधिकरण विदेशी नागरिकों को रहने के स्थान और गतिविधियों को लेकर आदेश दे सकता है। ऐसे लोगों को वापस भेजने के लिए उसकी नागरिकता की पुष्टि करनी होती है और यात्रा के लिए दस्तावेज जारी करने होते हैं। इसमें काफी वक्त लगता है। हालांकि जिन लोगों के पास वैध पासपोर्ट हैं, उन्हें तुरंत ही भेज दिया जाता है। (प्रेट्र)

न्यूज गैलरी

सीएए मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय : प्रधान

भुवनेश्वर : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएए को केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया। इसको लेकर देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक गलती को मोदी सरकार ने संसद में कानून लाकर सुधारा है। इसके खिलाफ कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। प्रधान ने यह बातें गुरुवार को यहां पत्रकार सम्मेलन में कहीं। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। ऐसे में बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को सरकार ने कानून बनाकर नागरिकता देने का रास्ता साफ किया है। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में विदेशी अल्पसंख्यक आकर भारत में रह रहे हैं। वे 70 साल से शरणार्थी के तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार ने प्रयास किया है। देश की जनता ने सरकार के निर्णय को स्वीकार कर लिया है, मगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अतीत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बांग्लादेशियों को नागरिकता दे चुकी हैं। (जासं)

'कांग्रेस शासित राज्य सीएए के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट'

जबलपुर : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ सभी कांग्रेस शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। तन्खा ने कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भले ही नए कानून की अपने हिसाब से व्याख्या करके जनता को गुमराह करने की कवायद में जुटी हो, लेकिन कांग्रेस जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून (सिटीजन एक्ट) साफ-सुथरे उद्देश्य वाला था, जिसे मौजूद केंद्र सरकार ने अपने हिसाब से मोड़ दिया है। संशोधन के जरिये दुरुपयोग का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के बार-बार बदलते बयानों से यह बात साफ हो गई है कि दाल में कुछ काला है। (नईदुनिया)

समाज में नफरत फैला रही मोदी सरकार : कन्हैया

मानसा : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पंजाब के मानसा की पुरानी अनाजमंडी में गुरुवार को 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' रैली निकाली गई। इस दौरान जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार असल मुद्दों को हल करने की बजाय एक साजिश के तहत भाईचारे में नफरत पैदा कर रही है। डॉ. बीआर आंबेडकर की विचारधारा को खत्म करने की साजिश हो रही है। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डॉ. वीके कांगो ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था बुरी से प्रभावित हुई है। युवाओं को रोजगार देने का वादा भी खोखला साबित हुआ है। (जासं)

एनपीआर के वेश में एनआरसी लाना चाह रही सरकार : कांग्रेस

उठाए सवाल ▶ चिदंबरम बोले– सरकार की नीयत साफ तो करे एलान, एनआरसी से लिंक नहीं करेंगे एनपीआर

एनपीआर के प्रस्तावित फार्म में मांगी गई जानकारी को पार्टी ने बताया एनआरसी जैसा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यूं तो सफाई दी गई है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनपीआर) की प्रश्नावली अभी तय ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस सोशल मीडिया पर चल रही प्रस्तावित प्रश्नावली को आधार बनाते हुए सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने एनपीआर की प्रस्तावित प्रश्नावली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार एनपीआर के वेश में एनआरसी लागू करना चाहती है। पार्टी ने यह भी कहा है कि एनपीआर फार्म में लोगों से एनआरसी से जुड़ी जानकारी सरकार मांगेगी तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। वहीं, पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि भाजपा सरकार की ओर से मंजूर एनपीआर संप्रग सरकार से अलग ही नहीं खतरनाक भी है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए चिदंबरम ने यह भी कहा है कि यदि उसकी नीयत साफ है तो फिर वह इसका स्पष्ट एलान करे कि एनपीआर को एनआरसी से नहीं जोड़ेगी।

नई दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर प्रेसवार्ता की। एएनआइ

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने प्रेस कांफ्रेंस कर सफाई दी कि संप्रग के वक्त एनपीआर की शुरुआत हुई थी मगर इसका मकसद नागरिकता के मसले तय करना नहीं था। संप्रग ने एनपीआर में देश में रहने वाले सामान्य निवासी की बात तय की थी जिसमें देश में छह महीने से अधिक समय से रहने वाले लोगों को नाम दर्ज करने की स्पष्टता थी। इसमें नागरिकता का सवाल था ही नहीं।

माकन ने कहा कि सोशल मीडिया पर सरकार के एनपीआर के पायलट प्रोजेक्ट के फार्म की जो प्रश्नावली सामने आयी है, उसमें लोगों से माता-पिता के जन्म स्थान और तिथि मांगी गई है। साथ ही आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी मांगी गई है वह साफ तौर पर इसे एनआरसी बनाने की ओर इशारा कर रही है। संप्रग के समय हुए एनपीआर में ये सवाल नहीं थे। माकन ने कहा कि सरकार का लोगों से इस तरह की जानकारी लेना स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के नागरिकों की निजता के अधिकार के फैसले का उल्लंघन है। एनपीआर पर कांग्रेस का आधिकारिक रुख पूछे जाने पर माकन ने कहा कि सरकार ने एनआरसी से लिंक करने वाले प्रश्नों को फार्म से नहीं हटाया तो पार्टी इसका विरोध करेगी।

वीडियो को ध्यान से सुना जाए : भाजपा सरकार चिदंबरम के गृह मंत्री रहने के दौरान एनपीआर पर दिए बयान के वीडियो के सहारे कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके मद्देनजर खुद चिदंबरम ने ट्वीट के जरिये सफाई देते हुए सरकार पर जवाबी सवाल दागे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उनके बयान का वीडियो दिखा रही है तो वे खुश हैं। मगर वे स्पष्ट कहेंगे कि वीडियो को ध्यान से सुना जाए जिसमें वे साफ कह रहे हैं एनपीआर में सामान्य निवासी होने का उल्लेख कर रहे हैं न कि नागरिकता का। चिदंबरम के मुताबिक, संप्रग के एनपीआर में धर्म और जन्म स्थान से परे सभी सामान्य निवासियों को शामिल किया गया और 2011 की जनगणना को एनपीआर से मदद मिली। चिदंबरम ने साफ कहा कि संप्रग के एनपीआर में एनआरसी शामिल नहीं था जबकि भाजपा सरकार ने अभी जिस एनपीआर को मंजूरी दी है उसके संदर्भ अलग ही नहीं ज्यादा खतरनाक हैं। एनडीए सरकार का प्रस्तावित एनपीआर उसके सुनियोजित राजनीतिक एजेंडे की मंशा को दर्शाता है। चिदंबरम ने सरकार को चुनौती दी कि वास्तव में एनपीआर पर उसकी नीयत में खोट नहीं है तो वह इसकी दो टूक घोषणा करे कि इसे एनआरसी से किसी हाल में नहीं जोड़ा जाएगा।

'सीएए नहीं, सरकार की नीयत व निशाने पर आपत्ति'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस अपना मोर्चा मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद आनंद शर्मा ने सवाल उठाया है कि गृह मंत्री बताएं कि आजादी के 72 वर्ष बाद कौन भारत की नागरिकता लेने के लिए बॉर्डर पर खड़ा है। नागरिकता देने का प्रावधान पहले से होने का तर्क देते हुए कहा कि हमें आपत्ति सीएए पर नहीं, बल्कि सरकार की नीयत और निशाने पर है। उन्होंने प्रदेश में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग भी की।

गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उप्र से ही सांसद हैं। वह बुधवार को यहां आए तो उन्हें इतनी गंभीर परिस्थिति में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। सांत्वना का मरहम लगाने के बजाए उन्होंने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि भाजपा से किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए।

लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद आनंद शर्मा साथ में उप्र कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू (बाएं)। जागरण

बेरोजगार और आर्थिक संकट पर बात करने के बजाय सरकार ने एक चिंगारी फूंक दी है। धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति संविधान नहीं देता है।

शर्मा ने कहा कि देश की तमाम गरीब जनता ऐसी है, जो संपत्ति या शैक्षिक दस्तावेज नहीं दिखा सकती। उप्र में ही 38 फीसद जनता के पास जन्म के दस्तावेज नहीं हैं। प्रधानमंत्री विविधता को दिल से स्वीकार करें। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की निंदा की। कहा कि वह सांविधानिक पद पर बैठे हैं, संत भी हैं, लेकिन वोट देने वाली जनता से बदला लेना चाहते हैं। कहा कि वर्तमान हालात में 53 देशों ने अपने पर्यटकों को एडवाइजरी की है। उन्होंने भारत के पर्यटन स्थलों पर आने की बुकिंग निरस्त करा दी है।

सीएए और एनआरसी मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष : राम माधव

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ **भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बोले– प्रत्येक भारतीय के सर्वाधिकार सुरक्षित**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) के मुद्दे पर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह किसी समुदाय या धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। प्रत्येक भारतीय के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। वह कश्मीर में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों का जायजा लेने पहुंचे थे।

पत्रकारों से राम माधव ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नागरिकता संशोधन बिल पर किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। यह किसी वर्ग या धर्म के खिलाफ नहीं है। विपक्षी दल जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। लोगों को भड़काने के लिए भ्रम पैदा कर रहे हैं, वे राजनीतिक फायदों के लिए इसे अनावश्यक रूप से तूल देते हुए पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने में जुटे हैं। जम्मू-कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक व सुरक्षा परिदृश्य से जुड़े सवालों के जवाब में राम माधव ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर घाटी में हालात बेहतर हुए हैं। पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, अलगाववादी गतिविधियां बंद हो चुकी हैं। आतंकी हिंसा पर भी रोक लगी है। ऐसे में अब यहां लोग विकास और शांति चाहते हैं।

जल्द बहाली होगी इंटरनेट सेवा : कश्मीर में इंटरनेट सेवा की बहाली पर उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कई होटलों, टूर ऑपरेटरों, छात्रों व कुछ अन्य संस्थानों के लिए यह सुविधा बहाल की है। सार्वजनिक तौर पर भी इंटरनेट सेवा जल्द बहाली की उम्मीद है। यह फैसला स्थानीय प्रशासन को लेना है। वह हालात की समीक्षा के आधार पर जल्द ब्राड बैंड सेवा को चरणबद्ध तरीके से बहाल करेगा।

कुछ नेताओं को रिहा किया : राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत विभिन्न राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर किसी स्पष्ट जवाब से बचते हुए उन्होंने कहा कि हालात में सुधार पर कुछ नेताओं को रिहा किया है। कइयों को उपजेल से उनके घरों में स्थानांतरित कर नजरबंद किया है। जो नेता हिरासत में हैं या नजरबंद हैं, उनकी रिहाई का फैसला स्थानीय प्रशासन स्थिति का आकलन करने के बाद करेगा। उन्होंने कहा कश्मीर में ब्राडबैंड सेवा की बहाली और राजनीतिक बंदियों की रिहाई स्थिति का आकलन के आधार पर प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से होगी।

झारखंड में ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी : राम माधव ने झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को पूरी तरह अप्रत्याशित बताया। उन्होंने कहा कि हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। झारखंड में कहां चूक हुई, कैसे हुई और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए पार्टी के वरिष्ठजनों की बैठक में मंथन किया जाएगा।

मंगलुरु हिंसा में मारे गए लोगों के स्वजनों को पांच-पांच लाख देगी बंगाल सरकार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ गुरुवार को पांचवी बार महानगर की सड़कों पर उतरीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को आग से नहीं खेलने की सलाह दी। उन्होंने कर्नाटक के मंगलुरु में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस फायरिंग में मारे गए दो लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा रोकने संबंधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बयान का भी जिक्र किया। उन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए बंगाल सरकार की ओर से पीड़ितों के स्वजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'हमारा आंदोलन अधिकारों की रक्षा की लड़ाई के लिए हैं। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सीएए वापस नहीं ले लिया जाता।'

बगैर डरे आंदोलन करें छात्र : विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन का समर्थन करते हुए ममता ने कहा-'छात्रों को धमकी दी जा रही है। कई जगह हॉस्टल बंद करवा दिए गए हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि छात्र बिना डरे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो हम उनके अधिकारों के समर्थन में हैं।'

विरोध करने वालों का दमन कर रही भाजपा : मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जगह सीएए-एनआरसी के खिलाफ जन आंदोलन के कारण कई लोगों की जानें गई हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 19 लोग मारे गए हैं। कर्नाटक में 2 और असम में 6 लोग मारे गए। भाजपा विरोध करने वालों का दमन कर रही है। यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा-'वह कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों की संपत्ति जब्त कर भरपाई की जाएगी तो मैं भाजपा से कहना चाहूंगी कि आग से न खेलें। सार्वजनिक और निरंतर आंदोलन में संपत्तियों को जब्त कर भरपाई किया जाना अनैतिक है। कानून राज्यों के पास भी है, लेकिन यह कानून लगातार आंदोलन के लिए लागू नहीं होता। अगर आप यूपी-दिल्ली में ऐसा करेंगे तो फिर विपक्ष की सरकारें विभिन्न राज्यों में अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं।'

ममता बनर्जी फाइल

▶ **सीएए और एनआरसी के खिलाफ पांचवीं बार कोलकाता की सड़कों पर उतरीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी**

▶ **कहा, कानून वापस नहीं लिए जाने तक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा आंदोलन**

> बंगाल ही नहीं, मैं अन्य राज्यों में भी सीएए-एनआरसी का विरोध कर रहे लोगों के साथ खड़ी हूं। तृणमूल के प्रतिनिधिदल को असम जाने से रोक दिया गया था। हमारे प्रतिनिधिदल को यूपी पुलिस ने लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया। यहां उनके नेता आते हैं। जहां मन, वहां रैली करते हैं क्योंकि हम किसी को रोकने में विश्वास नहीं करते।
>
> **–ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, बंगाल**

प्राण न्योछावर कर करेंगे अधिकारों की रक्षा

तृणमूल प्रमुख ने कहा–'अगर कोई हमारा अधिकार छीनने की कोशिश करेगा तो हम प्राण न्योछावर करके भी उसकी रक्षा करने का माद्दा रखते हैं।' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर एनआरसी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों के बयान विरोधाभासी हैं। एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए ममता ने 'भाजपा छी छी... सीएए छी छी, एनआरसी नहीं चलेगा' जैसे नारे लगाए।

भाजपा का कांग्रेस व ओवैसी पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा ने नागरिकता के मुद्दे पर कांग्रेस और एआइएमआइएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से विपक्षी दलों के झांसे में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक दफा एमए जिन्ना ने उन्हें दो देशों के सिद्धांत पर गुमराह किया था, लेकिन अब कांग्रेस उन्हें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, डिटेंशन सेंटर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर बरगला रही है। ओवैसी भी कांग्रेस की बी टीम हैं। मुसलमानों को बांटने की राजनीति करने वाले इन दलों की बातों में नहीं आना चाहिए। हुसैन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता की ओर से खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस अब बांटने की राजनीति पर उतर आई है। इस मौके पर भाजपा के किसान मोर्चा प्रमुख विरेंद्र सिंह मस्त ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना की भाषा का इस्तेमाल कर रही है।

इसी तरह भाजपा प्रवक्ता के. कृष्ण सागर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को अराजकतावादी और देश की संस्थाओं का विरोधी करार दिया है। साथ ही इसकी तुलना ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुसलमीन (एआइएमआइएम) के असदुद्दीन ओवैसी से की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने एआइएमआइएम और मुस्लिम एक्शन कमेटी को खुला समर्थन दे रखा है।

सीएए के खिलाफ

असम में 28 दिसंबर को सीएए विरोधी रैली को संबोधित करेंगे, प्रियंका 28 को लखनऊ में कांग्रेस स्थापना दिवस आयोजन में करेंगी शिरकत

सूबों में कांग्रेस के विरोध को गति देंगे राहुल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देशभर में जारी विरोध आंदोलनों को कांग्रेस का पूरा समर्थन होने का संदेश देने के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी असम में 28 दिसंबर को एक रैली करेंगे। गुवाहाटी में होने वाली इस रैली के जरिये राहुल कांग्रेस के इस मुद्दे पर विरोध को दिल्ली से बाहर राज्यों में ले जाने की आधिकारिक शुरुआत करेंगे। वहीं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 28 दिसंबर को लखनऊ में कांग्रेस के स्थापना दिवस आयोजन में शरीक होंगी और उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों पर पुलिस की कथित दमनात्मक कार्रवाई का मुद्दा उठाएंगी।

असम में कांग्रेस की सीएए विरोध रैली में राहुल गांधी के शामिल होने की पुष्टि पार्टी की ओर से कर दी गई है। सीएए को विभाजनकारी बता रही कांग्रेस राजग सरकार पर इसे वापस लेने का दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शनों के जारी रहने को जरूरी मान रही है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विरोध के अलावा राज्यों में जमीनी स्तर पर इसके खिलाफ पार्टी की सक्रियता बढ़ाने का फैसला लिया गया है। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर कांग्रेस ने सीएए के खिलाफ अपने सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन का सोमवार को आयोजन किया था जिसमें सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका समेत पार्टी के सभी दिग्गज शामिल हुए थे। अब इसी रणनीति के तहत राहुल असम में सीएए विरोध रैली को संबोधित करेंगे। मालूम हो कि सीएए के खिलाफ असम में शुरुआत में काफी हिंसक विरोध हुए। अभी भी सूबे में सबसे ज्यादा मुखर आंदोलन हो रहे हैं, जिसमें वहां के सभी समुदायों के लोग शामिल हो रहे हैं। राज्य के लोग सीएए को असम समझौते के खिलाफ बताते हुए इससे अपनी भाषा और संस्कृति के लिए खतरा मान रहे हैं। असम प्रदेश कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शनों को अपना पूरा समर्थन दे रही है। असम के अलावा आने वाले दिनों में राहुल समेत कांग्रेस के शीर्ष नेता अलग-अलग राज्यों में सीएए विरोधी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं, 28 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में रहेंगी। राज्य पार्टी दफ्तर में कांग्रेस स्थापना दिवस आयोजन समारोह के जरिये वे सूबे के कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी। पार्टी ने संकेत दिया है कि इस दौरान सूबे में सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों पर पुलिस फायरिंग से लेकर सख्त दमनात्मक कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेरा जाएगा। पुलिस कार्रवाई से पीड़ित लोगों से मिलने प्रियंका और राहुल गांधी मंगलवार को मेरठ भी गए थे मगर पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी और वापस लौटा दिया था।

राहुल गांधी फाइल

अखिल गोगोई के घर पर एनआइए ने की छापेमारी

गुवाहाटी, प्रेट्र : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने गिरफ्तार आरटीआइ कार्यकर्ता और किसान नेता अखिल गोगोई के घर पर गुरुवार को छापेमारी की और एक लैपटॉप समेत कई सामान जब्त कर लिया। कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के नेता गोगोई को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब असम में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध बढ़ रहा था।

आतंकरोधी एजेंसी के अधिकारियों ने गुवाहाटी स्थित गोगोई के घर पर सुबह सात बजे छापेमारी शुरू की, जो तीन घंटे तक चली। इस दौरान गोगोई का पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, चुनाव पहचान पत्र और बैंक का पासबुक भी जब्त कर लिया। छापेमारी के बाद गोगोई की पत्नी गीताश्री तमुली ने संवाददाताओं को जब्त सामान की सूची दिखाई। इस सूची में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का निबंधन प्रमाणपत्र, एएसआइ के अधीक्षण पुरातत्वविद मिलन कुमार चौले का एक पत्र, जेल 2015, जेल डायरी 2014 का भी जिक्र था। गीताश्री ने कहा कि एनआइए के अधिकारी हमारे घर में फाइलों को देखना चाहते थे और उनमें से चुनकर कुछ फाइलें उन्होंने ले ली। मैंने उनसे जब्त फाइलों की कॉपी देने की मांग की, लेकिन उन्होंने इससे इन्कार कर दिया। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि इससे पहले जेल जाने पर क्या अखिल आतंकियों से भी मिले थे? उन्होंने केएमएसएस ऑर्किड पार्क, काजीरंगा से संबंधित कागजात भी मांगे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। केएमएसएस के अध्यक्ष राजू बोरा ने बताया कि गांधीबस्ती इलाके में स्थित संगठन के कार्यालय पर भी अधिकारियों ने छापेमारी की और नौ किताबें जब्त कर ली। इनमें चीन के नेता माओत्से तुंग की जीवनी और मार्क्सवाद शामिल हैं।

अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा : विशेष एनआइए अदालत ने गुरुवार को अखिल गोगोई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने एनआइए द्वारा 10 दिन के लिए और हिरासत की मांग ठुकरा दी। गोगोई की एनआइए हिरासत शुक्रवार को खत्म हो रही है। उनको नई दिल्ली से यहां लाया गया है। एनआइए ने उन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और सीएए का विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है।

▶ **जांच एजेंसी ने एक लैपटॉप समेत कई सामान जब्त किया**

असम के गुवाहाटी में गुरुवार को कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के नेता अखिल गोगोई को एनआइए अदालत में पेश किया गया। प्रेट्र

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने असम के सभी इलाकों में एनआरसी को नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता नियम 2003 के तहत अपडेट करने का आदेश दिया था। यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से 2015 में शुरू हुई और एनआरसी की मुख्य सूची 31 अगस्त को जारी हुई। लगभग 19 लाख लोग इस सूची में बाहर हो गए थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 27 दिसंबर 2019

न्यूज गैलरी

समर्पण व समाज प्रेम संघ के कार्यों का मूल : भागवत

हैदराबाद : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि समर्पण, कठिन परिश्रम और समाज प्रेम संघ कार्यों के विस्तार का मूल है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए स्वयंसेवकों को समर्पण के साथ संगठन के उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। आरएसएस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि संघ प्रमुख भागवत ने तेलंगाना के स्वयंसेवकों के विजय संकल्प शिविर के अंतिम दिन गुरुवार को एक बड़ी सभा को संबोधित किया। इस शिविर की शुरुआत मंगलवार को हुई थी। इसमें पूरे प्रदेश के आठ हजार से भी ज्यादा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। इससे पहले संघ के प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों ने भी स्वयंसेवकों को संबोधित किया। (प्रेट्र)

क्षेत्र के देशों के बीच दूरी बढ़ा सकता है सीएए

नई दिल्ली : दक्षिण एशिया के चौदह प्रमुख नागरिकों ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) पर चिंता जाहिर की है। नागरिकों ने आरोप लगाया है कि इसमें क्षेत्र के देशों के बीच भूराजनीतिक अलगाव पैदा होने की पूरी संभावना है। बयान में कहा गया है, 'हम भारत के पड़ोसी देशों के स्वतंत्र नागरिक हैं। भारतीय संसद द्वारा मंजूर किए गए सीएए पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं। इसके माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।' बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में बांग्लादेश के मानवाधिकार कार्यकर्ता हमीदा हुसैन, नेपाली लेखक कनक मणि दीक्षित, पाकिस्तानी परमाणु भौतिक विज्ञानी परवेज हूधहोय और बांग्लादेशी फोटो पत्रकार शाहिदुल आलम शामिल हैं। (प्रेट्र)

उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा, उपद्रवियों के घर क्यों जाऊं

बिजनौर : उप्र व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गुरुवार को विवादास्पद बयान दिया। विगत शुक्रवार को सीएए के विरोध के बहाने हुई हिंसा के दौरान घायल युवक के परिजनों से मिलने पहुंचे मंत्री ने कहा कि हरसंभव मदद दी जाएगी। कस्बे में ही गोली लगने से मारे गए दो लोगों के घर नहीं जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे उपद्रवी थे, उनके घर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। गुरुवार दोपहर पत्रकारों से बातचीत में कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर वह नहटौर में घायल ओमराज सैनी से मिलकर आए हैं। उस परिवार को हरसंभव मदद दी जाएगी। नहटौर में गोली लगने से मारे गए दो अन्य लोगों के घर नहीं जाने के सवाल पर कहा कि वे उपद्रवी थे। कहा, कुछ लोगों को लगा कि मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता न बन जाएं, इसलिए लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। (जासं)

राहुल गांधी झूठे और ओवैसी देश के दुश्मन : गिरिराज

पलटवार ▶ कहा, राहुल को पता नहीं कि 2011 में किसने डिटेंशन कैंप बनाया

बोले, भारत में पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे ओवैसी

राज्य ब्यूरो, पटना, मुजफ्फरपुर

गिरिराज सिंह। फाइल

नित्यानंद राय। फाइल

सीएए, एनसीआर और डिटेंशन सेंटर को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस यह कहे कि उसने डिटेंशन सेंटर नहीं बनवाए हैं तो वह इस्तीफा दे देंगे।

राहुल गांधी को झूठा बताते हुए गिरिराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रति समर्पित हैं और एक राहुल गांधी हैं जो झूठ बोल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि 2011 में किसने डिटेंशन कैंप बनाया था? चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो कांग्रेस कह दे कि हमने डिटेंशन सेंटर नहीं बनवाए हैं। तब मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो वह हट जाएं। राहुल गांधी बस ये बताएं कि असम में किसकी सरकार ने डिटेंशन सेंटर खोला था?

वहीं गिरिराज सिंह ने ओवैसी को भारत की आस्तीन का सांप बताया हैं। कहा कि ओवैसी जैसे नेता देश के दुश्मन हैं। यही वजह है कि जब राष्ट्रगान होता है तो वह उठकर चल देते हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी भारत को तोड़ना चाहते हैं। यही नहीं, ओवैसी भारत के लिए खतरा हैं। ये सभी लोग टुकड़े-टुकड़े गैंग हैं, जो पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चला रहे हैं।

नित्यानंद राय ने कहा, सीएए से किसी भी भारतीय का हित नहीं होगा प्रभावित : वहीं मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के हित प्रभावित नहीं होंगे। यह कानून मानवता को सुनिश्चित करने वाला है। आज जब यह सपना साकार हुआ है तो हमें इस कानून को लेकर जागरूकता के स्तर पर तो काम करना ही होगा, साथ ही विपक्ष के दुष्प्रचार से भी पर्दा हटाना होगा। कहा, हमारे यशस्वी नेतृत्व द्वारा इस कानून के रूप में ऐसा ऐतिहासिक काम किया गया है, जिसकी आवश्यकता अनेक महान नेताओं ने बताई थी।

केंद्रीय मंत्री गुरुवार को शहर के एक निजी आवासीय होटल में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार और अन्य नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएए के प्रति लोगों के बीच भ्रम पैदा कर विपक्ष (कांग्रेस) ओछी राजनीति कर सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं होगा। भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच जागरूकता फैलाएंगे।

जिंदगी रही तो आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे : मौलाना

जासं, मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सरवट मदरसे के मोहतमिम मौलाना कलीमुल्ला ने गत शुक्रवार की घटना के लिए लोगों की ओर से माफी मांगी है। मदरसे में रात को हुई शांति समिति की बैठक के दौरान मोहतमिम व प्रशासनिक अधिकारियों के संबोधन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मोहतमिम माफी मांगने के साथ ही मौजूद अधिकारियों को लोगों की ओर से आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। सीएए के विरोध में गत शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर में कई स्थानों पर हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने वाहन फूंक दिए थे। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई थी। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस सिलसिले में दो दिन पूर्व थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सरवट मदरसे में हुई बैठक में मोहतमिम मौलाना कलीमुल्ला ने कहा था कि-'वह प्रशासनिक अधिकारियों के शुक्रगुजार हैं। आगे जिंदगी रही तो ऐसी गलती नहीं होगी। कलेक्टर से कहना चाहते हैं कि गलती जिससे भी हुई है माफ कर दें। मौलाना कलीमुल्ला आगे कहते हैं कि- कलेक्टर साहब सरवट का नाम जो बदनामी में आ गया है, आगे नहीं आएगा। वायरल वीडियो में एडीएम प्रशासन अमित सिंह कहते हैं कि-वह विश्वास दिलाते हैं कि उस के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी जो विरोध का हिस्सा रहा हो, लेकिन उपद्रवी न हो।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में दंगों की नियमित सुनवाई हो : पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- दिल्ली में सीएए विरोधी दंगे में दर्ज हुई हैं आठ एफआइआर
- अब तक कुल 63 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हुए आगजनी व उपद्रव के मामले में दिल्ली पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सभी मामलों की नियमित रूप से सुनवाई करे ताकि आरोपितों को जल्द सजा मिल सके। पुलिस फास्ट ट्रैक में सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार से भी अनुरोध करेगी।

इस मामले को लेकर हुए दंगों में पुलिस ने आठ एफआइआर दर्ज की है। इनमें सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, दरियागंज, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया नगर में एक-एक तथा दयालपुर में दो मामले दर्ज हैं। अब तक 63 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जामिया व न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुए दंगों को उसी दिन जांच के लिए क्राइम ब्रांच में स्थानांतरित कर दिया गया था।

जामिया में हुए दंगे के मामले में आरोप लगा था कि पुलिसकर्मियों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रावास में घुसकर छात्राओं के साथ मारपीट व बदसलूकी की है। इसलिए उक्त दोनों मामले की विस्तृत जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। उत्तर-पूर्वी जिले में हुए दंगे के पांच मामले व दरियागंज में हुए दंगे में पुलिस पर कोई आरोप नहीं है, इसलिए उन मामले की जांच स्थानीय पुलिस ही कर रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पुलिस दंगाइयों का एक डेटा बेस भी तैयार करेगी, जिसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंपेगी।

दरियागंज उपद्रव के आरोपितों की जमानत अर्जी का विरोध

दरियागंज में हुए उपद्रव मामले में तीस हजारी कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। पुलिस ने आरोपितों की तरफ से दायर जमानत अर्जी का विरोध किया है। उसने अदालत को बताया कि गिरफ्तार 15 आरोपितों के खिलाफ कई साक्ष्य और चश्मदीद गवाह हैं। वहीं आरोपितों की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन मनमाने तरीके से 15 को ही गिरफ्तार किया। अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसला 28 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में भी पुलिस दस मामले दर्ज कर सकती है।

पाया गया कि सीलमपुर दंगे के समय पुलिस द्वारा दंगाइयों को गोली मारने और उनमें छह की मौत हो जाने के बारे में गलत संदेश सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। ऐसा करने वाले के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी।

अदनान सामी ने कहा गर्व और खुशी से यहां रह रहे हैं मुस्लिम

नई दिल्ली, एएनआइ : पाकिस्तानी सोशल मीडिया में सीएए पर बहस चला रहे यूजरों को फटकार लगाते हुए गायक अदनान सामी ने कहा है कि भारत में मुस्लिम बहुत खुश हैं और गर्व के साथ रह रहे हैं। जो सीमा के पार हैं वे नागरिकता कानून पर बहस करना छोड़ दें।

गायक ने ट्विटर हैंडल पर पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने भारत में सीएए को लेकर हो रहे प्रदर्शन में रुचि लेने वाले पाकिस्तानियों को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, 'प्रिय पाकिस्तानियों जो सीएए बहस में बिन बुलाए मेहमान की तरह खुद को शामिल किए हुए हैं। पहले यदि आप मुस्लिमों के लिए पैरवी कर रहे हैं तो पहले जो आपको छोड़ना चाहते हैं उन्हें स्वीकार करें। दूसरा यदि आप मुसलमानों के लिए इतने चिंतित हैं तो उनके लिए अपनी सीमाएं खोल दें।' उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा है, 'आपके लिए सबसे निराशाजनक यह है कि मुस्लिम यहां बहुत गर्व और खुशी से हैं।' सामी सामाजिक उथल-पुथल के मुद्दों पर मूक दर्शक नहीं रहते हैं और कभी ट्रोल में हस्तक्षेप करने से भी पीछे नहीं हटते हैं।

ड्रेसिंग रूम खराब कर देते हैं खिलाड़ी

प्रथम पृष्ठ से आगे

शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट में पसंद-नापसंद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्टीव वॉ ने एंड्रयू साइमंड्स को खिलाना जारी रखा। वह 10 साल खेले। एबी डिविलियर्स ने क्विंटन डिकॉक को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा, उसे तैयार किया और आज देखिए वह क्या कर रहा है? हमारे यहां तो ड्रेसिंग रूम में ही खिलाड़ी को खराब कर दिया जाता है। लतीफ ने कहा कि यूसुफ को बहुत तंग किया गया। वह भी अच्छा खिलाड़ी था। बता दें कि योहाना मूल रूप से ईसाई थे। बाद में अचानक उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था।

कनेरिया ने किया समर्थन : कनेरिया ने अख्तर की बात का समर्थन किया है। कनेरिया ने कहा कि अख्तर इस खेल के दिग्गज रहे हैं। उनके शब्द भी उनकी गेंदबाजी की तरह सख्त हैं। जब मैं टीम में खेल रहा था तो मेरे पास इस सब बातों पर बोलने का हौसला नहीं था, लेकिन अख्तर भाई बोले। इंजमाम उल हक, मुहम्मद यूसुफ और यूनिस खान ने भी मेरा समर्थन किया है। जिन्होंने समर्थन नहीं किया मैं उनका नाम जल्द ही खोलूंगा। 39 वर्षीय कनेरिया को 2009 में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाया गया था। तब वह डरहम के खिलाफ एसेक्स के लिए खेल रहे थे। ईसीबी ने उन पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया था। छह वर्ष तक इन्कार करते हुए आखिरकार कनेरिया ने 2018 में स्पॉट फिक्सिंग की बात कबूल ली थी।

नसीम की उम्र पर शोएब का तंज :पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह की उम्र कथित तौर पर 16 साल है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ही कई रहस्योद्घाटन कर चुका है। शोएब ने कहा कि नसीम की कमजोरियां पता नहीं कौन दूर करेगा। सफेद क्रीम लगाने से कोई 16 साल का नहीं बन जाता।

जरूरत पड़े तो गठित करें एसआइटी

डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश दिया है कि हिंसात्मक प्रदर्शनों को लेकर दर्ज हुए मुकदमों की निष्पक्ष जांच की जाए। आरोपितों की गिरफ्तारी के दौरान मारपीट या अभद्रता किसी भी स्थिति में न की जाए। जिन जिलों में हिंसा में मौतें हुई हैं, वहां एएसपी क्राइम व अन्य किसी एएसपी के नेतृत्व में गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं, दिल्ली में भी इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने की तैयारी है।

नुकसान के आकलन और नोटिस जारी करने के काम में तेजी

अब तक 327 से अधिक मुकदमे दर्ज	बिजनौर में करीब 90 .30 लाख का हुआ नुकसान, 43 को नोटिस
1113 से अधिक आरोपितों की हो चुकी है गिरफ्तारी	अमरोहा में 55 आरोपितों को नोटिस जारी किए गए
हिंसा में 288 पुलिसकर्मी हुए हैं घायल, 61 पुलिसकर्मियों को लगी है गोली	संभल में 11.66 लाख रुपये की रिकवरी के लिए 26 उपद्रवियों को नोटिस
हिंसा के दौरान अब तक 19 लोगों की हो चुकी है मौत	फीरोजाबाद में 29 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई का नोटिस
मेरठ में रिकवरी के लिए 141 लोगों को नोटिस जारी	

सोशल मीडिया पर शिकंजा
- सोशल मीडिया पर 19409 पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई
- भड़काऊ पोस्ट के मामले में 93 मुकदमे दर्ज, 124 आरोपित गिरफ्तार

दिल्ली ही नहीं, यह देश की पहली योजना

शाह ने कहा कि समेकित विकास केंद्र के तहत ईस्ट दिल्ली हब बनना शुरू हो रहा है। जहां एक साथ रिहायश, व्यावसायिक केंद्र व सामुदायिक सुविधा होगी। 30 हेक्टेयर में बनने वाले इस परिसर के बीच से मेट्रो गुजरेगी। यहां सामान्य वर्ग के लिए 4526 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2088 फ्लैट बनेंगे। इससे एक नई कार्य संस्कृति की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में 3325 सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन उनके लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने एसआइटी बनाकर दंगा करने वालों को जेल में डाला और सभी प्रभावितों को पांच-पांच लाख रुपये दिए।

प्रदर्शन के दौरान घायल फीरोजाबाद के दो लोगों की मौत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के फीरोजाबाद में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ गत दिनों हुए प्रदर्शन के दौरान घायल दो लोगों की मौत हो गई। मुहम्मद शफीक (40) ने गुरुवार को सफदरजंग अस्पताल में और मुहम्मद हारून (30) ने एम्स ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य घायल मुकीम की भी 23 दिसंबर को अस्पताल में मौत हो गई थी। शफीक व मुकीम को 20 दिसंबर को सफदरजंग अस्पताल में लाया गया था। अस्पताल में संदेहास्पद बुलेट इंजरी मानकर इलाज किया जा रहा था। वहीं, हारून को बुधवार को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। ट्रॉमा सेंटर प्रशासन का कहना है कि उसके गले में गोली लगी थी। सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों मामलों में अस्पताल प्रशासन ने इस सूचना से इन्कार किया है कि ये प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे। वहीं, दिल्ली में सीएए के विरोध में कुछ संगठनों के लोगों ने यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। धारा 144 लागू होने के कारण पुलिस ने 213 लोगों को हिरासत में ले लिया।

ग्वालियर में विवि के प्रश्न-पत्र में क्रांतिकारियों को बताया आतंकी

नईदुनिया, ग्वालियर

- विद्यार्थियों ने किया हंगामा, बोले-हमारे आदर्शों की छवि धूमिल करने का प्रयास पेपर बनाने वाले को हटाएं

मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय (जेयू) में गुरुवार को राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में बड़ी चूक सामने आई है। क्रांतिकारियों के साथ आतंकवादी शब्द लिखा पेपर विद्यार्थियों को दिया गया। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने के लिए कम उम्र में कई क्रांतिकारी शहीद हुए थे, ये हमारे आदर्श हैं, लेकिन जेयू के प्रश्न पत्र में उनके सामने आतंकवादी शब्द लिखकर हमारे आदर्शों की छवि धूमिल करने का काम किया है। विवि के उप-कुलसचिव राजीव मिश्रा ने कहा कि पेपर बनाने वाले को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। कार्रवाई भी की जाएगी।

प्रश्न पत्र में यह पूछा था: जेयू के एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 'भारतीय आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत' के प्रश्न क्रमांक-4 में पूछा गया- 'क्रांतिकारी आतंकवादियों के कार्यकलाप का वर्णन कीजिए। उग्रवादी व क्रांतिकारी आतंकवादियों में क्या अंतर है।'

> प्रश्नपत्र बनाने वाले को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दस दिन के अंदर कार्रवाई भी की जाएगी।
>
> -राजीव मिश्रा, उप-कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

पर्चा पढ़कर भड़क उठे विद्यार्थी : पर्चा पढ़ने के बाद विद्यार्थी भड़क गए। छात्र संगठन डीएसओ के बैनर तले जेयू में प्रदर्शन करने पहुंचे। उनका कहना था कि हम लोग क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान तक गवां दी, लेकिन प्रश्नपत्र में उनका अपमान किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को भ्रमित भी किया गया है। इससे युवाओं में गलत संदेश जाएगा, इसलिए क्रांतिकारियों के सामने से आतंकवादी शब्द हटाया जाए। क्रांतिकारियों की जयंती व शहादत दिवस पर कॉलेज व स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। जिस भी टीचर ने यह पेपर बनाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

डीजीपी का आदेश- आतंकियों और उनके आकाओं को ढूंढ़-ढूंढ़ कर मारो

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- घाटी में आतंकरोधी अभियानों में तेजी लाने के दिए निर्देश
- राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी तत्वों से सख्ती से निपटा जाए

दिलबाग सिंह। फाइल

जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने घाटी में सक्रिय आतंकियों के सफाए के लिए आतंकरोधी अभियानों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं को ढूंढ़-ढूंढ़ कर मारो।

डीजीपी ने कहा कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों, राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति में आम नागरिकों के जानमाल और सम्मान की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाए। दिलबाग सिंह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों को हटाए जाने से उपजी स्थिति के बीच वादी के समग्र सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया।

बैठक में कश्मीर की मौजूदा कानून व्यवस्था और आतंकरोधी अभियानों पर चर्चा के दौरान डीजीपी ने कहा कि कानून सर्वोपरि है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आतंकी सरगनाओं और सीमा पार बैठे उनके आकाओं की साजिश को नाकाम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बेशक जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ हम सफल रहे हैं, लेकिन आतंकियों के खिलाफ हमें अपने अभियान जारी रखने की जरूरत है। आतंकियों के समूल नाश और जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति की बहाली के लिए प्रभावशाली रणनीति पर काम करने की जरूरत है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की ट्रेनिंग में भी व्यापक सुधार किया गया है। यह प्रक्रिया लगातार जारी है।

पुलिस महानिदेशक ने कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में जन सहयोग की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारी इस बात को सुनिश्चित बनाएं कि नागरिकों को कोई असुविधा न हो। सुरक्षा, शांति और विश्वास का माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस को कम्यूनिटी आधारित कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

बैठक में एडीजीपी सीआइडी डॉ. बी श्रीनिवास, आइजीपी कश्मीर एसपी पाणि, डीआइजी सेंट्रल कश्मीर रेंज वीके बिरदी, डीआइजी उत्तरी कश्मीर रेंज सुलेमान चौधरी, सभी जिला एसएसपी, एसएसपी एसबीके, एससपी सीआइके, एसपी ऑपरेशन श्रीनगर व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

उप्र के पीएफ घोटाले में ईडी ने दर्ज किया मनी लांड्रिंग का केस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- जल्द कई आरोपितों पर शिकंजा कसने की तैयारी, डिप्टी डायरेक्टर ने लखनऊ आकर जुटाए थे दस्तावेज

उप्र में हुए पीएफ घोटाले के आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्यालय ने पीएफ घोटाले में मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज कर लिया है। जल्द ही इस घोटाले में गिरफ्तार पावर कारपोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी मिश्र, निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी व सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता सहित 14 आरोपितों पर ईडी का भी शिकंजा कसेगा।

पीएफ घोटाले में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच में कालेधन को सफेद किए जाने व फर्जी ब्रोकर फर्मों के जरिए करोड़ों के कमीशन को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए जाने के तथ्य सामने आए थे। इसके बाद ही ईओडब्ल्यू ने ईडी से संपर्क कर मनी लांड्रिंग के तहत भी जांच किए जाने की सिफारिश की थी। मंगलवार को ईडी के दिल्ली स्थित मुख्यालय की स्पेशल इंवेस्टीगेशन यूनिट के डिप्टी डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने लखनऊ आकर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से जांच से जुड़े कई अहम दस्तावेज लिए थे। ब्रोकर फर्मों व बैंक खातों का ब्योरा जुटाने के बाद ईडी ने पीएफ घोटाले में केस दर्ज कर लिया है। ईडी निजी कंपनी डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) की जांच पहले से कर रही है। विजिलेंस भी आरोपित तत्कालीन एमडी एपी मिश्र, निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी व सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है।

ईओडब्ल्यू ने पीएफ घोटाले में अब तक 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन चार्टर्ड अकाउटेंट (सीए) व डीएचएफएल का एक पूर्व कर्मचारी भी शामिल है। ईओडब्ल्यू की जांच में सीए के जरिए कई फर्जी ब्रोकर फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराकर उनमें कमीशन के करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए जाने के तथ्य भी सामने आ चुके हैं। ब्रोकर फर्मों को दी गई कमीशन की रकम को अलग-अलग कई खातों में ट्रांसफर किया गया था।

नया सवेरा...

पंजाब के युवक की कहानी, 20 साल से बंद कमरे में कर रहा था मानसिक चुनौती का सामना, चाचा ने बाहर निकाला और ले जाने लगे अपनी कैंटीन पर

स्वस्थ समाज

बीस साल की 'कैद' से निकल अब जिंदगी बुन रहा 21 साल का अरविंद

नितिन धीमान, अमृतसर

पंजाब के अमृतसर में चाचा रमेश की दुकान संभालता अरविंद। जागरण

यह कहानी मानसिक चुनौती का सामना करने वाले एक बहादुर बच्चे की है। जिसे निराश स्वजनों ने बीते बीस साल से कमरे में कैद कर रखा था। उसके चाचा ने साहस किया और बंधन खोला तो अरविंद ने चुनौती को धता बता जिंदगी जीत ली।

सालभर पहले की ही बात है, जब अमृतसर निवासी 21 वर्षीय अरविंद ने 20 वर्ष बाद बाहर की दुनिया देखी। इतने वर्षों तक वह घर में ही दुबका रहा। बाहर की दुनिया से उसे डर लगता था। घर में कोई अपरिचित आ जाए तो कांपने लगता था। उसे इंसानों से भी डर लगता था। घर के कमरे की चारदीवारी उसे अच्छी लगती। वह इन दीवारों से बातें कर जीवन व्यतीत कर रहा था। आज उसकी दुनिया बदल गई है। वह चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज के साथ जुड़ गया है।

दरअसल, अरविंद बचपन से मानसिक रूप से कमजोर रहा। बचपन में ही उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। परिवार वालों ने कई मनोचिकित्सकों को दिखाया। दवाएं चलती रहीं, पर अरविंद की सुध-बुध लौट न सकी। वह अकेला ही कमरे में खुद को बंद कर लेता और चिल्लाने लगता। उसकी चीख-पुकार सुनकर पड़ोस के लोग उसकी हालत पर तरस खाते और ईश्वर से प्रार्थना करते कि उसे ठीक कर दे। अरविंद के माता-पिता और पूरा परिवार उसके ठीक होने की कामनाएं करता रहा। मां मंदिर में माथा टेकती तो पिता चिकित्सकीय उपचार करवाकर थक गए।

> आम तौर पर मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को इसी अवस्था में जीवनयापन करना पड़ता है। अरविंद को वर्षों बाद घर से बाहर लाया गया। व्यवसाय से जोड़कर एक जिम्मेदारी सौंपी गई। इसका निर्वाह करने के लिए उसने खुद को तैयार किया। फिर धीरे-धीरे वह इसी काम में तल्लीन हो गया। उसका उपचार भी साथ-साथ चला। दोनों से बात बन गई। उसे मानसिक बल मिला। उसका ठीक होना सुखद संकेत है कि ऐसे प्रयास से अन्य को भी लाभ मिल सकता है।
>
> -डॉ. संदीप अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर, पीडिएट्रिक विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर

अरविंद के चाचा रमेश शर्मा एक दिन उसे घर से बाहर निकाल लाए। वह डरा-सहमा सा उनका हाथ पकड़कर बाहर निकल तो गया, पर जोर-जोर से चिल्लाकर घर जाने की जिद करने लगा। रमेश ने बड़ी सूझबूझ, धैर्य और सावधानी के साथ काम किया। उसे सिविल अस्पताल ले गए। रमेश के विश्वास और सहयोग ने कमाल दिखाया। सिविल अस्पताल में कैंटीन चलाने वाले रमेश उसे अपने साथ कैंटीन तक ले जाने लगे। धीरे-धीरे अरविंद उनकी बात मानने लग गया। उसे वह कैश काउंटर पर बिठाने लगे। एक दिन बोले, बेटा आज से यह कैंटीन तुम्हारी है। तुम इसके मालिक हो। ग्राहकों को सामान दो और सारा हिसाब खुद देखो...। मानसिक रूप से कमजोर अरविंद के लिए यह सब कर पाना पहाड़ चढ़ने जैसा था, पर चाचा ने अपनी निगरानी में उससे यह काम शुरू करवाया।

यह अविश्वसनीय था कि अरविंद ने एक महीने में ही न केवल सारा काम समझ लिया, बल्कि ग्राहकों से किस तरह बातचीत करनी है यह भी जान गया। उसकी मानसिक दशा में भी तेजी से सुधार हुआ। अब वह कैंटीन का सामान भी खुद ही बाजार से खरीद ले आता है।

मजीठा रोड निवासी अरविंद के चाचा रमेश शर्मा बताते हैं कि एक वर्ष पूर्व जब वह अरविंद को बंद कमरे से बाहर निकाल लाए थे, तो यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी वह ठीक हो जाएगा। कहते हैं, आज पूरा परिवार बेहद खुश है। अरविंद अब सुबह दस बजे ऑटो पर बैठ कर घर से कैंटीन अकेला ही चला आता है। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। दस बजे से लेकर रात आठ बजे तक कैंटीन का सारा कामकाज संभालता है। अरविंद का मनोचिकित्सकीय उपचार भी जारी है, लेकिन यह भी सच है कि अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। बीस वर्षों तक वह कमरे में बंद रहा। किसी से बात नहीं करता, पर अब बोलचाल, रहन-सहन में भारी बदलाव आया है। उसके पिता वेदप्रकाश व मां विवेक रानी को खुशी है कि बेटा ठीक हो गया है। अब वह कमाने भी लगा है।

2 लाख रुपये देगी मध्य प्रदेश सरकार राज्य की दिव्यांग युवती से शादी करने पर। मप्र सामाजिक न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है।

साढ़े 18 साल की अरदास, डेढ़ महीने बाद हुए दर्शन

महिंदर सिंह अर्लीभन्न, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर): गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच रास्ता खोलने की पिछले साढ़े 18 साल तक अरदास करने वाली श्री करतारपुर रावी दर्शन अभिलाषी संस्था संस्था के सदस्य गुरुवार को गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए गए। संस्था के सदस्य हर अमावस पर सीमा पर खड़े होकर रास्ता खुलने की अरदास करते थे। अब तक वह 226 बार अरदास कर चुके हैं। डेरा बाबा नानक में कॉरिडोर खुलने के डेढ़ महीने के बाद संस्था के सदस्यों को श्री करतारपुर साहिब के दर्शन का मौका मिला है। गुरुवार को कॉरिडोर के रास्ते 1500 श्रद्धालु पाकिस्तान गए। इस जत्थे में पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह वडाला के पुत्र व नकोदर के विधायक गुरप्रताप सिंह वडाला और संस्था के महासचिव गुरिंदर सिंह बाजवा भी शामिल थे। कुलदीप सिंह वडाला ने 14 अप्रैल 2001 को श्री करतारपुर रावी अभिलाषी संस्था का गठन किया था। संस्था के सदस्य लगातार साढ़े 18 साल तक कॉरिडोर खोलने की अरदास करते रहे हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को कई बार इस संबंध में मांग पत्र भी दिए गए। 9 नवंबर को कॉरिडोर खुलने पर रवाना हुए पहले जत्थे में संस्था का एक भी पदाधिकारी शामिल नहीं था। विधायक गुरप्रताप सिंह वडाला का कहना है कि कई ऐसे लोग भी हैं, जो पासपोर्ट बनवाने में असमर्थ हैं। केंद्र सरकार पासपोर्ट की शर्त खत्म करे।

कांप रहा उत्तर भारत, राजस्थान में -3 डिग्री तापमान

ठंड से आफत ▶ दिल्ली में सामान्य से दो डिग्री कम 5 .8 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान

श्रीनगर से ज्यादा ठंडे रहे हरियाणा और पंजाब के कई शहर

जेएनएन, नई दिल्ली

भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान ठंड से कांप रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। सीकर में बीती रात तापमान माइनस 3 डिग्री पहुंच गया। वहीं, पिलानी में 0.5 डिग्री एवं चूरू में 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी और बर्फीली हवाओं का असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मप्र में भी ठंड का कहर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ठंड के चलते हरियाणा में एक और जम्मू में दो लोगों की मौत हो गई है।

दिल्ली को नहीं मिली शीतलहर से राहत : कड़ाके की ठंड से दिल्ली को गुरुवार भी राहत नहीं मिली। ऐसे में अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 7 डिग्री कम 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 75 से 100 फीसद रहा। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को भी ठिठुरन भरी ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं।

कश्मीर में जम गई डल झील : कश्मीर में डल झील समेत कई जलस्रोतों में पानी बर्फ की चादर में बदलता जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर के दिन के तापमान में सिर्फ दो डिगी सेल्सियस का अंतर है। जम्मू में दिन का तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस जबकि श्रीनगर का 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं, लेह गुरुवार को सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान माइनस 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहलगाम का न्यूनतम तापमान माइनस 12.7 और गुलमर्ग का माइनस 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड में भी आठ शहरों में न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकार्ड किया गया। वहीं, चमोली के जोशीमठ व कुमाऊं के मुक्तेश्वर में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुरुवार को ठंड के बीच आग तापते लोग। एएनआइ

शीतलहर की चपेट में पूरा हरियाणा

पहाड़ों में बर्फबारी के कारण पूरा हरियाणा शीत लहर की चपेट में हैं। ऐसे में गुरुवार को कुरुक्षेत्र का दिन का तापमान श्रीनगर के बराबर रहा। चंडीगढ़ व कुरुक्षेत्र का अधिकतम तापमान क्रमश: 8 .8 डिग्री और 9 डिग्री रहा, जबकि श्रीनगर में यह 8 .9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, पंजाब में अमृतसर, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब व कपूरथला में भी दिन का पारा गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इन जिलों में दिन के समय श्रीनगर, शिमला व मनाली से अधिक ठंड रही। वहीं, बठिंडा में सबसे कम चार डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

पिथौरागढ़ के रिलकोट में फंसे सात पोर्टर्स बर्फ पर चलकर खोल्ता पहुंचे

जासं, पिथौरागढ़: 14 दिनों से आइटीबीपी की रिलकोट चौकी में फंसे सात पोर्टर्स अपने जोखिम पर निकल कर चल दिए। यह लोग 24 किलोमीटर बर्फ पर चलकर खोल्ता गांव पहुंचे हैं। रिलकोट में अभी आठ आइटीबीपी जवान फंसे हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा। आइटीबीपी की 14वीं वाहिनी के सेनानी अशोक कुमार ने बताया कि गुरुवार को रिलकोट में फंसे सात पोर्टर्स अपने जोखिम पर पैदल चलकर शाम छह बजे खोल्ता पहुंच चुके हैं। सभी पोर्टर्स सुरक्षित और सकुशल हैं। शुक्रवार को पोर्टर्स मुनस्यारी पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि मार्ग पर कई फीट बर्फ है, इसके बाद भी पोर्टर्स अपने रिस्क पर आए हैं। उन्होंने बताया कि रिलकोट चौकी से जवानों को दो-तीन दिन से हेलीकॉप्टर से मुनस्यारी या पिथौरागढ़ लाया जाएगा। रिलकोट में फंसे जवानो के पास हथियार और सामान हैं। हथियार और सामान होने से जवान पैदल नहीं आ सकते हैं। गौरतलब है कि 12 और 13 दिसंबर को उच्च हिमालय में भारी हिमपात के चलते चौकी शिफ्ट होने के दौरान आठ जवान और सात पोर्टर्स रिलकोट और 19 आइटीबीपी जवान छह पोर्टर्स बगड़ियार चौकियों में ही फंस गए थे।

छत्तीसगढ़ में पांच नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

नईदुनिया, दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में पोटाली कैंप खुलने का सकारात्मक पहलु सामने आने लगा है। गुरुवार को इलाके के नीलावाया गांव के पांच नक्सली समर्पण करने एसपी कार्यालय पहुंचे। इनमें एक-एक लाख रुपये के दो इनामी भी हैं, जबकि तीन अन्य संघम और जनमिलिशिया सदस्य हैं। नीलावाया वही गांव है, जहां साल भर पहले नक्सली हमले में तीन जवान शहीद हुए थे और डीडी न्यूज के कैमरामैन की मौत हो गई थी। समर्पित नक्सलियों ने गांव के विकास में पुलिस का साथ देने और नक्सलियों को मार भगाने की बात कही है।

एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव और एएसपी सूरज सिंह परिहार ने गुरुवार बताया कि पोटाली पुलिस कैंप में पहुंचकर ग्रामीणों ने समर्पण की बात कही। इसके बाद उन्हें अरनपुर थानेदार और कैंप प्रभारी एसपी के पास लेकर पहुंचे। इनमें मड़कम देवा डीएकेएमएस (दंडकारण्य किसान मजदूर संगठन) का अध्यक्ष और सोना हेमला ग्राम कमेटी का अध्यक्ष है।

दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था, जबकि समर्पित नक्सली मड़कम मासा और सुक्का मंडावी जनमिलिशिया सदस्य तथा धुरवा सोरी संघम सदस्य है। समर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को शासन की नीतियों के तहत दस-दस हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक सौंपा गया।

न्यूज गैलरी

ट्विटर पर प्रशंसकों ने धर्मेंद्र प्रधान को सराहा

नई दिल्ली: पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के ट्वीट पर सख्त जवाब के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जमकर तारीफ हो रही है। ट्विटर पर प्रशंसक उनके जवाब की सराहना कर रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारी ने ट्वीट किया था, 'पाकिस्तान और दुनियाभर के ईसाइयों को क्रिसमस की बधाई। विशेषरूप से ओडिशा और हिंदुत्व के जुनूनी माहौल में रह रहे ईसाइयों को बधाई।' इस ट्वीट पर धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, 'यह बात ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो खुद धार्मिक और वैचारिक अल्पसंख्यकों के नरसंहार की धुरी पर बैठा है।' प्रधान के इस ट्वीट को प्रशंसकों की जमकर सराहना मिली। लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की। एक यूजर ने लिखा, 'उन्होंने अपने घर में सभी ईसाइयों को मार डाला है और अब पड़ोस के ईसाइयों की चिंता कर रहे हैं।' (आइएएनएस)

छग में बर्ड फ्लू का खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ में यकायक हजारों चूजों (मुर्गी के बच्चों) की मौत के बाद बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। जिले में कहीं भी पक्षियों की अस्वाभाविक मौत पर तुरंत पशु अस्पताल में सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। पशुधन सेवाएं विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉ. केके ध्रुव ने बताया कि दो दिन पहले जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के शासकीय पोल्ट्री फार्म में अचानक पांच हजार चूजों की मौत हो गई थी। इसके बाद शासकीय फार्म के सभी 12 हजार चूजों समेत आसपास के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में संचालित निजी पोल्ट्री फार्मों के चूजों को भी डिस्पोज कर दिया गया है। विशेष टीम गठित की गई है। (नईदुनिया)

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की कोठी अब तनेजा परिवार की

पंचकूला : हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल के कोटे से प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को आवंटित कोठी गुरुवार को तनेजा परिवार की हो गई। माधुरी के पति डॉ. श्रीराम माधव नैने ने क्लीयर ट्रिप डॉटकॉम के संस्थापक सदस्य अमित तनेजा, भूपिंद्र तनेजा और मनी तनेजा को इस रजिस्ट्री कर दी। पंचकूला तहसील कार्यालय में यह औपचारिकता पूरी की गई। वर्ष 1996 में भजनलाल ने पंचकूला के मनसा देवी कांप्लेक्स के सेक्टर-4 में कोठी (संख्या-310) माधुरी को उस समय दी थी, जब वह चंडीगढ़ आई थीं। (जासं)

रांची में आरएसएस के प्रशिक्षण वर्ग पर फेंका पेट्रोल बम

जागरण संवाददाता, रांची : रांची स्थित सिकिदरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चल रहे रांची जिला प्राथमिक शिक्षा वर्ग में गुरुवार की रात अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम से हमला किया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पेट्रोल बम से लगाए गए प्राथमिक वर्ग के बैनर को जलाने का प्रयास किया गया। डीएसपी चंद्रशेखर आजाद मामले की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने पेट्रोल बम जब्त कर लिया है। सिकिदिरी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

ओरमांझी प्रखंड के सांडी गांव स्थित मोतीराज देवी बीएड कॉलेज में 23 से 31 दिसंबर तक नौ दिवसीय आरएसएस का प्राथमिक शिक्षक वर्ग प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें रांची के विभिन्न प्रखंडों से 138 स्वयंसेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। सभी स्वयंसेवक बीएड कॉलेज में ठहरे हैं। स्वयंसेवक दिन में कॉलेज की बगल की जमीन में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी। छानबीन में जिस जमीन में आरएसएस का वर्ग चल रहा है,उसके मालिक ने बताया की मर्जी से ही प्रशिक्षण चल रहा है।

ब्रजेश ठाकुर की संस्था पर 8 .32 करोड़ का आयकर बकाया, नोटिस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

- मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा प्रकरण
- सेवा संकल्प व विकास समिति ही करती थी बालिका गृह का संचालन

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा प्रकरण में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प व विकास समिति पर आयकर विभाग का 8.32 करोड़ से अधिक बकाया है। इसे लेकर विभाग ने नोटिस भेजा है। यही संस्था बालिका गृह का संचालन करती थी। हालांकि ब्रजेश ठाकुर ने इस संस्था से किसी तरह का संबंध होने से बार-बार इन्कार किया है। संस्था को आयकर विभाग से मिली छूट को वापस लिए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। छह साल की आय व उसके बदले आयकर निर्धारण के बाद विभाग ने उसे नोटिस भेजा है। इसमें टैक्स देने के लिए एक माह की मोहलत दी गई है। इस मोहलत में अगर उसने टैक्स की राशि जमा नहीं की तो उसके बैंक खाता से इसे अटैच कर दिया जाएगा।

छह साल की आय पर टैक्स का निर्धारण : आयकर अधिकारी पवन कुमार की ओर से भेजे गए नोटिस में 2012 से 2018 तक की आय की गणना व टैक्स का निर्धारण किया गया है।

संस्था को मिली हुई थी आयकर से छूट

सेवा संकल्प व विकास समिति को आयकर की धारा 12 एए के तहत आयकर से पूरी तरह छूट मिली हुई थी। बालिका गृह मामला सामने आने पर सरकार ने यह छूट वापस ले ली। इसके बाद आयकर विभाग ने आय व आयकर की गणना की गई।

दो बार लगा जुर्माना : आयकर विभाग की ओर से सुनवाई के दौरान ब्रजेश ठाकुर की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उसकी ओर से कोई कागजात भी पेश नहीं किया गया। विभाग की ओर से दो बार दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन इसके बाद भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

पुल निर्माण प्रशिक्षण के दौरान हादसा, दो जवानों की मौत

पुणे, प्रेट्र: कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (सीएमई) में पुल निर्माण प्रशिक्षण के दौरान हादसा हो गया। गुरुवार को दोपहर बाद हुए इस हादसे में दो जवानों की मौत हो गई, जबकि पांच घायल हो गए। इस मामले में कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश दिए गए हैं।

सेना के आधिकारिक बयान के अनुसार, पुल निर्माण प्रशिक्षण के दौरान एक सपोर्ट टावर ढह गया। इसकी चपेट में छह-सात जवान आ गए। सभी घायलों को सैन्य अस्पताल किर्की में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल लांस हवलदार संजीवन पीके और नायक बीके वाघमोडे की मौत हो गई। बयान में बताया गया कि हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।

दिवंगत जवानों के परिजनों को हादसे के बारे में बता दिया गया है। दुर्गम क्षेत्रों में सेना के जवान मोबाइल पुलों का निर्माण व उनका इस्तेमाल करते हैं। यह हादसा तब हुआ जब जवानों की एक यूनिट पुल निर्माण का प्रशिक्षण ले रही थी। सीएमई भारतीय सेना के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने वाला प्रतिष्ठित संस्थान है।

दिल का दौरा पड़ा तो इंदौर में कराई इमरजेंसी लैंडिंग पर नहीं बची जान

नईदुनिया, इंदौर

एक निजी एयर लाइंस की कोलकाता से अहमदाबाद जा रही फ्लाइट में सवार एक यात्री को बुधवार देर रात दिल का दौरा पड़ गया। इस पर विमान को इंदौर के देवी अहिल्या बाई होल्कर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतारा गया। यात्री को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर वहां से सरकारी एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान यात्री की मौत हो गई।

इंदौर विमानतल प्रबंधन के अनुसार स्पाइस जेट की एसजी 406 उड़ान में सवार बैठे यात्री जयविजय वधु (67) को सीने में दर्द उठा था। उनके साथ जा रहे परिजन ने तत्काल एयर होस्टेस को सूचना दी। एयर होस्टेस ने रात 12.15 बजे पायलट को बताया। पायलट ने तुरंत इंदौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। एटीसी की मंजूरी मिलते ही विमान को देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय विमानतल पर उतारा गया। इस बीच मेडिकल इमरजेंसी की सूचना पाकर विमानतल स्टाफ तैयार था।

रात 2.10 पर रवाना हुआ विमान

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान को पौने दो घंटे तक विमानतल पर रहना पड़ा, क्योंकि अहमदाबाद से विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। रात दो बजे अहमदाबाद विमानतल से हरी झंडी मिलते ही विमान ने रात दो बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरी।

रात करीब 12 बजकर 31 मिनट पर विमान ने लैंडिंग की। एयरलाइंस और विमानतल स्टाफ ने यात्री को एंबुलेंस से एयरपोर्ट के समीप स्थित बांठिया हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां ड्यूटी डॉक्टरों ने यात्री की बिगड़ती हालत को देखकर दूसरे बड़े अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी। इसके बाद यात्री के परिजन ने बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने पर सहमति दी। लगभग 40 मिनट पर जयविजय को लेकर एंबुलेंस सरकारी अस्पताल एमवाय पहुंची। मगर थोड़ी देर बाद ही यात्री की मौत हो गई। यात्री के परिजन की मानें तो वे कोलकाता में अपने रिश्तेदार के घर गए थे।

मध्य प्रदेश में 16 साल बाद भी तय नहीं हो पाया 'राम वन गमन पथ'

राजीव सोनी, भोपाल

- भगवान राम वनवास के दौरान जहां से निकले थे वे स्थान नहीं हुए चिह्नित
- भाजपा के 15 साल पूरे होने के बाद कांग्रेस ने भी एक साल में कुछ नहीं किया

'राम वन गमन पथ' को भव्य स्वरूप में बनाने की योजना है। 'थीम पार्क' और कार्ययोजना का निर्माण अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने योजना का प्रेजेंटेशन किया जाना है। उनकी हरी झंडी मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा।

-पीसी शर्मा, आध्यात्म एवं जनसंपर्क मंत्री

त्रेता युग में भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान मौजूदा मध्य प्रदेश के जिन-जिन रास्तों से होकर गुजरे थे, राज्य सरकार पिछले 16 सालों में उन्हें खोज कर चिह्नित करने में विफल रही है। 15 साल तक प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, लेकिन वह भी 'राम वन गमन पथ' को तैयार नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कांग्रेस ने भी अपने वचन-पत्र में इसका रास्ता खोजने का एलान किया था। मौजूदा कांग्रेस सरकार भी अपनी पहली वर्षगांठ मना चुकी है, पर अब तक इसको लेकर कार्ययोजना तक नहीं बना सकी।

2004 में आया था पहला प्रस्ताव: मप्र में सबसे पहले वर्ष 2004 में सरकार के समक्ष 'राम वन गमन पथ' योजना का प्रस्ताव आया था, उसके तीन साल बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम पथ खोजने की घोषणा की थी। लेकिन, उनके पूरे कार्यकाल के दौरान योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया। मौजूदा कांग्रेस सरकार में भी विचार-विमर्श की ही कवायद चल रही है।

आध्यात्म विभाग को सौंपा जिम्मा : वनवास के दौरान भगवान राम मप्र में जहां रुके थे, ऐसे स्थानों की संख्या करीब एक दर्जन बताई गई है। उन्हें धार्मिक पर्यटन के लिहाज से विकसित किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। सरकार ने यह काम आध्यात्म विभाग को सौंपा है। रामचरित मानस में वर्णित स्थानों को व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिए वास्तुविदों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने को कहा गया है। इसमें औद्योगिक घरानों की दिलचस्पी तलाशी जा रही है। वर्ष 2008 में संस्कृति विभाग ने सभी क्षेत्रों (इतिहास, भूगोल, संस्कृत और धर्म-दर्शन शास्त्र) के विद्वानों की समिति बनाकर 'राम वन गमन पथ' योजना पर शोध भी कराया, अब उस रिपोर्ट की धूल झाड़ी जा रही है।

मप्र के छह जिलों व मौजूदा छत्तीसगढ़ होते हुए गए थे रामेश्वरम् : पौराणिक मान्यता है कि हजारों साल पहले त्रेता युग में 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ मौजूदा मप्र में सतना जिले के चित्रकूट से दाखिल होकर अमरकंटक और छत्तीसगढ़ होते हुए रामेश्वरम् की ओर रवाना हो गए थे। इस दौरान वे सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर, शहडोल और अनूपपुर जिलों की सीमा से निकले थे। चित्रकूट परिक्रमा मार्ग पर पीली कोठी ट्रस्ट के स्वामी डॉ. दिव्यानंद और प्रभुतानंद कहते हैं कि चुनाव के दौरान 'राम पथ' की खूब चर्चा रही।

हमले की धमकी के बाद सुरक्षा की अग्निपरीक्षा से गुजर रही रामनगरी

जागरण संवाददाता, अयोध्या

- आतंकी हमले की धमकी के बाद और कसा सुरक्षा घेरा
- वाहन चालकों को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य

सुप्रीम फैसले के बाद रौ में लौट रही रामनगरी को अब सुरक्षा की 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ रहा है। आतंकी हमले की धमकी के बाद सभी प्रवेश मार्गों पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। पैदल यात्री निगहबानी के बाद आ-जा पा रहे हैं, लेकिन वाहनों के रामनगरी में प्रवेश से पूर्व उनके कागजात और उसमें बैठे लोगों के पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। रामजन्मभूमि क्षेत्र का सुरक्षा घेरा और कस दिया गया है। रामकोट क्षेत्र में प्रवेश के विभिन्न मार्गों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। दोपहिया वाहनों को अनेक बैरियर-बैरीकेडिंग से मुकाबिल होते हुए गुजरना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में उन्हीं चारपहिया वाहनों को जाने की इजाजत दी जा रही है, जिनका विशेष पास है। सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम के चलते यात्रियों सहित स्थानीय नागरिकों के कदम थम रहे हैं। गुरुवार को रामजन्मभूमि की ओर जाने वाले मार्गों सहित पूरे शहर में 35 स्थानों पर सीसी कैमरों को सक्रिय किया गया। एक हजार से अधिक पुलिस एवं पीएसी के अतिरिक्त जवानों को ड्यूटी पर तैनात रखा गया है।

सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाकचौबंद : एसएसपी आशीष तिवारी के अनुसार हम हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाकचौबंद है और अयोध्या की सुरक्षा व निगरानी की प्रतिदिन समीक्षा के बाद आवश्यकता पड़ने पर इजाफा किया जाता है।

पूर्व में विफल हो चुका है आतंकी हमला : यह पहला मौका नहीं है, जब रामनगरी आतंकियों के निशाने पर है। पांच जुलाई 2005 को आत्मघाती आतंकियों का दस्ता रामकोट स्थित अधिगृहीत परिसर की सीमा तक आ धमका था। उन्होंने परिसर का पहला घेरा भी विस्फोट से उड़ा दिया था। संयोग ही कहेंगे कि आतंकियों ने परिसर में 26 ग्रेनेड फेंके पर एक भी नहीं दग सका। इस बीच जवानों ने जवाबी फायरिंग में सभी पांचों आतंकवादियों को ढेर कर दिया।

राम की जन्मभूमि को तपोभूमि से जोड़ेगा रेलवे

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट को उनकी जन्मभूमि अयोध्या से जोड़ने की कवायद रेलवे ने शुरू कर दी है। 2020 में मार्च तक नई ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। इसके लिए चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन का विस्तार कर प्लेटफार्म नंबर एक की तरफ अलग ट्रैक बिछाकर यार्ड का रूप दिया जा रहा है। अभी स्टेशन में मुख्य लाइन के साथ दो लूप लाइनें हैं। चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन में ऐसा स्थान नहीं है, जहां किसी ट्रेन को खड़ा रखा जा सके। रेलवे अब प्लेटफार्म नंबर एक और रेलवे कॉलोनी के बीच 18 बोगी यानी 300 से 380 मीटर का एक साइडिंग ट्रैक बिछा रहा है। इसे यार्ड के रूप में विकसित करने के साथ अन्य ट्रेनों का संचालन भी किया जा सकेगा। साथ में झांसी-मानिकपुर ट्रैक के दोहरीकरण में भी एक अतिरिक्त ट्रैक बिछाया जाएगा। अयोध्या का चित्रकूट से अटूट नाता है। भगवान राम का जन्म भले ही अयोध्या में हुआ, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा चित्रकूट से मिला। वनवास काल का सबसे अधिक समय भी उन्होंने चित्रकूट में बिताया था। इसीलिए चित्रकूट आने वाले तमाम श्रद्धालु यहां से अयोध्या जाना चाहते हैं।

जागरण विशेष

बंजर में बहार, राजस्थान में सफल साबित हुई जैतून की खेती, फल से तेल तो पत्ती से बन रही चाय, कम तापमान पर पैदा होने वाले जैतून ने तपते राजस्थान से कर ली यारी

जैतून ने कर ली राजस्थान से यारी, अब दूसरे राज्यों की बारी

मनीष गोधा, जयपुर

आमतौर पर सात से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच उत्पादित होने वाला जैतून राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में भी पैदा हो रहा है। जी हां, 'सुकुमार' जैतून ने तपते राजस्थान से कर ली 'यारी' कर ही ली। साल 2006 में इजरायल के सहयोग और तकनीकी परामर्श के साथ शुरू हुआ प्रयोग अब आम किसान के लिए मुनाफे का सौदा बन गया है। इसकी पौध अन्य राज्यों में भी जाना शुरू हो गई है।

कमाल यह भी है कि यहां जैतून न सिर्फ पैदा हो रहा है बल्कि जैतून तेल मिलों में इसका तेल तैयार हो रहा है। यही नहीं, इसकी पत्तियों से जैतून की चाय भी बनाई जा रही है। राज्य के कठिन भूभाग वाले क्षेत्रों के कई किसान खुद जैतून की खेती करने लगे हैं। यहां सरकारी तथा निजी क्षेत्र में मिलाकर करीब 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में जैतून की खेती हो रही है।

जैतून विदेशी पौधा है। मुख्य तौर पर इसकी खेती स्पेन, ग्रीस, इटली और ट्यूनिशिया जैसे ठंडे यूरोपीय देशों में होती है। इसके लिए कम तापमान चाहिए और पौधा लगाने के करीब पांच वर्ष बाद पहला फल लगता है। इसके बाद इसकी ज्यादातर किस्मों में एक वर्ष कम और एक वर्ष अच्छे फल लगते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से जैतून बहुत ही गुणकारी माना जाता है। राजस्थान में जैतून की खेती का विचार 2006 में तब आया जब कृषि विभाग के अधिकारियों का एक दल इजरायल दौरे पर गया था। इजरायल और राजस्थान की जलवायु परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं, लेकिन इजरायल में जैतून का सफल उत्पादन हो रहा था। ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस दिशा में काम करने को कहा। जल्द ही राजस्थान सरकार, एक इजरायली कंपनी और ड्रिप इरिगेशन का काम करने वाली एक निजी कंपनी के साथ मिलकर राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड (आरओसीएल) की स्थापना की गई। आरओसीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि उस समय हमने इजरायल से जैतून की सात किस्मों बरनिया, अरबिक्युना, कोरटिना, कोरोनोयकी, पिषुलीन, पिक्काल और फ्रंटोय के एक लाख 12 हजार पौधे मंगाए थे। इन पौधों की परवरिश (हार्डनिंग) जयपुर में नर्सरी स्थापित कर की गई और फिर राजस्थान में अलग-अलग जलवायु वाले सात क्षेत्रों श्रीगंगानगर, नागौर, बीकानेर, जालौर, झुंझुनूं, अलवर और जयपुर में कुल 182 हेक्टेयर क्षेत्र में जैतून की खेती शुरू की गई। करीब पांच साल बाद, 2014 में इनमें फल आए, लेकिन सात में तीन जगह ही ऐसे फल मिले, जिनका व्यावसायिक उपयोग कर जैतून का तेल निकाला जा सकता था। बाकी जगह फल तो आए, लेकिन वे व्यावसायिक रूप से उपयोगी नहीं थे। शेखावत ने बताया कि हमारे अभी तक के अनुभव के अनुसार राजस्थान के उत्तरी हिस्से के जिलों जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि जैतून की खेती के लिए आदर्श साबित हुए हैं क्योंकि यहां सर्दियों में जैतून के लिए उपयुक्त तापमान मिल जाता है। इस समय राजस्थान के इन जिलों के करीब 377 किसान जैतून की खेती कर रहे हैं और सरकारी फार्म हाउस के अलावा लगभग 935 हेक्टेयर निजी क्षेत्र में जैतून उगाया जा रहा है। सफलता के बाद हमने बीकानेर के लूणकरण क्षेत्र में जैतून तेल मिल की स्थापना की। यह तेल मिल सरकारी क्षेत्र में देश में जैतून की पहली तेल मिल है। 'राज ओलिव' ब्रांड के नाम से इसे बेचा जाता है।

जयपुर की एक नर्सरी में जैतून की पौध तैयार करतीं महिला किसान।

फल से लकदक पौधा। दोनों फाइल फोटो सौ. आरओसीएल

2006 में इजरायल के सहयोग और तकनीकी परामर्श के साथ शुरू हुआ था प्रयोग

1100 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही खेती, अब आम किसान खुद कर रहे खेती, कमा रहे मुनाफा

फल के अलावा जैतून की पत्तियां भी किसानों को मुनाफा दे रही हैं। इस सफलता के बाद जैतून के और भी उत्पाद तैयार करने का प्रयास जारी है। जल्द ही यह सामने होंगे। जयपुर की नर्सरी में बीस लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं और अब अन्य राज्यों को भी पौधे दिए जा रहे हैं। किसानो को पौधारोपण सामग्री पर 48 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान भी दिया जाता है।

-सुरेंद्र सिंह शेखावत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड

दैनिक जागरण
नम्रता से पेश आने में कुछ भी खर्च नहीं होता

सेना प्रमुख की खरी बात

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के इस सीधे-सपाट बयान पर हंगामा खड़ा किया जाना हैरान करता है कि लोगों को गलत दिशा दिखाने वाले नेता नहीं कहे जा सकते। आखिर इसमें गलत क्या है? क्या सेना प्रमुख के बयान पर बेवजह बिफर रहे लोग उनके मुख से ऐसा कुछ सुनना चाह रहे थे कि लोगों को गलत दिशा दिखाने वाले भी नेता कहे जाने चाहिए? सेना प्रमुख तो साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेंकते और हिंसा का माहौल बनाते नेताओं को आईना दिखाया और बिना किसी लाग-लपेट यह भी कहा कि हमने देखा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें हिंसा हो रही है। यदि उन्होंने हिंसा और आगजनी करती भीड़ का नेतृत्व करने वालों को सही नेतृत्व की संज्ञा देने से इन्कार कर दिया तो विपक्षी नेताओं को मिर्ची क्यों लग रही है? कहीं इसलिए तो नहीं कि वे खुद भी उन नेताओं में शामिल हैं जो हिंसा और अराजकता के लिए लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतार रहे हैं? यदि नहीं तो फिर उन नेताओं की गिनती करके बताएं जो आगजनी और पत्थरबाजी की निंदा कर रहे हों? जिन्हें यह लगता है कि सेना प्रमुख विरोध प्रदर्शन की आलोचना कर रहे हैं उन्हें उनके वक्तव्य को फिर से सुनना और समझना चाहिए। उन्होंने विरोध के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा और अराजकता की आलोचना की है। ऐसा करना तो हर भारतीय का धर्म है। नागरिकता कानून के विरोध के बहाने जो अराजकता हुई उसने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए।

आखिर कोई यह सोच भी कैसे सकता है कि आंतरिक सुरक्षा पर असर डालने वाली व्यापक हिंसा पर सेना प्रमुख मौन रहें? किसी भी सैन्य अधिकारी से यह अपेक्षा क्यों की जानी चाहिए कि वह इस भय से आंतरिक सुरक्षा पर असर डालने वाली घटनाओं पर बोलने से बचे कि कुछ नेता उसके बयान की मनमानी व्याख्या करके हाय-तौबा मचा सकते हैं? बिपिन रावत से तो यह अपेक्षा बिलकुल भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हर मसले पर बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। यह हास्यास्पद है कि जो नेता सेना प्रमुख को यह नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें संभलकर बोलना चाहिए उन्हें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वे खुद कितना संभल कर बोलते हैं? अगर कोई विपक्षी नेता यह कहता है कि नागरिकता कानून के विरोध में अराजकता नहीं फैलाई गई तो यह निरा झूठ ही नहीं, देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी है। बिपिन रावत ने इसी कोशिश को इशारे से बेनकाब किया है।

हिमाचल की उपलब्धि

हिमाचल प्रदेश बेशक छोटा राज्य है, लेकिन इसकी उपलब्धियां छोटी नहीं हैं। प्रदेश कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बना है। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद हिमाचल ने बड़े राज्यों को चुनौती पेश की है। विकास की दौड़ में आगे रहने की जिद और शासन-प्रशासन के गंभीर प्रयासों ने प्रदेश को इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश की सरकारों का दृष्टिकोण विकास के साथ बेहतर शासन देने के लिए प्रयासरत रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को मिले पुरस्कार इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रदेश में जनता की अपेक्षाएं पूरी करने की हरसंभव कोशिश की जा रही है। अब केंद्र सरकार द्वारा देश में राज्यों के शासन का आकलन करने वाला सुशासन सूचकांक (जीजीआइ) जारी किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने पर्वतीय व पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। समग्र रैंकिंग में प्रदेश ने शीर्ष पर रहकर प्रदेशवासियों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। अलग-अलग श्रेणियों में भी प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है। मानव संसाधन विकास क्षेत्र, सार्वजनिक ढांचागत क्षेत्र व न्यायिक एवं जन सुरक्षा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। अब आवश्यकता उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की है, जहां प्रदेश अपेक्षाकृत पिछड़ा है ताकि स्थिति को और भी बेहतर बनाया जा सके।

सुशासन सूचकांक में हिमाचल प्रदेश का पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों में अव्वल आना बड़ी उपलब्धि है। इससे भविष्य में बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी

कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र, जनस्वास्थ्य क्षेत्र व सामाजिक कल्याण एवं विकास क्षेत्र में काफी कुछ किया जाना जरूरी है ताकि इस दौड़ में हम किसी से पीछे न रहें। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए 93 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू इस बात की पुष्टि करते हैं कि निवेशकों का विश्वास जीतने में सरकार सफल रही है। इसी तरह कृषि व सहयोगी क्षेत्र में किसानों-बागवानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। कोई भी पुरस्कार या उपलब्धि इतराने का मौका देती है, साथ ही और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। साथ ही यह मंथन के लिए प्रेरित करती है कि जहां हम चूके हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। उम्मीद है कि शासन-प्रशासन इस दिशा में प्रयासों को तेजी देंगे। आर्थिक संसाधन प्रदेश के विकास की गति में रोड़ा न बनें, इसके लिए भी आय सृजन के अवसरों की तलाश करनी होगी और उन्हें भुनाना होगा।

नागरिकता कानून को सही संदर्भ में देखने से इन्कार

डॉ. एके वर्मा

आखिर देश हित की हर बात को मुस्लिम विरोध के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? क्या देश हित और मुस्लिम हित में कोई अंतर्विरोध है?

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर से जुड़े मसलों को गड्ड-मड्ड करने से भारतीय लोकतंत्र असहमति, विवाद और संघर्ष के मकड़जाल में फंस गया है। देश में बेचैनी का आलम है। जहां तक एनपीआर की बात है तो यह कांग्रेस सरकार में 2010 में भी बना और 2015 में मोदी सरकार में संशोधित हुआ। एनपीआर को नागरिकता कानून, 1955 के अंतर्गत बनाया गया। मोदी-2 सरकार ने जुलाई 2019 में ही एनपीआर को अपडेट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इतना ही नहीं बंगाल और केरल सहित सभी राज्य भी इसका नोटिफिकेशन कर चुके हैं। इसके बावजूद इन राज्यों सहित अन्य राज्यों में एनपीआर का विरोध समझ से परे है और एनआरसी तो अभी दूर की कौड़ी है। अनेक दलों द्वारा नागरिकता कानून को मुस्लिम विरोधी और संविधान विरोधी ठहराने की कोशिश की जा रही है। क्या वास्तव में ऐसा है? यदि सीएए या कोई भी कानून मुस्लिम या संविधान विरोधी है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सीएए को तो दे भी दे गई है। आखिर इसके बाद भी सीएए के विरोध के लिए हिंसा और सड़क पर प्रदर्शन क्यों?

प्रत्येक कानून का एक संदर्भ और उद्देश्य होता है। सीएए का भी विशेष संदर्भ और उद्देश्य है। सांप्रदायिक आधार पर विभाजन से पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल राज्य बने जिन्होंने इस्लाम को अपना राजधर्म घोषित किया। इससे वहां गैर-इस्लामिक लोगों मुख्यतः हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों पर अत्याचार होने लगे। इन देशों में उनकी संख्या लगातार घटती गई। पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 12 से घटकर 2 प्रतिशत और बांग्लादेश में 22 से घट कर 8 प्रतिशत हो गई है। मोदी सरकार ने 2015 और 2016 में दो अधिसूचनाएं जारी कीं जिनमें कहा गया कि बिना वैध दस्तावेजों के गैर-कानूनी रूप से रह रहे ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को देश से नहीं निकाला जाएगा। वर्तमान सीएए उसी तीन वर्ष पुरानी अधिसूचना को कानूनी जामा पहनाने का प्रयास है। इसमें उक्त तीन देशों के मुस्लिमों को शरीक करने का कोई औचित्य नहीं बनता। खुफिया ब्यूरो के अनुसार इससे तत्काल 31,313 लोगों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन गृह-मंत्रालय के अनुसार इससे गैर-कानूनी रूप से रह रहे लाखों लोगों को लाभ होगा।

यदि पड़ोसी देशों के मुस्लिम समाज के कुछ लोगों जैसे अहमदिया और बहाई का पकिस्तान या बांग्लादेश में उत्पीड़न होता है और यदि वे भारत आना चाहते हैं तो नागरिकता कानून में इसके लिए प्रावधान है। इसी के तहत मोदी सरकार ने पिछले छह वर्षों में 2830 पाकिस्तानी, 912 अफगानी और 172 बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता दी है। राजनीतिक दलों ने भ्रम और भय यह पैदा किया कि सीएए भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिमों को लक्ष्य करता है। सीएए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए है। देखा जाए तो सीएए का विरोध दलितों और महिलाओं का विरोध भी है, क्योंकि इन तीनों देशों में उत्पीड़न का शिकार ज्यादातर दलित और महिलाएं ही हैं।

अवधेश राजपूत

यूरोपियन यूनियन संसद की मई 2019 रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में प्रति वर्ष एक हजार लड़कियों का अपहरण कर उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। भारतीय नेताओं और दलों को अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना का दायरा कुछ बढ़ाना चाहिए और सीएए के परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए जिसमें राजनीति से इतर एक मानवीय पहलू भी है। अलबत्ता यह जरूर है कि मुस्लिमों को भड़काने के लिए एनआरसी का कनेक्शन काफी है, क्योंकि असम का अनुभव बताता है कि लाखों लोग असम एनआरसी से बाहर रह गए। असम का मसला अलग है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वहां एनआरसी बनाया गया जिसमें बांग्लादेश से आए बहुत से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक छूट गए। अब सीएए में 31 दिसंबर 2014 तक आए अवैध घुसपैठियों को छूट देकर बंगलादेशी हिंदुओं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जा सकती है। असम में जो हिंसक प्रदर्शन हुए उसके पीछे 'स्थानीय-जन बनाम बाहरी घुसपैठिये' विवाद रहा जिसमें मूलतः आर्थिक-राजनीतिक हितों का मुद्दा सबके मन में हावी था कि कहीं 1997 से घोषित बंगलादेशी 'डी-वोटर्स' देश की नागरिकता हासिल कर स्थानीय लोगों पर वर्चस्व न बना लें।

प्रत्येक देश को अपना राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) बनाने का अधिकार है। भारत में प्रथम एनआरसी 1951 तत्कालीन गृहमंत्री सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में बना, लेकिन उसके बाद से आज तक उसका नवीनीकरण नहीं किया गया जबकि असम में एनआरसी 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर और उसकी देखरेख में बना। यह भी ध्यान रहे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया आदि अनेक देशों में भी 'एनआरसी' व्यवस्था लागू है। आखिर भारत में 1951 के एनआरसी का नवीनीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है? इस पर कोई बहस भी नहीं। देश हित की हर बात को मुस्लिम विरोध के चश्मे से हम क्यों देखते हैं? क्या देश हित और मुस्लिम हित में कोई अंतर्विरोध है? यदि सीएए संविधान विरोधी है, अनु.14 और अनु.25 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त कर ही देगा। गैर-भाजपा दल वास्तव में सीएए, एनपीआर और एनआरसी का विरोध कर पूरे विमर्श को हिंदुत्व-विरोध और मुस्लिम-तुष्टीकरण से जोड़ रहे हैं जिससे अंततः देश में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और इन्हीं दलों को ही इसका नुकसान होगा। इधर तीन-तलाक और अनु.370 पर जिस तरह मोदी सरकार को मुस्लिम समर्थन मिला उससे गैर-भाजपाई दलों को अपना मुस्लिम जनाधार खिसकता दिख रहा है और वे मोदी एवं भाजपा विरोध का कोई सैद्धांतिक आधार खोज रहे थे जो सीएए और एनआरसी के मिश्रण में उनको मिल गया।

क्या विरोधी दल रोहिंग्या मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने के पक्षधर हैं? क्या भारत को इतना सहिष्णु होना चाहिए कि उसे सभी पड़ोसियों के उत्पीड़ितों की धर्मशाला बना दिया जाए? जनसंख्या की हमारी अपनी ही जटिल समस्या है। हमें सहिष्णुता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ-साथ अपनी सीमाएं भी समझनी होंगी और संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को राजनीतिक विवेक और कौशल के साथ ही संचालित करना होगा। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षेत्रीय एवं वैश्विक भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से संबद्ध करके ही देखना होगा, जिससे हमारी अस्मिता और लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

असमंजस के लिए कौन जिम्मेदार

जगदीप एस छोकर

यह मानना अत्यंत कठिन है कि गृहमंत्री अमित शाह के एनआरसी को लेकर दिए गए एक से अधिक बयान गलत हैं

आजकल देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर जो कुछ चल रहा है उसे देख कर अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार और नाटककार विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेमलेट की जानी मानी लाइन-टू बी ऑर नॉट टू बी की याद आती है। इसका संदर्भ उस बात से है जो देश के गृहमंत्री अमित शाह पिछले कई महीनों से कह रहे थे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने की 22 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा। इन दोनों नेताओं की बातों को सुनकर असमंजस यह होता है कि एनआरसी नाम की कोई चीज है (जैसा कि गृहमंत्री ने संसद के भीतर-बाहर बार-बार कहा) या फिर हम एक सपना देख रहे थे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने देश के सबसे चर्चित मैदान में भरी सभा में कहा। उनके अनुसार एनआरसी के बारे में तो अभी कोई बात तक नहीं हुई। यह मानना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है कि गृहमंत्री के एनआरसी पर एक से अधिक बयान गलत या फिर झूठ हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक तौर पर की गई घोषणा पर विश्वास करना भी ठीक नहीं होगा। आखिर देश असमंजस की इस स्थिति में कैसे पहुंचा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

असम में एनआरसी तो एक पुरानी ऐतिहासिक विरासत है जिसे उच्चतम न्यायलय ने एक नया जीवनदान देना उचित समझा। जैसे-जैसे असम में एनआरसी का काम चलता गया उसके नए-नए पहलू सामने आने लगे। इस सिलसिले में सत्तारूढ़ दल को महसूस हुआ कि इस प्रक्रिया को उसके 1996 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पीछे यह इरादा था कि जो लोग देश में गैरकानूनी या अवैध तरीकों से आए हुए हैं और जिन्हें सामान्यतः घुसपैठिया भी कहा जाता है उन्हें खोजकर निकालना और देश से बाहर भेजना। इस प्रक्रिया को 1996 के घोषणा पत्र में डिटेक्शन, डिलीशन और डिपोर्टेशन कहा गया था। अवैध रूप से आए लोगों को खोजने के लिए तो एनआरसी एक बना-बनाया तरीका था। इसके बाद गैर-कानूनी तरीकों से देश में आए लोगों के नाम को एनआरसी से हटाने या सम्मिलित न करने और अवैध घोषित करने के लिए एक कानूनी तरीके की जरूरत समझी गई। यह तरीका बना नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके। संशोधन में लिखे जाने वाले शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण थे। फैसला यह हुआ कि जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में आए हैं उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, अगर वे भारत में कम से कम पांच साल से रह रहे हों।

कभी-कभी होता यह है कि जो कहा गया या लिखा गया वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना वह जो नहीं कहा या लिखा गया। नागरिकता कानून में संशोधन में भी ऐसा ही हुआ। जिन समुदायों के नाम इसमें लिखे गए उनसे अधिक महत्वपूर्ण वह समुदाय था जिसका नाम नहीं लिखा गया। वह समुदाय कौन सा है, यह बताने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के नाते यह समझना होगा कि वह समुदाय है मुस्लिम। इसका औचित्य बताया गया कि ये तीनों देश अधिकृत रूप से इस्लामी देश हैं। इसलिए इन देशों में मुसलमानों का धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता। यह औचित्य कहां तक ठीक है या नहीं, इसका फैसला जनता स्वयं करें, लेकिन यह याद रखने की बात है कि इस्लाम में भी कई उप-समुदाय हैं जिनमें से कुछ आपस में एक-दूसरे का बहुत विरोध करते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर एनआरसी है भी तो उसमें और नागरिकता संशोधन अधिनियम में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो कैसे और अगर नहीं है तो ये दोनों लागू कैसे किए जाएंगे, यह देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए असम के आंकड़ों को लेकर देखते हैं कि यह काम कैसे होगा।

असम में एनआरसी हुआ और लगभग 3.3 करोड़ लोगों के नाम उसमें आए और लगभग 19 लाख के नहीं आए। जिन 19 लाख के नाम नहीं आए उनमें से लगभग 13 लाख हिंदू, सिख, बौद्ध जैन, पारसी और इसाई हैं और शेष छह लाख मुसलमान। कानूनी प्रावधान के तहत ये सब 19 लाख लोग फॉरेन नेशनल ट्रिब्यूनल्स यानी विदेशियों के लिए गठित विशेष अदालतों में अपने नाम एनआरसी में शामिल कराने के लिए याचिकाएं दे सकते हैं। नागरिकता कानून यानी सीएए का असर या काम यहां से आरंभ होता है। इस संशोधन के कारण इन 19 लाख में से जो 13 लाख हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे उन्हें तो अवैध प्रवासी नहीं गिना जाएगा और इस कारण भारत में पांच साल रहने के बाद वे भारतीय नागरिकता के हकदार होंगे, लेकिन जो छह लाख बाकी बचेंगे उन्हें अवैध प्रवासी गिना जाएगा और इसीलिए उन्हें ट्रिब्यूनल्स का सहारा लेना पड़ेगा। वहां जो होगा सो होगा। अब तक जो अनुभव असम में गठित इन ट्रिब्यूनल्स का हुआ है वह तो उत्साहजनक नहीं लगता। आगे क्या होगा, यह कहना कठिन है, लेकिन दो बातें तो स्पष्ट हैं। एक तो यह कि 1996 के घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने के लिए एनआरसी और सीएए, दोनों की आवश्यकता है और दूसरी, सीएए धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या संविधान में ऐसा परिवर्तन, इस तरीके से करना देश की जनता को स्वीकार है?

(लेखक आइआइएम अहमदाबाद के प्रोफेसर, डीन और डायरेक्टर इंचार्ज रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वाणी का महत्व

वाणी व्यक्तित्व का आभूषण है। वाणी से ही व्यक्ति के गुणों की पहचान होती है। गीता में तीन प्रकार के तपों की चर्चा है। इनमें शारीरिक तप, मानसिक तप तथा वाचिक तप शामिल हैं। वाचिक तप का आशय वाणी के प्रवाह से है। इसके संबंध में कहा गया है कि उद्वेग उत्पन्न न करने वाले वाक्य, हित कारक तथा सत्य पर आधारित वचन एवं स्वाध्याय वाचिक तप हैं। वास्तव में वाणी को संयम में रखने वाला व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है। इसके विपरीत अनियंत्रित वाणी वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता तो दूर अक्सर तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति सदैव मीठा बोलता है उसके मित्रों और शुभचिंतकों का दायरा बढ़ता जाता है। मृदुभाषी होने की स्थिति में लोगों के सहयोग और समर्थन में वह अत्यधिक ऊर्जा का संग्रह कर लेता है, जबकि कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है।

वाणी में आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों प्रकार के ऐश्वर्य हैं। मधुरता से कही गई बात कल्याणकारक रहती है, किंतु वही कटु शब्दों में कही जाए तो अनर्थ का कारण बन सकती है। कटु वाक्यों का त्याग करने में अपना और औरों का भी भला है। वाणी की शालीनता और शीतलता मनुष्य के व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाती है। मधुर एवं कर्णप्रिय वाणी बिगड़े काम बना देती है। मीठी वाणी सफलता के द्वार खोल देती है और तमाम उलझनों को सुलझा देती है। इसके उलट कर्कश वाणी से समस्याएं और गहराने लगती हैं। बने-बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए हमें सदैव मधुरवाणी को आत्मसात करना चाहिए। किसी मूर्तिकार की तरह हमें अपनी वाणी को तराशते रहना चाहिए। बोलने से पहले हमें शब्दों को तोल लेना चाहिए। हर शब्द में मिठास और शालीनता का रंग भरकर मुख से दूसरों के बीच रखना चाहिए। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई सुने तो वाह-वाह करे। संत कबीर ने कहा भी है कि 'ऐसी वाणी बोलिये,मन का आपा खोय। औरन को शीतल करें,आपहु शीतल होय।' इसे जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए।

नरपत दान चारण

राह से भटके बाल सुधार गृह

डॉ. अजय खेमरिया

'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015' भारत में करीब 20 वर्ष पुराना है। मौजूदा एक्ट वर्ष 2000 और 2006 का विस्तार है। इसका उद्देश्य प्रत्येक बालक को उसकी प्रतिभा और अवसरों का संरक्षण उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने इसके लिए देशव्यापी एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आइसीपीएस) लागू की है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 को बाल संरक्षण एवं देखभाल वर्ष घोषित किया है। इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुभवों पर चर्चा स्वाभाविक है। वहीं भारत में नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार, यौन हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं ने हमारे समाज और राजव्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वर्ष 2012 में बना पॉक्सो एक्ट भी अपराधियों में भय का माहौल नहीं बना पाया। इस बीच चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ट्रैफिकिंग और घरेलू उत्पीड़न की लगातार सिर उठाती चुनौतियां भी कम खतरनाक नहीं हैं।

देश के 119 जिलों में एक भी सीसीआइ यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट नहीं है जबकि 539 सीसीआइ गंभीर अनियमितताओं और यौन शोषण की शिकायतों के चलते बंद किए जा चुके हैं। सवाल यह है कि जिन संस्थाओं में ये बच्चे रहते हैं, तकरीबन वे सभी जिला मुख्यालयों में हैं। बाकी दूरदराज के इलाकों के हालात की बस कल्पना ही की जा सकती है। इससे बड़ी चिंता यह है कि किसी भी राज्य में सही मायनों में सुरक्षा और संरक्षण के पात्र बच्चों के पहचान की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। बाल मजदूरी, कचरा बीनने वाले, ड्रग एडिक्ट श्रेणी के बालकों के पुनर्वास की व्यवस्था भी जेजे एक्ट करता है, लेकिन सवाल यह है कि इन संस्थानों में पहले से रह रहे बच्चों के बालिग होने के बाद उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने की हमारे पास क्या व्यवस्था है।

भारत में एक ऐसी बाल संरक्षण योजना की आवश्यकता है जो हमारे स्थानीय सामाजिक परिवेश के अनुकूल हो

खासतौर से 18 साल की अवस्था पार कर चुकी बेटियों के लिए यह सवाल एक त्रासदी से कम नहीं है। 63 फीसद से अधिक बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कोई रोजगार नहीं मिला। 81 फीसद बालक 18 वर्ष बाद इन केंद्रों से बिना कोई कौशल या हुनर सीखे समाज में कैसे अपनी जगह बनाएंगे? हमें नीतिगत स्तर पर इसे समझना होगा कि जेजे एक्ट का दायरा सिर्फ 18 वर्ष तक सीमित नहीं है। भारत में अगर इन परित्यक्त, शोषित बच्चों को राष्ट्रीय उत्पादकता के साथ जोड़ना है तो हमें कालांतर में भी उनकी देखभाल की दिशा में ठोस काम करना होगा। इसके लिए श्रीलंका और बांग्लादेश के मॉडल को अपनाया जा सकता है जहां स्थानीय उद्योगों से ऐसे बालकों को जोड़ा गया है।

भारत की सामाजिकी के लिहाज से दत्तक ग्रहण बेहद कठिन विकल्प है, क्योंकि 90 फीसद से ज्यादा दंपती केवल छह वर्ष तक के अनाथ बच्चों को ही गोद लेना चाहते हैं, जबकि संरक्षण के जरूरतमंद सर्वाधिक बच्चे छह से 14 वर्ष के हैं। जाहिर है भारत में एक ऐसी बाल संरक्षण योजना की आवश्यकता है जो स्थानीय सामाजिक परिवेश के अनुकूल हो, क्योंकि बाल गृह किसी बुनियादी दिशा में लक्ष्यों के अनुरूप काम करने में फिलहाल नाकाम साबित हो रहे है।

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

विरोध का कारण वोट बैंक की राजनीति

नागरिकता संशोधित कानून पर कांग्रेस की मानसिकता का विश्लेषण सुरेंद्र किशोर ने 'अपने ही वादे से मुकरती कांग्रेस' शीर्षक लेख तहत किया। हमारे देश की राजनीति अब स्वार्थ और अवसरवाद की राह चल पड़ी है, इसलिए इसके लिए तो यह कहा जा सकता है कि, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या...। मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन बिल कुछ इस तरह पेश करना चाहिए था कि इस पर किसी को अंगुली उठाने का मौका न मिलता, जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए किया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में छात्र संगठन से असम समझौता किया था। उन्होंने भी इस समझौते के तहत 25 मार्च 1971 के बाद हमारे देश आने वाले शरणार्थियों या दूसरे लोगों को एनआरसी के जरिये देश से बाहर निकालने का फैसला लिया था, लेकिन अफसोस इस पर किसी सरकार ने काम नहीं किया था, मोदी सरकार ने भी शायद राजीव गांधी के अधूरे काम को पूरा करने के लिए नागरिकता कानून को हरी झंडी दे दी, इसलिए कांग्रेस को तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अनेक राजनीतिक पार्टियां क्यों इस बिल का विरोध कर रही, यह तो वो ही अच्छी तरह जानें, लेकिन मोदी सरकार को नागरिकता कानून बनाने की क्या जरूरत थी? क्या हमारा देश धर्मशाला है? इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों के प्रति ही क्यों हमदर्दी दिखाई गई, श्रीलंका और म्यांमार को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? मोदी सरकार को इस कानून की कमियों को दूर करने के उपाय अपनी हठधर्मिता को छोड़कर करने चाहिए, ताकि इससे देश के लिए कोई नुकसान न हो पाए। देश के हरेक धर्म के लोगों को देश की धर्म-संप्रदाय की संकीर्ण राजनीति से हमेशा बचकर रहना चाहिए, धर्म-संप्रदाय पर राजनीति करने वाला का मकसद लगभग अपना वोट बैंक ही होता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

सही सूचनाएं बेहद जरूरी

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), जो 2021 की जनगणना का हिस्सा है, तैयार किया जाना प्रारंभ हो रहा है। इसमें प्रगणक लोगों से मुख्यतः आर्थिक सवाल पूछते हैं, जैसे घर में कुकिंग गैस, बिजली, फ्रिज, स्कूटर, कार, जैसी चीजें हैं या नहीं ? इनके उत्तर के आधार पर परिवारों और उस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का आकलन किया जाता है एवं खुशहाली लाने की योजनाएं बनाई जाती हैं। सूचनाएं यदि सत्य नहीं हों तो आकलन गलत हो जाएगा और योजना गड़बड़। अतः सूचना सही देने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों को निभानी चाहिए। दुनिया के विकसित तथा कई विकासशील देशों में गलत जानकारी देने पर दंड का प्रावधान है। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां अक्सर गलत सूचनाएं दी जाती हैं। काफी संख्या में लोग खुद को निर्धन दिखाना चाहते हैं कि बाद में सरकारी मदद, यदि मिल रही हो तो उसे पाने वाली श्रेणी में आ सकें। इसलिए सरकार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में त्रुटिपूर्ण बात दर्ज करने पर सजा का प्रावधान करना चाहिए, ताकि आर्थिक सर्वेक्षण एकदम त्रुटिहीन हो। आम जनता को भी चाहिए कि इसमें सही सूचनाएं ही दर्ज कराएं। सही सूचना देने का लाभ जहां सरकार की योजनाओं के लिए लाभकारी होगा, वहीं खुद के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सी जानकारी अन्य सर्टिफिकेट में भी दर्ज होती हैं। अगर हर जगह अलग-अलग जानकारी होगी तो भविष्य में कभी मिलान करने पर अंतर आएगा और कोई फाइल इसी आधार पर रुक सकती है कि नाम मेल नहीं खा रहा है। ऐसी समस्या खासकर नाम में अधिक आती है।

ajay.mittal97khandak@gmail.com

झारखंड में हार से सबक ले भाजपा

झारखंड में भाजपा की हार की मुख्य वजह झामुमो-कांग्रेस और राजद का एक मजबूत गठबंधन बनना है। झामुमो ने अपने लिए ग्रामीण और कांग्रेस को शहरी सीटें देकर अच्छा रणनीतिक प्रयोग किया। आजसू से भाजपा का गठबंधन टूटना भी ठीक नहीं रहा। हरियाणा व महाराष्ट्र की तरह यहां भी बागियों ने भाजपा को हरवाया। आखिर इतनी संख्या में बागी क्यों खड़े हुए? पार्टी में इतने व्यापक असंतोष के क्या कारण थे? भाजपा नेतृत्व को इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने होंगे, अन्यथा आगामी चुनावों में भी पार्टी के लिए जीत हासिल करना मुश्किल होता जाएगा। साथ ही स्थानीय नेतृत्व को भी उचित रूप से तराशना होगा।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

300 से ज्यादा ईंट भट्ठे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास जिनमें ईंधन के तौर पर मुख्य रूप से कोयला इस्तेमाल होता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ावा देने में कोयला भी एक बड़ा कारण है।

आजकल

तथ्यों को समझे बिना उचित नहीं है हंगामा

न तो नागरिकता संशोधन कानून मुस्लिम विरोधी है, न ही राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण ही ऐसा होगा। यह धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित अपने विभाजन-पूर्व नागरिकों को पुन : नागरिकता प्रदान करना संविधान की मूलभावना सांप्रदायिक सद्भाव के अनुरूप है। यह संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के खिलाफ भी नहीं है। संविधान में ही तार्किक वर्गीकरण की व्यवस्था है जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सशक्तीकरण और सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं

प्रो. रसाल सिंह
अध्यापक, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू

देश भर में पिछले कई दिनों से एनआरसी यानी 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' और सीएए यानी 'नागरिकता संशोधन कानून' को लेकर असत्य, अफवाह और दुष्प्रचार के माध्यम से देश की विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन, हिंसा और उपद्रव कर रहे हैं। इससे देश की आंतरिक शांति, एकता-अखंडता और सद्भाव को क्षति पहुंच रही है। कुछ देशवासी भ्रमित होकर उनकी राजनीतिक स्वार्थसिद्धि का माध्यम बनते जा रहे हैं।

विपक्ष का दुष्प्रचार-तंत्र इस मामले को भड़काने में बड़ी कुटिल भूमिका निभा रहा है। वह पूर्वोत्तर भारत में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के आधारस्वरूप वहां की भूमि, साधनों-संसाधनों, रोजगार-व्यापार में इस कानून के तहत नागरिकता हासिल करने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों और पारसियों की भागीदारी का डर दिखाकर मूलवासियों को भड़का रहा है। इसके अलावा उनकी भाषा, संस्कृति, खान-पान, रीति-रिवाज, आदि की विशिष्टता की समाप्ति का डर भी दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, शेष भारत में मुस्लिम समुदाय को भी इस कानून के दायरे में शामिल न करने को मुद्दा बनाकर इस कानून को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश रची जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि पूर्वोत्तर भारत की उपरोक्त जो भी चिंताएं हैं, उनका सबसे बड़ा कारण मुस्लिम समुदाय ही रहा है। वह चाहे बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हों, या फिर रोहिंग्या घुसपैठिए। पूर्वोत्तर की भूमि और संसाधनों पर कब्जा करने वालों में यही लोग 'बहुसंख्यक' हैं। इन्होंने जो घुसपैठ की है, वह भी किसी धार्मिक प्रताड़ना या भेदभाव या विवशता के कारण नहीं, बल्कि भारत देश में मौजूद अवसरों और संभावनाओं को हड़पने के लिए स्वेच्छा से की है। इस प्रकार विपक्ष के ये विरोधाभासी तर्क हैं जो वह एकसाथ दे रहा है और स्थान विशेष और समुदाय विशेष के अनुरूप रणनीतिक रूप से भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना चाह रहा है।

केंद्र सरकार देशवासियों के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा करने तथा गैरकानूनी तरीके से भारत में मौजूद घुसपैठियों की पहचान करने के लिए इस 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' को अपडेट करना चाहती है। इसके बाद से ही समूचे देश में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। इन प्रायोजित विरोधों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से लगातार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि 'राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण' पूरी तरह निष्पक्ष होगा। जिन भारतीय नागरिकों का नाम इसमें सूचीबद्ध नहीं होगा, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भारतीय नागरिकता साबित करने का अवसर पुनः दिया जाएगा।

मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड बनाने के दौरान भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। किंतु अब इनसे बहुत अधिक लाभ हो रहा है। मतदाता पहचान पत्र की निष्पक्ष चुनाव में बड़ी भूमिका है। आधार कार्ड ने तमाम सरकारी योजनाओं के फर्जीवाड़े को रोका है। इसमें सरकारी नौकरियों में छद्म कर्मचारियों की उपस्थिति से लेकर छात्रवृत्ति, मनरेगा आदि के घोटाले व दुरुपयोग का पर्दाफाश शामिल है।

विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगातार यह भ्रम फैला रही हैं कि सरकार इसमें मनमानी करेगी। साथ ही वे यह डर भी फैला रही हैं कि जिनके नाम इस रजिस्टर में सूचीबद्ध नहीं हैं, उनको बिना सुनवाई के तत्काल 'देशनिकाला' दे दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार देश में पहले से नागरिकता प्राप्त मुसलमानों को भी भारत से बाहर निकाल देगी। गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक डराया जा रहा है कि उनके पास दस्तावेजों का अभाव उन्हें 'घुसपैठिया' साबित कर देगा और उन्हें देश से विस्थापित कर दिया जाएगा। इन वर्गों को भ्रमित किया जा रहा है कि उन्हें राज्य प्रदत्त सुविधाओं और संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। भारत की भूमि और संसाधनों पर इन घुसपैठियों को बसाने के कुकृत्य की जिम्मेदार गैर-भाजपा सरकारें रही हैं। ऐसा उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति के तहत लगातार किया है। अभी उनके द्वारा भड़काई जा रही हिंसा और अशांति का वास्तविक कारण भी यही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और असम की जनता की अपेक्षाओं-आकांक्षाओं और मांग को पूरा करने के लिए इस राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतन किया जा रहा है। असम के बाद इसे पूरे देश में लागू करने के लिए भी भारत सरकार कृतसंकल्प है ताकि घुसपैठियों की समस्या से राष्ट्रीय स्तर पर भी निपटा जा सके।

सरकार ने नीति बनाई है कि लोगों को अपना दावा प्रस्तुत करने और आपत्तियों के निवारण के लिए न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरण के पास जाने का भी समुचित अवसर दिया जाएगा। उनके दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अंतिम रूप से एनआरसी को जारी किया जाएगा। किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित न होने देना भारत सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। इसमें किसी जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ ही, अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और उनको राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ न बनने देना भी सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक की सरकारें अपने इस कर्तव्य के निर्वाह में विफल रही हैं। आज बड़ी भारी संख्या में देश में घुसपैठिए मौजूद हैं जो राष्ट्रीय संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं और अनेक प्रकार की आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों में भी संलग्न हैं।

कुछ राजनीतिक पार्टियां देश की युवा पीढ़ी को भारत की भूमि, संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार से वंचित करना चाहती हैं। यही कारण है कि देश की युवा पीढ़ी को इन षड्यंत्रों को समझना होगा और 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' और 'नागरिकता संशोधन कानून-2019' जैसे अनिवार्य और भारत हितकारी कानूनों के संबंध में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और अफवाहों से दूर रहना होगा। विपक्षी दलों को देश को बिगाड़ने की बजाय देश बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

झूठ के सहारे हिंसा और उपद्रव

तरुण विजय
पूर्व राज्यसभा सदस्य

भारत में रहने वाले लगभग सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नागरिकता कानून का किसी भी भारतीय नागरिक पर असर नहीं होगा। किसी भी भारतीय मुसलमान को नागरिकता कानून के कारण कभी कोई परेशानी होने का कोई कारण ही नहीं। नागरिकता कानून केवल उन पड़ोसी इस्लामी देशों में जहां हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अल्पसंख्यक हर दिन सताए जाते हैं, उनको शरण देने का एक करुणामय प्रयास है जो सदियों पुरानी भारतीय परंपरा का प्रतीक है। फिर भी केवल राजनीतिक शतरंज के लिए मुसलमानों में जानबूझकर झूठ की आग फैलाई जा रही है ताकि सरकार पर किसी बहाने चोट हो सके, भले ही इसके लिए देश का कितना ही विनाश क्यों न हो।

आज कई ऐसे मुसलमान नेता हैं जो जहर उगलकर केवल इसलिए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीमा पार के पीड़ित-शोषित सिखों, बौद्धों, हिंदुओं को राहत देना मंजूर नहीं। बहाना बनाया जा रहा है कि यह कानून मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। लेकिन खिलाफ कैसे है, यह कोई नहीं बताता। जो लोग जिहादी, वाम, ईसाई गठबंधन के विदेश प्रेरित षड्यंत्र की असलियत नहीं जानते वे भारत के भविष्य से अनभिज्ञ हैं। पिछली सदी के सातवें दशक में हाजी मस्तान के नेतृत्व में भारत की रक्षक-भुजा अनुसूचित जातियों को हिंदुओं से अलग करने की योजना के तहत दलित-मुस्लिम महासंघ बना था। समस्त नक्सलवादी आंदोलन एकमात्र हिंदुओं पर निशाना साधता है जिसका कट्टर वैश्विक वादियों से धन एवं मीडिया बल प्राप्त करने का गठबंधन स्पष्ट है।

ओडिशा में स्वामी लक्ष्मणानंद को ईसाई मतांतरण का विरोध करने के कारण माओवादियों ने ही मारा था। अब जेएनयू में वामपंथी उपद्रवों में उसी षड्यंत्र की गंध है। किसी भी तरह से, हर साधन और विदेशी सहायता से, भारत के नवीन उदय और हिंदू अस्मिता को प्रभावी बनने से रोकना इस गठजोड़ का उद्देश्य है। वे स्वयं को मुस्लिम हितैषी बताने का झूठ बोलते हैं क्योंकि इस षड्यंत्र का मुस्लिमों की भलाई से कोई संबंध नहीं है। भारत विकसित राष्ट्र न बने, विदेशियों पर निर्भर रहे तथा अराजकता में उलझे रहकर कांग्रेस-कम्युनिस्ट के नेतृत्व में यहां शासन चले, यही इनका 'मिशन' है। वरना पाकिस्तान में मुस्लिम संगठनों जैसे लश्करे-झंगवी, सिपाहे-सहाबा, तहरीके तालिबान द्वारा शिया मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए की जाने वाली हत्याओं पर चुप्पी क्यों? बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौजों द्वारा मारे जा रहे बलोच मुसलमानों के दुख पर खामोशी क्यों? चीन में दस लाख उइगर मुस्लिमों को जेल तथा रोजे-कुरान पर विभिन्न प्रतिबंधों की अनदेखी क्यों? सीरिया से लेकर अरब-ईरान तक कुर्द मुसलमानों की निर्दयता पूर्वक होने वाली हत्याओं पर जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ खामोश क्यों? पाकिस्तान की बेसहारा, गरीब मुस्लिम लड़कियों की चीनियों के हाथों विवाह के नाम पर शोषण-विक्रय पर आवाज क्यों नहीं उठाते ये जिहादी, क्योंकि हर उस देश के समर्थन में खामोशी ओढ़ना, जो देश भारत के विरुद्ध है, इन नापाक मिथ्याडंबरी इस्लाम- वाम षड्यंत्र का छुपा उद्देश्य है। आज तक इन लोगों ने कुर्दों, बलोचों, शियाओं, सूफियों तथा बरेलवियों को इस्लामी संगठनों द्वारा मारे जाने पर कभी मोमबत्ती प्रदर्शन नहीं किया, पाकिस्तानी उच्चायोग को विरोध पत्र नहीं दिया, भारत को उन बेचारे मुसलमानों की हमदर्दी में आवाज उठाने हेतु नहीं कहा।

लेकिन जहां हिंदू समाज की आवाज का सवाल उठता है, किसी बहाने, हर झूठ का सहारा लेकर, हर कृत्रिम भय निर्मित कर विरोध किया जाता है, उपद्रव करके देश-विदेश में अपने ही देश की छवि धूमिल की जाती है।

खरी-खरी

ठंडे बस्ते की गर्मी

नंदकिशोर बर्वे

चीजें, बातें या मुद्दे ठंडे बस्ते में जाकर कब गरम हो जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ठंडी जगह में जाकर मुद्दों की तासीर ठंडी हो जानी चाहिए। पर नहीं। ऐसा नहीं होता। इसका कारण ठंडे बस्ते की ही तासीर गर्मी की होती है। इसमें जाकर मुद्दे कब ज्वालामुखी की मानिंद फट पड़ेंगे, कहा नहीं जा सकता। जानकर बताते हैं कि ठंडे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने का काम बस्ते के जन्म के भी पहले से शुरू हो चुका था। जब मुद्दों को ठंडा करने की जरूरत लगी, तब कहीं जाकर बस्ते का जन्म हुआ।

जैसे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने के विशेषज्ञ होते हैं, वैसे ही मुद्दों को ठंडे बस्ते में से निकालकर गर्माने के भी पीएचडी होल्डर हुआ करते हैं। बल्कि कह सकते हैं कि मुद्दे को ठंडे बस्ते से निकालकर गर्मी देने में कहीं अधिक निपुणता की दरकार होती है। इसमें जरा-सी चूक मुद्दे को बासी कढ़ी बना सकती है, जो गरम तो हो सकती है, पर उसमें उबल नहीं आ सकता।

ठंडे बस्ते में डालने व निकालने का खेल रस्साकसी से कम नहीं होता जिसमें कभी किसी का पलड़ा भारी होता है तो कभी किसी का। कभी-कभी मुद्दे ठंडे बस्ते से निकल आदमखोर हो जाते हैं जिन पर काबू पाना शेर को वापस पिंजरे में डालने जैसा होता है।

कुछ लोगों का फुलटाइम जॉब ही ठंडे बस्ते में हाथ डालते रहना और झांकते रहना होता है। वे हमेशा मुद्दे टटोलते रहते हैं। कभी एक मुद्दा उठाते हैं, फिर दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं। इसमें एक के बाद एक कई मुद्दे उनके हाथों में आते और फिसलते रहते हैं।

ठंडा बस्ता भी मुद्दों के अनुसार अपने आकार को एडजस्ट कर लेता है। ठंडा बस्ता कभी भी अनिर्णय की स्थिति में नहीं होता। उसमें जो भी डालो, सबको अपना लेता है।

'आप यहां कब से हैं?' गरम मुद्दे ने ठंडे मुद्दे से पूछा।

'अनंत काल से।' पुराने ठंडे-गार मुद्दे ने ठंडे शब्दों में कहा।

'यहां बहुत ठंडापन है।' नए मुद्दे ने हाथ मसलते हुए कहा।

'धीरे-धीरे आदत हो जाएगी।' ठंडे-गार मुद्दे ने कहा ।

'आपका नाम?' नए ने फिर कुरेदा।

'यहां किसी का कोई नाम या पहचान नहीं होती। जो एक बार आ गया, वह 'ठंडे बस्ते का मुद्दा' नाम से ही जाना जाता है।

ठंडे बस्ते को टटोलने वाला हाथ देख ताजा मुद्दा मुस्करा उठा।

ट्वीट-ट्वीट

'इट इज इकोनॉमिक्स स्टुपिड!' अमेरिकी चुनावों के इस नारे को भारत के हाल के चुनाव नतीजों में पहचानना चाहिए। घर-जमीन, रोजी चुनावी प्रश्न बन गए हैं। चुनावी विमर्श इन्हीं के इर्द-गिर्द बुनना पड़ेगा।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

जहां भारत में कुछ लोग देश की वैश्विक छवि और आर्थिक संभावनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं वहीं विदेशी निवेशकों का नजरिया अधिक संतुलित है। एक अध्ययन में उन्होंने बांड और मुद्रा बाजारों के पैमाने पर अगले साल के लिए भारत को चीन से ऊपर रखा है तो इक्विटीज को लेकर उभरते बाजारों की सूची में भी भारत तीसरे पायदान पर है।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

सीएए में मुसलमानों को न जोड़ने को लेकर सवाल उठाने वाले पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे चाहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान छोड़ दें। अगर ऐसा है तो फिर पाक का वजूद व उसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। दूसरा सवाल कि अगर भारतीय मुस्लिमों की इतनी फिक्र है तो क्या उनके लिए अपनी सीमाएं खोल दोगे? अदनान सामी@AdnanSamiLive

ओमप्रकाश तिवारी
मुंबई ब्यूरो प्रमुख

महाराष्ट्र डायरी

तो तिनके का सहारा बनेगा नोडल अफसर

आजमगढ़ की लालगंज तहसील के रहनेवाले संजय सिंह मुंबई की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं। तनख्वाह इतनी भी नहीं मिलती कि घर का खर्च ठीक से चल सके। ऊपर से गांव की खिटखिट अलग। अक्सर गांव से उनके चाचा का फोन आता रहता है कि पड़ोसी पट्टीदारों ने कभी खेत कब्जा लिया, तो कभी उनके दरवाजे पर अपनी गाय बांधने लगे। दो-चार दिनों की छुट्टी लेकर जाएं भी तो वहां कोई सुननेवाला नहीं। यह समस्या अकेले एक संजय सिंह की नहीं है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से निकलकर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली में रह रहे उन सभी प्रवासियों की है, जो रोजी-रोटी की तलाश में अपना पुश्तैनी घर छोड़कर परदेश में जा बसे हैं। उनकी अचल संपत्तियों को लावारिस जान पड़ोसी-पट्टीदार और कभी-कभी तो सगे चाचा और भाई ही कब्जा जमाने लग जाते हैं। गांव में चलती भी उन्हीं की है, क्योंकि वहां के लोगों और व्यवस्था से वही परिचित होते हैं।

उत्तर प्रदेश मूल के मुंबई में रह रहे लोगों की आबादी लगभग 30 फीसद यानी 40 लाख के करीब है। ठाणे, नासिक, पुणे आदि शहरों को जोड़ लिया जाए तो यह 50 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। यही हाल गुजरात का भी है। गोवा में भी कई व्यवसायों पर इसी वर्ग का वर्चस्व है। इन सबकी समस्या वही संजय सिंह वाली है। ज्यादातर के गांव-घर में कोई न कोई झगड़ा चलता रहता है, और वे अपना धंधा-रोजगार छोड़कर उसे सुलझाने वहां नहीं जा सकते। ऐसे लोगों की लंबे अर्से से मांग रही है कि मुंबई में उत्तर प्रदेश सरकार अपना एक निवासी आयुक्त नियुक्त करे, जो उनकी समस्याएं यहीं बैठे-बैठे सुलझा सके। गांव गए बगैर उनकी समस्याओं का निदान हो जाए। मुंबई में 'अभियान' नामक सामाजिक संस्था के जरिये करीब 30 साल से उत्तर प्रदेश

राम नाईक।

दिवस मना रहे अमरजीत मिश्र काफी समय से यह मांग उठाते रहे हैं। मुंबई भाजपा का महासचिव बनने के बाद भी वह यह मांग उठाते रहे। वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों के बीच काम करनेवाली संस्था उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम भी यह मांग उठाती रही है। दो साल पहले हुए उत्तर प्रदेश सरकार के इन्वेस्टर्स समिट से पहले उसके मुंबई और अहमदाबाद के रोड शो के दौरान तो यूपीडीएफ यह कहते हुए इस मांग पर जोर डालता रहा कि मुंबई में बैठनेवाला उत्तर प्रदेश का निवासी आयुक्त प्रदेश के लिए वाणिज्यिक दूत का काम कर सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा में रहनेवाले उत्तर प्रदेश मूल के उद्यमियों एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच यह एक सेतु का काम करते हुए इन उद्यमियों को अपने गांव-जिले में निवेश के लिए प्रेरित कर सकता है।

लेकिन इस मांग को पंख तब लगे, जब मुंबई के भाजपा नेता राम नाईक को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। 'राम भाऊ' के नाम से मशहूर राम नाईक के चुनाव क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश मूल के लोगों की संख्या कम नहीं है। उनके विधायक और सांसद रहते हुए अक्सर उनके पास अपने गांव-घर की समस्या लेकर लोग पहुंचते रहे हैं। उनसे अपने जिले के अधिकारी या नेता को फोन करवाते रहे हैं। इसलिए राम भाऊ इस वर्ग की समस्याओं को बखूबी समझते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने के पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस समस्या पर चर्चा की तो योगी को भी समस्या की गंभीरता का अहसास हुआ। लिहाजा महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनाव प्रचार यात्रा की अंतिम सभा में योगी ने राम भाऊ की ही उपस्थिति में यहां एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का वादा कर दिया था। पिछले सप्ताह ही यह वादा पूरा भी हो गया, जब दिल्ली के उत्तर प्रदेश पर्यटन कार्यालय में कार्यरत उपनिदेशक स्तर के एक अधिकारी को मुंबई में उत्तर प्रदेश मूल के लोगों की समस्याएं सुलझाने वाले नोडल अधिकारी के रूप नियुक्त कर दिया गया।

लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह काम एक अधिकारी के वश का तो कतई नहीं है। राम भाऊ का तो स्पष्ट मानना है कि यह अधिकारी आइएएस से ऊपर यानी सचिव स्तर का होना चाहिए, ताकि उसके लिखे हुए आदेश की उत्तर प्रदेश के संबंधित विभाग में कुछ सुनवाई हो सके। वास्तव में नोडल अफसर की नियुक्ति की खबर फैलते ही मुंबई के अधिकारी के कार्यालय में बड़ी पंचायत जुटनी शुरू हो जाएगी। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास पहुंचेंगे। जबकि उसके पास बुनियादी ढांचा शून्य ही होगा। ज्यादातर लोगों की समस्याएं गृह विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधित होती हैं। इसलिए कम से कम लखनऊ स्थित इन दो विभागों में तो ऐसे कुछ अधिकारी सिर्फ इसी काम के लिए चिह्नित करने होंगे, जिन तक मुंबई स्थित नोडल अधिकारी यहां के लोगों के आवेदन भेजकर समय-समय पर उनसे उसकी प्रगति की भी जानकारी ले सकें। अभी यह नोडल अधिकारी दक्षिण मुंबई स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के कार्यालय में बैठ रहा है। भविष्य में उसके लिए अतिरिक्त स्टाफ के साथ नई मुंबई स्थित उत्तर प्रदेश भवन में व्यवस्था करनी होगी। इस अधिकारी के कार्यालय को गुजरात और गोवा में रहनेवाले उत्तर प्रदेश मूल के लोगों से भी संबद्ध करना चाहिए, ताकि वहां के लोग भी अपने गांव की समस्याओं का समाधान करवा सकें।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या प्रमुख देशों के चतुष्कोणीय टूर्नामेंट से वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ेगी?

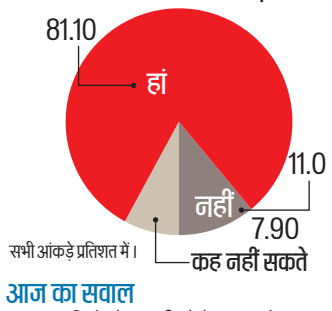

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या उपद्रवियों से वसूली जैसे कदम से उपद्रव की घटनाओं पर अंकुश लगेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y**, **N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

कंधे औरों के चढ़ी उछल रही कांग्रेस,
सत्ता का सुख भोगती बदल-बदल कर भेष।
बदल-बदल कर भेष उड़ाए स्वयं मलाई,
उद्धव अरु सोरेन बने उसकी परछाई।
ले औरों का साथ चलाती अपने धंधे,
होते इस्तेमाल कई दल देकर कंधे।
– ओमप्रकाश तिवारी

चिंताजनक

कोयला जनित प्रदूषण पर पाबंदी

अभिजीत
शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की भयावहता में कोयला का भी बड़ा योगदान है। इसे हमें समग्रता से समझना होगा और इस पर पाबंदी भी लगानी होगी

पिछले माह दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर चरम पर था। हालांकि अनेक संबंधित विशेषज्ञों, संगठनों द्वारा इसके विभिन्न कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण कोयला दहन भी है, जिसे शायद अब तक अनदेखा किया जाता रहा है। दरअसल वायु प्रदूषण में कोयले के योगदान का प्रभाव हाल में चर्चा का विषय तब बना जब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने एक कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली- एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने लिए कोयला का प्रयोग पूर्णतः बंद करना होगा। उन्होंने चीन के शहर बीजिंग का उदाहरण देते हुए कहा कि वह इसलिए प्रदूषण मुक्त हो पाया, क्योंकि वहां कोयला बिल्कुल नहीं जलाया जाता है।

दिल्ली में कोयला से होने वाला प्रदूषण एक ऐसा कारण है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमें नहीं लगता कि यह एक बड़ा कारण है और हम बस खेतों में पराली जलाने, गाड़ियों और निर्माण स्थलों से पैदा होने वाले प्रदूषण को ही केंद्र में रख कर सोचते हैं, इसीलिए हम जब उपाय भी सोचते हैं तो इन्हीं कारणों के रोकथाम के इर्दगिर्द सोचते हैं।

कोयला को जलाने से कई प्रकार के टॉक्सिन और अन्य तत्व जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड इत्यादि पर्यावरण में जाते हैं और यह लोगों में अस्थमा, कैंसर, सांस लेने में तकलीफ, दिमाग को नुकसान जैसी कई परेशानियां पैदा करता है। भारत सरकार ने महानगरों में हवा की गुणवत्ता जानने के लिए सफर नाम से एक पहल की शुरुआत की है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। सफर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 और 2018 के बीच दिल्ली में प्रदूषण के ट्रेंड में काफी बदलाव आ गया है। दिल्ली के वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले 26 कारण हैं जिसमें परिवहन व्यवस्था और निर्माण स्थल के अलावा कोयला प्रमुख रूप से शामिल है। प्रदूषण के 25 फीसद कम होने के दावों पर सफर का कहना है कि आठ सालों में यह प्रदूषण 15 फीसद बढ़ गया है जिसका कारण परिवहन, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन से होने वाले प्रदूषण में वृद्धि है।

अगर हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते हैं तो कोयला एक महत्वपूर्ण कारण है जिस पर नियंत्रण की जरूरत है। आज दिल्ली में कोयले का उपयोग बिजली के उत्पादन, ढाबों और रेस्टोरेंट के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में भोजन बनाने, खासकर तंदूर के रूप में और उद्योगों में हो रहा है। बिजली उत्पादन की बात करें तो दिल्ली में दो कोयला द्वारा संचालित बिजली उत्पादन संयंत्र हैं जिसमें से एक बदरपुर संयंत्र को पिछले साल अक्टूबर में बंद कर दिया गया था। वहीं अभी भी दिल्ली के आसपास कोयला द्वारा संचालित दस बिजली उत्पादन संयंत्र हैं जिनका प्रभाव दिल्ली पर सीधे तौर पर पड़ता है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2015 में ऐसे सभी संयंत्रों को निर्देश दिया जिसके अंतर्गत उनको कार्बन उत्सर्जन घटाने को कहा गया, लेकिन उद्योगों ने उसके लिए खर्च और बाकी विषयों पर चिंता के कारण समयसीमा को बढ़ा कर दिसंबर 2022 कर दिया। इसी साल के शुरू में ऊर्जा मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि दिसंबर तक सभी संयंत्रों को आदर्श स्थिति में कर दिया जाएगा, लेकिन केंद्रीय बिजली प्राधिकरण के अनुसार इन दस इकाइयों में से आठ ने अभी तक प्रदूषण कम करने वाले उपकरणों को लगाना तो दूर उनके खरीद को लेकर उतना ठोस कदम नहीं उठाया है ताकि उनके इस समयसीमा में इस दिशा में कुछ सकारात्मक हो।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार दिल्ली के 300 किमी के दायरे में ऊर्जा इकाइयां करीब 13.2 गीगावॉट बिजली उत्पन्न करती हैं, और ये इकाइयां प्रतिदिन करीब 57 टन पर्टिकुलेट मैटर, 686 टन सल्फर डाइऑक्साइड और 304 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन करती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास 300 से ज्यादा ईंट भट्ठे हैं जिनमें कोयला का इस्तेमाल होता है। अगर प्रदूषण की बात करें तो करीब 3,000 से ज्यादा उद्योगों की वायु प्रदूषण में हिस्सेदारी 18 फीसद के लगभग है। जब भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस आपात स्थिति में कोयला का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन शेष समय में ये काम करते हैं जिससे काफी मात्रा में प्रदूषण होता है।

कोयला के इतने दुष्परिणाम होने के बावजूद भी इसको लेकर नीति या सख्ती नहीं दिखती। कोयला का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को लेकर हमारी सरकारों को एक समग्र नीति बनाने की जरूरत है। जहां एक ओर बड़े उद्योगों को उत्सर्जन कम करने वाले उपकरणों को खरीदने और लगाने के लिए बाध्य करना होगा वहीं छोटे उद्योगों को इसके लिए जो भी संभव मदद हो वह करना होगा, क्योंकि छोटे उद्योग इतने सक्षम नहीं है कि खुद से इस दिशा में काम कर सकें। साथ ही बिजली के लिए कोयला द्वारा संचालित उत्पादन संयंत्रों की जगह दिल्ली में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार ने इस क्षेत्र में काम भी किया है और इस दिशा में निर्धारित समयसीमा के पहले सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है।

उपरोक्त तमाम प्रयासों के अलावा एक बात पर हमें पूरा जोर देना होगा कि कम से कम महानगरों में और उसके आसपास के इलाकों में तो कोयले के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी होनी ही चाहिए ताकि मानवता के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रही वायु प्रदूषण की समस्या से समय रहते निपटा जा सके।

3 देश बचे हैं दुनिया में जहां पोलिया को खत्म नहीं किया जा सका है। इनमें पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान का नाम शामिल है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 27 दिसंबर 2019

झारखंड

सकारात्मक राजनीति का भरोसा

झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। रघुबर दास ने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में बीते पांच सालों तक शासन किया, लेकिन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी, लिहाजा भाजपा को राज्य की सत्ता से वंचित होना पड़ा है। अब नई सरकार अपनी पारी शुरू करने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले अधिक मत प्राप्त हुआ है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में सीटों का जो हिसाब-किताब है उसके मुताबिक सीटों की संख्या के मामले में वह पिछड़ गई और महागठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका है। ऐसे में भाजपा को अपनी हार पर भी गंभीरता से मंथन करना होगा। फिलहाल चुनाव बीतने के साथ ही राज्य में सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू होना चाहिए। और उम्मीद भी कुछ इस तरह से की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष से नेता सदन की भूमिका में आए हेमंत सोरेन ने सकारात्मक भाव से काम करने और सबको साथ लेकर राज्य को दिशा देने का भरोसा दिलाया है।

झारखंड विधानसभा चुनावों में महागठबंधन को बहुमत मिला है और उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य नए सिरे से आगे बढ़ेगा

वहीं, सत्ताधारी दल से विपक्ष की भूमिका में आई भारतीय जनता पार्टी ने भी विकास के मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने का वादा किया है। हमें आशा करनी चाहिए कि दोनों ही पक्ष अपनी इस भूमिका का निर्वाह करते हुए राज्य को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि राजनीति नकारात्मक चोला उतारे। सत्ता पक्ष पूरी ईमानदारी से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाएं पहुंचाए और विपक्ष उसे दिशा दिखाए। विपक्ष की भूमिका सिर्फ सरकार की आलोचना तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए।

विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार दोनों ही पक्ष ने कटुता की सीमा को लांघा। चुनाव में आरोप-प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद माहौल बदलना चाहिए। ये बातें दलों के शीर्ष नेताओं के साथ-साथ निचले स्तर तक के नेताओं को भी समझनी चाहिए। सत्ता निजी हित और स्वार्थ साधने का हथियार नहीं है। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से तल्खी बढ़ती है और इससे विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। जिसे जनता ने जो आदेश दिया है, उसका पालन किया जाना चाहिए। हम सभी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता ने जिन्हें चुना है उस सरकार के कामकाज का आकलन किए बगैर उसे कैसे खारिज किया जा सकता है। आखिर सबका लक्ष्य झारखंड का विकास है। पिछड़ा राज्य होने के कारण नई सरकार के समक्ष तमाम चुनौतियां भी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना के साथ-साथ कृषि और अंतिम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। पिछली सरकार ने राज्य के विकास को एक दिशा दी थी, हम आशा करते हैं कि नई सरकार उन विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएगी और उससे बड़ी लकीर खींचेगी। जनादेश बदलाव के पक्ष में आया है और हमें भी यह भरोसा बनाए रखना होगा कि झारखंड बदलेगा और जल्द ही विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा।

पश्चिम बंगाल

व्यवस्था पर सवाल और वीजा विवाद

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के पुस्तकालय सेवा व जनशिक्षा मंत्री तथा जमीयत-ए-उलेमा हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी को बांग्लादेश ने वीजा नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि सिद्दीकुल्लाह ने हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी कि अगर इसे तुरंत वापस नहीं लिया गया तो उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर कदम रखने नहीं देंगे। अमित शाह को रोकने का एलान करने वाले मंत्री अब अपनी दिक्कतों का रोना रो रहे हैं। वह जिस गति से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे थे उसी गति में उन्हें बांग्लादेश ने झटका दिया है। मंत्री का कहना है कि उन्होंने वीजा की पूरी प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन बांग्लादेश के अधिकारियों ने उन्हें वीजा देने से इन्कार कर दिया।

दरअसल भारतीय व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करने वाले इस मंत्री ने बांग्लादेश के वीजा के लिए दस दिन पहले ही आवेदन किया था जबकि जानकारों का कहना है कि अर्जी डाले जाने के दो तीन दिन बाद ही वीजा मिल जाता है। आखिर बांग्लादेश ने चौधरी को क्यों नहीं वीजा दिया? जबकि वह नियमों का पालन करते हुए विमान का टिकट भी खरीद चुके थे और अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। वह गुरुवार को बांग्लादेश पहुंचकर 31 दिसंबर को स्वदेश लौटने वाले थे। अब वह अपनी आर्थिक क्षति की पीड़ा बयां कर रहे

सिद्दीकुल्लाह चौधरी

हैं और यह भी जता रहे हैं कि बांग्लादेश ने उन्हें वीजा न देने का कारण भी नहीं बताया है। वैसे कहा यही जा रहा है कि तकनीकी वजहों से मंत्री को वहां जाने का वीजा नहीं मिला, लेकिन मौके-बे-मौके उनके तीखे तीर चलाने की अदा से वाकिफ आवाम को हैरत है कि वह बांग्लादेश के बारे में कुछ तीखा क्यों नहीं बोल रहे हैं। अपने देश में तो वह नाफरमानी की आवाज बुलंद करने में पीछे नहीं रहते हैं। अभी भी लोग-बाग भूले नहीं जब उन्होंने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने से इन्कार कर दिया था। मंत्री को वीजा न देने का राजफाश बांग्लादेश हाईकमीशन ही करेगा, क्योंकि मंत्री तो खुद यह बता चुके हैं कि उन्हें वीजा नहीं मिला। वीजा क्यों नहीं मिला, इसको लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। उन्होंने अपनी पांच दिवसीय यात्रा में अपने कुछ निजी कार्यक्रम भी बना लिए थे। अब उनकी यात्रा पर रोक लग गई है। बंगाल की सियासत में वीजा का विवाद एक नया मुद्दा बन सकता है। खासकर यह देखते हुए कि ममता सरकार सीएए और नागरिकता रजिस्टर को लेकर केंद्र के खिलाफ तीखा मोर्चा खोले हुए है। दरअसल इस मामले में सबसे अधिक राजनीतिक रार बंगाल में ही देखी जा रही है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी इस मामले में केंद्र सरकार से आर-पार के मूड में हैं। बंगाल में ये मामले में जबरदस्त सियासत का विषय बने हुए हैं। वैसे तो पिछले काफी समय से बंगाल सरकार और केंद्रीय सत्ता के बीच खींचतान का सिलसिला चल रहा है, लेकिन सीएए और नागरिकता रजिस्टर को लेकर यह खींचतान कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ममता को लगता है कि इसके सहारे वह अपने वोट बैंक को और मजबूत कर सकती हैं, जबकि भाजपा राज्य में अपनी जड़ें और मजबूत करना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बंगाल में जिस तरह की सफलता हासिल हुई है उसे देखते हुए पार्टी की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। भाजपा भी इस राज्य में अपनी ताकत बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ती जा रही है।

उत्तराखंड

आयुष्मान योजना की प्रगति

उत्तराखंड में चलाई जा रही अटल आयुष्मान योजना में अभी तक की प्रगति निश्चित रूप से उत्साहजनक है। इस योजना के जरिये गरीबों को खासा लाभ मिल रहा है। बावजूद इसके पर्वतीय क्षेत्रों में इसका पूरी तरह लाभ न मिल पाना चिंताजनक है। अभी भी योजना के कड़े मानकों के चलते कई लोगों के गोल्डन कार्ड नहीं बन पाए हैं, जिससे इन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को एक वर्ष पूर्व लागू किया गया था। इस अवधि में अभी तक 34.70 गोल्डन कार्ड बनाए जा जा चुके हैं। एक साल में 1.10 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया गया है, जिस पर सरकार ने 105 करोड़ रुपये खर्च किए।

प्रतीकात्मक

सरकार का लक्ष्य प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार एक करोड़ गोल्डन कार्ड बनाने का है। गोल्डन कार्ड की संख्या की बात करें तो उत्तराखंड देश भर में केरल के बाद सबसे अधिक कार्ड बनाने वाला राज्य बन गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने इस योजना का प्रचार प्रसार भी किया। यदि कोई अच्छा कार्य किया गया है तो ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन एक बार फिर पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी सुस्त रफ्तार चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है। बात सिर्फ गोल्डन कार्ड बनाने की नहीं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को विकसित करने की भी है। यहां विभिन्न स्वास्थ्य जांच की पूरी व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को मैदानी क्षेत्र के अस्पतालों में ही इलाज के लिए आना पड़ता है। इस पर उनका खासा पैसा खर्च होता है। इस कारण इस योजना का उद्देश्य कहीं न कहीं प्रभावित दिख रहा है।

यदि पर्वतीय क्षेत्रों में जांच की पूरी सुविधाएं विकसित हो जाएं तो मर्ज की शुरुआत में ही पहचान की जा सकती है और उसे बड़ी बीमारी बनने से पहले ही ठीक किया जा सकता है। यही एक कारण भी है कि पर्वतीय क्षेत्रों से जो मामले बड़े अस्पतालों तक आते हैं, वे गंभीर बीमारियों के होते हैं। इस कारण इसमें खर्च भी ज्यादा होता है। इस दिशा में गंभीरता से मंथन किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में निजी अस्पताल व जांच लैब खोलने के लिए प्रयास करने होंगे।

सरकार को चाहिए कि वह पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक जांच उपकरण लगाए और इसके लिए स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कोर्स संचालित किए जाएं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी तेजी से कदम उठाने होंगे। सेहत के मोर्चे पर सरकार को हरसंभव कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से तमाम समस्याएं मौजूद हैं और इनका नतीजा यह है कि लोगों को जिस तरह की सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। सेहत के ढांचे में बुनियादी बदलाव समय की मांग है। केवल इक्का-दुक्का कामों से बात बनने वाली नहीं है। न केवल अस्पतालों की दशा सुधारने की जरूरत है, बल्कि उनमें पर्याप्त डाक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।

बिहार

एईएस बीमारी पर अंकुश की कवायद

बिहार में लगभग प्रत्येक वर्ष एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) नामक बीमारी से बड़ी तादाद में बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। इस वर्ष भी मुजफ्फरपुर में इस बीमारी से सौ से भी अधिक बच्चों का निधन हो गया था। बच्चों के स्वास्थ्य के लिहाज से यह मामला संवेदनशील बन चुका है। इस वर्ष तो यह मामला इतना अधिक तूल पकड़ चुका था कि देश भर में बिहार सरकार और खास तौर पर नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि इस बीमारी से बचाव के लिए वर्षों से कवायद की जा रही थी, लेकिन मुकम्मल उपाय नहीं हो पा रहा था। ऐसे में बिहार सरकार ने एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से प्रभावित परिवारों को तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इससे बचाव, उपचार और जागरूकता के लिए मोबाइल वाणी नामक एप जारी कर एक अच्छी पहल की है।

इस कवायद से यह साफ होता है कि सरकार इस खतरनाक बीमारी से हर स्तर पर लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने एईएस प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की तथा उनकी समस्याओं को जानने के बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित दो परिवारों को ठेला पर सब्जी व चाय की दुकान के लिए 25-25 हजार रुपये के मुद्रा लोन का चेक भी सौंपा। जाहिर है कि सरकार चाहती है कि वे व्यवसाय कर बेहतर जीवन जी सकें। राज्य सरकार इसके लिए सामाजिक सर्वेक्षण भी करा चुकी है। सच तो है कि यह बीमारी बिहार के लिए अभिशाप बन चुकी है। पहले तो तिरहुत प्रमंडल का इलाका ही इससे प्रभावित होता था, लेकिन अब दूसरे कई इलाकों में इसके मरीज पाए जाने लगे हैं। हर साल गर्मी शुरू होने के साथ ही इसका प्रकोप बढ़ता है। लोग जब तक कुछ समझ पाते हैं तब तक स्थिति भयावह हो जाती है और अंततः अस्पताल की देहरी पर पहुंचने के साथ ही बच्चों के जीवन की डोर टूट जाती है। एईएस या चमकी बुखार के लक्षण और स्पष्ट कारण को जानने के लिए सरकार ने काफी कोशिश की, लेकिन अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। लेकिन एक बात जाहिर हो चुकी है कि इस बीमारी का हद तक गरीबी से लेना-देना है।

एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) को नियंत्रित करने के लिए जनजागरूकता अभियान की मॉनीटरिंग भी करनी होगी ताकि फिर किसी मां की गोद सूनी न हो सके

कुपोषण के शिकार बच्चे जल्दी इसकी चपेट में आते हैं। इसी कड़ी में सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए मोबाइल वाणी लांच किया है जिसके जरिये जीविका दीदी लोगों के बीच जागरूकता फैलाएंगी। सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन मकसद में कामयाबी तो तभी मिलेगी जब एईएस प्रभावित परिवारों के सामाजिक सर्वेक्षण के आलोक में तय की गई कार्ययोजना को ईमानदारी से अमल में लाया जाएगा। इसके लिए बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) का टीका लगाने के काम को मुस्तैदी से पूरा करना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एईएस की रोकथाम में जेई वैक्सीन कारगर है। जिन बच्चों को जेई के टीके दिए गए वे एईएस की चपेट में नहीं आए। अच्छा होगा कि ऐसी स्थिति फिर न आए।

डाटागीरी

महिला अपराध के आरोपित जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी

महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपित जनप्रतिनिधियों से संबंधित एक रिपोर्ट बीते दिनों एडीआर ने जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसे आरोपित जनप्रतिनिधियों की संख्या में इजाफा हुआ है और ये सभी राजनीतिक दलों द्वारा टिकट पाने में सफल भी रहे हैं।

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

2009 से 2019 तक के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपित उम्मीदवारों की संख्या में 231 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच के विश्लेषण के अनुसार, ऐसे आरोपितों के सांसदों के रूप में निर्वाचित होने की संख्या भी नौ गुना बढ़ गई है।

एडीआर ने कुल 4,896 जनप्रतिनिधियों (776 सांसदों और 4,120 विधायकों) में से 4,822 के चुनावी हलफनामों (759 सांसदों और 4,063 विधायकों) का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि 76 सांसदों और विधायकों ने हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों का जिक्र किया है। इनमें से 18 सांसद हैं और 58 विधायक हैं। पिछले पांच सालों में लोकसभा और राज्यसभा के उम्मीदवारों के 572 ऐसे मामले सामने आए हैं। इनमें से किसी को भी अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। इनमें से 410 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा टिकट दिया गया था, जबकि शेष 162 स्वतंत्र उम्मीदवार थे।

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के 21 सांसद और विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपित हैं। वहीं, कांग्रेस के 16 सांसदों पर इस तरह के मामले दर्ज हैं। वहीं, तीसरे नंबर पर वाइएसआर कांग्रेस है। उसके सात सांसदों पर महिला अपराध के मामले दर्ज हैं। इसके बाद बीजद छह और तृणमूल कांग्रेस के पांच सांसद और विधायक हैं। पिछले पांच वर्षों में भाजपा ने ऐसे 66, कांग्रेस ने 46, बसपा ने 40, सीपीआइ (एम) ने 15, शिवसेना और समाजवादी पार्टी ने 13-13 उम्मीदवारों को टिकट दिया है।

राज्यों के मामले में बात करें तो महिलाओं के खिलाफ घोषित अपराध के बंगाल (16) में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक हैं। उसके बाद ओडिशा और महाराष्ट्र में 12, आंध्र प्रदेश (8), तेलंगाना (5) और मध्य प्रदेश (3) हैं। पिछले पांच वर्षों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र (84) में सबसे अधिक ऐसे उम्मीदवार हैं, उसके बाद बिहार में 75 और बंगाल में 69 उम्मीदवार हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा टिकट दिए गए थे।

वर्षवार बढ़े आंकड़े

महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपित सांसद पद के उम्मीदवार	
2009	38
2014	62
2019	126
महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपित सांसद	
2009	2
2014	2
2019	18
महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपित सांसद और विधायक	
कुल	76
भाजपा	28 प्रतिशत
कांग्रेस	21 प्रतिशत
वाइएसआर कांग्रेस	9 प्रतिशत
बीजद	8 प्रतिशत
तृणमूल कांग्रेस	7 प्रतिशत
अन्य	27 प्रतिशत
महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपित सांसद और विधायक पद के प्रत्याशी	
कुल	572
भाजपा	11 प्रतिशत
कांग्रेस	8 प्रतिशत
बसपा	7 प्रतिशत
निर्दलीय	28 प्रतिशत
अन्य	46 प्रतिशत

कौन-कौन से अपराध शामिल

एडीआर ने महिला अपराधों में जिन अपराधों को शामिल किया गया है उनमें दुष्कर्म, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, छेड़खानी आदि हैं।

झारखंड में जिन क्षेत्रों में महिला वोटर ज्यादा, वहां भाजपा हारी

81 में एक दर्जन सीटों पर पुरुषों से अधिक थी महिला वोटर, इन पर खराब रही भाजपा की स्थिति

नीरज अग्रवाल, रांची

झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में एक दर्जन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पुरुष मतदाताओं से अधिक महिलाएं थीं। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक को छोड़कर सभी में भाजपा की हार हुई है। इनमें से दो सीटें लंबे समय से भाजपा के खाते में थीं, लेकिन ये दोनों भी इसके हाथ से निकल गईं। इस विधानसभा चुनाव में 12 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों से अधिक महिला मतदाताएं थीं। इनमें एक खूंटी को छोड़कर सभी सीटों पर भाजपा की हार हुई। इनमें से पोटका और सिमडेगा दो ऐसी सीटें हैं, जो लंबे समय से भाजपा के कब्जे में थी। पोटका से मेनका सरकार लगातार जीत हासिल कर रही थीं, लेकिन इस बार वह अपना सीट नहीं बचा सकीं।

झामुमो के संजीव सरदार ने उन्हें 43 हजार से अधिक वोट से हराया। यही हाल सिमडेगा में हुआ। पार्टी ने यहां अपना प्रत्याशी बदल दिया था। यहां कांग्रेस के भूषण बाड़ा ने भाजपा प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा को नजदीकी मुकाबले में महज 285 वोट से हराया। यह इस विधानसभा चुनाव की सबसे छोटी जीत है।

महिला बहुल सीटों पर महज एक महिला जीती

महिला वोटर बहुल इन बारह विधानसभा क्षेत्रों में महज एक महिला प्रत्याशी जोबा मांझी (मनोहरपुर) को जीत हासिल हुई, जबकि एक महिला प्रत्याशी (मेनका सरदार) की परंपरागत सीट छिन गई।

इसी तरह, भाजपा की घाटशिला, खरसावां, चाईबासा, मनोहरपुर तथा मझगांव में जीत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। इन पांचों सीटों पर झामुमो का पहले से कब्जा था। इस बार भी पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखते हुए भाजपा के प्रत्याशियों को हराया। चाईबासा में पूर्व आइएएस जेबी तुबिद को इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। वहीं, चक्रधरपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ही हार गए। इस सीट पर भी झामुमो का कब्जा बरकरार रहा।

हालांकि उसके तत्कालीन विधायक शशिभूषण सामड टिकट नहीं मिलने पर बाबूलाल मरांडी के खेमे में चले गए थे। इसी तरह, संताल प्रमंडल के भी तीन विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे, जहां पुरुषों से अधिक महिला वोटर थीं। इन तीनों सीटों पर भी भाजपा की हार हुई। इनमें से दो सीटें शिकारीपाड़ा और महेशपुर में झामुमो तथा लिट्टीपाड़ा में झाविमो अपनी सीट बचाने में सफल रहा।

कहां कितने मतदाता और किस दल के प्रत्याशी जीते

सीट	पुरुष वोटर	महिला वोटर	विजयी पार्टी
घाटशिला	1,20,854	1,21,618	झामुमो
पोटका	1,43,394	1,44,377	झामुमो
खरसावां	1,03,717	1,05,071	झामुमो
चाईबासा	1,02,031	1,04,820	झामुमो
मझगांव	94,085	98,575	झामुमो
मनोहरपुर	98,482	98,855	झामुमो
चक्रधरपुर	90,680	90,763	झामुमो
खूंटी	1,03,910	1,06,103	भाजपा
सिमडेगा	1,12,074	1,13,491	कांग्रेस
लिट्टीपाड़ा	98,306	1,01,482	झाविमो
महेशपुर	1,07,979	1,08,486	झामुमो
शिकारीपाड़ा	1,03,521	1,05,022	झामुमो

सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने देश में राज्यों के शासन का आकलन करने वाला सुशासन सूचकांक (जीजीआइ) जारी किया है। इसमें राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है- बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें समग्र रैंकिंग के अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में भी राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। समग्र रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी पहले स्थान पर है।

सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश और झारखंड का स्थान है। जबकि पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। उसके बाद उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी अव्वल रहा। उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप हैं।

कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र

इस सेक्टर में बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश पहले, राजस्थान दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। जबकि पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन एवं दीव अव्वल रहा।

जन स्वास्थ्य क्षेत्र

इस मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल पहले, तमिलनाडु दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर रहा। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी पहले स्थान पर रहे।

सामाजिक कल्याण एवं विकास क्षेत्र

इस सेक्टर में बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन एवं दीव पहले स्थान पर हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र

इस क्षेत्र में बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर रहे।

सार्वजनिक ढांचागत क्षेत्र

इस सेक्टर में बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु पहले, गुजरात दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर रहा। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ अव्वल रहे।

न्यायिक एवं जन सुरक्षा क्षेत्र

इस सेक्टर में बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु पहले, केरल दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर हैं। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी पहले स्थान पर हैं।

मानव संसाधन विकास क्षेत्र

इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में गोवा, पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी पहले स्थान पर हैं।

आर्थिक शासन क्षेत्र

इस मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले, महाराष्ट्र दूसरे, तेलंगाना तीसरे, गुजरात चौथे और तमिलनाडु पांचवे स्थान पर है। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने पहला स्थान पाया है।

पर्यावरण क्षेत्र

इस मामले में बड़े राज्यों में बंगाल पहले, केरल दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ अव्वल हैं।

कृषि की गुड गवर्नेंस रैंकिंग में बिहार ने हरियाणा को पछाड़ा

राज्य ब्यूरो, पटना : कृषि से संबंधित गुड गवर्नेंस (सुशासन) की रैंकिंग में बिहार ने हरियाणा को पछाड़ दिया है। भले ही कृषि की इस रैंकिंग में बिहार को पहला स्थान नहीं मिला, लेकिन उसने हरियाणा जैसे प्रदेश को पीछे कर यह जता दिया है कि बिहार के किसान चाहे तो यहां की तस्वीर कभी भी बदल सकती है।

गवर्नेंस पर राज्यों की ताजा रैंकिंग में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के मामले में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। राजस्थान क्रम में दूसरे स्थान पर है, जबकि बिहार और हरियाणा के बीच हुए मुकाबले में बिहार ने हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। बिहार को चौथा और हरियाणा को रैंकिंग में पांचवां स्थान मिला है। कार्मिक मंत्री जीतेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस के मौके पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स लांच किया। मोदी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर के मौके पर भारत में सुशासन दिवस मनाने का एलान किया था।

अटल भूजल योजना में पंजाब को शामिल करने को कैप्टन ने लिखा पीएम को पत्र

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भूजल संरक्षण के लिए 6000 करोड़ रुपये वाली 'अटल भूजल योजना' में पंजाब को भी शामिल करने की मांग की है। अपने पत्र में पंजाब को इस स्कीम से बाहर रखने की मीडिया रिपोर्टों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश देने की अपील की है।

पंजाब में भूजल के गिरते स्तर के बाद भी उसे इस योजना में शामिल न करने पर कैप्टन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा राज्य के 22 जिलों में से 20 जिले भूजल के गिरते स्तर की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस साल के शुरू में इन जिलों का दौरा करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करके जिम्मा सौंपा गया था। सेंट्रल ग्राउंडवाटर बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के तीन चौथाई से ज्यादा ब्लॉकों को पानी की किल्लत से प्रभावित घोषित किया गया है, जिनमें कुछ की स्थिति काफी नाजुक है।

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पंजाब को देश की अनाज सुरक्षा को यकीनी बनाने में प्राकृतिक संसाधनों की काफी कीमत चुकानी पड़ी है। इस आधार पर जल संरक्षण के लिए तत्काल मदद को पंजाब का मजबूत केस बनता है। पहले भी उन्होंने केंद्र से मदद की अपील की थी।

योजना में ये राज्य हैं शामिल : केंद्र ने अटल भूजल योजना के लिए सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश का चयन किया है। इन राज्यों में पड़ते पानी की किल्लत वाले 8350 गांवों में यह योजना लागू करने का प्रस्ताव है।

दैनिक जागरण

सबरंग

प्लान वीकेंड के

नई दिल्ली, शुक्रवार, 27 दिसंबर 2019

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com

https://www.facebook.com/jagransabrang/

पानी में घुलकर खिल उठते हैं रंग

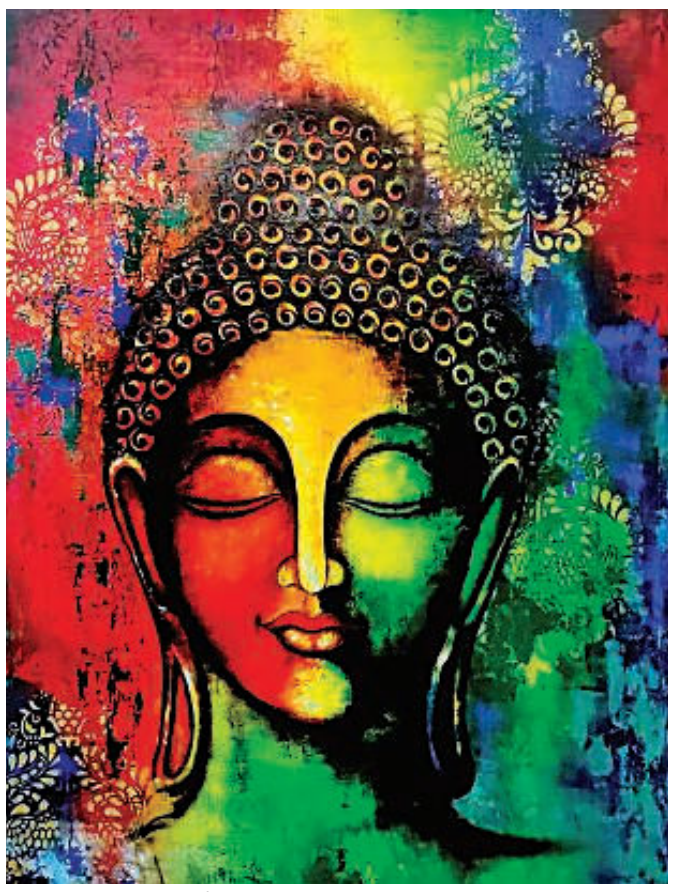

कलाकार मोहित भारद्वाज ने जब कैनवस पर अपनी भावनाएं उकेरीं तो कलाकृति ऐसे जीवंत हो उठी मानों बोल पड़ेगी। सौजन्य-आयोजक

रंगों की अभिव्यक्ति

प्रेम, प्रकृति और मानवीय भावनाओं की अद्भुत अभिव्यक्ति, रंगों का ऐसा समायोजन कि हर कदम ठहर जाएं। गुरु-शिष्य की इस जुगलबंदी में आधी आबादी का संघर्ष है तो शृंगार रस की भी कमी नहीं। कला के विविध आयामों से भी रूबरू होंगे। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसायटी में आयोजित हो रही कला प्रदर्शनी में करीब सौ से ज्यादा पेंटिंग्स के जरिये दर्शक जीवन के विविध रंगों को देख और जान पाएंगे।

गुरु-शिष्य जुगलबंदी का 'आलेख्य' : यहां केवल पेंटिंग ही नहीं, स्कल्पचर भी प्रदर्शित होंगे। कलाकार निधि बताती हैं कि गणेश प्रसाद साहू हमारे गुरु हैं। पेंटिंग मोहित और गुरु गणेश प्रसाद साहू की हैं, जबकि स्कल्पचर कृष्णा साहू के हैं। यहां वॉश पेंटिंग भी देखने को मिलेंगी। हालांकि अब धीरे-धीरे ये गायब होती जा रही है। इसकी खासियत यह है कि यह वाटर कलर होते हुए भी वाटर कलर की भांति नहीं दिखता है। यह एक तरह से ड्राइ पेस्टल लुक में दिखता है। इसकी विशेषता यह है कि पेपर को पानी में धोकर बनाया जाता है। जितनी बार रंगों का उपयोग होता है उतनी बार पानी से पेपर धोया जाता है। एक पेंटिंग बनाते समय पेपर को करीब 15 बार धोया जाता है। इसके अलावा एक्रेलिक ऑन कैनवस और रेगन वर्क से बनी पेंटिंग भी दिखेंगी।

कैनवस पर रेगन वर्क का प्रयोग: रेगन वर्क के बारे में निधि कहती हैं कि यह पेंटिंग आमतौर पर लकड़ी या लोहे के ऊपर की जाती है, लेकिन हमने अनूठा प्रयोग किया है। हमने कैनवस पर इसका माकूल प्रयोग किया है। प्रदर्शनी में मिरर वर्क भी दर्शकों को पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए आइने में से कलर को चिह्नित कर कैनवस पर मीनाकारी का काम किया जाता है। मीनाकारी आमतौर पर सोने, चांदी और पत्थरों पर रंग भरने की कला है। इस कला को जयपुर के शासक मान सिंह प्रथम लाहौर से लाए थे, वहीं कागजी मीनाकारी के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। कागज जैसे पतले पत्थर पर सोने या अन्य धातु के कार्य को कागजी मीनाकारी कहते हैं।

कलाकार निधी की कलाकृति। सौजन्य-आयोजक

आयोजन : आलेख्य
कहां : ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसायटी।
कब : 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक, सुबह दस से शाम सात बजे तक।
प्रवेश : निश्शुल्क।
नजदीकी मेट्रो स्टेशन : केंद्रीय सचिवालय।

आधी आबादी के विविध रंग: यहां कला में समाहित एक कलाकार की भावना भी देख सकेंगे। आधी आबादी के बारे में उनकी सोच भी यहां प्रदर्शित है। कलाकृतियों में महिलाएं संघर्ष करती दिखेंगी तो अपने अधिकार के लिए आवाज भी बुलंद करती नजर आएंगी। कई कलाकृतियां ऐसी होंगी जिसमें शृंगार रस झलकेगा। भगवान बुद्ध की जिंदगी के विविध समय जब वे एक राजा थे और जब उन्होंने वैराग्य का निर्णय लिया उन क्षणों को भी बेहद खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। करीब एक दशक से निधि की कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। रंगों की शक्ति और ब्रह्मांड में एक महिला शरीर की ताकत के बारे में उनका विश्वास उनकी कला के जरिये परिलक्षित होता है।

-संजीव कुमार मिश्र

नाट्य मंचन

गालिब और जौक के दिल न मिला सकी दिल्ली

गालिब की गजल से जौक जले...और जौक की नोकझोंक से गालिब ये भी कैसी घड़ी रही होगी जब दो बड़े शायर...एक दूजे की शायरी के 'दिल जले' हो गए। दिल्ली इनके कभी दिल न मिला सकी। यह वो वाक्या था जो दिल्ली की पुरानी गलियों में कई बार हुआ। और आखिरी बार इसका गवाह बना था लाल किला में 1857 से पहले हुआ वो आखिरी मुशायरा...जब मंच पर हुई थी गालिब और जौक की नोकझोंक। आज गालिब की जन्मतिथि के अवसर पर उसी प्रसंग को नाट्य रूपांतरण के माध्यम से रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

लाल किले का आखिरी मुशायरा नाटक का एक दृश्य जिसमें गालिब और जौक कुछ इस अंदाज में नजर आए। फाइल फोटो सौजन्य-आयोजक

नाटक : लाल किले का आखिरी मुशायरा
कहां : स्थल-एलटीजी आडिटोरियम, मंडी हाउस।
कब: 29 दिसंबर, दोपहर 12 बजे।
प्रवेश : आनलाइन बुकिंग, 100 रुपये से 1000 रुपये तक टिकट।
नजदीकी मेट्रो स्टेशन : मंडी हाउस।

तना दिलचस्प होगा जब लगभग 150 साल पुराने एक मुशायरे के प्रसंग नाट्य रूप में मंच पर जीवंत हो रहे होंगे वो भी गालिब की जयंती के अवसर पर। दरअसल 1857 से पहले लाल किले में जो आखिरी मुशायरा हुआ था जिसमें शम्मा नहीं थी, जो रोशन हुआ गालिब के अंदाज-ए-बयां से लेकर जौक और गालिब की सभ्य नोंकझोंक और मोमिन, दाग देहलवी की शायरी जैसे संस्मरण जुड़े हैं। नाटक के निर्देशक डॉ एम सईद आलम कहते हैं कि लाल किले पर दिल्ली के शहंशाह बहादुरशाह जफर की सदारत यानी अध्यक्षता में आखिरी उर्दू मुशायरा हुआ था। वह साहित्य और सत्ता के दौर में एक ऐतिहासिक अदबी घटना थी। उस मुशायरे में शहंशाह बहादुर शाह जफर के अलावा मिर्जा गालिब, उस्ताद जौक, हकीम मोमिन खान, आगा खान ऐश, दाग देहलवी, मुस्तफा खान शेफ्ता, मुफ्ती सदरुद्दीन आर्जुदा जैसे शिखर के शायर मौजूद थे। उसी मुशायरे को एक नाटक के रूप में दिलचस्प ढंग से पेश किया गया है। उन दिनों परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि उस ऐतिहासिक मुशायरे की कोई लिखित तफसील मिल सकती, लेकिन दिल्ली के अदबी क्षेत्रों में एक लंबे अरसे तक उस मुशायरे की चर्चा होती रही और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जिक्र भी दिल्ली के पुराने अदबी घरानों में जारी रहा।

बकौल सईद पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त विवरणों के अनुसार इस मुशायरे में ऐसे भी शायर मिलते रहे जो निजी जिंदगी में एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मसलन, उस्ताद जौक और मिर्जा गालिब। दोनों ही एक दूसरे पर फब्तियां कसते रहते थे। जौक शहंशाह के आधिकारिक रूप से उस्ताद माने जाते थे मगर गालिब को भी दरबार में उतनी ही इज्जत मिलती थी जितनी की उस्ताद जौक को। एक घटना अदबी इलाके में बेहद चर्चित रही थी। एक बार उस्ताद जौक पालकी में बैठ कर बादशाह के दरबार की तरफ जा रहे थे। रास्ते में चांदनी चौक में एक पान की दुकान पर बैठे मिर्जा गालिब ने उनकी पालकी देख जोर से एक व्यंग्य कस दिया।

बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता।

गालिब ने यह मिसरा इतनी जोर से पढ़ा कि उस्ताद जौक को भी सुनाई दे गया, वे बेहद तिलमिलाए। उन्होंने लाल किले में पहुंचते ही बादशाह से शिकायत की कि मिर्जा गालिब ने उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया है। बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फौरन मिर्जा गालिब को बुलावा भेजा। जफर ने गालिब से कहा, मिर्जा आप तो अदब की दुनिया के सरताज माने जाते हैं, आपसे तो ऐसी बेअदबी की उम्मीद नहीं थी।

मिर्जा गालिब व्यंग्यकार तो थे ही कमाल के हाजिर जवाबी भी थे। उन्होने सफाई दी ...आपने सही फरमाया आलम। मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं। मैंने तो अभी अपने ताजा शेर का पहला मिसरा ही पढ़ा था। उस्ताद जौक ने दूसरा मिसरा सुना ही नहीं और आपके पास आ गए शिकायत लेकर। मेरा पूरा शेर तो अपने बारे में था।

पूरा शेर यूं था...

बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता
वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है...।

बादशाह जफर गालिब की चतुराई भांप गए। उन्होंने विवाद को अच्छे ढंग से सुलझाने के लिए गालिब की जमकर तारीफ की। उस्ताद जौक को इस सारे प्रकरण में अपने द्वारा की गई शिकायत केलिए माफी मांगनी पड़ी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस आखिरी मुशायरे में बादशाह की आंख बार बार नम हो जाती थीं। अपने दरबार में शायरों को अशर्फियां देने वाले बादशाह का खजाना उस दिन खाली था। उस दिन बादशाह ने अपनी शॉल, गले में पहने कुछ आभूषण, अंगूठियां और चांदी की प्लेट ही शायरों को नजर की थीं। अशर्फी न दे पाने के लिए जफर ने सिर झुकाकर माफी मांगी थी एवं चेताया था कि शायद यह आखिरी मुशायरा होगा। इस मुशायरे में बादशाह ने भी शेर पढ़े थे। जो यह है- न था शहर देहली, ये था चमन, कहो किस तरह का था या अमन जो खिताब था वो मिटा दिया, फकत अब तो उजड़ा दयार है...।

और...न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं। मेरा रंग-रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा से उजड़ गया, मैं उसी की फस्ले-बहार हूं...।

लाल किले का आखिरी मुशायरा नाटक का एक दृश्य। फाइल फोटो सौजन्य-आयोजक

तब जफर हिंदुस्तान का एक बेबस राजा था। शायर थे इसलिए शायरी के शौकीन होने के चलते मुशायरा आयोजित कराते थे। बकौल डॉ आलम यह मुशायरा ऐतिहासिक था। बहादुर शाह जफर के दो शहजादों मिर्जा दाराबख्त और शाहरुख की मौत की वजह से बड़ी सादगी से यह आयोजित हुआ था। आजकल के मुशायरे में जो एंकरिंग की परंपरा है वो इसी मुशायरे से शुरू हुई थी। पहले मुशायरे में शम्मा जलाने का चलन था। शम्मा जिस शायर की तरफ जाती वो मंच पर आता। लेकिन इस मुशायरे में गालिब को एंकरिंग का जिम्मा सौंपा गया। इसी तरह मुशायरों में एक लाइन दे दी जाती थी। और सबको उसी रिदम में शायरी करनी होती थी लेकिन इसमें पहली बार शायरों को कोई भी शायरी पढ़ने की छूट दी गई।

कॉस्टयूम ड्रामा: अब बात लाल किला के उस आखिरी मुशायरा के नाटक में किरदारों की और उनके हूबहू रूपांतरण की करते हैं। कहते हैं कि यह एक तरह से कॉस्टयूम ड्रामा है। इसे रिक्रिएशन समझिए। कलाकार शायरों के वैसे ही की गेटअप में दिखेंगे। टॉम अल्टर इस नाटक में बहादुर शाह जफर की भूमिका निभाते थे। अब मिर्जा गालिब के रोल में खुद सईद, ज्ञानेश शर्मा जौक, अब आर्यन बहादुर शाह जफर की भूमिका में दिखेंगे। अब आपके जेहन में सवाल यही होगा कि आखिर वो पुराने ड्रेस कॉस्टयूम हमने कहां देखे? दरअसल ऐसे बहुत से पुराने चित्र पेंटिंग के मिले हैं उन्हीं के आधार पर सभी शायरों को मंच पर जीवंत करने की कोशिश की है। नाटक की शुरुआत भी शायरी से होती है और हर शायर की एंट्री भी उसकी शायरी के साथ होती है। इसी बीच शायरों के बीच नोंकझोंक भी होती है, जिसे दर्शक खूब पसंद करेंगे। यह मुशायरा गालिब की चालाकी के लिए भी जाना जाता है। होना यह था कि मुशायरे में सबसे सीनियर शायर को सबसे आखिर में प्रस्तुति देनी थी। गालिब को एंकरिंग का जिम्मा सौंपा गया। गालिब ने कहा कि मैंने बिस्मिल्लाह कर दिया है। बिस्मिल्लाह के बाद उस्ताद आता है, इसलिए मैं जौक को बुलाता हूं। लेकिन एक अन्य शायर ने गालिब को उस समय हक्का बक्का कर दिया जब कहा गया कि इस नए तरीके के मुशायरे में संचालन करने वाले को सबसे आखिरी में मौका मिलेगा। यह तो नाइसांफी होगी इसलिए गालिब को दूसरे नंबर पर ही बुलाया जाए। नाटक में एक बार पहले आप, पहले आप होता है तो जौक कहते हैं कि यह गफलत ना फैलाई जाए कि मुशायरा लखनऊ में हो रहा है। जौक जब शायरी सुनाने से पहले गालिब की इजाजत लेते हैं। गालिब कहते हैं कि मैं कैसे मना कर सकता हूं। इस पर जौक कहते हैं कि आपका हुक्म, हुक्म ए खुदा ठहरा।

सईद कहते हैं कि नाटक एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह उस मुशायरे का पक्षधर है जिसमें गंगा-जमुनी तहजीब पल्लवित और पुष्पित होती है।

गालिब की याद में

27 दिसंबर के दिन जन्में मिर्जा गलिब का 13 साल की उम्र से अंतिम सांस तक दिल्ली की धरा से नाता रहा। उन्होंने दिल्ली को सिर्फ जिया ही नहीं बल्कि नज्मों में भी गढ़ा। तभी तो दिल्ली हमेशा उन्हें शिद्दत से याद करती है। गालिब की जयंती के अवसर पर दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साहित्य कला परिषद तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें उर्दू के नामचीन शायर हिस्सा लेंगे। तीन दिवसीय आयोजन 27 से 29 दिसंबर तक चलेगा। 27 दिसंबर को मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। जबकि अगले दिन यानी 28 को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिसमें डॉ पद्म भूषण कथक नृत्यांगना उमा शर्मा की प्रस्तुति खास होगी। गालिब की रचनाओं पर आधारित चर्चा में पवन के वर्मा संग परिचर्चा में जावेद अख्तर या गुलजार भी शामिल हो सकते हैं। वहीं आखिरी यानी 29 नवंबर को गालिब की मजार पर चादर चढ़ाई जाएगी।

आयोजन : गालिब जयंती
कहां : इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, लोदी रोड।
कब : 27 से 29 दिसंबर तक, शाम साढ़े छह बजे।
प्रवेश : निश्शुल्क

एंटी पॉल्यूशन डिशेज से करें डीटॉक्स

जायका

हम में से ज्यादातर लोगों के सामने अगर लौकी और टिंडे की सब्जी रख दी जाए तो हम नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं। इसी तरह बथुआ, सरसों या कोई अन्य साग खाने के नाम पर बच्चे ना नुकर करने लगते हैं, लेकिन शेफ निशांत चौबे सर्दी की इन्हीं खास हरी पत्तेदार साग-सब्जियों से स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन बना कर लोगों को परोस रहे हैं। निशांत का कहना है, 'मेरे हिसाब से लोकल इज एग्जोटिक'। लोकल सामग्री से जितनी अच्छी डिशेज बन सकती हैं वह विदेशी सामग्रियों से संभव नहीं है। दिल्ली के ओबेरॉय होटल से लेकर ऑलिव व रोजिवंट में बतौर शेफ काम कर चुके निशांत इन दिनों भारत के क्षेत्रीय व्यंजनों पर काम कर रहे हैं।

हेल्दी सूप हो जाए...: इन दिनों दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस मौसम में लोग सूप सबसे अधिक पसंद करते हैं, निशांत कहते हैं कि उस सूप को थोड़े और प्रयास से स्वास्थ्यवर्धक बना दिया जाए तो शरीर में ठंड और प्रदूषण से लड़ने की ताकत आ जाएगी। सूप में चुकंदर व गोभी जरूर डालें। इसके अलावा साग और सभी प्रकार की सब्जियों से बेहतरीन सूप तैयार किया जा सकता है।

स्टर फ्राइड विवनोआ विद लोकल ग्रीस एंड हॉट बेसिल। सौजन्य : शेफ।

पशु प्रोटीन की जगह वीगन : बतौर निशांत पशु प्रोटीन (दूध और उससे बनी चीजें व मांस आदि) को उपयोग में लाने के बजाए वीगन को अपनाना ही बेहतर है। वीगन के तहत सोया, कोकोनट व काजू के दूध को पशुओं के दूध के बदले उपयोग में लाया जाता है। इससे शरीर में न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि इसका स्वाद भी लाजवाब होता है।

पकौड़ों के साथ शेफ निशांत चौबे। जागरण।

सोचा नहीं था कि शेफ बनूंगा

झारखंड जैसे छोटे से शहर से निकले निशांत ने कभी सोचा नहीं था कि वे शेफ बनेंगे। संभावनाओं की कमी के बावजूद उन्होंने होटल मैनेजमेंट की परीक्षा दी और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। इस दौरान उन्होंने पाया कि भारतीय क्षेत्रीय खानपान की परंपरा इतनी समृद्ध है कि उसमें स्वाद के साथ स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव के गुण भी हैं। इसी सोच का नतीजा है कि उनकी पाक कला का लोहा विश्व भर में माना जाता है। अमेरिका, दुबई और जापान में उनकी भारतीय डिशेज धूम मचा रही हैं। टोक्यो में पहली व एकमात्र भारतीय मिठाई की दुकान निशांत ने ही खोली है।

साग के पकौड़े और स्वीट डिश : इस समय बाजार में कई तरह के साग उपलब्ध हैं। पालक, बथुआ, चौलाई, नोनी, चना और पोय साग हर घर में लोग पसंद करते हैं। सरसों का साग बना रहे हैं तो उसमें सभी प्रकार के साग को मिक्स करें। उसमें लहसुन का तड़का जरूर लगाएं... और फिर देखिए स्वाद। चाहें तो साग के पत्तों से स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं। इस समय बाजार में ताजा हल्दी भी उपलब्ध है। आंवला भी मिलता है, इन्हें डिशेज में शामिल कर सकते हैं। इस ठंड मीठा बनाने के लिए किचन से चीनी को हटा दें। उसके बाद स्वास्थ्य में बदलाव देखें। प्रदूषण और ठंड का प्रभाव आपको छू तक नहीं पाएगा। आइए बताते हैं कि डेजर्ट कैसे बनाएं। पाम शुगर, गुड़, धनिया पाउडर डालकर हलवा बना लें। हल्दी एंटी कैंसर होती है तो आंवला विटामिन सी का भंडार है। आइए इसकी डिश भी बताते हैं...। आंवला, कच्ची अंबी (अगर उपलब्ध है), गाजर को घिसकर, पाम शुगर (ताड़ से बनी चीनी) आदि को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करें। चाहें तो आप इसमें पंच फोरन भी डाल सकते हैं और तीखेपन के लिए लाल मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। जितनी सब्जियां हैं उतना ही पाम शुगर डालें। अंत में धनिया पाउडर डालें। अब इस मिश्रण को ट्रे में सेट कर लें। यह मिक्सचर वात-पित्त रोगों से छुटकारा दिलाएगा। इसे छह महीने तक फ्रिज में सुरक्षित रखा जा सकता है, बस गीले चम्मच का उपयोग न करें।

बाटी का है मौसम: दाल बाटी का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। आप पसंदीदा दाल या चोखा के साथ बाटी का आनंद ले सकते हैं। इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें चने, सोया आदि दालों का आटा भी मिला कर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं।

- प्रियंका दुबे मेहता

इस बार यहां चलें

शून्य ए जर्नी

रीता झुनझुनवाला और श्रीकांत की कलाकृतियां पांच तत्वों यानी पंच तत्वों को प्रस्तुत करती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का जश्न मनाते हुए इस शो में 60 से अधिक कार्य शामिल होंगे। झुनझुनवाला की ये कलाकृतियां बनारस से प्रेरित हैं, जिसमें लद्दाख व तिब्बत भी झलकेगा।

- **कहां** : बिकानेर हाउस, इंडिया गेट, नई दिल्ली। • **कब** : 4 से 7 जनवरी, सुबह दस से शाम छह बजे तक। • **प्रवेश** : निश्शुल्क।

रुह-ए-गजल

पूरे सप्ताह भागदौड़ और तनाव के बाद वीकेंड में कुछ पल सुकून भरे संगीत के साथ बिताने का मौका मिल जाए तो...। रुह-ए-गजल में शकील अहमद के ओरिजनल कंपोजिशन सुनने को मिलेंगे। कार्यक्रम में शकील सौदा, मीर, इकबाल व साहिर लुधियानवी के जन्मों को सुनाएंगे।

- **कहां** : अमलतास ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, दक्षिणी दिल्ली।
- **कब** : 27 दिसंबर, शाम सात बजे।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

द होमलैंड

घर क्या होता है? ऐसे कौन से कारक हैं जो ईंट, गारे से बनी बिल्डिंग को घर बनाते हैं? रिश्तों की परिभाषा, उनकी संवेदनशीलता को एक कलाकार के नजरिये से जानने समझने का बेहतरीन जरिया है होमलैंड। घरौंदा : द होमलैंड सीरिज के तहत प्रदर्शित यह कलाकृतियां मौतुषी चक्रवर्ती की है।

- **कहां** : इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोदी रोड, दक्षिणी दिल्ली। • **कब** : 3 जनवरी तक, सुबह ग्यारह से शाम सात बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

कम्पी का सुशी स्वाद

नए साल का स्वागत बाहें फैलाकर कीजिए, वह भी लजीज जायकों के साथ। जापानी, सुशी, एशियन जायके का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कम्पी आकर देखें। यहां का शांत वातावरण और संगीत की मधुर ध्वनि जायके की लज्जत और बढ़ा देगी। सुशी, कॉकटेल, चीजी केक, क्रिस्पी चिकन लाजवाब है।

- **कहां** : वर्ल्ड मार्क 1, एयरोसिटी, नई दिल्ली। • **कब** : दोपहर 12 से रात पौने बारह बजे तक। • **शुल्क** : 3500 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

थियेटर फेस्टिवल

एक दिवसीय थियेटर फेस्टिवल में पांच नाटकों को देखने का मौका मिलेगा। दो अलग ऑडिटोरियम में दर्शक ट्रेन टू पाकिस्तान, जिस लाहौर नई वेख्या, दीवानगंज, काश, गालिब इन न्यू दिल्ली नाटक देख पाएंगे।

- **कहां** : कमानी व एलटीजी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस, नई दिल्ली। • **कब** : 29 दिसंबर, अपराह्न तीन बजे से। • **प्रवेश** : ऑनलाइन बुकिंग द्वारा। टिकट 100 रुपये से एक हजार तक।

हियर एवरीथिंग इज फाइन

यह आबिर कर्माकर की कलाकृतियों की प्रदर्शनी है, जिसमें व्यवस्थित जीवन को बहुत ही सुनियोजित तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया है। जो ठीक है क्या वह वाकई में ठीक है। इसे कैनवस पर देखने और समझने का बेहतरीन जरिया है यहां सब कुछ ठीक है।

- **कहां** : ग्रीन एवेन्यू स्ट्रीट, वसंत कुंज रोड, दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली। • **कब** : 11 जनवरी तक, सुबह 11 से शाम सात बजे तक। • **प्रवेश** : निश्शुल्क।

ड्यूटी फ्री

राजौरी गार्डन स्थित ड्यूटी फ्री का लुक जितना खूबसूरत है, उतना ही लाजवाब इसका जायका है। कॉंटिनेंटल, मैक्सिकन, नार्थ इंडियन का यहां समायोजन दिखता है। पिज्जा, मोमोज, कॉकटेल, व्हाइट सॉस पास्ता, स्प्रिंग रोल बेमिसाल है। जिसे खाने दिल्ली-एनसीआर से लोग यहां आते हैं।

- **कहां** : अपर ग्राउंड फ्लोर, विशाल एंक्लेव, राजौरी गार्डन, पश्चिमी दिल्ली। • **कब** : दोपहर 12 से रात 11 बजे तक। • **शुल्क** : 1500 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

सरकारी बैंक के प्रमुखों से शनिवार को मिलेंगी वित्त मंत्री

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों और शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकारी बैंकों के चालू वित्त वर्ष में अब तक के प्रदर्शन पर चर्चा की जाएगी। मांग को बढ़ावा देने और खपत बढ़ाने में सरकारी बैंकों की भूमिका को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में एनसीएलटी और गैर-एनसीएलटी तरीकों से एनपीए की रिकवरी पर भी चर्चा होगी। (प्रेट्र)

सत्रह साल पहले भारत में निवेश करते वक्त मुझे बड़ी मुश्किल आई थी। लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश डेस्टिनेशन है।
— अनिल अग्रवाल
चेयरमैन, वेदांता रिसोर्सेज

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
41,163.76	12,126.55	₹ 39,630	₹ 48,060	₹ 71.31	$ 67.25
297.50	88.00	₹ 116	₹ 454	₹ 0.04	

सूरतेहाल ▸ एयर इंडिया के साथ बीपीसीएल के विनिवेश में भी देरी के पूरे आसार

विनिवेश लक्ष्य हासिल होने में संदेह

1.05 लाख करोड़ रुपये का रखा गया है विनिवेश लक्ष्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पहले से ही राजस्व के मोर्चे पर कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रही केंद्र सरकार के लिए विनिवेश के मोर्चे से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.05 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल होता नहीं दिख रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ा योगदान विमानन कंपनी एयर इंडिया और ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के विनिवेश का होता। लेकिन इन दोनो कंपनियों के लिए खरीदार मिलते फिलहाल नजर नहीं आते। एयर इंडिया के विनिवेश से तो सरकार ने एक तरह से हाथ ही खड़े कर लिए हैं। जबकि बीपीसीएल का विनिवेश कार्यक्रम अगले वित्त वर्ष तक खिंच जाने के आसार बन रहे हैं।

वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी भी मान रहे हैं कि बीपीसीएल के विनिवेश को अगले तीन महीनों के भीतर पूरा करना मुश्किल होगा। इस कंपनी में कई देसी-विदेशी कंपनियों की रुचि होने के बावजूद इतनी बड़ी कंपनी की बिक्री की नीतिगत व नियमन संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने में तीन से चार महीने का समय लगेगा। अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में आशय पत्र भी जारी नहीं किया गया है। आशय पत्र जारी करने के बाद विदेशी कंपनियों की तरफ से इसे खरीदने का प्रस्ताव आने से लेकर उसे मंजूरी देने और देश की नियामक एजेंसियों से पूरी प्रक्रिया के लिए अनुमति लेने में दो से ढाई महीने का समय लग सकता है। बीपीसीएल के विनिवेश से सरकार को कम से कम 35 हजार करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद है। सरकार ने 20 नवंबर को बीपीसीएल समेत पांच बड़ी सरकारी कंपनियों के विनिवेश का फैसला किया था।

सरकार बीपीसीएल का नियंत्रण भी निजी हाथों को सौंपने के लिए तैयार है। प्रतीकात्मक

बीपीसीएल में सरकार की पूरी हिस्सेदारी के साथ प्रबंधन नियंत्रण भी निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला हुआ था। सरकार की यह भी मंशा है कि कोई विदेशी पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल को खरीदे।

शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआइ), कंटेनर कॉरपोरेशन (कॉनकॉर्प), टीएचडीसीआइ और नीपको की रणनीतिक बिक्री के फैसले को चालू वित्त वर्ष में अमली जामा पहनाया जा सकता है। इसमें से बिजली क्षेत्र की टीएचडीसीआइ और नीपको को सरकारी क्षेत्र की एनटीपीसी को ही बेचा जाना है। इन चारों से सरकार को जो राशि हासिल होगी वह सालाना विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए नाकाफी होगी। विनिवेश से अभी तक सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान तकरीबन 17,384 हजार करोड़ रुपये हासिल कर पाई है। एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर भी जो उम्मीदें थी वह अब ध्वस्त हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से बयान आ चुका है कि खरीदार नहीं मिलने पर 31 मार्च, 2020 से एयर इंडिया को बंद करना पड़ा सकता है। जाहिर है कि विनिवेश लक्ष्य हासिल नहीं होने का असर राजकोषीय घाटे पर भी दिखेगा। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 3.6 फीसद रखा गया है लेकिन हाल ही में कई एजेंसियों ने इस बात की आशंका जताई है कि यह एक फीसद तक ज्यादा हो सकता है।

मध्यम वर्ग को राहत देने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ आयकर में छूट के विकल्पों पर भी हो रहा विचार

▸ मध्यम वर्ग की खर्च करने लायक आमदनी बढ़ाने पर जोर

प्रतीकात्मक

राहत देने के मामले में मध्यम वर्ग आगामी बजट में सरकार के केंद्र में हो सकता है। वित्त मंत्रालय खासतौर पर नौकरीपेशा वर्ग के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कर रहा है जिससे इनकी खर्च करने लायक आमदनी बढ़ाई जाए। मंत्रालय में हो रही बजट-पूर्व चर्चाओं में ऐसे कई प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हो रहा है जिससे मध्यम वर्ग को बजट में कुछ अतिरिक्त राहत दी जा सके।

सूत्र बताते हैं कि इस तरह के विमर्श में आयकर में छूट का प्रस्ताव तो है ही, लेकिन उसके विकल्प के तौर पर ऐसी किसी स्कीम पर भी मंथन हो रहा है जिससे लोगों को सीधे राहत मिल सके। इसके लिए ऐसी किसी योजना की संभावना भी तलाशी जा रही है जिससे एक निश्चित आय-वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से मदद दी जा सके। कुछ अधिकारियों ने पीएम किसान की तर्ज पर इस तरह की स्कीम शुरू करने की सलाह भी दी है।

माना जा रहा है कि आगामी बजट में सरकार का फोकस मध्यम वर्ग को राहत देने पर रहेगा। पिछले कुछ बजटों में आर्थिक सुधारों को केंद्र में रखा गया था। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में सरकार ने इंडस्ट्री को कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाकर 1.45 लाख करोड़ रुपये का तोहफा दिया था। सरकार के इस कदम में माना गया कि यह देश में मांग बढ़ाने से लेकर कंपनियों के विस्तार में मददगार साबित होगा।

सूत्र बताते हैं कि इन चर्चाओं में यह बात उभरकर आई है कि बाजार में मांग बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग की आमदनी में वृद्धि होना आवश्यक है। जनता के पास अतिरिक्त राशि खर्च के लिए उपलब्ध होगी तो मांग भी बढ़ेगी। इसलिए आयकर में छूट के विभिन्न विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों के पास अतिरिक्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। आयकर में छूट की स्थिति न बनने की सूरत में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे विकल्पों पर भी मंथन की प्रक्रिया मंत्रालय में चल रही है।

सूत्र बताते हैं कि यह मंथन अभी शुरुआती स्तर पर है। विभिन्न विशेषज्ञों और बजट पूर्व बैठकों में आये सुझावों पर भी अलग अलग समूहों में विचार हो रहा है। बताया जाता है कि जनवरी के पहले सप्ताह के बाद ही यह तय हो पाएगा कि मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए मोटे तौर पर क्या विकल्प चुने जा सकते हैं। यह तय करने में इस बात की भूमिका भी काफी अहम होगी कि कौन सा विकल्प सरकार के खजाने पर कितना बोझ डालेगा।

न्यूज गैलरी

भीम एप से भी मिलेगी फास्टैग रिचार्ज की सुविधा

नई दिल्ली : नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइ) अब ग्राहकों को भीम यूपीआइ के माध्यम से भी फास्टैग रिचार्ज सुविधा मुहैया कराएगी। एक बयान में एनपीसीआइ ने कहा कि ग्राहक अब भीम यूपीआइ के माध्यम से भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) फास्टैग का रिचार्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है, जिसे गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। जिस वाहन पर फास्टैग लगा होता है, उसका टोल टैक्स टोल प्लाजा पर अपने आप कट जाता है और वाहन रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 15 दिसंबर से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। हालांकि वाहन चालकों को फास्टैग खरीद लेने के लिए एक महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। (प्रेट्र)

पीएमवीवीवाई के लिए अब आधार जरूरी

नई दिल्ली : सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के सब्सक्राइबर्स के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों की इस पेंशन योजना के तहत आठ प्रतिशत का निश्चित सालाना रिटर्न दिया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) लिमिटेड इस योजना का संचालन कर रही है। योजना की घोषणा 2017-18 और 2018-19 के बजट में की गई थी। वित्त मंत्रालय ने 23 दिसंबर की एक अधिसूचना में कहा कि इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को आधार कार्ड का विवरण देना अनिवार्य होगा। (प्रेट्र)

जनमत
मुद्दा

क्या अर्थव्यवस्था की सुस्ती में जान फूंकने के लिए आम बजट-2020 में सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

रिलायंस रिटेल की वैल्यू सवा दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा

नई दिल्ली, प्रेट्र : एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस रिटेल का मूल्य 3,400 करोड़ डॉलर यानी करीब 2.40 लाख करोड़ रुपये है। कंपनी के शेयरधारकों के लिए शेयरों की अदला-बदली की एक प्रस्तावित योजना के तहत कंपनी का यह मूल्य आंका गया है।

कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार रिलायंस रिटेल के शेयरधारकों को प्रति चार शेयर के बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर मिलेगा।रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बीएसई में गुरुवार को 1,515.95 रुपये पर बंद हुआ। इस हिसाब से इसका बाजार पूंजीकरण 9.6 लाख करोड़ रुपये रहा।

रिलायंस रिटेल वेंचर्स की गैर-सूचीबद्ध इकाई रिलायंस रिटेल लिमिटेड फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की परोक्ष सहायक शाखा है। रिलायंस रिटेल के पास 10,901 स्टोर का नेटवर्क है और पिछले साल उसने 1.3 लाख करोड़ रुपये मूल्य की बिक्री की। रिलायंस रिटेल में रिलायंस रिटेल वेंचर्स की 99.95 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेष 0.05 प्रतिशत हिस्सेदारी कंपनी के कर्मचारियों के पास है। रिलायंस रिटेल ने कहा कि उसने 2006 और 2007 में कर्मचारियों को शेयरों का विकल्प दिया था।

कंपनी के कर्मचारी पिछले कुछ समय से यह अनुरोध कर रहे थे कि उन्हें शेयर बिक्री का विकल्प दिया जाए। कर्मचारी आग्रह कर रहे थे कि इसके लिए रिलायंस रिटेल को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध भी कराया जा सकता है। चूंकि अभी कंपनी की सूचीबद्ध होने की योजना नहीं है, उसने शेयरों की अदला-बदली के जरिये कर्मचारियों को सूचीबद्ध कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर देने का निर्णय लिया है।

प्रतीकात्मक

▸ शेयरों की अदला-बदली योजना के तहत सामने आया यह मूल्य

▸ इस गैर-सूचीबद्ध कंपनी के ग्राहकों को मिलेंगे आरआइएल के शेयर

कंपनी ने कहा कि इस फैसले के बाद रिलायंस रिटेल लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की 23 जनवरी को एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में कंपनी के प्रस्ताव पर विचार किए जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया था कि अवधि के दौरान रिलायंस रिटेल के राजस्व में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

स्रोत : सॉल्वेन्ट एक्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया *संशोधित **अनंतिम पीटीआई ग्राफिक

फ्रॉड रोकने के बैंकों के दावों की कलई खुली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकारी क्षेत्र के बैंक चाहे जितनी भी सुरक्षित बैंकिंग व्यवस्था का बखान करें, हकीकत यह है कि वे बैंकिंग फ्रॉड यानी धोखाधड़ी को रोकने में एकदम विफल रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन धोखाधड़ी में ही इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि कर्ज वितरित करने या नकदी जमा कराने में होने वाले फ्रॉड भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में देश के बैंकिंग सेक्टर में कुल 71,543 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले सामने आए हैं। यह रकम वित्त वर्ष 2014-15 में बैंकों में हुए 19,455 करोड़ रुपये के फ्रॉड के मुकाबले करीब चार गुना है। इसमें भी 90.2 फीसद हिस्सा सरकारी बैंकों का है। बैंकिंग क्षेत्र का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) स्वयं मान रहा है कि बैंकों में बड़े स्तर के धोखाधड़ी मामले नहीं रुक पा रहे हैं और इस तरह के अधिकांश फ्रॉड सरकारी बैंकों में ही हो रहे हैं। बैंकिंग ट्रेंड व प्रोग्रेस पर आरबीआइ की पिछले दिनों आई रिपोर्ट से साफ है कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकारी बैंकों के स्तर पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है।

▸ पांच वर्षों में फ्रॉड से होने वाला नुकसान करीब चार गुना पर पहुंचा

▸ फ्रॉड से बैंकिंग सेक्टर को हुई हानि का 90 फीसद सरकारी बैंकों का

प्रतीकात्मक

आरबीआइ ने कहा है कि सबसे ज्यादा घाटा लोन पोर्टफोलियो में हो रहा है। इसमें घटनाओं की संख्या और शामिल राशि का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। धोखाधड़ी के जरिये बैंकों को चूना लगाने में नामी-गिरामी कंपनियां भी शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जो कंपनियां कर्ज की रकम किसी और काम में लगा देती हैं, उनकी तरफ से बैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मसलन, कई कंपनियों ने मुख्य कंपनी के नाम पर कर्ज लिया है और फिर उसे अपनी दूसरी फर्जी कंपनियों में लगा दिया है। इसके लिए उन्होंने कर्ज देने वाले बैंकों से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में भी नहीं लिया है। वर्ष 2018-19 में समूचे बैंकिंग सेक्टर को फ्रॉड से हुई 71,543 करोड़ रुपये की हानि में से 64,548 करोड़ रुपये की चपत कर्ज से जुड़े मामलों से ही लगी है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंकिंग फ्रॉड की 6,801 घटनाओं में से 55.4 फीसद सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हिस्से आई है जबकि इससे हुई हानि में 90.2 फीसद हिस्सा इन बैंकों का है। बड़े घोटाले (50 करोड़ रुपये से ज्यादा) में तो सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 91.6 फीसद है।

बहरहाल, आरबीआइ की रिपोर्ट बताती है कि बैंकों के स्तर पर लगातार तमाम दावे के बावजूद इनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले लगातार सफल हो रहे हैं। अगर बैंकों की व्यवस्था दुरुस्त होती तो वर्ष 2014-15 में फ्रॉड से होने वाले नुकसान की जो राशि 19,455 करोड़ रुपये थी, वह पांच वर्षों बाद यानी 2018-19 में बढ़कर 71,543 करोड़ रुपये नहीं हो गई होती। इसी दौरान लोन मामलों में फ्रॉड की राशि 17,122 करोड़ रुपये से बढ़ कर 64,548 करोड़ रुपये हो गई।

5-जी के लिए स्पेक्ट्रम का नया बैंड जारी करने की तैयारी में सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार 5-जी सेवाओं के लिए उपलब्ध मौजूदा स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त एक नया बैंड जारी करने पर विचार कर रही है। 'मिलिमीटर वेव बैंड' कहे जाने वाले 24.75 से 27.25 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण और अन्य प्रक्रियागत शर्तों पर विचार के लिए एक प्रस्ताव जल्द टेलीकॉम नियामक ट्राई को भेजा जा सकता है। सरकार की योजना इस स्पेक्ट्रम को अगले साल नीलाम करने की है।

डिजिटल कम्यूनिकेशंस डिपार्टमेंट (डीसीसी) ने 20 दिसंबर को ही स्पेक्ट्रम नीलामी के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है जिससे 5.22 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाने का अनुमान है। मार्च-अप्रैल, 2020 के दौरान होने वाली इस स्पेक्ट्रम नीलामी में सभी 22 सर्किल में बिक्री के लिए 8,300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तावित नया बैंड नीलामी की इस प्रक्रिया से अलग होगा। 5-जी के लिए वर्तमान में 700 और 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज का बैंड उपलब्ध है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों के मुताबिक नए बैंड के संबंध में नियम व शर्तें और मूल्य तय करने के संबंध में विभाग ट्राई से जल्द संपर्क करेगा। सूत्रों ने बताया कि जनवरी में इस प्रस्ताव को ट्राई के पास भेजे जाने की संभावना है। ट्राई की सिफारिशों के आधार पर अगले साल किसी वक्त 5-जी स्पेक्ट्रम के नए बैंड को नीलामी के लिए उतारा जा सकता है।

प्रतीकात्मक

▸ मूल्य निर्धारण और अन्य प्रक्रियागत मुद्दों पर विचार को ट्राई को प्रस्ताव भेजेगा डीओटी

▸ 24.75 से 27.25 गीगाहर्ट्ज बैंड का नया स्पेक्ट्रम लाने की तैयारी

जहां तक स्पेक्ट्रम नीलामी के मौजूदा प्रस्ताव का सवाल है, तो सूत्रों का कहना है कि 5.22 लाख करोड़ रुपये की प्रस्तावित नीलामी में 5-जी की हिस्सेदारी केवल 35 परसेंट है। हालांकि टेलीकॉम सूत्रों का मानना है कि सेक्टर भले ही वित्तीय दबाव में हो, लेकिन इससे नीलामी प्रक्रिया होने की आशंका बहुत कम है। नीलामी में हिस्सा लेने वाली टेलीकॉम कंपनियों को एकमुश्त केवल 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। वैसे भी, सरकार ने कंपनियों को राहत देते हुए स्पेक्ट्रम के मद में भुगतान के लिए दो वर्षों का वक्त दिया है। साथ ही अपफ्रंट भुगतान के बाद शेष राशि को 16 किस्तों में चुकाना है। सरकार का मानना है कि देश को अगर 5-जी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने का विजन लेकर कंपनियां चल रही हैं तो कम से कम इतना निवेश तो उन्हें करना ही होगा।

गौरतलब है कि 5-जी का इस्तेमाल मशीन-टु-मशीन कम्यूनिकेशन के लिए भी सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आया है। 5-जी की रफ्तार 4-जी के मुकाबले कम से कम तीन गुना है। इसलिए इसे मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

दक्षिण भारत में भी विस्तार करेगा रेड चीफ

हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार को विस्तार योजनाओं की जानकारी देते लियान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मनोज ज्ञानचंदानी। जागरण

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : अग्रणी फुटवियर ब्रांड रेड चीफ अपने कारोबार का विस्तार दक्षिण भारतीय बाजार में भी करने जा रहा है। इसके तहत पहले चरण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को चुना गया है। रेड चीफ ब्रांड की ओनर लियान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मनोज ज्ञानचंदानी ने गुरुवार को कहा कि कंपनी अगले महीने महिलाओं के लिए लामोर नाम से फुटवियर की नई कटेगरी लांच करेगी। इसके साथ ही कंपनी ने अगले दो वर्षों में देश में लगभग 100 एक्सक्लूसिव आउटलेट्स और खोलने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने अभिनेता विक्की कौशल को कंपनी ने अपना ब्रांड एंबेसडर चुना है।

ज्ञानचंदानी ने संवाददाताओं को बताया कि डिजिटल युग में ग्राहकों के व्यवहार में काफी बदलाव आया है। इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार का विस्तार हुआ है। वर्तमान में देशभर में रेड चीफ के 170 से अधिक एक्सक्लूसिव स्टोर हैं। इसके अलावा यह ब्रांड 3,000 से ज्यादा मल्टीब्रांड आउटलेट्स और सभी अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। ज्ञानचंदानी के मुताबिक फुटवियर इंडस्ट्री का तेजी से विकास हुआ है। बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती आय के कारण ग्राहकों में भी रेड चीफ ब्रांड के प्रति रुचि बढ़ी है। इंटरनेट की टियर-2 व टियर-3 क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों तक पहुंच बढ़ी है।

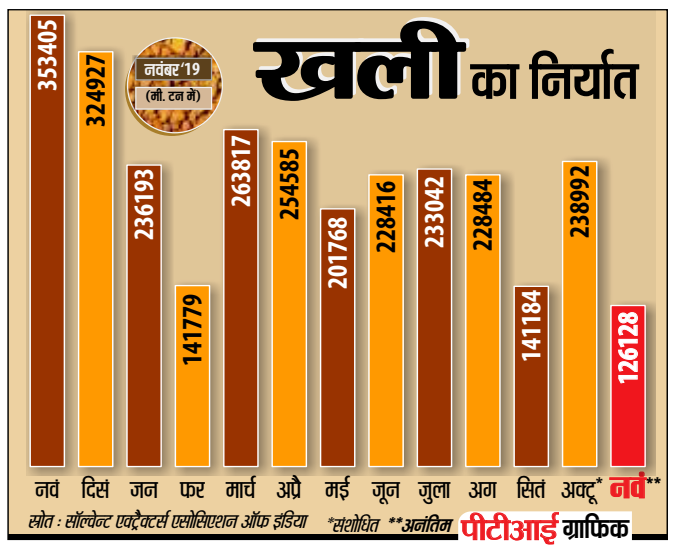

सुस्ती

297.50 अंक टूटकर 41,163.76 अंक पर स्थिर हुआ सेंसेक्स, 88 अंकों की गिरावट के साथ 12,126.55 अंकों पर स्थिर निफ्टी

बड़े शेयरों में फिसलन से बाजारों में गिरावट का रुख

मुंबई, प्रेट्र : रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल जैसे बड़े स्टॉक्स के प्रति निवेशकों की बेरुखी के चलते घरेलू शेयर बाजारों के गिरने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। दिसंबर के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) की एक्सपायरी के बीच बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स गुरुवार को 297.50 अंक यानी 0.72 प्रतिशत टूटकर 41,163.76 अंक पर स्थिर हुआ। इंट्रा-डे में सेंसेक्स 41,132.89 अंक तक टूटा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक निफ्टी भी 88 अंकों यानी 0.72 प्रतिशत की गिरावट के साथ 12,126.55 अंकों पर स्थिर हुआ।

सेंसेक्स पैक में गुरुवार को सबसे ज्यादा 2.23 प्रतिशत का नुकसान भारती एयरटेल को झेलना पड़ा। आरआइएल, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी), सन फार्मा, मारुति सुजुकी, टाइटन और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर भी गिरकर बंद हुए। हालांकि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी), नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी), टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) के शेयरों में दिखी चुस्ती ने शेयर बाजारों को और गिरने नहीं दिया।

प्रतीकात्मक

सेक्टोरल इंडेक्स के मामले में बीएसई टेलीकॉम, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, बैंकेक्स, ऑयल एंड गैस, टेक और हेल्थकेयर 1.73 प्रतिशत तक टूट गए। मेटल और बेसिक मैटीरियल्स इंडेक्स में ही थोड़ी मजबूती दिखी। बीएसई मिडकैप 0.13 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ, जबकि स्मॉलकैप में 0.38 प्रतिशत का उछाल देखा गया।

जानकारों का कहना था कि दिसंबर के एफएंडओ एक्सपायरी के चलते शेयर बाजारों में थोड़ी अस्थिरता देखी गई। घरेलू और विदेशी बाजारों में छुट्टियों का सीजन शुरू हो जाने के चलते भी कारोबार में सुस्ती देखी गई। दिन के कारोबार के बारे में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अमेरिका के कई देशों से घटते कारोबारी विवाद से शेयर बाजारों में थोड़ा संतोष दिख रहा है। हालांकि घरेलू शेयर बाजारों के मामले में अब आगामी बजट से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम ही बड़ा बदलाव दिखा सकते हैं।

एशिया के अन्य बाजारों के मामले में शंघाई, टोक्यो और सियोल के शेयर बाजार सकारात्मक स्तर पर बंद हुए। दुनियाभर के शेयर बाजारों की बात करें तो हांगकांग, सिडनी और वेलिंगटन के शेयर बाजार सरकारी छुट्टी की वजह से बंद रहे।

सोना-चांदी में मजबूती

नई दिल्ली, प्रेट्र : घरेलू सराफा बाजारों में गुरुवार को थोड़ी हलचल देखी गई। दिन के कारोबार में सोना 116 रुपये मजबूती के साथ 39,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी में भी 454 रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 48,060 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंचा। विदेशी बाजारों में सोना थोड़ा चढ़कर 1,504 डॉलर और चांदी 17.94 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर कारोबार कर रहे थे। सराफा बाजार के कारोबार के बारे में एचडीएफसी सिक्युरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा कि क्रिसमस और नए वर्ष के चलते विदेशी निवेशक फिलहाल थोड़ा सुस्त दिख रहे हैं।

आरबीआइ फिर खरीदेगा 10 हजार करोड़ रुपये के बांड्स

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने पूंजी उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के बाद विशेष खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के जरिये 10 हजार करोड़ रुपये के बांड्स खरीदने की घोषणा की। बैंक इतने ही मूल्य के बांड्स की बिक्री भी करेगा। यह प्रक्रिया 30 दिसंबर को होगी।

इसी सप्ताह की शुरआत में आरबीआइ ने ओएमओ के जरिये 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के लंबी अवधि के बांड्स खरीदे थे। बैंक ने उस दिन 6,825 करोड़ रुपये मूल्य के बांड्स की बिक्री की। यह पहला मौका था जब केंद्रीय बैंक ने खुले बाजार में एक साथ बांड्स की खरीद और बिक्री की। केंद्रीय बैंक ने कहा, 'मौजूदा पूंजी स्थिति की समीक्षा और आकलन के बाद आरबीआइ ने 30 दिसंबर, 2019 को ओएमओ के तहत एक बार फिर 10,000-10,000 करोड़ रुपये के सरकारी बांड्स खरीदने और बेचने का फैसला किया है।'

200 घरों को लीलने वाली आग पर आखिरकार हेलीकॉप्टर की मदद से हजारों गैलन पानी छिड़कने के बाद काबू पा लिया गया है चिली में। यहां वैलपरासियो शहर में हुई आगजनी तेज हवाओं के कारण भड़क गई थी, जिसके बाद लोगों को अपने घर छोड़ जाना पड़ा था।

पाक में सेना प्रमुख के सेवा विस्तार मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान की इमरान सरकार ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत में गुरुवार को दाखिल याचिका में फैसले को रद करने और मामले की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ बनाने की अपील की गई है। अटार्नी जनरल अनवर मंसूर के जरिये दाखिल याचिका में सरकार ने मामले की सुनवाई कैमरे की निगरानी में करने का भी आग्रह किया है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने गत 28 नवंबर को बाजवा का कार्यकाल छह माह बढ़ाने की मंजूरी दी थी। सरकार ने कोर्ट को यह भरोसा दिया कि वह सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में छह माह के अंदर कानून बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जिस दिन आया था, उसी दिन बाजवा (59) को सेवानिवृत्त होना था। प्रधानमंत्री इमरान खान ने गत अगस्त में अधिसूचना के जरिये जनरल बाजवा का कार्यकाल तीन साल के लिए

इमरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई बड़ी पीठ में करने की अपील

कमर जावेद बाजवा। फाइल

बढ़ा दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

कोर्ट ने गत 26 नवंबर को कार्यकाल बढ़ाने के तौर-तरीके में अनियमितता के चलते सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि मुल्क में सेना प्रमुख की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा विस्तार के संबंध में कोई कानून ही नहीं है।

शरीफ के विदेश में रुकने के बारे में समिति लेगी निर्णय

लाहौर, आइएएनएस : इलाज के लिए विदेश में रुकने की अवधि बढ़ाने संबंधी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गुजारिश पर निर्णय के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने चार सदस्यीय समिति गठित की है। पंजाब के कानून मंत्री मुहम्मद बशारत रजा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। शरीफ ने इस संबंध में पंजाब के गृह सचिव को पत्र लिखा है।

भ्रष्टाचार मामले में जेल की सजा काट रहे शरीफ को तबीयत बिगड़ने पर पिछले महीने अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चार सप्ताह की जमानत मिलने पर पाकिस्तान की इमरान सरकार ने उन्हें इलाज के लिए बिना शर्त विदेश जाने की इजाजत दे दी थी। अदालत ने इसके साथ ही शरीफ को निर्देश दिया था कि इलाज के लिए जमानत अवधि बढ़ाने की जरूरत पड़ने पर उन्हें पंजाब सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी।

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री दुलर्भ बीमारी का इलाज करवाने लंदन ले जाया गया था।

आतंकरोधी और जलवायु परिवर्तन मोर्चे पर संरा में भारत का डंका

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : भारत ने 10 साल के अथक प्रयासों के बाद 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने में सफलता हासिल की। यह संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद-विरोधी मोर्चे पर भारतीय नेतृत्व की अहमियत को बताता है। भारत ने जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास के मुद्दे पर भी आगे बढ़कर पूरी दुनिया का नेतृत्व किया।

जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने में मिली सफलता

आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई और आतंकियों को न्याय के कठघरे तक पहुंचाने की इसकी प्रतिबद्धता को वर्ष 2019 के ऐतिहासिक लम्हों के तौर पर याद किया जाएगा। जैश-ए-मुहम्मद द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले ने सभी को आक्रोशित कर दिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी इसकी कड़ी निंदा की। पहली बार सयुंक्त राष्ट्र की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों ने एक बयान जारी किया। बयान

सैयद अकबरुद्दीन। फाइल

सुरक्षा परिषद में निर्विरोध चयन

वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक जीत का एक पहलू यह भी रहा कि एशिया-प्रशांत समूह द्वारा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को 2021-22 के लिए निर्विरोध चुनने की वकालत की गई। दो वर्ष की अवधि 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद के पांच अस्थायी सदस्यों का चुनाव अगले साल जून में होगा। भारत की आसान जीत उसे शक्तिशाली देशों के बराबर ला खड़ा करेगी। कुल मिलाकर साल 2019 भारत के लिए कई मामलों में बेहद सफल रहा है।

में पुलवामा में घृणित और कायराना आत्मघाती हमले की सख्त लहजे में निंदा की गई। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।

इस घटना के दो महीने बाद भारत को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी, जब सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति ने 1 मई को अजहर पर पाबंदी लगा दी। परिषद के स्थायी सदस्य चीन ने शुरुआत में तकनीकी आधार पर अड़ंगा लगाते हुए वीटो का प्रयोग किया, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रस्ताव के बाद चीन पीछे हट गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, 'अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो यह साल हमारे लिए कई सफलताओं वाला रहा। यह ऐसा साल रहा, जब हमें हमारे वर्षों के प्रयासों का फल मिला। लगभग एक दशक की कोशिशों के बाद हम मसूद अजहर को आतंकवादियों की सूची में डलवाने में सफल रहे।'उन्होंने कहा, 'पुलवामा हमले के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को लेकर बयान जारी किया। हाफिज को आतंकवादियों की सूची से बाहर करने की कोशिशों को भी हमने विफल किया।' भारत ने यूएन में अन्य कई मुद्दों पर भी पूरी दुनिया की अगुआई की।

मलाला को घोषित किया दशक की सबसे मशहूर टीनएजर

इस्लामाबाद, आइएएनएस : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को दुनिया में दशक की सबसे मशहूर टीनएजर घोषित किया है। यूएन ने अपनी 'डेकेड इन रिव्यू' रिपोर्ट में मलाला के अलावा साल 2010 से 2019 के दौरान की बड़ी घटनाओं को शामिल किया है। इसमें हैती में वर्ष 2010 में आए विनाशकारी भूकंप से लेकर 2011 से सीरिया में छिड़े संघर्ष तक का जिक्र किया गया है।

न्यूज गैलरी

ईरान के साथ चीन और रूस करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास

बीजिंग : ईरान, चीन और रूस की नौसेनाएं ओमान की खाड़ी में शुक्रवार से चार दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही हैं। ईरान के साथ चीन और रूस का यह सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका के साथ इस इस्लामिक देश के रिश्ते बेहद खराब हैं। ईरान के खिलाफ पूर्व में तय समझौते से हटते हुए अमेरिका उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। चीनी विदेश मंत्रालय ने तीनों देशों के इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया। वहीं रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वु कियान ने कहा, इसका लक्ष्य तीनों देशों की नौसेना के बीच सहयोग और आपसी अदला-बदली को बढ़ाना है। चीन ने इस अभ्यास में मिसाइल से लैस युद्धपोत शिनिंग को भी शामिल किया है। (एएफपी)

ब्रूस ली की बेटी ने फूड कंपनी से मांगा 213 करोड़ का हर्जाना

शंघाई : मार्शल आर्ट सुपरस्टार ब्रूस ली की बेटी शैनॉन ने चीन की एक फास्ट फूड कंपनी पर मुकदमा किया है। इस मुकदमे में शैनॉन ने बिना इजाजत उनके पिता की तस्वीर कंपनी के लोगो में इस्तेमाल करने के लिए 21 करोड़ युआन (करीब 213 करोड़ रुपये) के हर्जाने की मांग की है। शैनॉन की कंपनी ब्रूस ली इंटरप्राइजेज ने फूड रेस्तरां चलाने वाली चीन की बड़ी कंपनी कुंगफू कैटरिंग मैनेजमेंट पर आरोप लगाया है कि बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत कीमत चुकाए बगैर कंपनी 15 वर्षों से अपने लोगो में सुपरस्टार ब्रूस ली की तस्वीर का इस्तेमाल कर रही है। कुंगफू कैटरिंग मैनेजमेंट ने इस पर कहा है कि हम मामले का अध्ययन कर रहे हैं। कंपनी के पूरे देश में 600 से ज्यादा रेस्तरां चल रहे हैं। (एएफपी)

म्यांमार के रखाइन में सूकी की पार्टी के नेता की हत्या

यंगून : अंतरराष्ट्रीय अदालत में रोहिंग्या नरसंहार मुद्दे पर सुनवाई के बीच म्यांमार के अशांत रखाइन प्रांत में आंग सान सूकी की पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी गई। इस हत्या में रोहिंग्या समर्थक आतंकी गुट अराकान आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के नेता ये थेइन को गत 11 दिसंबर को अगवा कर लिया गया था। उसी दिन नीदरलैंड्स के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत में म्यांमार सरकार के खिलाफ नरसंहार के आरोप पर सुनवाई शुरू हुई थी। अदालत में म्यांमार सरकार का पक्ष रखने के लिए सूकी खुद हेग गई थीं। वर्ष 2017 में रखाइन में हुई सैन्य कार्रवाई से डरकर लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश पलायन कर गए थे। म्यांमार सरकार रोहिंग्या समर्थित अराकान आर्मी पर ऐसी वारदातों को अंजाम देने का आरोप लगाती रही है। (एएफपी)

इजरायल में आज तय होगा पीएम नेतन्याहू का भविष्य

प्राइमरी चुनाव ▶ लिकुड पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए कराया गया मतदान

भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे नेतन्याहू को अपनी ही पार्टी में मिल रही चुनौती

यरुशलम, आइएएनएस : भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी ही पार्टी के भीतर चुनौती मिली है। सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी का नया नेता चुनने के लिए गुरुवार को प्राइमरी चुनाव कराया गया। नेतन्याहू का सियासी भविष्य तय करने वाले इस चुनाव का नतीजा शुक्रवार को आने की उम्मीद है।

सबसे लंबे समय तक इजरायल के प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू 2005 से लिकुड पार्टी के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। इस चुनाव में उनका मुकाबला पार्टी के सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री गिदोन सार से है। यह पहला मौका है जब नेतन्याहू को पार्टी के भीतर चुनौती मिली है। यरुशलम अखबार के अनुसार, इस चुनाव में लिकुड पार्टी के कुल एक लाख 16 हजार सदस्यों के लिए देशभर में 106 मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान से पहले नेतन्याहू और सार ने बुधवार को अपने लिए वोट की अपील की।

बेंजामिन नेतन्याहू। फाइल/रायटर

गिदोन सार। रायटर

नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'मैं जॉर्डन वैली पर इजरायल की संप्रभुता को मान्यता दिलाने के लिए अमेरिका को राजी करूंगा। केवल मैं ही हूं, जो ऐसा कर सकता है।' जबकि सार ने यह वादा किया कि वह वेस्ट बैंक की बस्तियों में इजरायली कानून को पूरी तरह लागू करेंगे।

नेतन्याहू की जीत का अनुमान : इजरायली मीडिया का अनुमान है कि भ्रष्टाचार मामले में आरोपित किए जाने के बाद पीएम पद से इस्तीफे के बढ़ते दबाव के बावजूद नेतन्याहू इस चुनाव को बड़े अंतर के साथ जीतेंगे।

रॉकेट हमले के कारण बीच में छोड़ी रैली

नेतन्याहू को बुधवार को अश्केलान शहर में एक रैली बीच में ही छोड़नी पड़ी। रॉकेट हमले का सायरन बजने पर उन्हें ऐसा करना पड़ा। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि गाजा पट्टी की ओर से इजरायल की तरफ एक रॉकेट दागा गया था, लेकिन रॉकेट रोधी प्रणाली आयरन डोम ने उसे मार गिराया।

ट्रंप के महाभियोग पर उनकी ही पार्टी में उठने लगे विद्रोही स्वर

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग के सवाल पर उनकी रिपब्लिकन पार्टी में असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। अलास्का से पार्टी की सीनेटर लीजा मर्कोस्की ने कहा है कि महाभियोग पर पार्टी के रुख से वह व्यथित हैं। सीनेट में पार्टी के नेता मिच मैककॉनेल के व्हाइट हाउस से पूरी तरह से समन्वय स्थापित होने के बयान से लीजा असहमत हैं। वह महाभियोग के आरोपों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिए जाने की पक्षधर हैं।

एक न्यूज चैनल से साक्षात्कार में लीजा ने कहा, उन्होंने जबसे मैककॉनेल के बयान को सुना है, तभी से वह व्यथित और परेशान हैं। आरोपों पर ध्यान दिए बगैर क्या हमें केवल राष्ट्रपति का बचाव करना चाहिए? लीजा सीनेट में महाभियोग उचित प्रक्रिया और गुण-दोष के आधार पर चलाए जाने की पक्षधर हैं। लीजा को प्रगतिवादी रिपब्लिकन माना जाता है। वह पहले भी कई मौकों पर राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर चुकी हैं। अक्टूबर 2018 में उन्होंने ट्रंप के मनोनीत व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने के खिलाफ वोट दिया था। उस व्यक्ति पर महिला से यौन दुर्व्यवहार का आरोप था। उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधि सभा ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। प्रतिनिधि सभा में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। जनवरी में यह प्रस्ताव सीनेट के पटल पर रखा जाएगा।

ब्लूमबर्ग ने चुनावी विज्ञापनों पर खर्च किए 855 करोड़ रुपये

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : मीडिया मुगल माइकल ब्लूमबर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए डिजिटल और टीवी विज्ञापनों पर अब तक करीब 12 करोड़ डॉलर (करीब 855 करोड़ रुपये) खर्च कर चुके हैं। अमेरिका में अगले साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं।

इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार बनने के लिए करीब डेढ़ दर्जन लोग अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी में करीब दो माह बाद राज्यवार प्राइमरी चुनाव होने हैं। इस दौड़ में 77 वर्षीय ब्लूमबर्ग ने गत नवंबर में अपनी दावेदारी पेश की थी। पोलिटिको मैगजीन के अनुसार, न्यूयॉर्क के मेयर रह चुके ब्लूमबर्ग अमेरिका के सभी 50 राज्यों में विज्ञापनों पर जमकर खर्च कर रहे हैं। लेकिन कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे बड़े राज्यों में उनकी खास नजर है।

मेयर चुनाव में ब्लूमबर्ग के लिए काम कर चुके सियासी रणनीतिकार जिम मैकलाघलिन ने कहा, 'हमें प्राइमरी चुनाव

न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर ने डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पेश की है दावेदारी

मीडिया मुगल और न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग की फाइल फोटो। एएफपी

में इतना भारी-भरकम खर्च देखने को कभी नहीं मिला।'

सर्वे में पांचवें स्थान पर मीडिया मुगल

क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी की ओर से गत हफ्ते जारी एक राष्ट्रव्यापी सर्वे के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवारी की दौड़ में पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन 30 फीसद वोटों के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद 17 फीसद वोटों के साथ सांसद एलिजाबेथ वारेन हैं। ब्लूमबर्ग महज सात फीसद वोटों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

चीन की सेना ने कहा, भारत-चीन संबंधों में हो रहा सुधार

बीजिंग, प्रेट्र : चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने कहा है कि भारतीय सेना के साथ रणनीतिक वार्ता, वास्तविक सहयोग और आदान-प्रदान में उसके रिश्ते में सुधार आ रहा है। पीएलए ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

दोनों सेनाओं के बीच संबंधों की उत्साहजनक तस्वीर पेश करते हुए रक्षा प्रवक्ता कर्नल वु किआन ने कहा कि हाल ही में भारत में संपन्न आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभ्यास से दोनों तरफ की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। दोनों पक्ष क्षेत्रीय स्थिरता के साथ ही आतंकवाद से लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों की सेनाएं 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की निगरानी जैसा दुरूह कार्य करती हैं।

कर्नल वु ने कहा, 'भारत-चीन सैन्य संबंध संपूर्ण रिश्ते का महत्वपूर्ण अवयव है।' उनसे पूछा गया था कि इस साल अपने भारतीय समकक्ष के साथ संबंधों को लेकर

पीएलए ने इसके लिए मोदी और शी को धन्यवाद दिया

प्रतीकात्मक

पीएलए का विचार क्या है।उन्होंने कहा, 'दोनों देशों के प्रमुखों के प्रयास को धन्यवाद कि सैन्य रिश्ते में सुधार हो रहा है। दोनों देश रणनीतिक वार्ता बनाए रख रहे हैं और वास्तविक सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही अपनी सीमाओं के साथ आदान-प्रदान भी मजबूत कर रहे हैं।'

2018 में वुहान और इस वर्ष चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच हुई शिखर वार्ता में सैन्य संबंध महत्वपूर्ण अवयव था। दोनों नेताओं के बीच 2017 में डोकलाम में 73 दिनों तक चले गतिरोध के बाद शिखर वार्ताएं हुई हैं।

हांगकांग में शॉपिंग सेंटरों के बाहर प्रदर्शन जारी

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में गुरुवार को भी आंदोलन जारी रहा। सैकड़ों लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों ने महानगर के शॉपिंग मॉल के सामने से जुलूस निकाला और वहां होने वाला कारोबार बाधित किया। आंदोलनकारियों ने ऐसा टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक मॉल को सील करने के पुलिस के कदम के खिलाफ किया। क्रिसमस पर इस मॉल में बवाल होने से पुलिस ने इसे सील कर दिया था। बवाल के दौरान एक नौजवान मॉल में गिरकर घायल हो गया था।

क्रिसमस के मौके पर मंगलवार को आंदोलनकारियों ने पूरे महानगर के शॉपिंग मॉल पर प्रदर्शन आयोजित किए थे। कई इलाकों में पुलिस ने जब आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े तो वे हिंसक हो उठे। इसके बाद से शॉपिंग मॉल के बाहर प्रदर्शन जारी हैं। इन प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने शॉपिंग सेंटरों के इर्द-गिर्द सुरक्षा और गश्त बढ़ा दी है। सैंडी नाम के युवा आंदोलनकारी ने बताया कि क्रिसमस पर आंदोलन का मकसद लोगों को यह दिखाना था कि त्योहार पर वे अपना लक्ष्य भूले नहीं हैं, लोकतंत्र की मांग उनका सबसे पहला लक्ष्य है। लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले और

शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई का किया विरोध

प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए हांगकांग में शॉपिंग सेंटरों के पास खड़े पुलिसकर्मी। रायटर

लाठी चलाकर टकराव का माहौल बना दिया जिससे जनसामान्य को परेशानी हुई। करीब सात महीने के आंदोलन के दौरान पुलिस ने दर्जनों बार इस तरह से माहौल बिगाड़ा है। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग किया जिससे हालात बिगड़े। जबकि पुलिस ने कहा है कि हालात बिगड़ते देख उसने न्यूनतम बल का प्रयोग किया। शॉपिंग सेंटर जाने वाले लोगों को रोका जा रहा था और वहां के कारोबार को बाधित किया जा रहा था।

ताइवान स्ट्रेट से फिर गुजरा चीन का विमानवाहक युद्धपोत

ताइपे, एएफपी : नौसेना के बेड़े में हाल ही में शामिल व स्वदेश निर्मित विमानवाहक युद्धपोत शैनडोंग को चीन ने गुरुवार को ताइवान स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) से होकर गुजारा। चीन की इस हरकत का विरोध करते हुए ताइवान ने इसे चीन द्वारा ताइवान के नागरिकों को डराने की कोशिश करने वाला कृत्य करार दिया है। चीन के पड़ोसी व स्वायत्तशासी ताइवान का यह बयान इस संदर्भ में आया है कि ताइवान में 11 जनवरी को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चीन उसके मतदाताओं को डराने में लगा है। इस क्षेत्र से गत माह भी चीन का एक विमानवाहक पोत गुजरा था।

गुरुवार की हरकत पर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है। लोकतांत्रिक ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति व चुनाव में फिर से किस्मत आजमा रहीं साई इन-वेन चीन की मुखर आलोचक रही हैं। चीन ताइवान को अपने देश का ही एक हिस्सा मानता है।

ओसीआइ कार्ड की खामियों को दूर करने की मांग

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में रह रहे कई भारतीयों को ओसीआइ कार्ड के चलते कठिनाई झेलनी पड़ रही है। प्रमुख अप्रवासी भारतीय ने कहा है कि भारत सरकार को इस जीवन पर्यंत वीजा प्रणाली की खामियों को दूर करना चाहिए जिससे यह अपने उद्देश्यों पर खरा उतर सके।

ओसीआइ कार्ड के प्रावधानों में 20 वर्ष से कम और 50 वर्ष से ज्यादा के धारकों को पासपोर्ट के नवीनीकरण के साथ अपने कार्ड का भी नवीनीकरण कराना होता है। लेकिन भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस नवीनीकरण की सूचना को आगे बढ़ाने में अक्षम साबित हो रहा है। दुनिया के कई प्रमुख हवाई अड्डों और एयरलाइन कंपनियों के पास ओसीआइ कार्ड के नवीनीकरण की सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके चलते यात्रियों को भारत जाते समय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई अप्रवासी भारतीयों को तो बीच रास्ते से ही वापस जाना पड़ा है। कार्ड धारकों से अपना पुराना पासपोर्ट साथ लेकर भी यात्रा करने के लिए कहा गया है जिससे वे कठिनाई से बच सकें।

ब्रेक्जिट मामला

टिम्मरमंस ने यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलगाव पर जताया अफसोस, कहा- 28 सदस्यीय समूह में इस देश की वापसी का हमेशा किया जाएगा स्वागत

ईयू के उपाध्यक्ष ने ब्रिटेन को लिखा 'लव लेटर'

लंदन, एएफपी : यूरोपीय यूनियन (ईयू) के एक शीर्ष अधिकारी ने ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन को 'लव लेटर' लिखा है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के फैसले पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इस 28 सदस्यीय समूह में इस देश की वापसी का हमेशा स्वागत किया जाएगा।

यूरोपीय कमीशन के उपाध्यक्ष फ्रैंस टिम्मरमंस ने गुरुवार को गार्जियन अखबार में लिखा, 'मैं आपको अब जान गया हूं और आइ लव यू। मैं आपके पुराने प्रेमी की तरह हूं। मैं आपकी क्षमताओं और कमजोरियों को जानता हूं। आपके अलग होने के फैसले ने मेरा दिल तोड़ दिया है, लेकिन मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं।' टिम्मरमंस ने 'ब्रिटेन के लिए मेरा प्रेम पत्र : पारिवारिक संबंध वास्तव में कभी टूट नहीं सकते' शीर्षक से छपे अपने पैगाम के आखिर में लिखा, 'हम दूर नहीं होने जा रहे हैं और वापसी पर आपका सदैव स्वागत किया जाएगा।' उन्होंने ब्रेक्जिट पर 2016 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन के जनमत संग्रह कराने के फैसले को गलती करार दिया है।

2016 में हुआ था जनमत संग्रह

ब्रिटेन में ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने) पर साल 2016 में जनमत संग्रह कराया गया था। तब ब्रेक्जिट के पक्ष में 52 फीसद वोट पड़े थे, लेकिन तब से इस मसले पर ब्रिटेन में सियासी गतिरोध बना बना हुआ है।

फ्रैंस टिम्मरमंस। फाइल

31 जनवरी तक ब्रेक्जिट को अंजाम देने का वादा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसी माह बहुमत के साथ आम चुनाव जीतने पर वादा किया था कि 31 जनवरी की तय समय सीमा पर ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। ब्रिटेन में गत 12 दिसंबर को हुए आम चुनाव में जॉनसन की सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी की जीत ब्रेक्जिट विरोधी दलों के लिए करारा झटका मानी गई थी। लेबर पार्टी समेत कई दलों ने संसद में यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया था। इसके बाद जॉनसन ने मध्यावधि चुनाव का एलान किया था।

उत्तर कोरिया पर नजर रख रहे हैं अमेरिकी टोही विमान

सियोल, आइएएनएस : उत्तर कोरिया द्वारा लगातार धमकी दिए जाने के मद्देनजर अमेरिकी टोही विमान कोरियाई प्रायद्वीप पर लगातार नजर रख रहे हैं। रडार पर मिली सूचना के अनुसार, गुरुवार को अमेरिका के विशेष खोजी विमानों को फिर से इस क्षेत्र में उड़ान भरते हुए देखा गया। कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर बीते दो दिनों में चार अमेरिकी टोही विमानों को उड़ान भरते देखा गया था।

अमेरिका के इन खोजी विमानों को उत्तर कोरिया की उस चेतावनी के जवाब में देखा जा रहा है, जिसमें इस कम्युनिस्ट देश ने कहा था कि साल के अंत तक वह अमेरिका को 'क्रिसमस गिफ्ट' दे सकता है। उत्तर कोरिया की इस धमकी को परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर अमेरिका से संभावित किसी बातचीत से पहले दबाव बनाने के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका से अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में छूट नहीं मिलने की दशा में उत्तर कोरिया ने अगले वर्ष से अपनी रणनीति बदलने की धमकी भी दे रखी है।

इमरान को गुलाम कश्मीर पर भारत के हमले का भय

इस्लामाबाद, प्रेट्र : भारत अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए आजाद कश्मीर (पाकिस्तान के कब्जे वाला) पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तानी सेना भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने झेलम जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इमरान ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की फायरिंग में दो पाकिस्तानी जवानों को मारे जाने के कुछ घंटों बाद यह बात कही।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पर लगातार भड़काव वाली फायरिंग कर रही है। कहा, वह पांच महीनों से दुनिया को बता रहे हैं कि भारत की मोदी और आरएसएस की सरकार जम्मू-कश्मीर और नए नागरिकता कानून से पैदा अशांति से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर हमला करवा सकती है। इमरान ने कहा, उन्होंने सेना प्रमुख जनरल बाजवा से भारतीय की

- **कहा, अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए पीओके पर कर सकता है सैन्य कार्रवाई**
- **जनरल बाजवा ने किया है आश्वस्त कि हम पूरी तरह तैयार**

धमकियों के बारे में बात की है। उन्होंने (जनरल बाजवा ने) आश्वस्त किया भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से तैयार है। इमरान ने नियंत्रण रेखा पर मारे गए दोनों पाकिस्तानी सैनिकों के परिजनों के लिए संवेदना भी जाहिर की।

इमरान ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून ने और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के कारण भारत ने में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान आंदोलित हैं। उन्होंने कहा, वह पाकिस्तान में वैसा कुछ नहीं करने जा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ किया है उससे उनकी लोकप्रियता कम होने की शुरुआत हो चुकी है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज बेहद रोमांचक होगी।
— रविचंद्रन अश्विन, भारतीय स्पिनर

स्टेन और नाइल मेलबर्न स्टार्स टीम में शामिल

मेलबर्न, आइएएनएस : दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन और ऑस्ट्रेलिया के नाथन कुल्टर नाइल को बिग बैश लीग (बीबीएल) के मौजूदा सत्र के लिए मेलबर्न स्टार्स की 13 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। अगस्त में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले स्टेन को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने छह मैच खेलने की इजाजत दी थी और वह ऑस्ट्रेलियाई टी-20 लीग में पदार्पण करेंगे।

स्मिथ की निगाह एक और शतक पर

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दिन बनाए चार विकेट पर 257 रन स्टीव 77 रनों पर टिके

मेलबर्न, एएफपी : स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने नाबाद 77 रन बनाकर एक और शतक की तरफ कदम बढ़ा दिए है जिससे ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले दिन चार विकेट पर 257 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा।

न्यूजीलैंड का यह 1987 के बाद मेलबर्न क्रिकेट मैदान (एमसीजी) पर पहला 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट मैच है जिसमें कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। बादल छाए हुए थे और ऐसे में उनका फैसला सही साबित हुआ क्योंकि जो बर्न्स पहले ओवर में आउट हो गए और लंच से पहले डेविड वार्नर (41) भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद मार्नस लाबुशाने (63) और स्मिथ ने अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को वापसी दिलाई और अनुशासित गेंदबाजी करने के बावजूद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को निराश किया। पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय स्मिथ के साथ ट्रेविस हेड 25 रन पर खेल रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में कोलिन डि ग्रैंडहोम ने 48 रन देकर दो विकेट लिए।

न्यूजीलैंड के लिए स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि मेलबर्न में पिछले चार टेस्ट मैचों में शतक जड़ने वाले स्मिथ एक और सैकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। स्मिथ ने कहा, 'उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की और क्षेत्ररक्षण सजाया उसे देखते हुए मुझे ध्यान से खेलना पड़ा। यह ऐसा विकेट नहीं था जिसमें आप हावी होकर खेल सको। मुझे लगता है कि हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया।' न्यूजीलैंड को तीन मैचों की सीरीज बराबर करने के लिए इस दूसरे टेस्ट मैच में जीत की दरकार है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में पहला टेस्ट मैच 296 रन से जीता था। विलियमसन ने बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही पिच पर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। पहले ओवर में लगा कि उनका यह फैसला सही है। पसली की चोट से उबरकर वापसी करने वाले बायें हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पहली तीन गेंदों पर वार्नर को परेशान किया और चौथी गेंद पर बर्न्स का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। न्यूजीलैंड के प्रशंसकों ने इस अच्छी शुरुआत का दिल खोलकर स्वागत किया। इसके बाद वार्नर और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे लाबुशाने ने पारी संवारने की कोशिश की, लेकिन नील वैगनर ने लंच से पहले न्यूजीलैंड को दूसरी सफलता भी दिला दी। उनकी स्विंग लेती गेंद वार्नर के बल्ले को चूमकर स्लिप में टिम साउथी के पास चली गई। लाबुशाने ने फिर से खुद को ऑस्ट्रेलिया की नई दीवार साबित किया, लेकिन जब वह 63 रन पर खेल रहे थे तो अजीबोगरीब तरीके से आउट हो गए। कोलिन की उठती गेंद को उन्होंने छोड़ना चाहा, लेकिन वह उनकी कोहनी से लगकर विकेटों पर गिर गई। लाबुशाने ने वार्नर के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 और स्मिथ के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 रन जोड़े। मैथ्यू वेड (38) आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज थे जिन्हें कोलिन ने विकेटकीपर बीजे वाटलिंग के हाथों कैच कराया। स्मिथ और वेड ने चौथे विकेट के लिए 70 रन जोड़े। इस बीच, स्मिथ ने 103 गेंदों पर अपना 28वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया।

बॉक्सिंग-डे टेस्ट-1

मैच देखने पहुंचे रिकॉर्ड दर्शक

मेलबर्न : बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन 80000 से अधिक दर्शक मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर पहुंचे जोकि इन दोनों देशों के बीच मैच में दर्शकों की रिकॉर्ड संख्या है। इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में एशेज मैच के पहले दिन कुल 91112 दर्शक एमसीजी पहुंचे जो एक रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे मैच के पहले दिन 80473 दर्शकों ने स्टेडियम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह एशेज से इतर किसी मैच में दूसरी सबसे बड़ी दर्शक संख्या है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 1975 में बॉक्सिंग डे के पहले दिन मैच देखने के लिए 85661 दर्शक पहुंचे थे। न्यूजीलैंड 1987 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेल रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख केविन रॉबर्ट्स ने कहा कि दर्शक संख्या से दोनों देशों में इस खेल की लोकप्रियता का पता चलता है। क्रिकेट प्रशंसकों का आभार जिन्होंने एमसीजी पर इतिहास रचा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मेलबर्न में एक दिन में सर्वाधिक दर्शकों का पिछला रिकॉर्ड 51087 का था।

624 रन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 2015 के बाद से बॉक्सिंग डे टेस्ट की छह पारियों में बनाए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 77 रनों के अलावा 102*, 76, 165*, 70*, 134* की पारियां भी खेली हैं

स्कोर बोर्ड

टॉस : न्यूजीलैंड (गेंदबाजी)

ऑस्ट्रेलिया पहली पारी 257/4 (90 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
डेविड वार्नर का. साउथी बो. वैगनर	41	64	03	00
जो बर्न्स बो. बोल्ट	00	01	00	00
मार्नस लाबुशाने बो. कोलिन	63	149	06	01
स्टीव स्मिथ नाबाद	77	192	08	01
मैथ्यू वेड का. वाटलिंग बो. कोलिन	38	78	03	00
ट्रेविस हेड नाबाद	25	56	03	00

अतिरिक्त : (बा-1, लेबा-11, वा-1) 13

कुल : 90 ओवर में चार विकेट पर 257 रन

विकेट पतन : 1-1 (बर्न्स, 0.4), 2-61 (वार्नर, 21.2), 3-144 (लाबुशाने, 49.5), 4-216 (वेड, 73.3)

गेंदबाजी : ट्रेंट बोल्ट 20-2-60-1, टिम साउथी 21-5-63-0, डि ग्रैंडहोम 21-5-48-2, नील वैगनर 21-7-40-1, मिशेल सेंटनर 7-1-34-0

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ • एएफपी

स्मिथ ने एमसीजी पर भी दर्शकों की हूटिंग झेली

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कैलेंडर के सबसे बड़े दिन पर ऑस्ट्रेलिया का कोई भी क्रिकेटर दर्शकों की फब्तियों की उम्मीद नहीं करेगा लेकिन पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्मिथ ने बाद में कहा, 'क्या ऐसा हुआ? मुझे पता नहीं है।' ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिरने के बाद स्मिथ जब 80000 से अधिक दर्शकों के सामने क्रीज पर उतरे तो कुछ दर्शकों ने तालियां बजाई तो कुछ ने उनकी हूटिंग की। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह हूटिंग स्मिथ पर मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ के मामले में लगे एक साल के प्रतिबंध के कारण की गई। स्मिथ तब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। उन्होंने कहा, 'जब मैं बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर जाता हूं तो वास्तव में ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देता। प्रशंसा हो या आलोचना। मैंने इन पर ध्यान नहीं देना सीख लिया है।'

77 रन बनाने वाले स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ग्रेग चैपल (7110) से आगे निकल गए। चैपल को पीछे छोड़ने में उन्हें 39 रन की दरकार थी। अब उनके 7149 रन हो गए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर पहुंचे। इस सूची में रिकी पोंटिंग (13378) शीर्ष पर हैं

डिकॉक ने द. अफ्रीका को संभाला

नई दिल्ली, जेएनएन : शुरुआती झटकों के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के उपयोगी अर्धशतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को सेंचुरियन में खेले जा रहे बॉक्सिंग-डे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम की पारी को संभाल लिया। डिकॉक ने 95 रन बनाए और उनकी पारी से दक्षिण अफ्रीका ने पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद 82.4 ओवर में नौ विकेट पर 277 रन बनाए। क्रीज पर वर्नोन फिलेंडर (28*) डटे हैं। मेहमान टीम की ओर से सैम कुर्रन (4/57) ने सर्वाधिक विकेट झटके।

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले को अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने सही साबित भी किया जब उन्होंने सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर (00) को मैच की पहली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद भी मेजबान टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। एडेन मार्करैम (20) और जुबैर हमजा (39) ने टीम की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सैम कुर्रन ने मार्करैम को बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी का अंत किया। टीम के खाते में 111 रन ही जुड़े थे और आधी टीम पवेलियन बैठी थी। यहां से डिकॉक ने ड्वेन प्रिटोरियस के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी कर स्कोर बोर्ड को चलाना जारी रखा लेकिन कुर्रन ने प्रिटोरियस (33) को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। हालांकि एक छोर पर खड़े डिकॉक ने फिलेंडर के साथ सातवें विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी करके अपने शतक की उम्मीद जगाई, लेकिन इस बार भी कुर्रन ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। इंग्लिश तेज गेंदबाज ने डिकॉक को टेस्ट करियर का छठा शतक जड़ने से रोक दिया। उन्होंने अपने करियर का 18वां अर्धशतक लगाया।

एंडरसन का 150वां टेस्ट मैच, ओवरऑल नौवें क्रिकेटर : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन गुरुवार को अपना 150वां टेस्ट मैच खेलने उतरे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन मैदान पर वह इंग्लिश कैप में उतरे और उन्होंने खास उपलब्धि अपने नाम की। 22 मई 2003 को अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले एंडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में एलेस्टियर कुक (161) के बाद दूसरे नंबर पर हैं। एंडरसन ने अपने टेस्ट करियर में अभी तक 576 विकेट लिए हैं। वह 150 टेस्ट मैच खेलने वाले ओवरऑल नौवें क्रिकेटर बने। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच भारत के सचिन तेंदुलकर (200) ने खेले हैं। उनके बाद रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ (168), जैक कैलिस (166), शिवनारायण चंद्रपॉल और राहुल द्रविड़ (164), कुक (161) और एलन बॉर्डर (156) का नंबर आता है।

फोटोग्राफर के चोटिल होने से देर से शुरू हुआ मैच : फोटोग्राफर क्रिस्टियन कोट्जे साइटस्क्रीन के सामने ही चोटिल हो गए। इससे मैच के शुरू होने में देरी हुई। एएफपी न्यूज एजेंसी के लिए काम कर रहे कोट्जे ने टेस्ट शुरू होने से पहले कुछ फोटो क्लिक कीं और साइटस्क्रीन के सामने चलने लगे लेकिन अचानक बाउंड्री की रस्सी पर गिर पड़े।

बॉक्सिंग-डे टेस्ट-2

- विकेटकीपर बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए उपयोगी 95 रन
- द. अफ्रीका ने पहले टेस्ट के पहले दिन नौ विकेट पर 277 रन बनाए

इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद क्विंटन डिकॉक • रायटर

10 सालों में टेस्ट की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज

गेंदबाज	बल्लेबाज	जगह	वर्ष
जेम्स एंडरसन	डीन एल्गर	सेंचुरियन	2019
सुरंगा लकमल	केएल राहुल	कोलकाता	2017
मिशेल स्टार्क	डी. करुणारत्ने	गाले	2016
सुरंगा लकमल	क्रिस गेल	पल्लीकल	2010
डेल स्टेन	एंड्रयू स्ट्रॉस	जोहानिसबर्ग	2010

एक गेंदबाज द्वारा सर्वाधिक टेस्ट मैच

मैच	गेंदबाज	देश
150	जेम्स एंडरसन	इंग्लैंड
145	शेन वॉर्न	ऑस्ट्रेलिया
135	स्टुअर्ट ब्रॉड	इंग्लैंड
133	मुरलीधरन	श्रीलंका
132	अनिल कुंबले	भारत

दशक में 400 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने ब्रॉड

सेंचुरियन : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 10 साल में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। ब्रॉड से पहले उनके ही देश के जेम्स एंडरसन ने इस दशक में यह मील का पत्थर छुआ है। ब्रॉड ने यहां दक्षिण अफ्रीका के साथ जारी पहले टेस्ट मैच के दौरान यह मुकाम हासिल किया। ब्रॉड ने मेजबान कप्तान फाफ डुप्लेसिस को 29 रन पर आउट करते हुए खुद को इस क्लब में शामिल किया। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने पिछले 10 सालों में 376, श्रीलंका के रंगना हेराथ ने 363 और भारत के रविचंद्रन अश्विन ने 362 टेस्ट विकेट लिए हैं।

03 इंग्लिश गेंदबाज पहले ही किसी टेस्ट मैच की पहली गेंद पर विकेट ले चुके हैं। जेम्स एंडरसन, रियान साइडबॉटम, जैफ ऑर्नल्ड (02 बार) और मॉरिस टैट के बाद ऐसा करने वाले चौथे इंग्लिश गेंदबाज बने

32 वें बल्लेबाज बन गए हैं डीन एल्गर जो टेस्ट मैच की पहली गेंद पर आउट हुए हैं। उनका विकेट इंग्लिश तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने लिया

50 से ज्यादा का स्कोर छह बार क्विंटन डिकॉक ने अपने घर में पिछली आठ टेस्ट पारियों में किया है और उनका औसत 70 के आसपास रहा है

एशिया एकादश का हिस्सा नहीं होंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर : बीसीसीआइ

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : खराब राजनयिक रिश्तों के बीच भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को साथ खेलते देखने की संभावना फिलहाल नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी अगले साल एशिया एकादश टीम में एक साथ नहीं खेलेंगे। मार्च 2020 में बांग्लादेश की मेजबानी में एशिया एकादश और विश्व एकादश के बीच दो टी-20 मैच खेले जाने हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब उर रहमान की जन्मशताब्दी मना रहा है और इसी के चलते उसकी मेजबानी में अगले साल मार्च में दो टी-20 मैच खेले जाएंगे। आइसीसी इन मैचों को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने को तैयार भी हो गया है। ये दोनों मैच 18 से 22 मार्च, 2020 के बीच खेले जाने हैं।

बीसीसीआइ के संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज ने कहा कि साफ संदेश है कि पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को एशिया एकादश टीम का हिस्सा बनने के लिए बुलाया नहीं जाएगा। बीसीसीआइ के मुखिया सौरव गांगुली यह तय करेंगे कि भारत के कौन से पांच खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा बनेंगे। जॉर्ज ने कहा कि हमें यह जानकारी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी एशिया एकादश का हिस्सा नहीं होंगे। सवाल नहीं उठता कि दोनों देश साथ खेलें। हालांकि गांगुली ने पहले कहा था कि यह मुकाबला एशिया एकादश बनाम विश्व एकादश है और इसके लिए आइसीसी की ओर से स्वीकार्यता चाहिए होगी।

विराट, धौनी बन सकते हैं हिस्सा : जानकारी के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी, रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को एशिया एकादश टीम का हिस्सा बनने को कहा है। बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन ने कहा था कि हम इन मैचों के लिए मौजूदा टीम में से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल करने के बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि इन मैचों का अंतरराष्ट्रीय दर्जा होगा। ऐसे में हर खिलाड़ी इसे गंभीरता से लेगा।

भारत-पाक क्रिकेट संबंध ठंडे बस्ते में : भारत और पाकिस्तान के बीच तल्ख राजनयिक रिश्तों के चलते दोनों देशों के क्रिकेट संबंध भी निलंबित हैं। हालांकि आइसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप जैसे बहुदेशीय टूर्नामेंट ये दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। विश्व एकादश टीम ने अब तक तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जबकि एशिया एकादश ने कोई भी टी-20 मैच नहीं खेला है। विश्व एकादश ने आखिरी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान पर 31 मार्च, 2018 को खेला था।

अगले साल बांग्लादेश में विश्व एकादश और एशिया एकादश के बीच होने हैं दो टी-20 मैच

देवांग पर अनधिकृत तरीके से ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करने का आरोप, क्रिकेटर मनोज तिवारी ने जताई थी आपत्ति

राष्ट्रीय चयनकर्ता को बंगाल ड्रेसिंग रूम से निकाला गया

खेल संवाददाता, कोलकाता : राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ता देवांग गांधी को गुरुवार को ईडन गार्डेंस स्टेडियम में बंगाल रणजी टीम के ड्रेसिंग रूम से निकल जाने को कहा गया। बंगाल टीम के पूर्व कप्तान मनोज तिवारी के आपत्ति जताने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की भ्रष्टाचार-रोधी टीम के अधिकारी सौमेन कर्मकार ने देवांग को यह निर्देश दिया। देवांग पर अनधिकृत तरीके से ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करने का आरोप लगा है। दूसरी तरफ पूर्वी क्षेत्र से इस चयनकर्ता ने आरोप से इन्कार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। बीसीसीआइ की भ्रष्टाचार-रोधी टीम के एक अधिकारी से अनुमति लेकर वह ड्रेसिंग रूम में आए थे।

उन्होंने आगे कहा कि बंगाल टीम के कोच अरुण लाल ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में आमंत्रित किया था, जो उनके पहले कप्तान भी रहे हैं। उनकी पीठ में समस्या है इसलिए बंगाल टीम के फिजियो को मेडिकल रूम में बुलाने के लिए वहां गए थे लेकिन मनोज को इसमें मुद्दा दिख गया। इससे सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि बंगाल की पूरी क्रिकेट बिरादरी को बुरा लगा है। वह मनोज के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कर युवाओं के लिए अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया है। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार-रोधी संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है। राष्ट्रीय चयनकर्ता अनधिकृत तरीके से ड्रेसिंग रूम में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल खिलाड़ी और टीम के सपोर्ट स्टाफ ही आ सकते हैं।' इस घटना की जानकारी बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली को दी गई है।

कैब ने कहा, देवांग ने नहीं किया नियमों का उल्लंघन : इस बीच बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) ने देवांग का बचाव किया है। कैब की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि राष्ट्रीय चयनकर्ता देवांग गांधी ड्रेसिंग रूम एरिया में उस वक्त आना चाहते थे, जब खेल नहीं चल रहा था। देवांग गांधी को भ्रष्टाचार-रोधी टीम के अधिकारी ने मैच रेफरी से अनुमति लेकर अस्थायी आगंतुक के तौर पर खिलाड़ियों एवं मैच अधिकारियों के एरिया में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। देवांग गांधी कुछ चिकित्सा कराना चाहते थे। उन्होंने इसकी भ्रष्टाचार-रोधी टीम के अधिकारी को जानकारी दी थी। उक्त अधिकारी ने नियमों को देखते हुए उन्हें खिलाड़ियों एवं मैच अधिकारियों के एरिया के बाहर स्थित मेडिकल रूम में जाने को कहा था और उनके कहे अनुसार गांधी वहां चले गए थे।

289 रन पर सिमटी बंगाल की पहली पारी : आंध्र प्रदेश के खिलाफ रणजी मैच के दूसरे दिन बंगाल की पारी 289 रन पर सिमट गई। इस दिन बंगाल के छह विकेट महज 48 रन पर गिर गए। हालांकि इसकी बड़ी वजह खराब रोशनी बताई जा रही है। सूर्यग्रहण और बदली छाए रहने के कारण रोशनी काफी कम थी। दो बार खेल रोकना पड़ा था। दूसरे दिन 21 ओवर का ही खेल हो पाया। बंगाल की पारी सिमटने के बाद दूसरे दिन का खेल स्थगित कर दिया गया। आंध्र की ओर से चिरुपल्ली स्टीफन और केवी शशिकांत ने चार-चार विकेट लिए।

रणजी ट्रॉफी

हरियाणा ने बनाए 285 रन

जमशेदपुर : हरियाणा ने ग्रुप सी के मुकाबले में गुरुवार को झारखंड के खिलाफ पहली पारी में छह विकेट पर 285 रन बना लिए हैं। दूसरे दिन खराब मौसम और कम रोशनी के कारण सिर्फ चार ओवर का ही खेल हो सका। पहले दिन के स्कोर छह विकेट पर 274 रन से आगे खेलने उतरी हरियाणा अपने स्कोर में 11 रन ही जोड़ सकी। चेतन्य बिश्नोई 75 और हर्षल पटेल 47 रन बनाकर नाबाद हैं।

सौराष्ट्र के खिलाफ उप्र की वापसी

नई दिल्ली : सौराष्ट्र के खिलाफ राजकोट में ग्रुप बी मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने दूसरे दिन जबरदस्त वापसी की। सौराष्ट्र को 323 रनों पर ऑलआउट करने के बाद उत्तर प्रदेश ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट के नुकसान पर 222 रन बना लिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए सलामी बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने 52, अक्शदीप नाथ ने नाबाद 80 और मुहम्मद सैफ ने नाबाद 41 रन बनाए। इससे पहले लेग स्पिनर सौरभ कुमार के चार और कलाई के स्पिनर जीशान अंसारी के तीन विकेट की बदौलत उत्तर प्रदेश ने सौराष्ट्र की पहली पारी 323 रन पर समेट दी थी। सौराष्ट्र के लिए चेतेश्वर पुजारा और शेल्डन जैक्सन ने सबसे ज्यादा 57-57 रन बनाए। सौराष्ट्र जैसी मजबूत टीम के सामने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस मैच में काफी शानदार संघर्ष दिखाया है। उत्तर प्रदेश की टीम के दिग्गज खिलाड़ियों के प्रदेश छोड़ने और प्रवीण कुमार जैसे तेज गेंदबाज के संन्यास लेने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की टीम बेहद जूझ रही है। सुरेश रैना भी चोटिल होने के कारण फिलहाल टीम से बाहर हैं।

बदली आबोहवा कड़ाके की ठंड में रीयल कश्मीर का मैच देखने के लिए जुटे कश्मीरी

जन्नत पर चढ़ा फुटबॉल का खुमार

रजिया नूर • श्रीनगर

कश्मीर की आबोहवा गुरुवार को कुछ बदली-बदली नजर आ रही थी। खिले चेहरे और सीटियां बजाती दर्शकों की भीड़। तनाव तो मानो छूमंतर हो चुका था। कड़ाके की ठंड (न्यूनतम तापमान माइनस पांच और अधिकतम 8.4 डिग्री) भी गर्मी का एहसास करवा रही थी। ऐसा हो भी क्यों न, कश्मीर में यह फुटबॉल के जादू का असर है। मानो जन्नत पर फुटबॉल का खुमार चढ़ गया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यहां पहली बार कोई मैच हुआ है।

श्रीनगर के टीआरसी टर्फ मैदान में कश्मीर के युवाओं की धड़कन रीयल कश्मीर क्लब और चेन्नई सिटी के बीच आइ-लीग का पहला फुटबॉल मुकाबला खेला गया। रोमांच और रफ्तार से भरा यह मैच रीयल कश्मीर ने 2-1 से जीत लिया। श्रीनगर में डेढ़ घंटे तक जारी रहे इस रोमांचक मैच के पहले हाफ में रीयल कश्मीर ने चेन्नई के खिलाफ दो गोल दागे। पहला गोल दानिश फारूक ने खेल शुरू होने के चंद मिनट बाद ही ठोक दिया। दूसरा गोल जेडी आरमांड ने हाफ टाइम शुरू होने से 12 मिनट बाद किया। दो गोल की बढ़त से मैच देखने आए रीयल कश्मीर के दर्शकों का उत्साह व जोश चरम पर पहुंच गया। युवाओं ने सीटियां व तालियां बजाकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ाया।

चेन्नई की टीम हाफ टाइम शुरू होने के 18 मिनट बाद रीयल कश्मीर के खिलाफ गोल करने में कामयाब हुई। यह गोल चेन्नई की तरफ से काटसुमी यूसा ने दागा। पूरा खेल रोमांच से भरा रहा। दोनों टीमें एक-दूसरे पर हावी होने के लिए जी तोड़ कोशिश करती नजर आईं। गोल करने की कोशिश में चेन्नई के दो खिलाड़ी घायल भी हो गए। रीयल कश्मीर का अगला मैच पांच जनवरी को मोहन बगान के खिलाफ होगा। इससे पहले 12 और 15 दिसंबर को खेले जाने वाले मैच खराब मौसम के चलते स्थगित करने पड़े थे।

श्रीनगर के टीआरसी मैदान में मैच देखने के लिए हजारों युवा उमड़े। अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते रीयल कश्मीर के समर्थक। कामरान रशीद बट

पिता बोले, ओलंपिक में अच्छा करना चाहते हैं पेस

टेनिस

दिग्गज टेनिस खिलाड़ी पेस अगले साल टेनिस से लेंगे संन्यास

कोलकाता, आइएएनएस : अगले साल टेनिस को अलविदा कहने का एलान कर चुके भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता डॉ. वेस पेस का कहना है कि उनका बेटा अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों और डेविस कप विश्व ग्रुप क्वालीफायर में चमकदार प्रदर्शन के साथ इस खेल को अलविदा कहना चाहते है।

वेस ने गुरुवार को कहा, 'डेविस कप मार्च में है और फिर जुलाई-अगस्त में टोक्यो में ओलंपिक है। पेस दोनों टूर्नामेंटों में देश के लिए खेलना चाहते हैं और अपना शत-प्रतिशत देना चाहते हैं। वह 35 साल खेलने के बाद इस खेल को अलविदा कहेंगे।' पेस 46 साल के हैं और उन्होंने कहा है कि अगले साल वह कुछ चुनिंदा टूर्नामेंटों में खेलेंगे। पेस के नाम 18 डबल्स और मिक्स्ड डबल्स ग्रैंडस्लैम खिताब हैं और इसके अलावा 1996 के अटलांटा ओलंपिक में वह कांस्य पदक जीत चुके हैं। वह 1992 से 2016 तक लगातार ओलंपिक में खेले हैं। वह सात बार ओलंपिक खेलने वाले दुनिया के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। वेस पेस ने आगे कहा, 'लिएंडर बीते चार-पांच महीनों से संन्यास के बारे में सोच रहा था। वह 46 का हो गया है और अब उम्र उस पर हावी होने लगी है। वह अपनी बेटी के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है और यही कारण है कि उसने 2020 में टेनिस को अलविदा कहने का मन बनाया है।' अपने करियर में पेस ने 54 डबल खिताब जीते हैं। वह डेविस कप इतिहास के सबसे सफल डबल्स खिलाड़ी रहे हैं। 1972 में हॉकी में म्यूनिख ओलंपिक में भारत के लिए खेल चुके वेस पेस ने कहा, 'मुझे उसकी सफलता पर गर्व है। कभी-कभी इसे बयां करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते। वह अपने पूरे करियर में चैंपियन की तरह खेला है।'

कोहली दशक के पांच सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटरों में शामिल

लंदन, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन क्रिकेट अलमानैक ने चार अन्य खिलाड़ियों के साथ दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है। कोहली के अलावा दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और एबी डिविलियर्स, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और महिला क्रिकेट की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पैरी इस सूची में शामिल हैं। कोहली के लिए पिछले 10 साल बेहद ही शानदार रहे हैं।

कोहली ने पिछले 10 साल में किसी भी अन्य बल्लेबाज की तुलना में 5,775 अधिक रन बनाए और वह इस दशक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे। इस 31 वर्षीय बल्लेबाज को दशक की विजडन टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है जबकि वह वनडे टीम में भी शामिल हैं। विजडन ने लिखा है कि विराट प्रतिभाशाली हैं। इंग्लैंड के 2014 के दौरे के आखिर से लेकर बांग्लादेश के खिलाफ नवंबर में कोलकाता टेस्ट तक उन्होंने 63 की औसत से रन बनाए जिसमें 21 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं। इसमें लिखा गया है कि वह तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में कम से कम 50 की औसत से रन बनाने वाले अकेले बल्लेबाज हैं। यहां तक कि हाल में स्टीव स्मिथ ने भी टिप्पणी की थी कि उनके जैसा कोई नहीं है। विजडन के अनुसार पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेने और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के करियर के अवसान की तरफ बढ़ने के बाद विश्व में कोई भी अन्य क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो हर दिन कोहली जैसे दबाव में खेलता हो।

कोहली ने पिछले 10 साल में टेस्ट क्रिकेट में 27 शतकों की मदद से 7,202 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने वनडे में 11,125 और टी-20 में 2,633 रन बनाए। उनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 70 शतक दर्ज हैं और वह केवल तेंदुलकर (100) और रिकी पोंटिंग (71) से पीछे हैं।

उपलब्धि

- ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिस पैरी को भी मिली जगह
- स्टेन, डिविलियर्स और स्टीव स्मिथ का भी नाम

क्रिसमस के दौरान प्रीमियर लीग मैचों के कार्यक्रम पर भड़के क्लॉप

लंदन, आइएएनएस : मौजूदा यूरोपीयन चैंपियन लिवरपूल के मुख्य कोच जुर्गेन क्लॉप ने क्रिसमस के दौरान प्रीमियर लीग के मैचों के कार्यक्रम की आलोचना की है। लिवरपूल को गुरुवार रात लिसेस्टर सिटी के खिलाफ और रविवार को वोल्व्वेस के खिलाफ मैच खेलना है जबकि मैनचेस्टर सिटी को शुक्रवार को वोल्वेस से और रविवार को शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ अपना अगला मैच खेलना है।

यह देखकर काफी अच्छा लगता है कि असम से अब काफी मुक्केबाज आ रहे हैं।
– जमुना बोरो, भारतीय महिला मुक्केबाज

न्यूज गैलरी

ओलंपिक क्वालीफायर ट्रायल्स में नहीं चुने जाने पर भड़के बिधूड़ी

नई दिल्ली : विश्व चैंपियनशिप के पूर्व कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज गौरव बिधूड़ी ने अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के मद्देनजर आगामी ट्रायल्स के लिए चयन प्रक्रिया को चुनौती दी और इस मामले में खेल मंत्री किरण रिजिजू के हस्तक्षेप की मांग की। रिजिजू, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण को लिखे पत्र में बिधुड़ी ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के बेल्लारी में 29 व 30 दिसंबर को होने वाले ट्रायल्स से अनुचित तरीके से बाहर रखा गया। बिधूड़ी ने कहा कि मैं अन्यायपूर्ण व्यवस्था से तंग आ चुका हूं। इस साल विश्व चैंपियनशिप के पदकधारियों को सीधे ओलंपिक क्वालीफायर में प्रवेश दिया गया था। (प्रेट्र)

खेलो इंडिया से मदद मिली : हजारिका

नई दिल्ली : आइएसएसएफ जूनियर विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता ह्रदय हजारिका ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेलों के तीसरे सत्र से उन्हें 2020 में होने वाले टूर्नामेंटों की तैयारी में मदद मिली। ये खेल 10 से 22 जनवरी तक गुवाहाटी में आयोजित किए जाएंगे। हजारिका ने जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता जो 2016 के बाद उनका पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। गुवाहाटी में 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हजारिका ने कहा कि मैंने दो विश्व कप के बीच भारत और विदेश में कई टूर्नामेंट खेले जिनसे मुझे 2018 में स्वर्ण पदक जीतने में मदद मिली। (प्रेट्र)

कपिल ने 10 अंडर का शानदार कार्ड खेला

जमशेदपुर : दिल्ली के गोल्फर कपिल कुमार ने सत्र की अंतिम टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2019 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 अंडर 62 का कार्ड खेला। वह टाटा स्टील पीजीटीआइ में खेले जाने वाले पिछले दो टूर्नामेंट में भी प्रबल दावेदार थे। कोलकाता के भारतीय गोल्फ स्टार एसएसपी चौरसिया ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले दौर में नौ अंडर 63 का कार्ड खेला जिससे वह दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। पीजीटीआइ आर्डर ऑफ मेरिट खिताब के प्रबल दावेदार दिल्ली के राशिद खान 64 का कार्ड खेलकर बेंगलुरु के खालिन जोशी, कोलकाता के शंकर दास और बांग्लादेश के मुहम्मद जमाल हुसैन मुल्ला के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। (प्रेट्र)

इशांत और सिमरजीत ने किया दिल्ली को मजबूत

रणजी ट्रॉफी ▸ हैदराबाद के खिलाफ पारी की जीत के लिए चाहिए आठ विकेट

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और सिमरजीत सिंह की शानदार गेंदबाजी के दम पर दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप-ए के मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ पारी से जीत की ओर कदम बढ़ा दिए। पहली पारी में 284 रन बनाने के बाद दिल्ली ने यहां अरुण जेटली स्टेडियम में हैदराबाद को 29 ओवर में 69 रनों पर ऑलआउट आउट कर दिया। इशांत ने 10 ओवर में 19 रन देकर और सिमरजीत ने 10 ओवर में 23 रन देकर चार-चार विकेट लिए। बायें हाथ के तेज गेंदबाज पवन सुयाल को दो विकेट मिले।

सूर्यग्रहण के कारण दूसरे दिन गुरुवार को पूरे समय का खेल नहीं हुआ। फॉलोऑन खेलते हुए हैदराबाद ने दूसरी पारी के दो विकेट 20 रन पर गंवा दिए थे। दोनों विकेट ऑलराउंडर कुंवर बिधूड़ी ने लिए। हैदराबाद को पारी की हार से बचने के लिए 185 रन और बनाने हैं। इससे पहले दिल्ली ने आखिरी चार विकेट 15 रन के भीतर गंवा दिए। शिखर धवन (140) आउट होने वाले दिल्ली के आठवें बल्लेबाज रहे।

हिमाचल ने बनाई अहम बढ़त : नई दिल्ली : ग्रुप बी मुकाबले में मैसूर में हिमाचल प्रदेश ने कर्नाटक के खिलाफ पहली पारी में अहम बढ़त ले ली है। हिमाचल के गेंदबाजों ने कर्नाटक को 166 रनों पर समेट दिया था, जिसके जवाब में हिमाचल ने दिन का खेल खत्म होने तक सात विकेट के नुकसान पर 235 रन बना लिए है। हिमाचल के लिए ऋषि धवन 72 और आकाश वशिष्ठ 18 रन बनाकर नाबाद हैं। इन दोनों के अलावा प्रियांशु खंडुरी ने 69 रन बनाए। कर्नाटक के लिए वसुकी कौशिक ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए।

बाबुल को नहीं मिला दूसरे बल्लेबाजों का साथ

पटना : प्लेट ग्रुप में यहां गोवा के खिलाफ बिहार की टीम पहली पारी में 326 रनों पर सिमट गई। अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक जमाने वाले बाबुल कुमार (160 रन) को दूसरे बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। हालांकि मोइनुल हक स्टेडियम में खेल के दूसरे दिन गोवा ने पहली पारी में 65 रनों पर दो विकेट गंवा दिए हैं। ये दोनों विकेट बिहार के कप्तान ऑफ स्पिनर आशुतोष अमन ने लिए। दिन का खेल खत्म होने के समय आदित्य कौशिक 44 रन और अमूल्य पेंडरेकर तीन रन बनाकर क्रीज पर जमे हैं।

हैदराबाद के बल्लेबाज को आउट करने के बाद दिल्ली के गेंदबाज इशांत शर्मा। प्रेट्र

दूसरा दिन भी मौसम से रहा प्रभावित

जम्मू : मौसम बिगड़ने से लगातार खराब रोशनी मेजबान जम्मू-कश्मीर और मेहमान असम की टीम के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आलम यह है कि जीजीएम साइंस कॉलेज के हॉस्टल मैदान में जारी चार दिवसीय रणजी ट्रॉफी में अब तक दो दिन बीत जाने के बावजूद महज 52 ओवर का ही खेल संभव हो पाया है।

जम्मू-कश्मीर की टीम ने दूसरे दिन 18 ओवर में 59 रन से आगे पारी की शुरुआत की लेकिन खराब रोशनी के कारण मुकाबला अपने निर्धारित समय से दो घंटे के बाद सुबह 11.30 बजे ही शुरू हो पाया। जम्मू-कश्मीर की टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 52 ओवर में दो विकेट गंवाकर 210 रन बना लिए हैं।

सूर्यांश रैना 125 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 73 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि शुभम खजूरिया 120 गेंदों में 12 चौकों और एक छक्के की मदद से 72.50 के स्ट्राइक रेट से 87 रन बनाकर नाबाद हैं जबकि दूसरे छोर पर हीनान नजीर 13 रन बनाकर नाबाद हैं।

वेंकटेश ने एक वर्ष बाद वापसी कर जड़ा अर्धशतक

इंदौर : मध्यप्रदेश और तमिलनाडु के बीच ग्रुप बी मैच के दूसरे दिन सूर्यग्रहण के कारण मैच निर्धारित समय से दो घंटे देरी से शुरु हुआ। तमिलनाडु के पहली पारी में 149 रन के जवाब में वेंकटेश अय्यर (88), रमीज खान (87) और मिहिर हिरवानी (54*) ने अर्धशतक लगाते हुए मप्र को सात विकेट पर 281 रन तक पहुंचा दिया।

इस तरह मेजबान टीम को 132 रन की बढ़त मिल गई है जबकि उसके तीन विकेट शेष है। होलकर स्टेडियम में सुबह मप्र ने 56/3 से आगे खेलना शुरू किया। यश दुबे (12) को थंगरासु नटराजन ने आउट किया। विकेटकीपर बल्लेबाज हिमांशु मंत्री (2) को भी नटराजन ने ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिकने दिया। इसके बाद रमीज को वेंटकेश का बखूबी साथ मिला। ऑलराउंडर वेंकटेश ने अपना पिछला प्रथम श्रेणी मैच पिछले वर्ष छह दिसंबर को हैदराबाद के खिलाफ इसी मैदान पर खेला था और एक साल बाद वापसी करते हुए उन्होंने चौथे मैच में अपना पहला प्रथम श्रेणी अर्धशतक पूरा किया।

'टीम से बाहर था, अंतररात्मा की आवाज सुनी'

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले साल वनडे विश्व कप के लिए अनदेखी किए जाने के बाद भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के लिए आत्मनिरीक्षण करना काफी सकारात्मक रहा जिसने उन्हें चीजों को स्वीकार करने में मदद की। जब भारतीय टीम के धुरंधर इंग्लैंड में विश्व कप खेल रहे थे तब वह काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे।

वह 2015 विश्व कप तक सफेद गेंद के लिए पहली पसंद रहे थे लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया और उन्हें महसूस हुआ कि सफलता का पीछा करना हमेशा आदर्श नहीं होता। रहाणे ने कहा कि कभी कभार हम सफलता का पीछा करने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और तब हमें अचानक महसूस होता है कि हमें रुककर, बैठकर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। जब मुझे 2019 विश्व कप के लिए नहीं चुना गया तो मैंने बिलकुल ऐसा ही किया। साउथैंप्टन में हैंपशायर के लिए खेलते हुए दो महीने रहने के दौरान उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया। वेस्टइंडीज दौरे पर उन्होंने वापसी की और तीन साल में पहला टेस्ट शतक जड़ा। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी एक सैकड़ा जमाया।

संतुष्टि

- रहाणे ने कहा, काउंटी खेलने और द्रविड़ से बात करके मिली काफी मदद
- कहा, सफलता का पीछा करना हमेशा नहीं होता आदर्श

रहाणे ने कहा कि इस समय मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं और यह वेस्टइंडीज सीरीज से शुरू हुआ। मैं इंग्लैंड में था, काउंटी क्रिकेट खेल रहा था जिस दौरान मैंने सिर्फ क्रिकेटर के तौर पर नहीं बल्कि इंसान के तौर पर काफी कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि दो महीनों में मैंने सात मैच खेले इसलिए मैंने सिर्फ मैदान के अंदर की चीजें नहीं सीखीं बल्कि मैदान के बाहर की बातें भी सीखीं। रहाणे ने कहा कि मैं कभी कभार पार्क में अकेला पैदल चला, कभी कभार जॉगिंग की। कभी कभार मैं आराम से बैठकर कॉफी पीते हुए पिछले दिनों के बारे में सोचता।

यह भी सोचता कि जब मैंने अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था, उससे पहले जब मैं क्लब क्रिकेट या उम्र ग्रुप के क्रिकेट खेलता था तो मैं कैसा महसूस करता था। कैरेबियाई दौरे में खेलने से पहले रहाणे ने राहुल द्रविड़ से भी बातचीत की और उनसे बेहतर 'गाइड' उनके लिए कोई और नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि राहुल भाई से बातचीत ने भी मेरी मदद की कि मुझे अपनी बल्लेबाजी को बिलकुल सरल रखना चाहिए। एक बार में एक मैच के बारे में सोचो। सकारात्मक सोच रखो।

रहाणे ने कहा कि अब मैं बहुत ही अच्छी स्थिति में हूं। जो भी पहले हुआ, वह हो चुका है। अब मुझे आगे आने वाली चीजों पर ही ध्यान लगाना होगा।

हवाई शॉट खेलना गलत नहीं है : रोहित

मुंबई, प्रेट्र : भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा कि हवाई शॉट खेलना कोई अपराध नहीं है और युवाओं को अपना स्वाभाविक खेल दिखाने की छूट मिलनी चाहिए। रोहित ने अपना अंतरराष्ट्रीय करियर मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में शुरू किया लेकिन वह बाद में सीमित ओवरों के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज बन गए। रोहित यहां युवा अंडर-19 टीम के लिए यह बात कह रहे थे, जो विश्व कप खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंची हुई है।

रोहित ने कहा कि बड़े शॉट खेलने में कोई बुराई नहीं है। जब हम छोटे थे, तब खूब हवाई शॉट लगाते थे और हमें नेट्स से बाहर कर दिया जाता था क्योंकि आखिर में तो आप नतीजे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई खिलाड़ी हवाई शॉट खेलकर भी आपको नतीजे दे रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। युवाओं को ऐसे शॉट खेलने की चाहत रहती है। बल्लेबाजी करते समय हर कोई आकर्षक लगना चाहता है लेकिन यह भी जरूरी है कि वह अपना स्वाभाविक खेल दिखाए।

नजरिया

- भारतीय बल्लेबाज ने दी अंडर-19 विश्व कप टीम को शुभकामनाएं
- कहा, युवाओं को स्वाभाविक खेल दिखाने की मिले छूट

32 वर्षीय भारतीय ओपनर ने कहा कि हमें इसका ध्यान रखना होगा कि ये गलतियां बार-बार नहीं होनी चाहिए। किसी बल्लेबाज को यह ध्यान रखना होगा कि अगली बार कैसे खेलना है। हवाई शॉट खेलना कोई गुनाह नहीं है। आप 100 रन 50 गेंद में बनाएं या 200 गेंद में, रहेगा वो शतक ही।

उन्होंने कहा कि यदि कोई खिलाड़ी अपने हुनर को लेकर आत्मविश्वास से ओतप्रोत है तो मैं उसकी हौसलाअफजाई करूंगा। इन युवाओं पर बल्लेबाजी को लेकर कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। उन्हें खुलकर खेलने देना चाहिए। इसी तरह से वे नतीजे देंगे। उन्होंने गत चैंपियन भारत की अंडर-19 टीम को विश्व कप के लिए शुभकामनाएं भी दी। रोहित के लिए साल 2019 बेहद शानदार रहा जिसमें उन्होंने विश्व कप में पांच शतक समेत तीनों प्रारूप में कुल 10 बार 100 या इससे ज्यादा का स्कोर बनाया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ओपनिंग करते हुए दमदार प्रदर्शन किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दोहरा शतक समेत कुल तीन शतक जड़े।

एक कार्यक्रम के दौरान मुंबई में युवा क्रिकेटरों से बातचीत करते भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। प्रेट्र

विविध

अभिनेत्री मोना सिंह आज श्याम के साथ लेंगी सात फेरे

एंटरटेनमेंट डेस्क, मुंबई : अभिनेत्री मोना सिंह शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध जाएंगी। वह इनवेस्टमेंट बैंकर श्याम के साथ सात फेरे लेंगी। दक्षिण भारतीय श्याम के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

अभिनेत्री मोना सिंह। जागरण

करीबी दोस्त गौरव गेरा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर मोना की मेहंदी समारोह की कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किया। इनमें मोना और गौरव के अलावा उनके अन्य दोस्त भी नजर आ रहे हैं। गौरव ने लिखा, 'मोना की मेहंदी, मोना की शादी।' सूत्रों के मुताबिक, मोना और श्याम की शादी मुंबई में होगी। शादी समारोह में उनके कुछ रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को ही बुलाया गया है।

'जस्सी जैसी कोई नहीं' धारावाहिक से अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली मोना ने '3 इडियट्स' फिल्म में भी अभिनय किया है। उनकी वेबसीरीज 'मॉम : मिशन ओवर मार्स' हाल ही में रिलीज हुई थी। मोना जल्द ही फिल्म 'लाल सिंह चड्ढ़ा' में आमिर खान के साथ भी नजर आएंगी।

सूर्यग्रहण पर लगा कोहरे का 'ग्रहण'

पूरे समय घने धुंध में समाये भगवान भाष्कर को तलाशती रहीं आंखे

जेएनएन, नई दिल्ली

पौष मास की अमावस्या पर गुरुवार को लगा वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर कोहरे की घनी चादर में समाया। इससे भगवान भाष्कर की झलक भले न मिली लेकिन धर्मानुरागियों ने पूरी आस्था-श्रद्धा के साथ शास्त्र सम्मत विधान निभाया। शीतलहर व सर्द हवाओं के बीच श्रद्धालु परिक्रमा और भजन-कीर्तन करते रहे जबकि सुबह से ही मंदिरों के पट बंद रहे। दोपहर में ग्रहण पूर्ण होने के बाद श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आरती और पूजन कर दान-पुण्य किया।

वाराणसी के घाटों पर जुटे श्रद्धालु : वाराणसी में सुबह 8.20 बजे ग्रहण स्पर्श के साथ श्रद्धालुओं ने स्नान किया और पथरीली सीढ़ियों पर जप-तप के लिए स्थान पकड़ लिया। सुबह 9.40 पर स्नान के साथ भगवान सूर्य को पीड़ा मुक्ति कामना से पानी में उतरे और प्रार्थना के स्वर जोर पकड़ने लगे। ठीक 11.13 बजे मोक्ष मान के तहत स्नान -दान और आराध्य देवों के दर्शन पूजन विधान पूरे किए। सूर्य के मूल नक्षत्र व धनु राशि पर ग्रहण के संपूर्ण काल 2.53 घंटे लोगों ने पूजा-आराधना व साधना में बिताए। बुधवार रात सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक (वेध) लगने के साथ ही संकट मोचन मंदिर, दुर्गाकुंड, शीतला मंदिर समेत देवालयों के पट बंद हो गए थे। हालांकि काशीपुराधिपति बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पट सुबह छह बजे से 11.25 बजे तक बंद रहे। ग्रहण मोक्ष के बाद देवालयों में धुलाई और साज-श्रृंगार कर आरती पूजा का आरंभ किया गया। बाबा दरबार में बुधवार रात व गुरुवार दोपहर में भोग आरती में फलाहार समर्पित किया गया। घाटों पर सुबह की नैत्यिक आरती भी 11.30 बजे के बाद की गई।

बांकेबिहारी मंदिर सहित सभी मंदिरों के पट रहे बंद : वृंदावन में ठा. बांकेबिहारी मंदिर सहित सभी मंदिरों के पट गुरुवार की सुबह से बंद रहे। दर्शन के इंतजार में कुछ श्रद्धालु प्रवेशद्वार के पास बैठ भजन कीर्तन करते रहे। सर्द हवाओं और गलन में भी पंचकोसीय परिक्रमा में भीड़ रही। सूर्यग्रहण अस्त होते ही श्रद्धालुओं ने यमुना स्नान कर दान-पुण्य किया। ठा. बांकेबिहारी मंदिर के अलावा सप्तदेवालयों, राधाबल्लभ मंदिर, इस्कॉन, प्रेममंदिर समेत हर मंदिर, मठ और देवालय में दर्शन गुरुवार दोपहर तक श्रद्धालुओं को सुलभ न हो सके। दोपहर 12 बजे जब दर्शन खुले तो श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में टूट पड़ी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पट तीन बजे खोले गए। कासगंज स्थित सोरों के मंदिर के पट गुरुवार को ग्रहण मोक्ष के बाद दोपहर बाद एक बजे खोले गए। इसके बाद ही पूजा अर्चना की गई।

ओडिशा के अधिकतर शहरों में नहीं दिखा अद्भुत दृश्य : ओडिशा के आसमान पर छाए बादलों के चलते इस साल का आखिरी, दुर्लभ व अद्भुत सूर्यग्रहण देखने से राज्य के अधिकतर शहर के लोग वंचित रह गए। प्रदेश के अधिकांश शहरों में सुबह से ही बादल छाए रहे। वहीं, भुवनेश्वर में आकाश बादलों से ढका रहा। संबलपुर, बालेश्वर और पुरी में भी यही हाल बना रहा।

उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने देखा सूर्य ग्रहण : साल के अंतिम सूर्य ग्रहण (वलयाकार) का उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने दीदार किया। सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर साढ़े दस बजे तक सूर्य ग्रहण देखा गया। सूतक के चलते चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों समेत सभी मंदिरों के कपाट बंद रहे। हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर रोजाना सूर्योदय के समय होने वाली गंगा आरती भी ग्रहण का सूतक समाप्त होने के बाद 11.15 बजे हुई।

सूर्य ग्रहण का मोहक नजारा... : देश-दुनिया के लोग गुरुवार को पूरी उत्सुकता और रोमांच के साथ साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के गवाह बने। हालांकि दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग धुंध और बादलों के कारण सूर्य ग्रहण नहीं देख पाए तो कुछ जगहों पर सूर्य ग्रहण पूरी स्पष्टता के साथ नजर आया। इंडोनेशिया में सूर्य ग्रहण का मनमोहक नजारा। ग्रहण शुरू होने के साथ सूर्य धीरे-धीरे चंद्रमा की छाया में लगभग पूरी तरह ढक गया (मध्य में)। हालांकि फिर धीरे-धीरे चंद्रमा की छाया हट गई और सूर्य चमकने लगा। साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण को खगोलविदों ने 'रिंग ऑफ फायर' (आग का छल्ला) नाम दिया था। रायटर

फर्जी कागजों पर लोन कराकर गाड़ी खरीदने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- बिसरख कोतवाली पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अलग-अलग सोसायटी में रहकर फर्जी कागजों पर लोन कराकर गाड़ी खरीदने व उसको कम दाम में किसी अन्य को बेचने वाले गिरोह का बिसरख कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है जबकि कई अन्य आरोपित अभी फरार है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चार लग्जरी गाड़ियां, पांच दो पहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपित आधार कार्ड, वोटर आइडी सहित कई अन्य पहचान पत्र से छेड़छाड़ कर फोटो बदल देते थे और फर्जी फोटो लगाकर उक्त पते पर गाड़ी फाइनेंस कराते थे। जो लोग ऐसी गाड़ियों को बिना जांच पड़ताल के खरीदते थे, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है।

एसपी देहात रणविजय सिंह ने बताया कि बिसरख कोतवाली में एक व्यक्ति ने गत दिनों मुकदमा दर्ज कराया था कि क्षेत्र में फर्जी कागजों पर लोन कराकर गाड़ी खरीदने वाला गिरोह सक्रिय है। सूचना को गंभीरता से लेकर सीओ तृतीय राजीव कुमार सिंह व बिसरख कोतवाली प्रभारी मनोज पाठक की टीम ने आरोपितों की तलाश शुरू की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले दो आरोपितों अजहर खान निवासी निराला स्टेट व साजिश अली निवासी गौर सिटी को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। आरोपितों के कब्जे से वर्ना, क्रेटा, आइ 20, आइ टेन कार व पांच दो पहिया वाहन बरामद किए गए है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि साजिद पहले एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी कर चुका है। इस वजह से उसको फाइनेंस की पूरी प्रक्रिया पता है।

इंस्पेक्टर मनोज पाठक ने बताया कि आरोपितों ने क्रेटा महज दो लाख रुपये में बेच दी थी। जिस व्यक्ति को क्रेटा बेची गई थी, वह अभी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। वहीं फर्जी तरह से लोन कराकर खरीदी गई दो पहिया गाड़ियां महज बीस हजार रुपये में बेच दी जाती थी।

ऐसे कराते थे लोन : आरोपित अपने परिचितों का आधार कार्ड किसी तरह से हासिल कर लेते थे। इसके बाद फोटोशॉप का इस्तेमाल कर आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। नाम किसी और का और फोटो किसी और की लगा दी जाती थी। जालसाजी से आरोपित बैंक स्टेटमेंट तैयार करवाते थे और आसानी से बैंक से लोन ले लेते थे।

बैंकों को लगा चुके है करोड़ों का चूना

आरोपित दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग बैंकों को करोड़ों का चूना लगा चुके है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपित अब तक पचास से अधिक गाड़ियां फाइनेंस करा चुके है। फाइनेंस गाड़ियों को अलग-अलग लोगों को कम दाम में बेच देते थे।

छाप रहे थे नकली नोट और अमेरिकी डॉलर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाली करेंसी छापने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये लोग दिल्ली में भारतीय करेंसी सहित अमेरिकी डॉलर की छपाई करके देशभर में सप्लाई कर रहे थे। इनके पास से एक करोड़ 17 लाख 25 हजार के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसमें 54 लाख 89 हजार के नकली नोट और एक लाख 67 हजार से ज्यादा के नकली अमेरिकी डॉलर हैं। ये नोट लक्ष्मीनगर स्थित एक घर में छापे जा रहे थे। आरोपित अब तक छह करोड़ रुपये से ज्यादा के नकली नोट बाजार में खपा चुके हैं। इनके पाकिस्तानी और बांग्लादेशी संपर्क भी खंगाले जा रहे हैं।

स्पेशल सेल के डीसीपी पीएस कुशवाहा ने बताया कि कुछ दिनों से पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि एक गिरोह दिल्ली में नकली नोट व अमेरिकी डॉलर छापकर बाजार में खपा रहा है। गिरोह को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर सुनील, रविंद्र जोशी और विनोद बडोला की टीम को लगाया गया था। जांच में सुराग मिलने पर पुलिस ने 20 दिसंबर को लक्ष्मी नगर इलाके के एक मकान पर छापा मारकर वहां से मध्य प्रदेश के सतना निवासी तबरेज अहमद, दिल्ली के लक्ष्मीनगर निवासी शोएब मलिक और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी रघुराज सिंह को दबोच लिया। उनके पास से दो हजार, पांच सौ, दो सौ सहित पचास और दस रुपये के तीन लाख मूल्य के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपितों से उनके साथियों के बारे में पूछताछ की गई। इसके बाद दिल्ली के मुस्तफाबाद निवासी दानिश मलिक और दरियागंज के रहने वाले अनवान अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तस्करों के पास से पुलिस ने कुल 51 लाख 76 हजार पांच सौ के नोट और 100 डॉलर मूल्य के 1675 नकली अमेरिकी डॉलर जब्त किए।

उनके आवास से प्रिंटर, वटर पेपर के अलावा दो पिस्टल और चार कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में पता चला कि तबरेज गिरोह का सरगना है। मूल रूप से मध्य प्रदेश निवासी तबरेज ने ही दानिश के साथ मिलकर दिल्ली में शोएब के घर पर नकली नोट छापने की साजिश रची थी। आरोपितों पर पहले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज आज

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन शुक्रवार से शुरू होगा। रायपुर के सांइस कॉलेज मैदान में होने वाला यह महोत्सव 27 से 29 दिसंबर तक चलेगा। शुक्रवार को सुबह 10 बजे इसका आगाज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। वह आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे।

राज्य में पहली बार हो रहे इस आयोजन में पांच देश और 25 राज्यों के कलाकार शामिल होंगे। आयोजन में 39 जनजातीय प्रतिभागी दल जुटेंगे। 1350 प्रतिभागी आदिवासी नृत्य करेंगे। चार विधाओं में 43 नृत्य शैलियां देखने को मिलेंगी। देश- विदेश के नर्तक दल गुरुवार को ही पहुंच गए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत कांग्रेस के कई आला-नेता शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे।

अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को भी न्योता दिया गया है। पार्टी के आला-नेताओं ने संभावना जताई है कि वे भी राहुल के साथ आ सकती हैं, लेकिन गुरुवार रात तक उनके दौरे का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नहीं मिला।

मौसम विशेष

पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। दिन ठंडा बना रहेगा। दोपहर में हल्की धूप खिलेगी। जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क के साथ कंपकपाती सुबह में हल्का कोहरा व कुहासा रहेगा। दिन भी छिटपुट बादलों के साथ ठंडा रहेगा।

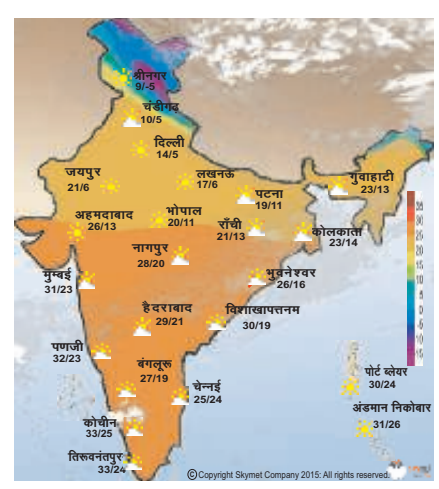

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	32/22/आंबा	अहमदाबाद	27/10/आंबा
कोलकाता	22/14/सा	बड़ौदा	28/16/आंबा
चेन्नई	32/23/आंबा	नागपुर	27/19/आंबा
हैदराबाद	28/20/आंबा	इन्दौर	21/14/सा
बंगलूरू	28/18/आंबा	राँची	23/10/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/25/सा	पटना	25/11/सा
गुवाहाटी	24/12/आंबा	जमशेदपुर	27/11/आंबा
गंगटोक	11/02/आंबा	पुणे	29/19/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 27 दिसंबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

मुस्लिम देशों में पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं बेनजीर की हत्या

आज ही के दिन 2007 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की रावलपिंडी में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। वह 2008 के आम चुनावों के लिए प्रचार कर रही थीं। वह किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थीं।

देश का राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में आज ही के दिन पहली बार 1911 में देश के राष्ट्रगान जन-गण-मन को गाया गया। संविधान सभा ने देश के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया। इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा, जिसका बाद में अनुवाद किया गया।

हुई मुद्दत की 'गालिब' मर गया पर याद आता है

आज ही 1797 में आगरा में मिर्जा असदुल्लाह बेग खान यानी मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। उमराव बेगम से बहुत कम उम्र में शादी हुई। 11 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। बाद में वह दिल्ली आ गए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन्हें दाबिर उल मुल्क, मिर्जा नोशा और नज्म उद दौला से नवाजा। गालिब ने उर्दू के साथ ही फारसी और तुर्की में भी शायरी की है। गजलों-नज्मों की जब बात चलती है तो गालिब का नाम सबसे ऊपर आता है। आज भी युवा शायर उनसे सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका निधन 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ।

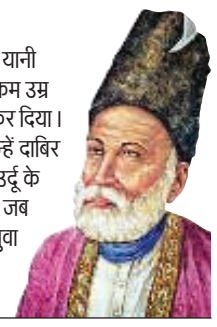

इधर-उधर की

कॉफी पीएं और खा जाएं कप

वेलिंगटन, एजेंसी : जिस कप में आपने अभी-अभी कॉफी पी है, उसे खाना। ये बातें कुछ हजम नहीं होती। लेकिन एयर न्यूजीलैंड ने कुछ ऐसा किया है जो आपकी सोच बदल देगा। दरअसल, इस एयरलाइन ने वनीला फ्लेवर्ड कप में यात्रियों को कॉफी परोसना शुरू किया है। इसे खाया भी जा सकता है। यह अनूठा प्रयोग विमानों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया गया है। कप बनाने के लिए एयरलाइंस ने एक विशेषज्ञ कंपनी से करार भी किया है। एयरलाइन की एक अधिकारी निक्की चावे ने बताया कि न्यूजीलैंड के विमानों में प्रतिवर्ष करीब अस्सी लाख कप कॉपी परोसे जाते हैं। ऐसे में इन कपों से काफी सहूलियत होगी। यात्रियों का फीडबैक भी संतोषप्रद है। ऐसा पहली बार नहीं है कि न्यूजीलैंड ने इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट किया है। पहले भी फ्लाइट और लाउंज में ऐसे विशेष कपों का चलन शुरू किया था।

जालसाजी रोकने में मदद करेगी नई स्याही

- सीएसआइआर और एनपीएल के वैज्ञानिकों ने तैयार की स्याही
- नकली दवाओं की पैकिंग और जाली नोटों को पहचानना होगा आसान

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सुरक्षा स्याही विकसित की है, जो पासपोर्ट जैसे दस्तावेज की नकल, नकली दवाओं की पैकिंग और मुद्रा नोटों की जालसाजी को रोकने में मददगार हो सकती है।

एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर इस स्याही में दो रंग उभरने लगते हैं। सामान्य प्रकाश में यह स्याही सफेद रंग की दिखाई देती है। लेकिन, जब इस पर 254 नैनोमीटर की आवृत्ति से पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो इससे लाल रंग उत्सर्जित होने लगता है और पराबैंगनी प्रकाश को बंद करते ही स्याही से हरा रंग उत्सर्जित होने लगता है।

पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से इस स्याही से लाल रंग 611 नैनोमीटर और हरा रंग 532 नैनोमीटर की आवृत्ति से उत्सर्जित होता है। लाल रंग का उत्सर्जन प्रतिदीप्ति (फ्लूअरेसंस) और हरे रंग का उत्सर्जन स्फुरदीप्ति (फॉस्फोरेसेंस) प्रभाव के कारण होता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), नई दिल्ली और एकेडेमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, गाजियाबाद के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ मैटेरियल्स केमिस्ट्री-सी में प्रकाशित किया गया है।

ऐसे तैयार की स्याही : स्याही के अपेक्षित गुण प्राप्त करने के लिए दो रंगों को 3:1 के अनुपात में मिलाया गया है। इस मिश्रण को 400 डिग्री तापमान पर तीन घंटे तक ऊष्मा से उपचारित किया गया है। इस तरह, एक तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति पर दो रंगों का उत्सर्जन करने वाली स्याही बनाने के लिए महीन सफेद पाउडर का विकास किया गया है। स्याही के उत्पादन पर पिगमेंट एक दूसरे से चिपक जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक तत्वों का ऊष्मीय उपचार किया गया है। अंततः पाउडर को पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) माध्यम के साथ मिलाया गया है ताकि चमकदार सुरक्षा स्याही प्राप्त की जा सके।

अब तक नहीं हुआ प्रयोग : पदार्थों के अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल उत्सर्जित करने के गुण को फ्लूअरेसंस कहते हैं। जबकि, फॉस्फोरेसेंस से तात्पर्य दहन या ज्ञात ऊष्मा के बिना किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश उत्सर्जन से है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए दोहरे रंग की चमक उत्सर्जित करने की यह एक नवीनतम तकनीक है और इसका इस्तेमाल नोटों या गोपनीय दस्तावेज की छपाई के लिए पहले नहीं किया गया है।

फ्लूअरेसंस और फॉस्फोरेसेंस के सिद्धांत पर है आधारित

एनपीएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख शोधकर्ता डॉ. बिपिन कुमार गुप्ता ने बताया कि इस स्याही का विकास प्रतिदीप्ति (फ्लूअरेसन्स)-स्फुरदीप्ति (फॉस्फोरेसेंस) सिद्धांत पर आधारित है, जो एक तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति पर ही दो रंगों का उत्सर्जन करती है। आमतौर पर दो रंगों के उत्सर्जन के लिए दोहरी आवृत्ति के तरंग दैर्ध्य की जरूरत पड़ती है। लाल एवं हरा रंग उत्सर्जित करने वाली यह चमकदार स्याही विकसित करने के लिए रासायनिक तत्वों (सोडियम इट्रियम फ्लोराइड, यूरोपियम डोप्ड और स्ट्रोन्टियम एल्युमिनेट) को यूरोपियम-डिस्प्रोसियम के साथ संश्लेषित किया गया है।

नए मॉडल से खुलेंगे मस्तिष्क के राज

तकनीक ▶ अल्ट्रास्मॉल मेटलिक वायर से वैज्ञानिकों ने विकसित किया नेटवर्क

मस्तिष्क की गणना प्रणाली को समझने में मिलेगी मदद

यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

टोक्यो, प्रेट्र : दुनिया में कई ऐसी गुत्थियां हैं, जिसे सुलझाने की कवायद जितनी अधिक होती है, वह उतनी ही उलझती जाती है। इन्हीं में एक इंसानी दिमाग के काम करने की गुत्थी भी है। इसे लेकर अभी तक कई शोध और अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन सटीक पता नहीं लग सका है कि हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग कैसे काम करता है। हालांकि, अब शोधकर्ताओं ने अल्ट्रास्मॉल मेटालिक वायर से बने एक नेटवर्क को विकसित किया है। माना जा रहा है कि यह मस्तिष्क की गणना प्रणाली को समझने का नया रास्ता दिखा सकता है। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने मानव के मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों खासतौर पर याददाश्त, सीखना और भूलने जैसी प्रक्रिया की नकल बनाने के लिए मेटालिक नैनोवायर नेटवर्क का प्रयोग किया।

जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैटेरियल साइंस सहित अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं के अनुसार, मस्तिष्क की तरह काम करने में सक्षम प्रणाली मस्तिष्क विज्ञान को और अधिक विकसित स्तर पर ले जाने में प्रभावी साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं ने एक बयान में कहा कि इस अध्ययन के लिए उन्होंने न्यूरोन्स और उनके बीच जोड़ने वाले सिनैप्स (सूत्रयुग्मन) जैसे मस्तिष्क के बुनियादी घटकों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। हालांकि, अभी भी मस्तिष्क से जुड़े कई सवाल पूरी तरह अनुत्तरित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रायोगिक शोध में जीवंत मस्तिष्क के साथ हेरफेर करना मुश्किल है, क्योंकि तब मस्तिष्क एक 'रहस्यमयी अंग' बना रहता है। उन्होंने इन चुनौतियों से पार पाने के लिए एक प्रणाली विकसित की, जो मस्तिष्क की तरह काम करने में सक्षम हो, ताकि ज्ञान-संबंधी प्रक्रिया के पीछे के तंत्र की पड़ताल की जा सके।

ऐस बनाया नया मॉडल : शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क की तरह अपने जटिल नेटवर्क को बनाने के लिए पॉलिमर इंसुलेशन से लिपटे सिल्वर नैनोवायर का प्रयोग किया। इसमें सिनैप्स बनाने के लिए दो नैनोवायर के बीच एक जोड़ का भी प्रयोग किया गया। अध्ययन के अनुसार, नैनोवायर में बड़ी संख्या में परस्पर प्रभाव वाले विस्तृत सिनैप्टिक होते हैं और यही 'न्यूरोमॉर्फिक नेटवर्क' का निर्माण करते हैं। जब इस नेटवर्क में विद्युत बल का प्रयोग किया जाता है, तो यह अपना सर्वोत्तम प्रवाह का रास्ता तलाशने में 'जद्दोजेहद' करता है। शोधकर्ताओं की टीम ने नेटवर्क से विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद प्रवाह के मार्ग निर्माण, अवरोधन और निष्क्रियता को मापा। उन्होंने पाया कि जैसे-जैसे इनमें प्रगति होती है, वैसे-वैसे इनमें उतार-चढ़ाव आता है। यह प्रक्रिया कुछ उसी तरह है, जैसे मानव का मस्तिष्क याददाश्त, सीखने और भूलने की प्रक्रिया के दौरान काम करता है।

मेमोरी डिवाइस बनाने में जुटे शोधकर्ता : वैज्ञानिकों के अनुसार, इन दोनों की प्रक्रिया में भी एकरूपता होती है, जिसके जरिये मस्तिष्क चौकन्ना होता है या शांत होता है। शोधकर्ता अब इन निष्कर्षों के आधार पर मस्तिष्क की तरह मेमोरी डिवाइस विकसित कर रहे हैं, जो फिलहाल कंप्यूटर में प्रयोग हो रहे सिद्धांतों से बिल्कुल तरह से काम करते हैं।

शोध अनुसंधान

एआइ की मदद से हो सकेगी ब्लड कैंसर की जांच

कैंसर की समय पर जांच इसके इलाज की दिशा में महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार जांच के ऐसे तरीके विकसित करने के प्रयास में हैं, जिनसे अलग-अलग प्रकार के कैंसर को सटीक तरीके से पहचाना जा सके। शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) की मदद से ब्लड कैंसर के अलग-अलग प्रकार की पहचान की है। जांच की यह प्रक्रिया खून में मौजूद कोशिकाओं की जीन गतिविधि पर केंद्रित है। शोधकर्ता प्रोफेसर जाओचिम स्कल्ज ने कहा, 'इस संबंध में कई शोध हुए हैं और उनका डाटा भी उपलब्ध है।' वैज्ञानिकों ने ऐसे डाटा को एकत्र कर एआइ की मदद से उनका विश्लेषण किया। इस सफलता के बाद वैज्ञानिक डिमेंशिया समेत अन्य बीमारियों की सटीक जांच के लिए भी ऐसा तरीका विकसित करने की कोशिश में हैं। - एएनआइ

नियंत्रित हो सकेगी जीन थेरेपी की प्रक्रिया

वैज्ञानिकों ने एक विशेष मॉलीक्यूलर मैकेनिज्म तैयार किया है, जिसकी मदद से जीन थेरेपी की प्रक्रिया को नियंत्रित करना संभव हो सकेगा। इस शोध को विज्ञान पत्रिका 'नेचर बायोलॉजी' में प्रकाशित किया गया है। जीन थेरेपी कई गंभीर बीमारियों के इलाज में कारगर साबित होती है। इस दौरान पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि इसमें जीन को सक्रिय कर इलाज किया जाता है। जीन की सक्रियता और स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करने में चूक से इलाज पर असर पड़ता है। अब वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक विकसित की है, जिसकी मदद से जरूरत के हिसाब से इलाज नियंत्रित करना संभव है। एनीमिया के लिए होने वाली जीन थेरेपी पर इसे आजमाया गया। - एएनआइ

आइस हॉकी मैच में पुतिन ने टीम को दिलाई जीत

रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (सामने) ने रेड स्क्वायर में आइस रिंक पर नाइट हॉकी लीग के एक प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लिया। इस दौरान पुतिन ने एथलेटिक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। क्रिसमस के मौके पर खेले गए सालाना मैच में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को 8-5 से जीत दिलाई। टीम के लिए आधे से अधिक गोल राष्ट्रपति पुतिन ने ही किए। खेलों के शौकीन पुतिन जूडो ब्लैकबेल्ट हैं। रायटर

सील ने किया आगामी चंद्र वर्ष का स्वागत

एशिया के कई देशों में नव वर्ष के साथ-साथ चंद्र वर्ष के आगमन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। उधर, जापान के हक्केजिमा सागर के पास एक समारोह में गुरुवार को इस सोलह वर्षीय सील 'लियो' ने अपने मुंह से ब्रश उठाकर एक कागज पर चीनी भाषा में 'चूहा' लिखकर आगामी चंद्र वर्ष का स्वागत किया। बता दें कि हर साल चंद्र वर्ष किसी न किसी जानवर को समर्पित होता है। आने वाला चंद्र वर्ष चूहे को समर्पित किया जाएगा। वर्ष 2019 सुअरों के नाम था। एएफपी

फिल्म रिव्यू

गुड न्यूज

प्रमुख कलाकार: अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी, आदिल हुसैन, टिस्का चोपड़ा
निर्देशक: राज मेहता
अवधि: 2 घंटे 13 मिनट

चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े मसले हमेशा से फिल्मकारों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो सरोगेसी के मुद्दे पर मेघना गुलजार ने फिल्म 'फिलहाल' बनाई थी। हाल की बात करें तो 'गब्बर इज बैक' में मेडिकल क्षेत्र में व्याप्त धांधली रही। उसके अलावा दुर्लभ बीमारियों पर 'तारे जमीं पर', 'गुजारिश', 'पा' जैसी अनेक फिल्में बनी हैं। हालांकि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन (आइवीएफ) केंद्रित कोई फिल्म नहीं आई है। कई बार माता-पिता बनने की ख्वाहिश रखने के बावजूद दंपती उस सुख से वंचित रह जाते हैं। उन हालात में महंगी होने के बावजूद आइवीएफ तकनीक उनके वंश को आगे बढ़ाने के सपने को पूरा करती है। हालांकि गुड न्यूज के चक्कर में आइवीएफ में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो दपंती को मानसिक तौर पर निजी जीवन में किन दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, उन्हीं बिंदुओं के मदेनजर 'गुड न्यूज' गढ़ी गई है।

सात साल के वैवाहिक जीवन के बावजूद मुंबई में रह रहे वरुण बत्रा (अक्षय कुमार) और उनकी पत्नी दीप्ति बत्रा (करीना कपूर खान) निःसंतान है। दोनों नौकरीपेशा हैं। आइवीएफ की मदद से बच्चा होने की उनमें आस जागती है। गुड न्यूज का इंतजार कर रहे बत्रा दंपती की जिंदगी में तब खलबली मच जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि तकनीशियन से बड़ी भूल हो गई है। डॉक्टर बताते हैं कि दीप्ति के अंडाणु का निषेचन एक अन्य बत्रा हनी (दिलजीत दोसांझ) के स्पर्म से हो गया है, वहीं हनी की पत्नी मोनिका (कियारा आडवाणी) के अंडाणु का निषेचन वरुण के स्पर्म के साथ। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट दीप्ति गर्भपात न कराने का निर्णय लेती है। उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को वरुण स्वीकार करने को राजी नहीं है। वहीं मोनिका माता रानी का आशीर्वाद मानकर खुश है, जबकि हनी अपने बच्चे की चाहत में गिरफ्तार है। दोनों दंपती के आपसी द्वंद्व और टकराव के साथ चारों की जिंदगी किस दिशा में जाती है, कहानी यही बताती है।

ताजगी से भरपूर कहानी

ज्योति कपूर की कहानी और स्क्रीनप्ले में ताजगी और नवीनता है। उन्होंने पढ़ी-लिखी और नौकरीपेशा दीप्ति के साथ घरेलू मोनिका के आंतरिक द्वंद्व को उभारने के साथ और पितृसत्तात्मक समाज की सोच पर करारा प्रहार किया है। निःसंतान दंपती पर बच्चे को लेकर सामाजिक दबाव, डॉक्टरों द्वारा अपनी क्लीनिक चलाने को लेकर किए जाने वाले प्रचार-प्रसार, पुरुषों की रुढ़िवादी मानसिकता को भी संवदेनशीलता से उठाया है। महिलाएं परिवार की खुशियों की खातिर जानते-बूझते हुए भी खामोशी से सब सह जाती हैं। वहीं वरुण और हनी समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रुढ़िवादी सोच और मानसिकता के शिकार हैं। ज्योति ने जिस बारीकी से हर पहलू को उठाते हुए स्क्रीनप्ले गढ़ा है, वह काबिलेतारीफ है। ज्योति के साथ राज मेहता और ऋषभ शर्मा ने फिल्म के डायलॉग लिखे हैं, जो हंसाने के साथ झकझोरते भी हैं।

राज मेहता की बतौर स्वतंत्र निर्देशक यह पहली फिल्म है। उन्होंने कहानी के सुर को बरकरार रखा है। उसे कायम रखने में उन्हें कलाकारों का पूरा सहयोग मिला है। अक्षय अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को गुदगुदाने में पूरी तरह सफल रहते हैं। करीना बेहद स्टाइलिश लगी हैं। मोनिका की मासूमियत को दर्शाने में कियारा आडवाणी सहज नजर आती हैं। दिलजीत दोसांझ अपनी अदायगी से दिल जीतने में कामयाब रहते हैं। -स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

पहले डरता था कि पार्टी में कोई आएगा या नहीं : सलमान

सात सवाल

सलमान खान आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन से पहले उन्होंने दिए कुछ सवालों के जवाब :

● आप इस उम्र में भी जवां दिखते हैं। इसका राज क्या है?

माता-पिता ने अच्छे जीन्स दिए हैं। वर्कआउट कर लेता हूं। पहले सीनियर्स से प्रतिस्पर्धा मुश्किल थी, अब जूनियर्स से प्रतिस्पर्धा करना और भी मुश्किल हो गया है। फैंस ने इतनी इज्जत दी है तो अब मेहनत करनी ही पड़ेगी।।

● स्टार बनने से पहले आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते थे?

- वैसे ही जैसे अब मनाता हूं। उस वक्त जब लोगों को बुलाता था, तो डर लगता था कि कोई आएगा या नहीं आएगा। पार्टी देने में थोड़ी तकलीफ होती थी। अब हालात उलट हैं। पहले एक को बुलाते थे, तो एक भी नहीं आता था। अब एक को बुलाते हैं, तो साथ में दस आ जाते हैं।

● इस पड़ाव पर खुद को कैसे परिभाषित करेंगे...

- जैसा था, वैसा ही हूं। मुझमें कोई बदलाव आया ही नहीं। जितनी बातें सीखनी थी बचपन में उतनी सीख लीं, उसी को इंप्रोवाइज और इंप्रूव किए जा रहा हूं।

● सुपरस्टार बनने की खासियत क्या है?

- सुपरस्टार बनने में कुछ भी स्पेशल नहीं है। जो लोग अपने आपको आज सुपरस्टार समझते हैं, उन्हें पहले कोई देखा नहीं करता था। 25-50 प्रतिभाशाली लोगों ने उस इंसान को कैमरे के सामने खड़े करके ऐसे दर्शाया कि पूरा हिंदुस्तान उसके लिए पागल हो गया। उसमें उसका क्या योगदान है? स्टारडम जब नहीं रहता है, तब उसे बहुत तकलीफ होती है। अभिनय करना मुझे पसंद है। मेरे पास पूरी टीम है, जो मुझे उस तरीके से पेश करती है, ताकि फैंस को पसंद आए। अकेला इंसान यह काम नहीं कर सकता है। पर्दे पर दिखने वाली चीजों के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है।

● क्या अभिनेता रिटायर होते हैं?

- एक्टरों को हटा दिया जाता है। जब उनकी टिकटें नहीं बिकती हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। कोई एक्टर रिटायर नहीं होना चाहता है।

● आपकी बहन अलवीरा, भाई अरबाज के बच्चे इस क्षेत्र में आने के लिए तैयार हो रहे हैं?

- अभी तक तो कोई तैयार नहीं हो रहा है।

● अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाता है, तो आप उसे कितना माफ कर पाते हैं?

- कुछ लोग बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें तुरंत माफ कर देता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मैंने माफ कर दिया तो सबसे बड़ा इडियट मैं ही साबित होऊंगा। - स्मिता श्रीवास्तव

निक ने प्रियंका को दिया क्रिसमस का तोहफा

कुछ दिनों पहले अपनी शादी का सालगिरह पर प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनास को एक डॉग गिफ्ट किया था। अब निक ने क्रिसमस को प्रियंका के लिए खास बना दिया। प्रियंका ने निक के तोहफों की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। निक ने प्रियंका को इलेक्ट्रिक स्नोमोबाइल (एक प्रकार की बाइक, जिसे बर्फ पर चलाया जा सकता है) गिफ्ट की, जिसे प्रियंका तक खुद सांता ने चलाकर पहुंचाई। अमेरिका में स्नो के बीच प्रियंका ने निक को अपने पीछे बिठाकर स्नो पर वह स्नोमोबाइल चलाई भी। प्रियंका ने लिखा, 'मेरे पति मुझे अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद बेबी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं।' निक ने भी तोहफे के साथ प्रियंका की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'उसे हंसता हुआ देखने से बेहतर और कुछ नहीं है।' इस मौके पर प्रियंका की मम्मी मधु चोपड़ा और भाई सिद्धार्थ भी मौजूद थे। प्रियंका ने परिवार के साथ क्रिसमस पार्टी की तस्वीर भी साझा की है। प्रियंका फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं। वह निक के साथ संगीत प्रोजेक्ट भी को-प्रोड्यूस करने वाली हैं।

कुछ ऐसी थी राधिका की पहली डेट...

बेबाक अभिनेत्रियों में राधिका आप्टे का नाम भी शुमार है। 'अंधाधुन', 'बाजार', 'पैडमैन' जैसी फिल्में कर चुकीं राधिका अपने व्यक्तिगत जीवन पर खुलकर बात करती हैं। नेटफ्लिक्स के प्रसिद्ध शो 'द ब्रैंड न्यू शो' में उन्होंने अपनी लव लाइफ से जुड़ी बातें बताईं। शो के होस्ट ने जब राधिका से उनके डेटिंग अनुभवों के बारे में पूछा, तब राधिका ने बताया कि उन्होंने कभी अपने से छोटी उम्र के लड़के को डेट नहीं किया। राधिका ने बताया कि एक ऐसा वक्त था, जब उन्हें दो लड़कों ने एक दिन एक ही समय पर डेट का ऑफर दिया। राधिका परेशान थीं कि किसके साथ जाएं। दो लड़कों में से एक थे बेनेडिक्ट टेलर, जो आज राधिका के पति हैं। राधिका ने बताया कि दोनों में से एक को चुनने के लिए उन्होंने बिल्ली की मदद ली, जो रोज उनके घर आया करती थी। राधिका उसे मछली खाने को देती थीं। राधिका ने तय किया कि अगर बिल्ली ने मछली खा ली, तो वह बेनेडिक्ट के साथ जाएंगी, अगर नहीं खाई तो दूसरे लड़के साथ। बिल्ली ने मछली खा ली और राधिका बेनेडिक्ट के साथ डेट पर चली गईं। उसके बाद बेनेडिक्ट से राधिका की शादी वर्ष 2012 में हुई।

अध्ययन

अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने किया दावा, कहा- एकीकृत रोमन साम्राज्य के 69 शासकों में से 43 की हिंसक घटनाओं में हुई थी मौत

हिंसा के कारण गई ज्यादातर रोमन सम्राटों की जान

वाशिंगटन, प्रेट्र: रोमन सम्राटों को अपने शासन काल के शुरुआती वर्षों में हिंसक घटनाओं का सामना करना पड़ा और कई राजाओं की मौत भी वीभत्स तरीके से की गई थी। हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं का कहना है कि रोमन सम्राटों के शासनकाल की शुरुआती अवधि में उनकी मौत में एक खास पैटर्न नजर आता है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि एकीकृत रोमन साम्राज्य के 69 शासकों में से 43 (62 फीसदी) की मौत हिंसक तरीके से की गई थी। चाहे वह हत्या, आत्महत्या या फिर युद्ध के दौरान हत्या ही क्यों न हो।

ऐतिहासिक विवरण आमतौर पर हर मौत की पड़ताल एकल और अचानक घटित घटना के तौर पर करता है। इसमें कुछ खास कारकों जैसे उनकी निष्ठा और संपत्ति का योगदान होता है।

रोमन साम्राज्य की बुनियाद : रोमन साम्राज्य की नींव उस वक्त पड़ी, जब ऑगस्टस सीजर ने 31 ईसा पूर्व खुद को रोम का पहला सम्राट घोषित किया। रोमन साम्राज्य का खात्मा 1453 में कांस्टेंटीनोपुल के पतन के साथ हुआ। पलग्रेव कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से बताया गया है कि यह ज्ञात नहीं है कि मृत्यु से पहले हर सम्राट के शासनकाल की अवधि कितने वर्षों की रही।

रोमन सम्राट कांस्टेंटीन की प्रतिमा। फाइल

ऐसे लगाया पता : शोधकर्ताओं ने व्यावहारिक घटकों की विश्वसनीयता की जांच के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाली सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग करते हुए एक सम्राट के शासनकाल और उसकी मृत्यु के बीच की अवधि का पता लगाया। उन्होंने घटकों की विफलता और सम्राटों की मौत में समानता पाई। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जोसेफ सालेह ने कहा, 'रोमन सम्राटों ने अपने शासन के शुरुआती वर्ष में हिंसक मौतों का सबसे अधिक खतरा झेला था। उन्होंने बताया कि मौत का जोखिम आठवें वर्ष में कम हुआ, लेकिन फिर 12 वर्षों के शासन के बाद बढ़ गया। ऐसा उनकी थकान, खामियों और अराजकता की वजह से हुआ। जब आंकड़ों का ग्राफ बनाया गया, तो रोमन सम्राटों की विफलता की रेखा बाथटब जैसी दिखी, जो आमतौर पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल घटकों में दिखती है।

हालांकि, शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आंकड़ों की सीमा को भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि प्राचीन इतिहास के स्रोत अक्सर एक समान नहीं (अस्थिर) होते हैं और इससे विभिन्न स्रोतों के कारण मौत की वजहें भी अलग-अलग हो सकती हैं।